

उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों की
कार्यदशाएँ, सफलताएँ तथा समस्याओं
का समाजशास्त्रीय विश्लेषण :
इलाहाबाद तथा कानपुर
क्षेत्र के सन्दर्भ में

इलाहाबाद विश्वविद्यालय कला संकाय की डी० फिल्ड
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध



निर्देशक

प्रो० ए. आर. एन. श्रीवास्तव

पी०एच०डी० (एरिजोना)

विभागाध्यक्ष

मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

शोधार्थी

मधु सिसौदिया

एम०ए० (समाजशास्त्र)

शोध छात्रा (समाजशास्त्र)

मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

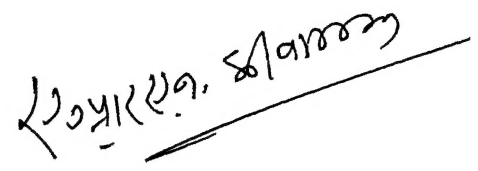
2002



विभागाध्यक्ष: मानव विज्ञान व समाजशास्त्र

4 नवम्बर 2002

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध "उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों की कार्यदशाएँ, सफलताएँ तथा समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण . इलाहाबाद तथा कानपुर क्षेत्र के संदर्भ में", मधु सिसौदिया (एम०ए० समाजशास्त्र) द्वारा समाजशास्त्र विषय में डी० फिल० उपाधि हेतु मेरे निर्देशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नियमानुसार सम्पन्न किया गया है। इस मौलिक कार्य का प्रणयन इनके द्वारा एकत्रित किये गये तथ्यों पर आधारित है।


(ए० आर० एन० श्रीवास्तव)
निर्देशक

‘समर्पित’

मैं अपना शोध-प्रबन्ध कार्य
अपने पूज्य बाबा जी
“स्वर्गीय श्री फतेहसिंह जी”
को समर्पित करती हूँ।

दो-शब्द

किसी महत्वपूर्ण कार्य के सम्पादन में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करने वाले सम्मानीय व्यक्तियों के प्रति आभार प्रदर्शन करना महज एक औपचारिकता है। वस्तुतः शोध कार्य के पथ पर प्रदीप तुल्य इन महानुभावों के द्वारा प्रदत्त आलोक मेरे लिए पथ प्रदर्शन रहा है। जिसका परिणाम प्रस्तुत शोध प्रबन्ध है।

सर्वप्रथम मैं अपने योग्य गुरु 'प्रो० ए० आर० एन० श्रीवास्तव' जी की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने शोध विषय का चुनाव कार्य की रूपरेखा निर्मित करने से लेकर अन्त तक, पग-पग पर सहयोग व आशीर्वाद प्रदान किया, जिससे यह शोध प्रबन्ध पूर्ण हुआ।

इसी के साथ-साथ मैं 'डॉ० ए० के० झा', लेक्चरर, ज्ञानपुर डिग्री कालेज, ज्ञानपुर के समय-समय पर दिये गये मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ।

यह शोध कार्य करने की प्रारम्भिक प्रेरणा मुझे मेरी मम्मी 'श्रीमती मजू सिंह सिसौदिया' एवं पापा 'श्री दीप चन्द्र सिसौदिया' से प्राप्त हुई! जिन्होंने इस शोध कार्य की समाप्ति तक हर पल मेरा उत्साहवर्धन एवं सहयोग किया, जिसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकती हूँ।

इसी श्रृंखला में उन लोगों का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे शोध कार्य के लिए तथ्यों को एकत्रित करने में सहायता दी। सर्वप्रथम मैं अपने मामा 'श्री शिवमगल सिंह', अवकाश प्राप्त "पुलिस अधीक्षक" का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे पुलिस मुख्यालय से महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध करायी और कानपुर क्षेत्र की महिला पुलिस कर्मियों से प्रश्नों के उत्तर भरवाने के लिए मुझे अपने साथ लेकर एस०एस०पी० आफिस, चौकी गए। पुलिस मुख्यालय से सूचना प्राप्त कराने में अकल 'स्व० शमशेर सिंह चंदेल' (पुलिस उपाधीक्षक) की भी आभारी हूँ। मेरे ममेरे भाई 'श्री विक्रम आनन्द सिंह' (प्लान्टून कामाण्डर, पी०ए०सी०) और 'श्री विवेकानन्द सिंह' (चिकित्सक) ने कानपुर जिले में दूर-दराज के पुलिस थानों और चौकियों में मेरे साथ जाकर महिला पुलिस कर्मियों

से अनुसूचियाँ भरवाने में मदद की। इसके अलावा मेरे छोटे मामा 'श्री सहदेव सिंह' (वर्कशाप इन्सपेक्टर, रोडवेज, झूँसी), मामी 'श्रीमती अमरजीत सिंह' (सुपरवाइजर—समाज कल्याण विभाग) एवं 'श्रीमती सतोष सिंह' (अवकाश प्राप्त—मैट्रिन) ने भी सूचनादाताओं तक पहुँचाने और सूचना एकत्र करने में सहायता की।

अन्य सहयोगियों में 'श्री पंकज शुक्ला' (छात्र—एम०सी०ए०) ने सामान्य सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त कराने में सहायता की। मेरे छोटे भाई 'अनिरुद्ध सिंह सिसौदिया' (कम्प्यूटर प्रोग्रामर) ने अपने अति व्यस्त दिनचर्या के बीच भी समय निकालकर सारणी का चित्रो में प्रस्तुतिकरण करके मेरे शोध प्रबन्ध को पूरा करने में अविस्मरणीय योगदान किया। मेरे सबसे छोटे भाई 'प्रद्युम्न सिंह सिसौदिया' (छात्र—बी०आई०टी०) ने शोध प्रबन्ध को टाइप कराने और सारणी को दिल्ली भेजने (बड़े भाई के पास), और फिर चित्र को वापस प्राप्त करने में मुझे महत्वपूर्ण मदद दी।

मैं उन लोगों का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिनका समय और सहयोग किसी एक जगह पर नहीं बल्कि स्थान—स्थान पर आवश्यकता की माँग के अनुरूप रहा है। जैसे—मेरी छोटी बहन 'नीतू सिंह सिसौदिया' एवं मेरी मौसी 'श्रीमती सावित्री सिंह', भइया 'विजय वीर विक्रम सिंह' एवं 'महेन्द्र विक्रम सिंह'। 'श्री रतन खरे' (प्रबन्धक, जय दुर्गे माँ कम्प्यूटर प्वाइट, मनमोहन पार्क, कटरा, इलाहाबाद), 'श्री रमेश कुमार यादव', 'श्री सतोष दास', 'श्री चन्द्रभान सिंह' की भी आभारी हूँ, जिन्होंने अल्प समय में शोध प्रबन्ध तैयार करवाकर मुझे सहायता प्रदान की है।

(मधु सिसौदिया)

शोधार्थी

मधु सिसौदिया

4.11.2002.

विषय-सूची (Contents)

		पृष्ठ संख्या
अध्याय-१	◆ भारत में पुलिस बल समाजशास्त्रीय आयाम	1-26
	❖ भूमिका	1-6
	❖ चयनित पूर्व अध्ययनों का सारांश	1-5
	❖ महिला पुलिस कर्मियों के सम्बन्ध में सक्षिप्त विवरण	7-10
	❖ उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस बल	10
	❖ उत्तर प्रदेश के तीन धार्मिक स्थलों के सुरक्षार्थ स्वीकृत पदों का विवरण	10
	❖ महिला थानों की संख्या, जनपद जहाँ पर महिला थाने हैं तथा उनके लिए स्वीकृत पदों का विवरण	11
	❖ उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस का जनपदवार स्वीकृत नियतन	12-14
	❖ मुख्यालय और प्रमुख	15-26
	❖ प्रशासनिक संगठन	15-16
	❖ नियतन	16-25
	❖ पुलिस प्रशिक्षण	26
	❖ सन्दर्भ ग्रन्थ	27
अध्याय-२	◆ शोध-प्ररचना	28-49
	❖ शोध-प्ररचना का तात्पर्य	28-30
	❖ अनुसंधान प्ररचना के प्रमुख प्रकार	30-32
	❖ प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य	32
	❖ उपकल्पनाएँ	32-33
	❖ तथ्य प्राप्ति के स्रोत	33-34
	❖ अध्ययन इकाईयों का निर्धारण	34
	❖ अध्ययन क्षेत्र	34-35
	❖ इलाहाबाद और कानपुर का सामान्य परिचय	36-42
	❖ निदर्शन	42-44
	❖ तथ्य सकलन विधि	44
	❖ पूर्वगामी सर्वेक्षण	44-45
	❖ स्वतंत्र चर	45-46
	❖ आश्रित चर	46
	❖ सारणीयन एवं विश्लेषण	46
	❖ कठिनाईयों	47-48

	❖ सन्दर्भ ग्रन्थ	49
अध्याय-३	◆ उत्तरदाताओं का परिचय	50-70
	❖ आयु	50-53
	❖ लिंग	53-55
	❖ सेवाकाल	56-58
	❖ शिक्षा	58-61
	❖ वैवाहिक स्थिति	61-63
	❖ धर्म	65-66
	❖ जाति	66-69
	❖ निवास निर्धारण	69-70
अध्याय-४	◆ महिला पुलिस की भूमिका और प्रास्थिति	71-99
	❖ महिला पुलिस की भूमिका और प्रास्थिति	71-75
	❖ महिला पुलिस कर्मियों की स्वयं की "भूमिका पालन" के बारे में मत	76-77
	❖ पुरुष पुलिस कर्मियों का महिला पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के बारे में विचार	78-80
	❖ किसी मामले को निपटाने में महिला पुलिस कर्मियों के प्रति सामान्य सूचनादाताओं (विभिन्न क्षेत्र से सम्बन्धित स्त्री/पुरुष) का दृष्टिकोण	80-81
	❖ त्यौहार, उत्सव, व्रत इत्यादि अवसरों पर तनाव की स्थिति . महिला पुलिस कर्मियों का मत	82-83
	❖ पुलिस विभाग की महिला से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने में क्या कोई दिक्कत महसूस करेंगे ? सामान्य सूचनादाताओं का मत	83-85
	❖ महिला पुलिस कर्मियों से विवाह न करने के कारण सामान्य सूचनादाताओं का मत	85
	❖ महिला पुलिस कर्मियों से वैवाहिक सम्बन्ध में बनाने पर पुरुष पुलिस कर्मियों का मत	86-88
	❖ अपने बहन या बेटी को पुलिस विभाग में आने से मना करने के बारे में पुरुष पुलिस कर्मियों का मत	88-91
	❖ स्वयं के सदर्भ समूह के बारे में महिला पुलिस कर्मियों के मत	92-93
	❖ अपने बच्चों को पुलिस विभाग में आने देगी या नहीं महिला पुलिस कर्मियों के मत	93-95
	❖ आपकी बेटी या बहन को इस विभाग में आना चाहे तो क्या आप उसे आने देंगे पुरुष पुलिस कर्मियों के मत	95-96
	❖ अपनी बेटी या बहन जो इस विभाग में आना चाहे तो क्या उसे आने देंगे सामान्य	96-97

	सूचनादाताओं का मत	
❖	वो सामान्य सूचनादाता जो अपनी बहन या बेटी को इस विभाग में आने देगे उनके पद के सम्बन्ध में मत	98
❖	सन्दर्भ ग्रन्थ	99
अध्याय-९	❖ महिला पुलिस की कार्यदशा और सफलता	100—158
❖	महिला पुलिस कर्मियों का मत महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता	100—102
❖	महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता महिला पुलिस कर्मियों का पदानुसार मत	102—107
❖	महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता पुरुष पुलिस कर्मियों का मत	107—109
❖	महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता सामान्य सूचनादाताओं का मत	109—112
❖	महिला पुलिस कर्मियों को कोई विशेष कार्य सौंपने के सम्बन्ध में महिला पुलिस कर्मियों का मत	112—114
❖	विगत महीने या वर्षों में सौंपे गये कार्यों में महिला आरक्षियों का मत	114
❖	विगत महीने या वर्षों में सौंपे गये कार्यों में महिला उपनिरीक्षक का मत	115—117
❖	महिला पुलिस को दी गयी ड्यूटी उनकी क्षमता या सामर्थ्य के अनुरूप पुरुष पुलिस कर्मियों के विचार	117
❖	महिला पुलिस कर्मियों के कार्य को कभी सराहा गया महिला पुलिस कर्मियों का मत	118—119
❖	विभाग से प्राप्त दायित्व महिला आरक्षियों का मत	120—121
❖	विभाग से प्राप्त दायित्व महिला उपनिरीक्षकों का मत	122—123
❖	विभाग से प्राप्त दायित्व भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों के विचार	123—124
❖	अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सम्बन्ध महिला पुलिस कर्मियों के विचार	124—125
❖	सामान्यतः उनकी उच्च महिला अधिकारी का व्यवहार उनके प्रति कैसा रहता है पुरुष पुलिस कर्मियों के विचार	125—127
❖	अपने साथ कार्य करने वाली समान पदों की महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार पुरुष पुलिस कर्मियों का मत	127—129
❖	पुरुष पुलिस कर्मियों का अपने पद से नीचे की महिला पुलिस के अपने प्रति व्यवहार पर विचार	129—130
❖	महिला पुलिस का व्यवहार पुरुष पुलिस की अपेक्षा कैसा रहता है सामान्य सूचनादाताओं का मत	131—132

कैसा रहता है सामान्य सूचनादाताओं का मत	133—134
❖ पुरुषों के व्यवहार में उनके प्रति कोई परिवर्तन आया है महिला पुलिस कर्मियों के विचार	135—136
❖ पुलिस विभाग की महिला में अन्य विभाग की महिला की अपेक्षा अन्तर होता है? सामान्य जन सूचनादाताओं (केवल पुरुषों का) मत	136—138
❖ सामान्य सूचनादाताओं के पुरुषों का मत पुलिस विभाग की महिला एवं अन्य विभाग महिला में अन्तर का कारण	138—140
❖ पुरुष पुलिस कर्मियों का मत साधारण महिला एवं महिला पुलिस में स्वभाव सम्बन्धी क्या कोई अन्तर पाते हैं ?	140—141
❖ क्या सूचनादाता स्वयं अपनी वर्तमान सेवा से सतुष्ट है? महिला पुलिस कर्मियों के विचार	142—144
❖ वर्तमान सेवा से असन्तुष्टि के कारण महिला आरक्षियों का मत	144
❖ वर्तमान सेवा से असन्तुष्टि के कारण महिला उपनिरीक्षकों का मत	145—147
❖ ड्यूटी के दौरान किसी तरह का अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है ? महिला पुलिस का मत	147
❖ अपनी उच्च महिला अधिकारियों को वैसा ही सम्मान दे पाते हैं जैसा कि पुरुषों को पुरुष पुलिस कर्मियों का मत	148—149
❖ महिला पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में पुरुष पुलिस कर्मियों के व्यवहार में नियंत्रण लगता है ? पुरुष पुलिस कर्मियों का मत	150—151
❖ उनकी स्वयं की भाषा में परिवर्तन या अपशब्द का प्रयोग करना बढ़ जाता है महिला पुलिस के विचार	152—153
❖ अन्य विभाग की महिला एवं पुलिस विभाग की महिला में क्या कोई खास अन्तर पाती है ? सामान्य सूचनादाताओं की महिलाओं का मत	154—155
❖ महिला पुलिस कर्मियों की अन्य विभाग की महिलाओं से अन्तर होने के विभिन्न कारण सामान्य सूचनादाताओं (महिलाओं) का मत	156—158
❖ महिला पुलिस का व्यवहार अपराधी के प्रति पुरुष पुलिस की अपेक्षा क्या अलग रहता है महिला पुलिस का मत	
अध्याय-६ ❖ महिला पुलिस की समस्याएँ	159—207
❖ कर्तव्य पालन में तनाव या दबाव भ्रष्टाचार जैसे	159—161

कारणों से महसूस करती है महिला पुलिस का मत	
❖ इस विभाग की महिला में विवाह में क्या कोई खास दिक्कत होती है? महिला पुलिस कर्मियों का मत	161—164
❖ महिला पुलिस कर्मियों से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने पर क्या पुरुष पुलिसकर्मी दिक्कत महसूस करेंगे, के बारे में पुरुष पुलिस कर्मियों के मत	164—165
❖ क्या महिला पुलिसकर्मी किसी प्रकार के शोषण के शिकार हैं महिला पुलिस का मत	165—166
❖ शोषण के प्रकार के बारे में महिला आरक्षियों के विभिन्न मत	166—168
❖ शोषण के प्रकार के बारे में महिला उपनिरीक्षकों के विभिन्न मत	168—170
❖ महिला पुलिस कर्मियों का शोषण होता है या नहीं पुरुष पुलिस कर्मियों का मत	170—171
❖ पदोन्नति के बारे में महिला आरक्षियों के विभिन्न मत	172—173
❖ पदोन्नति पर महिला उपनिरीक्षकों के विभिन्न मत	173—175
❖ पदोन्नति पर भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत	175
❖ विभाग द्वारा दी गयी छुट्टियाँ पर्याप्त हैं, और समय से मिल जाती हैं इस पर महिला पुलिस कर्मियों के विभिन्न विचार	175—178
❖ स्थानान्तरण के बारे में महिला आरक्षियों के विभिन्न	178—180
❖ मतस्थानान्तरण के बारे में महिला उपनिरीक्षकों के विभिन्न मत	180
❖ स्थानान्तरण पर भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत	181
❖ वेतन एवं भत्ते पारिवारिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त हैं महिला पुलिस कर्मियों का मत	181—183
❖ विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियाँ महिला आरक्षियों का मत	183—184
❖ विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियाँ महिला उपनिरीक्षकों का मत	184—186
❖ विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियाँ भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत	186—188
❖ ड्यूटी के सम्बन्ध में महिला पुलिस कर्मियों का मत	188—189
❖ किस तरह की ड्यूटी में सुविधा या असुविधा महिला आरक्षियों का मत	189—191
❖ किस तरह की ड्यूटी में सुविधा या असुविधा होती	191—192

	है महिला उपनिरीक्षको का मत	
❖	ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानिया आती है ? महिला आरक्षियों का मत	192—194
❖	ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की शारीरिक या मानसिक परेशानियों आती है महिला उपनिरीक्षको का मत	194—195
❖	ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानियों आती है ? भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत	195—197
❖	क्या महिला पुलिस अपनी नौकरी का कभी लाभ उठाती है ? महिला पुलिस कर्मियों का मत	197—198
❖	क्या महिला पुलिस अपनी नौकरी का कभी लाभ उठाती है ? पुरुष पुलिस कर्मियों का मत	199—201
❖	यूनिफार्म या वर्दी महिला आरक्षियों का मत	201—203
❖	वर्दी या यूनीफार्म महिला उपनिरीक्षको का मत	203—204
❖	उनके प्रति परिवार के सदस्यों का व्यवहार आम महिला की तरह या खास महिला पुलिस कर्मियों का मत	204—206
❖	क्या आपकी दृष्टि में महिलाओं का पुलिस विभाग में आना उचित है महिला पुलिस कर्मियों का मत	206—207
अध्याय-७	◆ निष्कर्ष एवं सुझाव	208—225
	❖ निष्कर्ष	208—221
	❖ महिला पुलिस कर्मियों के विभाग में सशोधन पर सुझाव	221—223
	❖ शोधार्थी के सुझाव	223—225
	◆ सन्दर्भ सूची	

सूची

ग्राफ एवं सारणी

ग्राफ की पृष्ठ सख्या	सारणी की सख्या	ग्राफ की पृष्ठ सख्या	सारणी की सख्या
52	3 1, 3 2	137	5 20
54	3 3,	139	5 21, 5 22
56	3 4, 3 5	142	5 23
59	3.6, 3 7	143	5 24
62	3 8	145	5 25, 5 26
64	3 9	148	5 27
68	3 12, 3 11	150	5 28
76	4 1	152	5 29
78	4 2	154	5 30
83	4 4, 4 5	156	5 31
86	4 7	160	6 1
93	4.9, 4 10	163	6 2, 6 3
96	4 11, 4 12	167	6 4, 6 5, 6 6
101	5 1	169	6 7
103	5 2	173	6 8, 6 9, 6 10
106	5 3	176	6 11
111	5 4, 5 5	179	6 12, 6 13, 6 14
113	5 6	182	6 15, 6 16
116	5 7, 5 8	185	6 17, 6 18
118	5 9	187	6 19
120	5 10	190	6 20, 6 21
123	5 11, 5 12, 5 13	193	6 22, 6 23, 6 24
126	5.14, 5 15	196	6 25
128	5 16	199	6 26
131	5 17	202	6 27, 6 28
133	5 18	205	6 29, 6 30
135	5.19		

अध्याय—१

भारत में पुलिस बल : समाजशास्त्रीय आयाम (Police Strength in India : Sociological Perspectives)

भूमिका

मौलिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के अभाव में अध्ययन, दिशाहीन, अवैज्ञानिक एवं सतही हो जाता है। ऐसे प्रयासों के निष्कर्ष एवं सुझाव भी विवादों में उलझ जाते हैं और दृष्ट-स्वरूप वास्तविक स्वरूप से भिन्न हो जाने के कारण विभ्रम की स्थिति यदाकदा उपस्थित करता ही रहता है। पुलिस पर अध्ययन इन मौलिक सिद्धान्तों की खोज एवं प्रतिपादन के प्रयास बहुत कम हुए हैं।

चयनित पूर्व अध्ययनों का सारांश

(1) भारतीय पुलिस

इस पुस्तक के लेखक डा० परिपूर्णानन्द वर्मा हैं। भारतीय पुलिस आयोग का सदस्य या उपाध्यक्ष होने के नाते इन्हें तत्कालीन भारत की पुलिस व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान था यह पुस्तक अंग्रेजी शासन काल में लिखी गई। अतः इसमें ब्रिटिशकाल की भारतीय पुलिस के संरक्षण स्वरूप कर्तव्य, अधिकार एवं सुविधाओं को वर्णन है। इसके वर्णन में परतत्र भारत की विवशता है। फिर भी तत्कालीन पुलिस व्यवस्था का इससे अच्छा ज्ञान होता है। इसमें महिला पुलिस का उल्लेख नहीं है। परन्तु पुलिस प्रशासन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ हमारे अध्ययन के लिए पृष्ठभूमि का काम करता है।

(2) द पुलिस इन फ़ि इंडिया

यह पुस्तक पी० बी० सिंह द्वारा लिखी गयी है। इसमें स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय पुलिस व्यवस्था में हुए परिवर्तनों का उल्लेख है। यह ग्रंथ समग्र पुलिस विभाग के बारे में अच्छी जानकारियाँ प्रस्तुत करता है। इसमें स्वतंत्रता के बाद

* सभी फुटनोट अध्याय के अन्त में दिये गये हैं।

भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस बल की संख्या, प्रशासन, पुलिस के कर्तव्य, अधिकार तथा सुविधाओं का वर्णन है। इसमें महिला पुलिस का भी संक्षिप्त उल्लेख मिल जाता है।

(3) द पुलिस एण्ड पालिटिकल डिबलपमेन्ट इन इंडिया

1989 में प्रकाशित डेविड एच बैली द्वारा लिखित यह पुस्तक अच्छी सूचनाएं देती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनैतिक विकास के साथ-साथ समाज में जो परिवर्तन हुए, तथा जो सामाजिक विघटन उत्पन्न हुए उस परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उल्लेख इस ग्रंथ में प्रमुख रूप से दिया हुआ है। इस ग्रंथ में महिला पुलिस की आवश्यकता, संगठन और कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला गया है।

(4) फ्रीडम इज नाट फ्री

यह ग्रंथ 1975 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक एस० के० घोष हैं। इस पुस्तक में भारतीय पुलिस की ज्यादतियों, अमानवीय कृत्यों तथा अधिकारों के दुरुपयोग का मुख्य रूप से उल्लेख है। पुस्तक बहुत उपयोगी है। इसमें महिला के संगठन, वितरण एवं कमियों का उल्लेख मिलता है।

(5) द इण्डियन पुलिस

जे० सी० काइ द्वारा लिखित यह पुस्तक अंग्रेजी शासनकाल में 1932 में प्रकाशित हुई। इसमें अंग्रेजों की साम्राज्यवादी व्यवस्था में पुलिस संगठन तथा उसके योगदान का मुख्य रूप से विवरण दिया गया है।

(6) ह्यूमन राइट्स एण्ड पुलिस

इस ग्रंथ के रचनाकार डा० एस० सुब्रमण्यम्, राजनीतिशास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। इस ग्रंथ में मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय पुलिस की गतिविधियों की समालोचना की गई है। विश्व के रंगमंच पर मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों को स्वीकृत किया गया। किसी भी प्रशासनिक पुलिस या सैनिक संगठन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह

अमानवीय तरीके से मानवता का हनन करे। इस ग्रंथ में मानवाधिकारों की सीमा में रहते हुए पुलिस विभाग को कार्य करने के दिशानिर्देश दिये गये हैं।

(7) अमानवीय व्यवहार एवं पुलिस

इस पुस्तक के लेखक जगदीश प्रसाद आर्य, भारतीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुलिस विज्ञान नामक पत्रिका के प्रधान सम्पादक हैं। इन्हें भारतीय पुलिस के बारे में विशद ज्ञान है। इस पुस्तक में केन्द्रीय पुलिस बल तथा भारत के विभिन्न राज्यों में पदस्थ सिविल पुलिस द्वारा अपराधियों के साथ किये जाने वाले अमानवीय कृत्यों का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ से मध्य प्रदेश पुलिस जिसमें महिला पुलिस भी शामिल है के क्रूर तरीकों का ज्ञान होता है, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

(8) स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व

डा० कृष्ण मोहन माथुर द्वारा लिखित यह पुस्तक उनके राजनीति विज्ञान सम्बन्धी परिपक्व ज्ञान का परिचायक है इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत में और राज्यों में पुलिस की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। पुलिस विभाग की कमियों का वर्णन करते हुए इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि जनसहयोग के अभाव में पुलिस निकम्मी हो जाती है। महिला पुलिस तो कार्य कर ही नहीं सकती। अतः पुलिस के प्रति जनसहयोग, सहानुभूति तथा सद्भाव बहुत आवश्यक है। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत तथा राज्यों में अपराधों को नियंत्रित करने के लिए जनसहयोग पर बल दिया गया है।

(9) पुलिस और समाज

इस पुस्तक के लेखक द्वय श्री ए० एल० इराईल तथा जैन्के वैडाकुभचेरी बहुत लम्बे समय तक केन्द्रीय पुलिस बल से सम्बन्धित रहे। इस ग्रंथ में उन्होंने पुलिस को समाजोपयोगी बनाने हेतु अनेक उपयोगी सुझाव दिये हैं। पुलिस की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए लेखकों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के हितों की रक्षा करने के लिए पुलिस बल में अनेक प्रकार के परिवर्तन

करने के सुझाव दिये हैं। इनके विचार में पुलिस प्रशिक्षण से लेकर शीर्षस्थ प्रशासन तक में आमूल-चूल परिवर्तन आवश्यक है।

(10) विकासशील समाज और पुलिस

इस ग्रंथ के लेखक जी० राम रेड्डी और के० शेषाद्री हैं इन लेखकों ने इस पुस्तक में भारतीय समाज में हो रहे तीव्र परिवर्तनों का उल्लेख किया है। इसमें भारतीय समाज पर पंचवर्षीय योजनाओं के प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप पुलिस की व्यवस्था के न होने का उल्लेख करते हुए इन्होंने, पुलिस विभाग में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने के सुझाव दिये।

(11) पुलिस की छवि कैसे सुधारे

यह पुस्तिका श्री के० एस० माथुर द्वारा लिखी गई है जो लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली में पुलिस विभाग के उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। इस ग्रंथ दीर्घ अनुभव का परिणाम है। इसमें भारतीय पुलिस को अधिक सक्षम, सक्रिय, मानवीय और संगठित करने के विविध तरीकों का उल्लेख है। लेखक के विचार में पुलिस जनता का स्वामी नहीं, सेवक है। यह पुस्तक सरल भाषा में लिखी हुई है तथा पठनीय है।

(12) भारतीय महिला पुलिस

श्री जगदीश प्रसाद आर्य द्वारा लिखित यह पुस्तक महिला पुलिस के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्रस्तुत करती है। इसमें भारतीय महिला पुलिस के संगठन का इतिहास उसके कर्तव्यों, अधिकारों तथा कार्यकलापों का अच्छा विवरण है। 1991 तक की महिला पुलिस की स्थिति के अनेक प्रकार के आकड़े भी इस ग्रंथ में मिल जाते हैं। आज दूरियाँ सिमटकर छोटी हो गई हैं। जनसामान्य अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। महिलाओं से सम्बन्धित अपराध बड़ी संख्या में हो रहे हैं। महिलाएँ भी अपराध की ओर अग्रसर हो रही हैं। लेखक ने इन तमाम सन्दर्भों का आकलन करते हुए महिला पुलिस के बारे में एक अच्छी रचना प्रस्तुत की है।

(13) भारतीय स्वातंत्र्य और महिला पुलिस

डा० रश्मि बत्रा द्वारा लिखित तथा अजमेर से प्रकाशित यह पुस्तक 290 पृष्ठों की है। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला पुलिस के गठन में परिवर्तन, विभिन्न राज्यों में उनका सख्यात्मक अनुपात तथा भूमिका का उल्लेख है। पुस्तक काम चलाऊ है, इससे महिला पुलिस के बारे में सामान्य सूचनाएँ मिल जाती हैं।

(14) पुलिस विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित उपर्युक्त 4 लेखों से इस शोधकार्य में सहायता मिली है। ये चारों लेख क्रमशः पुलिस विज्ञान अंक 47, 48, 49 और 50 में उपलब्ध हैं। इनमें विषय से सम्बन्धित विवरणों का उल्लेख मिलता है। श्री अरविंद तिवारी द्वारा लिखित “अपराधी सुधार पद्धति में महिला पुलिस का योगदान” शीर्षक लेख के अन्दर महिला पुलिस को महिला अपराधिनियों के प्रति अपने व्यवहार को अधिक मीठा और सौजन्यपूर्ण बनाने की सलाह दी गई है। दूसरे लेख जिसका शीर्षक है “राज्यों तथा संघ राज्यों में स्थापित महिला सेल के कार्य, यह पुलिस विज्ञान अंक 50 जनवरी-मार्च 1995 के पृष्ठ 30-38 पर प्रकाशित एक रिपोर्ट है। इनमें अन्य संघ राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में स्थापित महिला सेल के कार्यों का भी विवरण है। इससे सम्बन्धित भरपूर आकड़े भी दिये दिये गये हैं।

(15) “दहेज हत्याएँ और महिला पुलिस” शीर्षक लेख श्री सूर्य नारायण मिश्र द्वारा लिखा लेख है। इसमें दहेज हत्याओं को रोकने में तथा उसके बाद की कार्यवाहियों में महिला पुलिस के योगदान का उल्लेख है। श्रीमती किरण वेदी का साक्षात्कार ‘पुलिस विज्ञान’ अंक 44 जुलाई-सितम्बर 1993 में पृष्ठ 27-29 में प्रकाशित है। इसमें श्रीमती किरण वेदी ने महिला पुलिस की शक्तियों, क्षमताओं, कार्य करने की पद्धति तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। उनके विचार में महिला पुलिस कठिन से कठिन कार्य भी कर सकती है।

भारत में पुलिस का वर्गीकरण नागरिक (Civil) व सशस्त्र (armed) पुलिस के रूप में किया गया है। देश में कुल स्वीकृत (Sanctioned) पुलिस बल (1995 में) 13 29

लाख (10.11 लाख सिविल और 3.1 लाख सशस्त्र) हैं¹। इसमें से 53 प्रतिशत पद जनवरी 1996 में रिक्त थे। इस प्रकार 1995 में वास्तविक (Actual) कुल पुलिस बल 12.5 लाख व्यक्तियों का था। इसमें से 9.7 लाख (73.34%) सिविल पुलिस और 2.81 लाख (26.6%) सशस्त्र पुलिस है। (Crime in India, 1995 329)। कुल सिविल पुलिस कार्मिकों में से, 86.8 प्रतिशत कान्सटेबिल और सहायक उप-निरीक्षक के, 12.3 प्रतिशत सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (SI) और उप सुपरिन्टेण्डेंट पुलिस (Deputy Superintendent Police) और 0.3 प्रतिशत सुपरिन्टेण्डेंट पुलिस (SP), उप-महानिरीक्षक (DIG), और महानिरीक्षक (IG) और पुलिस महानिदेशक (Director General of Police) के हैं। सिविल पुलिस का सबसे बड़ा दस्ता (Contingent) (1.21 लाख या 12.8 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश में है तथा महाराष्ट्र में यह संख्या (1.15 लाख या 12.3 प्रतिशत) है। केन्द्र शासित प्रदेशों में देहली सब से अधिक 40,212 सिविल पुलिस कर्मी हैं (Ibid 329) है। सशस्त्र पुलिस में, 94.4 प्रतिशत सहायक उप निरीक्षक (ASI) पद से नीचे के कान्सटेबिल और अफसर हैं, 4.9 प्रतिशत सहायक उप निरीक्षक (ASI), उप-निरीक्षक (SI) और निरीक्षक श्रेणी के, 0.5 प्रतिशत सहायक सुपरिन्टेण्डेंट पुलिस (ASP) और उप-सुपरिन्टेण्डेंट (DSP) श्रेणी के अधिकारी, और 0.2 प्रतिशत सुप पुलिस (SP), उप-महानिरीक्षक (DIG), महानिरीक्षक (IG), और पुलिस महानिदेशक (DG) श्रेणी के हैं। सशस्त्र पुलिस बल (12.1%) सब से अधिक उत्तर प्रदेश में है।

देश में महिला पुलिस बल भी गठित किया गया है। स्वीकृत महिला सिविल पुलिस बल की कुल संख्या (1995 में) 18,373 थी जबकि वास्तविक संख्या 15,337 थी। (Ibid 329) यह अनुपात कुल वास्तविक सिविल पुलिस का 1.63 है। कुल महिला पुलिस बल का 89.9 प्रतिशत कान्सटेबिल व हेड कान्सटेबिल है, 9.8 प्रतिशत उप-सहायक, सहायक और इन्स्पेक्टर है, 0.3 प्रतिशत सहायक व उप-सुपरिन्टेण्डेंट है, और 0.1 प्रतिशत सुपरिन्टेण्डेंट और उप-महानिरीक्षक है। महिला पुलिस बल महाराष्ट्र में सबसे अधिकतम (16.4%) है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। जहाँ तक सशस्त्र महिला पुलिस का प्रश्न है, केवल आसाम, मध्य प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर और देहली में ही ऐसा पुलिस बल है। 1995 में देश में सशस्त्र महिला बल की कुल संख्या 677 थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस (ऐतिहासिक परिचय)

उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता पूर्व “उत्तरी पश्चिमी प्रान्त” के नाम से प्रसिद्ध था। इस प्रान्त में कलकत्ते में काम कर रहे 1860 के पुलिस आयोग की सस्तुतियों प्राप्त होने से पूर्ण ही पुलिस का गठन कर लिया गया था। प्रान्त में प्रथम पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति नवम्बर 1860 में की गयी थी। उस समय इस प्रान्त में सात परिक्षेत्र थे जिस पर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किये गये थे। जिलों के लिये सहायक पुलिस अधीक्षक भी रखे गये। छ पुलिस उप महानिरीक्षकों के पद बाद में सृजित किये गये। उस समय प्रान्त में 39 जिले थे²।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में प्रान्तों का पुनर्गठन किया गया और इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। फलस्वरूप प्रदेशीय पुलिस का नाम “उत्तर प्रदेश पुलिस” पड़ा।

उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव सुखियों में स्थान प्राप्त करती रही है। अपने गौरवपूर्ण एवं निन्दनीय कार्यकलापों के फलस्वरूप यह सदैव यश और अपयश दोनों की भागीदार रही है।

क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से देश के बड़े प्रदेशों में से एक होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस संगठन देश के अन्य पुलिस बलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ सन् 1861 में वार्षिक परेड का आयोजन किया गया था, तब से इस परम्परा का निर्वाह प्रादेशिक पुलिस आज निरन्तर करती आ रही है।

सन् 1947 के पश्चात् कानून, वर्दी, पद और कैडर के वितरण में कई संशोधन हुये हैं। संख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश पुलिस चौथे स्थान पर और श्रेष्ठता के रूप में बम्बई के पश्चात् इसका स्थान आता है। वर्ष 1952 में सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को कलर प्रदान किया गया जो कि राज्य पुलिस के अत्यन्त सम्मान की बात थी। तत्पश्चात् अन्य राज्यों की पुलिस ने इस मार्ग का अनुसरण किया। उत्तर प्रदेश के पश्चात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल की पुलिस भी यह सम्मान प्राप्त कर चुकी है³।

वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों की सेवा शर्तों और प्रोन्नति के सम्बन्ध में सशोधन का प्रस्ताव किया गया था जिसमें यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक कान्सटेबल सेवानिवृत्ति तक निरीक्षक के पद तक तीन प्रोन्नति पाने के योग्य है। उप निरीक्षक को निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक तक, पुलिस उपाधीक्षक को पुलिस अधीक्षक एवं अन्य उच्च पदों तक प्रोन्नति प्रदान की जायेगी और अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को क्रमशः पुलिस महानिदेशक पद तक प्रोन्नत किया जायेगा⁴। प्रदेशीय पुलिस में सुधार लाने के दृष्टि से वर्ष 1960-61 एवं 1970-71 में प्रदेश में दो बार पुलिस आयोग गठित किये गये।

राज्य की पुलिस को प्रादेशिक पुलिस सेवा कहते हैं किन्तु इसे पहचानने के लिए प्रत्येक प्रदेश इनके नाम से पहले अक्षर को लेकर जोड़ता है जैसे—उत्तर प्रदेश पुलिस को उ०प्र०पु० के नाम से जाना जाता है। जो कि धातु के ढले हुये बैच के रूप में कमीज के कन्धे पर लगाये जाते हैं⁵।

महिला पुलिस कर्मियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण

आज समाज में महिला पुलिस की विशिष्ट भूमिका बन रही है। बाल अधिनियम, महिला एवं बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार, भिक्षुक अधिनियम एवं कमजोर वर्गों के लिये बनाये गये विभिन्न अधिनियमों को भलीभाँति क्रियान्वित करने और सदिग्ध महिला अपराधियों की नारी मर्यादा को बनाये रखने हेतु देश ही नहीं वरन् समस्त विश्व में महिला पुलिस की आवश्यकता ही नहीं वरन् एक अनिवार्यता हो चुकी है। विश्व के समस्त प्रगतिशील देशों में महिला पुलिस कार्यरत है। 1845 में न्यूयार्क शहर में विश्व में प्रथम महिला पुलिस की भर्ती की गयी।

वर्ष 1938 में जनपद कानपुर में श्रमिक अशान्ति हो गयी थी जिसमें महिलाओं ने भी हड़ताल व धरने में भाग लिया था। इस सम्बन्ध में शासन ने एक दर्जन (12) महिला आरक्षी भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान की थी। जिसमें बिना प्रशिक्षण के महिला कर्मचारियों से काम लिया गया। हड़ताल समाप्त होने पर उक्त महिला कर्मचारियों के पद समाप्त कर दिये गये।

वर्ष 1952 में प्रयोग के तौर पर जनपद लखनऊ में एक सब-इन्स्पेक्टर एवं दो मुख्य आरक्षियों के पद सृजित किये गये किन्तु बाद में उक्त पद भी समाप्त कर दिये गये।

वर्ष 1964 में एक सब-इन्स्पेक्टर तथा दो मुख्य आरक्षियों के पद अभिसूचना विभाग में स्वीकृत किये गये।

वर्ष 1966 में जनपद मेरठ के लिए एक मुख्य आरक्षी एवं चार आरक्षियों के पद महिलाओं के लिए सृजित किये गये।

वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश शासन ने महिला पुलिस के नियमित गठन के आदेश दिये।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1979 ने महिला पुलिस की अनिवार्यता को अनुभव किया और पुलिस में महिलाओं की भर्ती किये जाने की सन्तुष्टि की। इसके उपरान्त से आज देश के लगभग सभी प्रदेशों में महिला पुलिस किसी न किसी रूप में तथा संख्या में देखने को मिल ही जाती है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को अलग से भर्ती नहीं किया जाता है और न ही कोई अलग से महिला पुलिस नामक शाखा है वरन् सामान्य भर्ती के समय कुछ निर्धारित अनुपात एवं आवश्यकतानुसार महिला पुलिस की भर्ती की जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में राजपत्रित एवं अराजपत्रित, भारतीय पुलिससेवा, प्रादेशिक पुलिस सेवा, निरीक्षक, उपनिरीक्षक मुख्य आरक्षी और आरक्षी सभी पदों पर महिलाएँ कार्यरत हैं। यही नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछेक शाखाओं को छोड़कर अधिकांश शाखाओं में महिलाएँ नियुक्त हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जिन महत्वपूर्ण शाखाओं में महिलाएँ नियुक्त नहीं हैं वे हैं—अग्निशमन सेवा और पी०ए०सी०।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग^१ ने अपनी रिपोर्ट में महिला पुलिस के विषय में अनेक सुझाव दिये हैं—पुलिस अन्वेषणकार्य, नगर क्षेत्र में किशोर अपराध निरोध के रूप में, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, मजदूर बस्तियों, झुग्गी झोपड़ी, गरीबों की बस्ती, में महिला पुलिस से गश्त करायी जा सकती है। यह ने केवल अपराधी बालक एवं महिलाओं को दूढ़ेगी बल्कि जनता से सम्पर्क स्थापित करेगी तथा महिला एवं बाल

यात्रियों का मार्गदर्शन कर सकती है। यातायात नियन्त्रण पर भी महिला पुलिस लगायी जा सकती है, स्कूल, बाजार, मेला, त्यौहार तथा अन्य ऐसी स्थितियों में जहाँ महिलाये बड़ी संख्या में आती जाती है। महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने में भी महिला पुलिस का उपयोग किया जा सकता है⁷।

सारिणी संख्या-1.1

उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस बल⁸

	पद				
	इन्सपेक्टर	सब-इन्सपेक्टर	हेड कान्सटेबिल	कान्सटेबिल	
संख्या	—	53	128	724	पुलिस महा निदेशक उ०प्र० को प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत पुरुष वर्ग से समायोजन द्वारा
	—	—	—	538	अष्टम वित्त आयोग के माध्यम से स्वीकृति
	—	96	1	200	उ०प्र० के 13 जनपदों हेतु समायोजन से भरे जाने हेतु स्वीकृति पद
	11	34	13	13	13 थानों हेतु स्वीकृति नवीन पद
	—	10	15	112	तीन धार्मिक स्थलों क्रमशः अयोध्या, वाराणसी और मथुरा की सुरक्षार्थ स्वीकृति
योग	11	193	157	1698	

सारिणी संख्या-1.2

उत्तर प्रदेश के तीन धार्मिक स्थलों के सुरक्षार्थ स्वीकृत पदों का विवरण

धार्मिक स्थल	सब-इन्सपेक्टर	हेड-कान्सटेबिल	कान्सटेबिल
वाराणसी	3	7	51
मथुरा	3	5	42
अयोध्या	4	3	19
योग	10	15	112

सारिणी संख्या-1.3

महिला थानों की संख्या, जनपद जहाँ पर महिला थाने हैं तथा उनके लिए स्वीकृत पदों का विवरण⁹

क्र०सं०	जनपद का नाम	पदवार स्वीकृत नियतन				जनपद के नियतन से समायोजन द्वारा		
		निरीक्षक	सि० ड०	हो० का०	का०	सि० ड०	हो० का०	का०
1	आगरा (रकबगज म०पु० थाना)	1	1	3	1	9	0	18
2	इलाहाबाद (सिविल लाइन्स)	1	1	3	1	8	0	12
3	झाँसी (नवावाद)	1	1	2	1	8	0	8
4.	लखनऊ (हजरतगज)	1	1	3	1	11	0	28
5	फैजाबाद (रकावगज)	1	1	3	1	11	0	28
6	बरेली (सिविल लाइन्स)	1	1	3	1	11	0	10
7	मुरादाबाद (सिविल लाइन्स)	1	1	2	1	8	0	4
8	अल्मोडा	1	0	1	1	8	0	8
9	मेरठ (सिविल लाइन्स)	1	1	3	1	11	0	28
10	पौडीगढवाल (श्रीनगर)	1	0	2	1	7	1	4
11	गोरखपुर (थाना पुलिस लाइन)	1	1	3	1	11	0	12
12	वाराणसी (कोतवाली)	1	1	3	1	11	0	12
13	कानपुर नगर (पुलिस लाइन)	1	1	3	1	11	0	28
योग		13	11	34	13	125	1	200

साटिणी संख्या-1.4

दिनांक 30/04/2000 की स्थिति

उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस का जनपदवार स्वीकृत नियतन¹⁰

क्र०स०	जनपद का नाम	निरीक्षक	उ० नि०	हे० का०	का०
मेरठ जोन					
मेरठ परिक्षेत्र					
1	मेरठ	1	19	4	79
2	बागपत	0	0	0	0
3	गाजियाबाद	0	4	3	28
4	गौतमबुद्ध नगर	0	0	0	0
5	बुलन्दशहर	0	3	2	16
योग		1	26	9	123
सहारनपुर परिक्षेत्र					
6	सहारनपुर	0	1	3	28
7	मुजफ्फरनगर	0	2	3	28
8	हरिद्वार	0	0	0	0
योग		0	3	6	56
गढ़वाल परिक्षेत्र					
9	टिहरीगढ़वाल	0	1	1	12
10	उत्तरकाशी	0	0	1	12
11	चमोली	0	0	1	12
12	पौड़ीगढ़वाल	0	2	3	23
13	देहरादून	0	2	3	24
14	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0
योग		0	5	9	83
मेरठ जोन का योग		1	34	24	262
गोरखपुर जोन					
देवीपाटन परिक्षेत्र					
15	बहराइच	0	0	2	16
16	गोण्डा	0	0	2	16
17	श्रावस्ती	0	0	0	0
18	बलरामपुर	0	0	0	0
योग		0	1	4	32
गोरखपुर परिक्षेत्र					
19	गोरखपुर	1	9	4	61
20	कुशीनगर	0	0	0	0
21	देवरिया	0	0	2	16
22	महाराजगंज	0	0	0	0
योग		1	9	6	77
23	बस्ती	0	0	2	16
24	सिद्धार्थनगर	0	0	0	0
25	सन्तकबीर नगर	0	0	0	0
योग		0	0	2	16
गोरखपुर जोन का योग		1	10	12	125

क्र०स०	जनपद का नाम	निरीक्षक	उ० नि०	हे० का०	का०
कानपुर ज़ोन					
कानपुर परिक्षेत्र					
26	कानपुर नगर	1	23	4	79
27	कानपुर देहात	0	1	0	6
28	इटवा	0	0	2	16
29	फतेहगढ़	0	0	3	28
30	औरैया	0	0	0	0
31	कन्नौज	0	0	0	0
योग		1	24	9	129
आगरा परिक्षेत्र					
32	आगरा	1	19	4	67
33	अलीगढ़	0	1	3	28
34	एटा	0	0	2	16
35	फिरोजाबाद	0	0	0	0
36	मैनपुरी	0	1	2	16
37	मथुरा	0	3	8	70
38	हाथरस	0	0	0	0
योग		1	24	19	197
कानपुर ज़ोन का योग		2	48	28	326
लखनऊ ज़ोन					
लखनऊ परिक्षेत्र					
39	लखनऊ	1	20	4	79
40	उन्नाव	0	0	2	16
41	रायबरेली	0	0	2	16
42	खीरी	0	0	2	16
43	सीतापुर	0	1	2	16
44	हरदोई	0	0	2	16
योग		1	21	14	159
फैजाबाद परिक्षेत्र					
45	फैजाबाद	1	22	7	94
46	अम्बेडकर नगर	0	0	0	0
47.	सुल्तानपुर	0	0	2	16
48	बाराबंकी	0	0	2	16
योग		1	22	11	126
लखनऊ ज़ोन का योग		2	43	25	285
बरेली ज़ोन					
बरेली परिक्षेत्र					
49	बरेली	1	9	4	59
50	बदायूँ	0	0	2	16
51	शाहजहाँपुर	0	1	3	28
52	पीलीभीत	0	1	2	16
योग.		1	11	11	119

क्र०स०	जनपद का नाम	निरीक्षक	उ० नि०	हे० का०	का०
मुरादाबाद परिक्षेत्र					
53	मुरादाबाद	1	3	4	50
54	बिजनौर	0	1	2	16
55	ज्योतिबाफुले नगर	0	0	0	0
56	रामपुर	0	0	3	28
	योग	1	4	9	94
कुमायूँ परिक्षेत्र					
57	नैनीताल	0	1	3	34
58	पिथौरागढ़	0	0	1	12
59	चम्पावत	0	0	0	0
60	ऊधमसिंह नगर	0	0	0	0
61	बागेश्वर	0	0	0	0
62	अल्मोडा	0	4	2	28
	योग	0	5	6	74
	बरेली जोन का योग	2	20	26	287
इलाहाबाद जोन					
इलाहाबाद परिक्षेत्र					
63	इलाहाबाद	1	11	4	59
64	कौशाम्बी	0	0	0	0
65	फतेहपुर	0	0	2	16
66	प्रतापगढ़	0	0	2	16
	योग	1	11	8	91
चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बौदा					
67	बौदा	0	0	2	16
68	चित्रकूट	0	0	0	0
69	महोबा	0	0	0	0
70	हमीरपुर	0	1	2	16
	योग	0	1	4	32
झाँसी परिक्षेत्र					
71	झाँसी	1	8	4	52
72	ललितपुर	0	0	2	16
73	जालौन	0	0	2	16
	योग	1	8	8	84
	इलाहाबाद जोन का योग	2	20	20	207
वाराणसी जोन					
वाराणसी परिक्षेत्र					
74	वाराणसी	1	16	11	114
75	चन्दौली	0	0	0	0
76	जौनपुर	0	1	2	16
77	गाजीपुर	0	0	2	16
	योग	1	17	15	146
आजमगढ़ परिक्षेत्र					
78	आजमगढ़	0	1	2	16
79	बलिया	0	0	2	16
80	मऊ	0	0	0	0
	योग	0	1	4	32

मुख्यालय और प्रमुख

प्रदेशीय पुलिस का मुख्यालय प्रदेश की भूतपूर्व राजधानी इलाहाबाद में स्थित है। परन्तु पुलिस प्रमुख—“पुलिस महानिदेशक” का कार्यालय वर्तमान राजधानी लखनऊ में स्थित है। प्रदेशीय मुख्यालय को इलाहाबाद से लखनऊ लाने के काफी प्रयास किये गये परन्तु अभी इसमें आशिक सफलता ही प्राप्त हो सकी है, यथा—अग्निशमन सेवा आदि विभागों के मुख्यालयों का लखनऊ में स्थापित हो जाना। प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के मुख्यालय आज लखनऊ में स्थित हैं और उनके प्रमुख भी लखनऊ में निवास करते हैं। मात्र पुलिस का प्रशासनिक विभाग ही इलाहाबाद में स्थित है।

उत्तर प्रदेश में प्रदेशीय सरकारों के बदलने के साथ ही पुलिस प्रमुख भी बदलते रहते हैं। यथा जनवरी 1967 से अब तक 25 वर्षों में 23 सरकारों ने प्रदेश में शासन किया है—श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री चन्द्रभानु गुप्ता, श्री चरण सिंह, राष्ट्रपति शासन, श्री चन्द्रभानु गुप्त, श्री चरण सिंह, राष्ट्रपति शासन, श्री टी० एन० सिंह, श्री कमलापति त्रिपाठी, राष्ट्रपति शासन, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री नारायणदत्त तिवारी, राष्ट्रपति शासन, श्री रामनरेश यादव, श्री बनारसी दास, राष्ट्रपति शासन, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री श्रीपति मिश्र, श्री वीर बहादुर सिंह, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री मुलायम सिंह यादव और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के श्री कल्याण सिंह। प्रत्येक मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यपालों ने पुलिस विभाग पर न केवल अपने विचारों को ही आरोपित किया है वरन् अपनी रुचि के पुलिस प्रमुखों के नियुक्त किया है। वर्तमान समय में इस पद पर श्री प्रकाश सिंह नियुक्त हैं जो कि पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाते हैं।

प्रशासनिक संगठन

व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस विभाग ने प्रदेश को प्रशासनिक स्तर पर छ ज़ोन में विभाजित किया है जिसके प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक पद के अधिकारी हैं। प्रत्येक ज़ोन में दो अथवा तीन परिक्षेत्र रखे गये हैं। प्रदेश में इस समय इन परिक्षेत्रों की कुल संख्या 13 है। प्रत्येक परिक्षेत्र का प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक पद का

अधिकारी है। प्रत्येक परिक्षेत्र में अलग-अलग सख्या में कई जनपद हैं। वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 63 जनपद हैं। इनमें 23 जनपदों पर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा शेष 40 जनपदों पर पुलिस अधीक्षक स्तर का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी प्रभारी के रूप में कार्यरत है। प्रत्येक जनपद में अलग-अलग सख्या में तहसील एवं थाने हैं। तहसील स्तर को पुलिस में एक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है जिस पर एक राजपत्रित अधिकारी नियुक्त होता है जिसे बोलचाल की भाषा में क्षेत्राधिकारी और सी० ओ० सर्किल आफिसर भी कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग सख्या में थाने होते हैं। इन थानों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के निरीक्षक और उप निरीक्षक प्रभारी होते हैं। निरीक्षक पद के थानों पर एक ज्येष्ठ उप निरीक्षक का भी पद होता है। प्रत्येक थाने में कई पुलिस चौकियाँ होती हैं और प्रत्येक पुलिस चौकी के अन्तर्गत बीट अथवा कई ग्राम होते हैं। इन ग्रामों के चौकीदार भी पुलिस की मदद करते रहते हैं। प्रत्येक जनपद में पुलिस प्रभारी ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक का अपना एक कार्यालय, पुलिस लाइन एवं अन्य विभिन्न शाखाओं के कार्यालय होते हैं¹¹।

नियतन

उत्तर प्रदेश पुलिस एक बड़ा बल है जिसमें 1380 पुलिस थाने हैं जिनकी सख्या में प्रतिदिन आवश्यकतानुसार वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों से सम्बन्धित विवरण निम्न सारणी में द्रष्टव्य है¹²—

सारणी संख्या-1.5

दिनांक 31-12-1990 को प्रदेश में नागरिक पुलिस एवं जिला सशस्त्र पुलिस का नियतन

क्र०स०	पद	स्वीकृत नियतन	
		नागरिक पुलिस	सशस्त्र पुलिस
1	पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक	326	0
2	सहायक पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक	901	0
3	निरीक्षक/उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक	8,856	312
4	सहायक उप निरीक्षक से नीचे के अधिकारी	67,290	23,839
	योग	77,373	24,151

नोट: 1 एक-पुलिस महानिरीक्षक, सात-पुलिस उपमहानिरीक्षक, 34-सेनानायक, 183-सहायक सेनानायक जो कि पी०ए०सी० में नियुक्त हैं, इसमें शामिल नहीं हैं।

2 इन आकड़ों में 53 उप निरीक्षक तथा 1390 हेडकान्स०/कान्सटेबिल कुल संख्या 1443 महिला पुलिस नियतन भी सम्मिलित हैं।

उक्त सारणी के अध्ययन से प्रकट होता है कि अधिकारियों तथा नागरिक पुलिस के अन्य पदों की कुल शक्ति 77,373 है जिसमें हेड कान्सटेबिल और कान्सटेबिल की संख्या 87 प्रतिशत है, जबकि सशस्त्र पुलिस में सहायक उप निरीक्षक से निम्न स्तर की शक्ति प्रदेश के सशस्त्र पुलिस बल की स्वीकृत संख्या का 98 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्रदेश में महिला पुलिस शक्ति संख्या दिनांक 31-12-90 को नगण्य सी थी जबकि इस वर्ग में 53 उप निरीक्षक और 1390 हेड कान्सटेबिल और कान्सटेबिल ही प्रदेश में नियुक्त थी।

स्पष्ट है कि प्रदेश में कुल पुलिस शक्ति का 75.9 प्रतिशत नागरिक पुलिस का स्वीकृत नियतन है और दिनांक 31-12-90 को प्रदेश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मात्र 34.1 पुलिसजन उपलब्ध थे जबकि प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मात्र 0.7 प्रतिशत पुलिसजन उपलब्ध थे। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि वर्ष 1989 में अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस की स्थिति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश के समान ही थी परन्तु प्रति हजार जनसंख्या के पीछे

अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस की स्थिति 14 प्रतिशत थी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदर्शित आकड़ों से दोगुनी है। प्रदेश में प्रति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल के पीछे रामपुर जनपद में सर्वाधिक (86.4 प्रतिशत) पुलिस का घनत्व था¹³।

श्रेणी के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश पुलिस का तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी में भारतीय पुलिस सेवा के सहायक पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक पद के अधिकारी रखे जा सकते हैं, द्वितीय श्रेणी में प्रादेशिक पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक और तृतीय श्रेणी में कान्सटेबिल से लेकर उपनिरीक्षक/निरीक्षक पदों को रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुलिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मी भी होते हैं, परन्तु उन्हें पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत भर्ती न किये जाने के कारण उन्हें पुलिसकर्मी नहीं माना जाता है। इसी प्रकार पुलिस की विभिन्न शाखाओं में मोटर परिवहन अधिकार, पुस्तकालयाध्यक्ष, फोटोग्राफर आदि अपुलिसीय अधिकारी/कर्मचारी भी सेवारत हैं¹⁴।

प्रदेश पुलिस के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पदों के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है—

१. पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक

1861 के पुलिस अधिनियम के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में की गयी थी, परन्तु स्वतन्त्रता उपरान्त वर्ष 1974 इस पद को पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कर दिया गया है। इसकी स्थिति अभी तक 1861 के अधिनियम के अनुसार समस्त मामलों सरकार के साथ कौंसिलर की सी है। 1861 के पुलिस अधिनियम के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक को कि वर्तमान समय में पुलिस महानिदेशक कहलाता है प्रदेश पुलिस बल के सम्पूर्ण प्रशासनिक उत्तरदायित्व को वहन करता है और राज्य सरकार के प्रति जबाबदेह होता है। पुलिस प्रशासन के अलावा इसका कर्तव्य यह भी है कि वह पुलिस की संख्या, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासनिक कार्यों के लिये समय-समय पर प्रदेशीय सरकार को सम्मति दे। प्रदेश छ जिलों के पुलिस महानिरीक्षक एवं परिक्षेत्र स्तर

पर नियुक्त पुलिस उपमहानिरीक्षक के माध्यम से जिला पुलिस प्रमुखों से सम्पर्क बनाये रखकर प्रदेश में होने वाली हर छोटी बड़ी राजनीतिक, अपराधिक, श्रमिक, विदेशी, साम्प्रदायिक घटनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी और उनके नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना प्रदेश सरकार को समय से उपलब्ध कराता है।

२. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

प्रदेश में वर्तमान में कई पुलिस शाखाओं के प्रमुख का पद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक का है यथा—रेलवे पुलिस, पी०ए०सी०, प्रशिक्षण आदि। इनका कार्य अपनी शाखाओं के कार्य का नियन्त्रण एवं संचालन करना है।

३. पुलिस महानिरीक्षक

- प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा हेतु छ ज़ोन में बाटा गया है जिसके प्रमुख के रूप में पुलिस महानिरीक्षक को नियुक्त किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक अपने-अपने के अन्तर्गत आने वाले परिक्षेत्रों एवं जनपदों के पुलिस अधिकारियों एवं उनके कार्यों का नियन्त्रण एवं संचालन करता है और अपने ज़ोन में होने वाली राजनीतिक, अपराधिक, श्रमिक, छात्र, साम्प्रदायिक, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक गतिविधि के प्रति उत्तरदायी है और उन पर नियन्त्रण करने के लिए अपने अधीन पुलिस अधिकारियों का उचित मार्ग निर्देशन करता है। साथ ही अपने ज़ोन की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी वह पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध कराता है।

इसके अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अपने ज़ोन के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों (भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर) के स्थानान्तरण एवं उनके अन्य आवश्यक मामलों को निपटाने के लिए सक्षम है और इस सम्बन्ध में अधिकारों विकेंद्रीकरण कर दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं में भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को समय-समय पर प्रोन्नत कर उनके प्रमुखों के अधीन पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है जो कि अपनी-अपनी शाखाओं के प्रमुखों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं।

४. पुलिस उपमहानिरीक्षक

प्रदेश में 13 परिक्षेत्र हैं और प्रत्येक परिक्षेत्र का प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक होता है जो अपने परिक्षेत्र की पुलिस एवं उसमें होने वाली प्रत्येक घटना एवं गतिविधियों तथा उनके प्रति होने वाली कार्यवाहियों के प्रति उत्तरदायी होता है। पुलिस महानिरीक्षक को जिस प्रकार अपने ज़ोन में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हैं उसी प्रकार पुलिस उपनिरीक्षक को अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हैं।

परिक्षेत्र के अतिरिक्त प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं में भी आज अनेक पुलिस उपमहानिरीक्षक पद के अधिकारी नियुक्त हैं जो अपनी-अपनी शाखाओं के विभिन्न सौंपे गये कार्यों को सम्पादित करते हैं।

५ ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक

प्रदेश के 63 जनपदों में प्रत्येक में आज भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी जनपद प्रभारी के रूप में नियुक्त है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रदेश के 23 जनपदों के प्रभारी ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और शेष 40 जनपदों के प्रभारी पुलिस अधीक्षक कहलाते हैं। इन तीस जनपदों में समस्त कर्वाल नगर भी सम्मिलित हैं। जिला पुलिस प्रधान का प्रथम कर्तव्य है कि जिले के पुलिस कर्मी ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करें तथा न्यायालय और अधिकारियों के आदेशों का शीघ्रता से पालन हो। वह अधिकारी वर्ष में एक बार जिले के प्रत्येक थाने का स्वयं निरीक्षण करता है अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी जैसे सहायक पुलिस अधीक्षक अथवा क्षेत्राधिकारी द्वारा करवाता है। अपने जनपद में होने वाली प्रत्येक गतिविधि एवं घटना के लिये वह उत्तरदायी होता है और उसकी त्वरित सूचना अपने उच्चाधिकारियों एवं प्रदेश पुलिस प्रमुख को उपलब्ध कराता है। जनपद के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण भी यह समय-समय पर कराता रहता है। जनपद स्तर पर यह पुलिस कल्याण के कार्यों को भी देखता है।

६. सहायक पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

जिला पुलिस प्रभारी ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त कतिपय नये पुलिस पद भी सृजित किये गये हैं जिन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सहायक पुलिस अधीक्षक कहा जाता है जिन पर भारतीय पुलिस सेवा के सीधी भर्ती के नये अधिकारी अथवा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक पदोन्नत करके नियुक्त किये जाते हैं। इनका कार्य उनको जिला पुलिस प्रभारी द्वारा आवंटित कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन एवं जिला प्रमुख के सहायक के रूप में कार्य करना है।

७. पुलिस उपाधीक्षक

प्रादेशिक पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारी को पुलिस उपाधीक्षक कहा जाता है। ये सीधी भर्ती एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित निरीक्षकों को प्रोन्नति प्रदान कर भरे जाते हैं। इन्हें क्षेत्राधिकारी भी कहते हैं। क्षेत्राधिकारी पुलिस का मुख्य कर्तव्य, अन्वेषण की निगरानी करना, अपराधों को रोकना एवं पता लगाना, क्षेत्र का अपराध रजिस्टर रखना तथा अधीनस्थ थाना प्रभारियों के कार्य का निरीक्षण करना है। यह अपने क्षेत्र के अपराधों की मासिक आख्या भी पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करते हैं।

८. निरीक्षक

निरीक्षक पहले पुलिस सर्किल के मुख्य अधिकारी होते थे, परन्तु 1977 के पुलिस आयोग एवं प्रदेशीय पुलिस आयोग की सस्तुति के अनुसार सर्किल इन्स्पेक्टर (निरीक्षक) का पद समाप्त कर दिया गया है तथा इसे पुर्नगठित करके पुलिस स्टेशनों का प्रभारी बनाया गया है। इन पुलिस निरीक्षकों के कर्तव्य इन पुलिस उप निरीक्षकों के समान ही हैं जो विभिन्न थानों के प्रभारियों के होते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश पुलिस में यह पद पुलिस उपनिरीक्षकों को प्रोन्नति प्रदान कर भरा जाता है।

९. उप निरीक्षक

प्रत्येक थाने का प्रभारी भूतकाल में उप निरीक्षक पद का अधिकारी होता था परन्तु अब धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवर्तन होता जा रहा है और धीरे-धीरे थानों पर निरीक्षकों को प्रभारी बनाया जाने लगा है। परन्तु अब भी बहुत से थाने ऐसे हैं जिनका प्रभारी आज भी उप निरीक्षक ही होता है। एक थाने पर कई उप निरीक्षक होते हैं। ये अपने क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत पुलिस का प्रबन्ध करते हैं। अपने क्षेत्र की सीमा में होने वाली प्रत्येक वैध-अवैध गतिविधियों की जानकारी रखना और बदमाशों पर निगरानी रखना इसका दायित्व है। उपनिरीक्षक पद 1902 में पुलिस आयोग की सन्तुति से सृजित किया गया था। इसे सीधी भर्ती द्वारा तथा विभागीय मुख्य आरक्षियों को प्रोन्नति देकर भरा जाता है। थाने के प्रभारी के अतिरिक्त प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर द्वितीय अधिकारी उप निरीक्षक भी होते हैं। उनका मुख्य कार्य उन अपराधों का जो थाना प्रभारी सुपुर्द करे अन्वेषण करना होता है। अन्वेषण का परिणाम एवं आख्या वह थाना प्रभारी को देता है।

१०. मुख्य आरक्षी (हेड कान्सटेबिल)

यह प्रोन्नत पद है जो कि कान्सटेबिलों को प्रोन्नति प्रदान कर भरा जाता है। इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं—थाना लेखक के रूप में, थाने के कार्यालय का रक्षक, लेखक और हिसाब रखने वाला एक मुख्य आरक्षक कहलाता है जिसे हेड मोहर्रिर भी कहते हैं। यह अधिकारी रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखता है, हिन्दी रोकड बही एवं धन सम्बन्धित अन्य लेख प्रमाण ठीक रखता है। सम्मानों का तामील आदि के आदेश थाना प्रभारी को सूचना देता है एवं गांव चौकीदारों की उपस्थिति अंकित करता है। थाना प्रभारी द्वारा बताये गये कार्यों की लिखा पढी का कार्य भी यही सम्पादन करता है विशेष अवसरों पर यह पचनामा लिख सकता है। इसके अतिरिक्त यह चौकी प्रभारी के रूप में भी कार्य करता है। पुलिस चौकी प्रभारी के रूप में मुख्य आरक्षी का प्रथम कर्तव्य थाना प्रभारी को सूचना देना तथा अनुदेश प्राप्त करना होता है। क्षेत्रीय अपराध और भारी वारदातों की उसे थाना प्रभारी को अविलम्ब सूचना देनी होती है। अन्वेषण करने का मुख्य आरक्षी को कोई अधिकारी नहीं है।

११. आरक्षी (कान्सटेबिल)

पुलिस विभाग में आरक्षी सबसे निम्न स्तर का पद है। इसके द्वारा सतरी डियुटी, एस्कोर्ट डियुटी, डाक, ड्रिल और परेड, अर्दली डियुटी, संदेश वाहक डियुटी, शस्त्र सफाई, रात्रिगश्त, चौकसी, लाइसेंस की जाँच, न्यायालय में जाना, प्रशिक्षण देना, समन व वारंट तामील करना, मोटर वाहन चलाना तथा वायरलेस सेट संचालन, दिन की गश्त, थाना नियन्त्रण, शिकायतों की जाच और अधिसूचनाओं के सकलन कार्यों को सम्पादित किया जाता है।

जन सामान्य के साथ सम्पर्क, समझ में होने वाली किसी भी गतिविधि की जानकारी, अपराध घटित होने अथवा हर प्रकार की वैध और अवैध गतिविधि की प्रथम सूचना एवं सम्पर्क, राजनीतिक, अपराधिक, आतंकवादी, श्रमिक, युवा, छात्र, आन्दोलन, धार्मिक गतिविधियों के होने पर पुलिस के जिस वर्ग का सर्वप्रथम सम्पर्क होता है वह है थाना स्तर का स्टाफ सर्वप्रथम किसी भी घटना के घटित होने पर कार्यवाही करता है। इस स्टाफ की कार्यवाही एवं कार्यकलापों का सीधा सम्बन्ध जन साधारण से रहता है और प्रभाव भी जनसामान्य पर परिलक्षित होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि—“देश में पुलिस की छवि अधिकतर उस स्टाफ से बनती है जो थाना स्तर पर कार्य करता है। कान्सटेबुलरी इस स्टाफ का अधिकांश भाग होता है और सम्पर्क पुलिस ढाँचे का आधार यही है”¹⁵।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा कान्सटेबुलरी के सम्बन्ध में की गयी सन्तुष्टि निम्न प्रकार है—

देश में पुलिस व्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए तथा कान्सटेबुल को जनता के साथ पड़ने वाले कार्यों में नैतिक मूल्यों को समझते हुए विवेक और स्वनिर्णय से काम करने वाले जिम्मेदार कर्मचारी बनाने के महत्व को ध्यान में रखते हुये हम यह महसूस करते हैं कि मौजूदा प्रणाली को तत्काल बदल दिया जाये ताकि निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

- 1 कास्टेबुलरी को केवल मात्र यात्रिक प्रकार के कार्य करने वाल सवर्ग नही समझा जाना चाहिए जैसा कि 1902 के पुलिस आयोग ने कल्पना की थी। उनकी भर्ती तथा प्रशिक्षण इस प्रकार से होने चाहिए कि उन्हे ऐसे कार्यों पर भी लगाया जा सके जिनमे किसी स्थिति मे जनता के सहयोग की परम आवश्यकता को ध्यान मे हुये समझ-बूझ और विवेक से काम करना और निर्णय लेना अपेक्षित हो।
- 2 कास्टेबुल को जाच तथा अन्वेषण कार्य मे उपनिरीक्षक को ठोस और सोद्देश्यपूर्ण ढंग से सहायता पहुँचाने मे सक्षम होना चाहिए।
- 3 उन्हे 5 या 6 वर्ष की अवधि मे ऐसे कार्यों का अनुभव प्राप्त कर कस्त्तन्त्र रूप से अन्वेषण का कार्य कर सकने योग्य हो जाना चाहिए और इस प्रकार पदोन्नति द्वारा सहायक उप निरीक्षक तथा उससे ऊपर के पदो तक पहुँचना चाहिए।
- 4 पुलिस प्रणाली के भीतर पदोन्नति सम्बन्धी नीति को बदल कर युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि कान्सटेबुल के पद से शीघ्र तथा बराबर पदोन्नति होती रहे। कान्सटेबुल के लिये पुलिस के कार्य मे अपनी योग्यता दिखाते हुए पदोन्नति द्वारा ऊँचे पदो सबसे ऊँचे पद तक भी पहुँच जाना सम्भव होना चाहिए।

राज्य सरकार का गृहमन्त्री पुलिस विभाग के कार्यों को देखता है और सचिवालय स्तर पर गृह सचिव, विशेष गृह सचिव आदि कई पद सृजित है जो पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यों का पर्यवेक्षण एव समीक्षा करके उनमे गृहमन्त्री को अवगत कराते है।

उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार के अन्य विभागो से अलग अत्यन्त विस्तृत आकार वाला विभाग है। इसमे नित नवीन शाखाये खुलती है और पुलिस विभाग का विस्तार होता रहता है। वर्तमान समय मे इस विभाग मे निम्न शाखाये विद्यमान है—

- 1 नागरिक पुलिस
- 2 सशस्त्र पुलिस
- 3 घुडसवार पुलिस
- 4 पी० ए० सी०
- 5 अपराध अनुसंधान विभाग—इसके अन्तर्गत निम्न उप शाखाये कार्यरत है—
 - (क) अपराध शाखा
 - (ख) भ्रष्टाचार निवारण सगठन
 - (ग) आर्थिक अपराध सगठन
 - (घ) राज्य विद्युत परिषद
 - (ङ) महिला सहायता प्रकोष्ठ
 - (च) विशेष जॉच सेल
- 6 अभिसूचना विभाग
- 7 रेलवे पुलिस
- 8 अग्निशमन सेवा
- 9 पुलिस प्रशिक्षण
- 10 तकनीकी सेवाये—इसके अन्तर्गत निम्न उप शाखाये कार्यरत है—
 - (क) पुलिस कम्प्यूटर
 - (ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला
 - (ग) पुलिस रेडियो
 - (घ) राज्य मोटर परिवहन प्रशिक्षण केन्द्र
 - (ङ) अगुलि छाप सग्रहालय
 - (च) राज्य अपराध सूचना ब्यूरो
 - (छ) यातायात निदेशालय
- 11 होमगार्ड्स एव नागरिक सुरक्षा
- 12 रूल्स एव मैनुअल शाखा

पुलिस प्रशिक्षण

1902 के पुलिस आयोग की सस्तुतियों के फलस्वरूप प्रदेश में सर्वप्रथम मुरादाबाद में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया। यह संस्था तब से लेकर आज तक अनेक उतार-चढ़ाव देख चुकी है और आज प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण का एक व्यापक जाल बिछा हुआ है जहाँ आरक्षी से लेकर भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनर्स तक पुरुष एवं महिला अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में लखनऊ में स्थित है और इसका विभाग का प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद का अधिकारी है। वर्तमान समय में राज्य में तीन पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (मुरादाबाद में—2 तथा सीतापुर में एक), एक—सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर, पांच पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (एक—मुरादाबाद में, एक—उन्नाव में तथा 3—गोरखपुर में), एक रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र, चुनार में स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रदेशीय आवश्यकतानुसार जनपद इकाईयों एवं पी०ए०सी० इकाईयों में रिक्रूट कान्सटेबुल के प्रशिक्षण हेतु आर०टी०सी० समय-समय पर स्थापित की जाती रहती है। इसके अतिरिक्त शाहजहापुर पुलिस लाइन में महिला कान्सटेबुल प्रशिक्षणार्थियों हेतु एक आ० टी० सी० कार्यरत है।

- 1 क्राइम इन इंडिया (1995), पृ० 329
- 2 सविधान के प्रथम एवं चतुर्थ संशोधन आदेश 1960 (G O 3 Dec 25 01 1950)
- 3 लखनऊ सिटी मैगजीन, दिसम्बर 1988, प्रिन्टडएट प्रकाश पैकजर्स, 257, गोलगज, लखनऊ, लेख-एन इन साइड व्यू, पृ० 12
- 4 पूर्वोक्त, पृ० 12
- 5 पूर्वोक्त, पृ० 12
- 6 पूर्वोक्त, पृ० 13
- 7 नेशन पुलिस कमीशन रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट।
- 8 पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद।
- 9 पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद।
- 10 पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद।
- 11 उ० प्र० पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आकड़ों के आधार पर।
- 12 क्राइम इन उत्तर प्रदेश-1990, स्टेट क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो, लखनऊ, पृ० 111-113
- 13 पूर्वोक्त पृ० 111-112
- 14 लखनऊ सिटी मैगजीन, दिसम्बर 1998, पृ० 12
- 15 नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट, प्रथम, पृ० 15

अध्याय—२

शोध-प्ररचना

(Research Design)

शोध-प्ररचना का तात्पर्य

अनुसधान प्ररचना के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए स्वभावतः हमें दो शब्दों शोध या अनुसधान एवं प्ररचना को समझना होगा।

सामाजिक विज्ञान में शोध का अर्थ है, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तार्किक एवं व्यवस्थित ढंग से नए तथ्यों की खोज एवं पुराने तथ्यों का सत्यापन। यद्यपि सामाजिक अनुसधान की परिभाषा देते हुए कहा है, कि “सामाजिक अनुसधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमवद्ध पद्धतियों द्वारा नवीन एवं पुराने तथ्यों का अन्वेषण एवं उसमें पाये जाने वाले अनुक्रमों, अतः सम्बन्धों, कारण-व्यवस्था तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है”¹। तार्किक एवं क्रमवद्ध पद्धति के प्रयोग को सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। जिसके कारण इसे हम वैज्ञानिक अनुसधान भी कहते हैं।

प्ररचना शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थों में किसी रूप या रूपरेखा के लिए होता है। इससे हमारा तात्पर्य किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व निर्मित कार्यक्रम है, जो वास्तविक कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के नियंत्रण एवं समाधान के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इसके आधार पर वास्तविक कार्य के अनुकूलतम एवं व्यवहारिक कार्यविधि ज्ञात की जाती है। इस प्रकार प्ररचना का अर्थ कार्य प्रारम्भ होने के पूर्ण सभावित स्थिति के नियंत्रण के लिए तैयार की गई रूपरेखा या कार्यक्रम की योजना और अनुसधान प्ररचना का अर्थ हुआ अनुसधान कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व का एक विधिवत कार्यक्रम जैसे—उद्देश्य का निर्धारण, पद्धति एवं उपकरण संबंधी योजना, तथ्य-संकलन एवं विश्लेषण का प्रारूप। दूसरे शब्दों में, अनुसधान प्ररचना सम्पूर्ण अनुसधान का एक नियोजन है

जिससे अनुसंधान सम्बन्धी सभी भावी परिस्थितियों का बोध हो जाता है और शोधकर्ता उन्हें नियंत्रित कर सकता है।

अनुसंधान प्ररचना की एक अच्छी व्याख्या कालेजर ने प्रस्तुत की है। उनके अनुसार, “अनुसंधान प्ररचना का अन्वेषण की योजना, सरचना एवं रणनीति है, जिसके शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकें एवं प्रकरण (Variance) को नियंत्रित किया जा सके”²।

इस परिभाषा में शोध प्ररचना के तीन पक्ष स्पष्ट किए गये हैं—

(1) योजना

इसमें वे सभी प्रणालियाँ एवं कार्यक्रम सम्मिलित हैं, जिन्हें शोधकर्ता अनुसंधान के विभिन्न चरणों के रूप में सम्पन्न करना चाहता है, अर्थात् उपकल्पना के निर्माण से तथ्य विश्लेषण तक आवश्यक एवं प्रमुख चरणों की रूपरेखा स्पष्ट की जाती है।

(2) संरचना

इसके अन्तर्गत अनुसंधान के स्वरूप को व्यवहारिक स्तर पर स्पष्ट किया जाता है, जैसे—परिवर्त्यों एवं अवधारणाओं की व्यवहारिक तथा कार्यकारी व्याख्या, उनके अंत सम्बन्धों का स्वरूप आदि।

(3) शोध-नीति

इसके अन्तर्गत उन तकनीकों या प्रविधियों का उल्लेख रहता है, जो उपकल्पना, परीक्षण तथ्य सकलन एवं विश्लेषण के लिए प्रयुक्त होंगे।

इस प्रकार अनुसंधान प्ररचना, शोध प्रक्रिया की रूपरेखा (योजना) उसकी कार्यकारी एवं व्यवहारिक स्वरूप (सरचना) तथा तथ्य सकलन, उपकल्पना परीक्षण तथा तथ्य विश्लेषण के प्रविधि सम्बन्धी निर्णय (शोध-नीति) से सम्बन्ध एक नियोजित कार्यक्रम है, जिसके आधार पर शोध के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

कालेजर ने अपनी परिभाषा में अनुसंधान प्ररचना के दो उद्देश्यों की चर्चा की है।—

- (1) शोध सम्बन्धो प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना
- (2) घटने बढने या प्रसरण से उत्पन्न दोषो को नियत्रित करना जिससे वे उत्तर विश्वसनीय एव वैध है।

अनुसंधान प्ररचना के प्रमुख प्रकार

कुछ समाज वैज्ञानिको के अनुसार, अनुसंधान प्ररचना के तीन प्रचलित प्रकार है, जो प्रतिदर्शन और तथ्य विश्लेषण की पद्धति पर आधारित है।—

- (1) सर्वेक्षण अनुसंधान
- (2) वैयक्तिक अध्ययन
- (3) प्रायोगिक अध्ययन

इसी प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन उद्देश्य के आधार पर भी अनुसंधान प्ररचना का वर्गीकरण किया गया है। सेल्टिज, जहोदा आदि के अनुसार प्रत्येक अनुसंधान के विशिष्ट उद्देश्य होते है और उन्ही के अनुरूप अनुसंधान प्ररचना भी विकसित करनी पडती है। इन शोध उद्देश्यो को हम निम्नलिखित प्रमुख वर्गों मे रख सकते है—

- (1) किसी घटना या विषय के बारे मे अर्तदृष्टि प्राप्त करना अथवा अनुसंधान समस्या एव उपकल्पना का निर्माण करना। इस प्रकार के अध्ययन अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अध्ययन कहे जाते है।
- (2) किसी व्यक्ति या समूह अथवा विशेष स्थिति की विशेषताओ का (उपकल्पना के साथ अथवा उपकल्पना के बिना) विवरण प्रस्तुत करना। इस प्रकार के अध्ययन वर्णनात्मक अध्ययन कहलाते है।
- (3) तीसरा उद्देश्य है किसी घटना या वस्तु की आवृत्ति का अध्ययन अथवा दो घटनाओ के बीच सम्बन्ध की पद्धति की व्याख्या। ऐसे अध्ययन साधारण उपकल्पना के साथ किए जाते है, (यद्यपि बिना उपकल्पना के भी ऐसे अध्ययन किए गये है)। ऐसे अध्ययन निदानात्मक अध्ययन के नाम से जाने जाते है।

- (4) अतः मे दो या दो से अधिक घटना अथवा परिवर्तनों के बीच कार्यकारण सम्बन्ध दर्शाने वाली उपकल्पना का परीक्षण होता है, ऐसे अध्ययन प्रयोगात्मक अध्ययन कहलाते हैं।

इस तरह उद्देश्यों की उपर्युक्त भिन्नता के आधार पर अनुसंधान प्ररचना के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार हैं।

- (1) अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान प्ररचना।
- (2) वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना।
- (3) निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना।
- (4) प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना।

प्रस्तुत शोध में “वर्णनात्मक शोध” प्ररचना को आधार बनाया है। इस शोध प्रारूप का उद्देश्य विषय या समस्या के सम्बन्ध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है। यहाँ मुख्य जोर इस बात पर दिया जाता है कि विषय से सम्बन्धित एकत्रित किये गये तथ्य वास्तविक एवं विश्वसनीय हो अन्यथा जो वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा, वह वैज्ञानिक होने के बजाय दार्शनिक ही होगा। तथ्यों को प्राप्त करने हेतु अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली अथवा किसी अन्य प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे शोध में घटनाओं को यथार्थ रूप में चित्रित करने पर विशेष बल दिया जाता है।

वर्णनात्मक शोध कार्य के सफलतापूर्वक संचालन के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरना आवश्यक होता है।

- (1) शोध के उद्देश्यों की प्रविधियों का चुनाव
- (2) तथ्य सकलन की प्रविधियों का चुनाव
- (3) निदर्शन का चुनाव
- (4) आकड़ों का सकलन एवं उनकी जाँच

(5) तथ्यों का विश्लेषण

(6) प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का प्रस्तुतीकरण

उपर्युक्त चरणों से गुजर कर ही वर्णनात्मक शोध कार्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य (Aims of the Present Research)

किसी भी सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक स्थिति, निष्पक्ष निष्कर्ष वास्तविक ज्ञान उसमें प्रयुक्त वैज्ञानिक पद्धति की सफलता, सामाजिक प्रघटनाओं के सम्बन्ध में अनुभावात्मक ज्ञान की प्राप्ति, सत्यापन की आवश्यकता एवं भावी अनुसंधान की सम्भावनाओं को विकसित करने के लिए अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित करा अनिवार्य हो जाता है। अतः शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किये गये।

एक कथन के रूप में हमारी शोध समस्या निम्न है— एक परिभाषित क्षेत्र को आंतरिक व्यवस्था को बनाये रखने में महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका उनके निर्धारित कर्तव्य, कर्तव्य अनुपालन में सफलताएँ तथा बाधक कारकों का समाज शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करना। उपरोक्त समस्या में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है।

(1) महिला पुलिस की भूमिका

(2) महिला पुलिस की सफलताएँ एवं कार्य दशाएँ।

(3) कर्तव्य पालन में आने वाली बाधाएँ।

वस्तुतः ये तीन बिन्दु ही प्रस्तुत शोध अध्ययन के तीन विशिष्ट उद्देश्य प्रस्तावित हैं।

इन्हीं प्रस्तावित उद्देश्यों से सम्बन्धित तथ्यों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण इस शोध अध्ययन में किया जायेगा।

उपकल्पनाएँ (Hypothesis)

किसी भी शोध कार्य में गति लाने और सम्भावित दिशा देने में कतिपय पूर्व कल्पनाये महत्वपूर्ण कार्य करती है। समाजशास्त्री राबर्ट के मर्टन ने इसे कार्यकारी पूर्व कल्पना कहा है।

प्रस्तुत अध्ययन की कार्यकारी पूर्व कल्पनाएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आंतरिक व्यवस्था के परिचालन में पुरुष पुलिस बल के अतिरिक्त महिला पुलिस की आवश्यकता है।
- (2) निर्धारित कर्तव्यों के अनुपालन में महिला पुलिसकर्मी सफल रही है।
- (3) महिला पुलिसकर्मी की सेवा का प्रभाव स्थानीय जनसमुदाय पर प्रभावशाली सिद्ध हुआ है।
- (4) महिला पुलिस की मुख्य समस्याएँ सामाजिक और प्रशासनिक तंत्रों की उदासीनता से सम्बन्धित रही है।

तथ्य प्राप्ति के स्रोत (Sources of data)

“उत्तर-प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों की कार्यदिशाएँ, सफलताएँ और समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण” शोध का एक ऐसा विषय है, जिस पर अभी तक उ०प्र० में कोई भी शोध प्रकाश में नहीं आया है। अतः इस समस्या के सदर्भ में महिला पुलिस कर्मियों की इन क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त करने का शोधार्थी द्वारा प्रथम बार प्रयास किया जायेगा।

किसी शोध विषय पर प्रथम बार एकत्र किए तथ्यों का सकलन अथवा सूचनाओं के एकत्रिकरण की प्रक्रिया को प्राथमिक स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है, चूँकि यह विषय अभी तक अछूता ही रहा है। अतः इस विषय पर शोधकर्ता द्वारा स्वयं क्षेत्र में जाकर सामान्य जन एवं महिला पुलिस कर्मियों और पुरुष पुलिस कर्मियों से प्रस्तावित विषय के सदर्भ में प्रथम बार जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया है।

प्राथमिक स्रोतों से तथ्यों के सकलन के रूप में औपचारिक व अनौपचारिक साक्षात्कार, अनुसूची का प्रयोग मुख्य तौर पर तथा अवलोकन का प्रयोग किया है।

प्राथमिक स्रोतों से तथ्यों के सकलन करने के अलावा चूँकि शोध समस्या का सम्बन्ध महिला पुलिस कर्मियों के साथ—साथ विभाग के पुरुष पुलिस कर्मियों से भी है। अतः विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार से सूचनाएँ (विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाओं के रिकार्ड, प्रकाशित आकड़े, पत्र—पत्रिकाओं की रिपोर्ट आदि) हैं। प्रकाशित शोध या अप्रकाशित शोध ग्रंथों एवं पुस्तकों द्वारा द्वैतियक तथ्यों का सकलन किया गया है।

अध्ययन इकाइयों का निर्धारण (Units of Study)

शोधकार्य में इकाई का निर्धारण विषय के ऊपर निर्भर करता है वही इकाई का उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त होना अनुसंधान के उद्देश्य पर। प्रस्तुत शोध विषय महिला पुलिस कर्मियों की कार्यदिशाओं, सफलताओं और समस्याओं से सम्बन्धित है। इनके बारे में वास्तविक मूल्यांकन तभी हो सकता है, जबकि महिला पुलिस कर्मियों के साथ—साथ उनके सहकर्मियों यानि पुरुष पुलिस कर्मियों एवं सामान्य जन सूचनादाता, जो विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं उनसे तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली जाय।

अतः प्रस्तुत शोध के लिए तीन प्रकार की इकाइयों का निर्धारण आवश्यक है। प्रथम महिला पुलिसकर्मी, द्वितीय पुरुष पुलिसकर्मी तथा तृतीय इनके सम्पर्क में आने वाले सामान्य जन।

सामान्य जन से ली गयी इकाइयों का चयन करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है, कि समस्या के सम्बन्ध में जानकारी परिपक्व आयु वर्ग के विभिन्न व्यवसायों एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ ही महिला एवं पुरुष दोनों को ही लिया गया है।

पुलिस जन के इकाइयों के रूप में चयन करने समय प्रस्तुत सर्वेक्षण के लिए आरक्षी से लेकर भारतीय पुलिस सेवा तक के अधिकारियों को समग्र रूप से इकाई हेतु चयन किया गया है, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों ही हैं।

अध्ययन क्षेत्र (Area of Study)

शोध समस्या के निधारण उपरान्त शोधकर्ता को अपने अध्ययन के लिए क्षेत्र का निश्चय करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में समस्या की प्रकृति एवं महत्ता के साथ-साथ शोधकर्ता को अपने ससाधनों का भी ध्यान रखना परम आवश्यक हो जाता है।

‘उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों की कार्यदशाएँ, सफलताएँ और समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण’ समस्या पर अध्ययन पकरने हेतु शोधकर्ता ने अपनी सीमित ससाधनों एवं व्यापकता से बचाव तथा शोध कार्य की वैज्ञानिकता को बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्रों जैसे—इलाहाबाद और कानपुर को चुना है। इन दोनों क्षेत्रों में उ०प्र० के महिला पुलिस कर्मियों की झलक देखी जा सकती है। अतः इसे अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया।

इलाहाबाद और कानपुर का सामान्य परिचय

इलाहाबाद का संक्षिप्त परिचय³

जनसंख्या

इलाहाबाद की जनसंख्या (2001 की जनगणना के आधार पर) 4941510 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 2625872 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 2315638 है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 26.72 प्रतिशत और स्त्री-पुरुष अनुपात 882-1000 है।

क्षेत्रफल

इलाहाबाद का क्षेत्रफल 5246 वर्ग किमी० है।

जनसंख्या घनत्व

2001 की जनगणना के आधार पर इलाहाबाद की जनसंख्या घनत्व 911 है।

शिक्षा

इलाहाबाद, उत्तर-प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पर अन्य जिलों से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए, परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। जिसमें से काफी लोग कोचिंग सस्थाओं का सहारा लेने भी आते हैं। इस तरह इस जनपद का माहौल पठन-पाठन का केन्द्र सदैव बना रहता है। इस जिले की साक्षरता 62.89 प्रतिशत (2001 की जनगणना के आधार पर) है। 1922 प्राथमिक विद्यालय, 586 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 230 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 16 महाविद्यालय, 4 पॉलिटेक्निक एंव आई०टी०आई० है। सम्प्रति इलाहाबाद में तीन विश्वविद्यालय हैं।

अन्य

नगरपालिका, परिषदों की संख्या 1 है। तहसीलों की संख्या 20 है। जैसे-हण्डिया, धनूपुर, प्रतापपुर, सैदाबाद, बहादुरपुर, बहरिया, फूलपुर, होलागढ़, कौडिहार, मऊआइमा, सोरॉव, चाका, करछना, कौधियारा, जसरा, शकरगढ़, कोरॉव, माण्डा, मेजा, उरवा। 3074 ग्रामों की संख्या है।

जनपद मे लोकसभा सदस्यों की संख्या 3 एवं विधानसभा सदस्यों की संख्या 14 है। 207 प्रारम्भिक उद्भिन्न ऋण, सहकारी समितियाँ हैं। 36 जिला सहकारी बैंक शाखाएँ हैं। 246 अनुसूचित व्यावहारिक बैंक शाखाएँ हैं।

विद्युतीकरण ग्रामी की संख्या 1713 है। 127 चिकित्सालय एवं औषधालय हैं।

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 212875 हेक्टेयर है।

प्रमुख उद्योग

राइस मिल, दाल मिल, इलेक्ट्रानिक्स।

कुल पक्की सड़कें

3223 किमी०

प्रमुख नदियाँ

गंगा, यमुना, मनसैइता

कानपुर का संक्षिप्त परिचय⁴

भौगोलिक स्थिति

भौगोलिक दृष्टि से जनपद कानपुर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में 25°—26° से 26°—58° उत्तरी अक्षांश तथा 79°—31° से 80°—34° पूर्वी देशान्तर के बीच टेढ़े-मेढ़े चतुर्भुज के आकार में बसा हुआ है, जिसके उत्तर पूर्व की सीमा गंगा नदी से बनी हुई है। जिसके उस पार हरदोई तथा उन्नाव हैं। पूर्व दक्षिण में यह जनपद फतेहपुर की बिदकी तहसील से जुड़ा हुआ है। दक्षिण पश्चिम की सीमा जमुना नदी से घिरी हुई है उसके उस पार जनपद हमीरपुर तथा जालौन हैं। उत्तर पश्चिम में यह क्रमशः जनपद—इटावा, औरंगा तथा विधून तहसील और जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कन्नौज से जुड़ा हुआ है। 1981 की जनगणना के अनुसार कानपुर जिले की जनसंख्या कुल 37,90,548 हुई, जिसमें पुरुषों की संख्या 19,45,316 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 17,30,992 थी। 1981 की जनगणना के बाद जिला दो भागों में बँट गया—कानपुर महानगर जनपद और देहात जनपद ।

2001 की जनगणना के अनुसार 4137489 कानपुर महानगर की जनसंख्या है जिसमें पुरुषों की जनसंख्या—2213955 एवं स्त्रियों की जनसंख्या 1923534 है। जनसंख्या में दशकीय दृष्टि दर 27.17 प्रतिशत है एवं स्त्री—पुरुष का अनुपात 869—1000 है।

घनत्व

कानपुर महानगर के म्युनिसिपल क्षेत्र में आबादी का घनत्व प्रति वर्ग मील 71,360 तथा प्रति एकड़ 115 व्यक्ति है। छावनी क्षेत्र में यह औसत प्रति वर्ग मील 6,885 तथा प्रति एकड़ 17.6 है। नगर के कुछ भाग दूसरे भागों की अपेक्षा बहुत घने बसे हुए हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार कानपुर नगर की जनसंख्या घनत्व 1366 है।

क्षेत्रफल

जिला कानपुर का क्षेत्रफल 3015 वर्ग किमी० है

सीमा

जिला कानपुर के पूर्व में जिला फतेहपुर तथा पश्चिम में जिला इटावा और फर्रुखाबाद है। उत्तरी सीमा गंगा तथा दक्षिणी सीमा यमुना नदी बहती है गंगा नदी के उत्तर में जिला उन्नाव तथा यमुना नदी के क्षेत्र में जालौन व हमीरपुर जिले हैं। प्रशासन के दृष्टिकोण से 24 अप्रैल 1981 से कानपुर महानगर व कानपुर देहात को पृथक कर दिया गया।

विस्तार

कानपुर जिले की लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 112 किलोमीटर (70 मील) तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 104 किलोमीटर (65 मील) है।

जलवायु एवं वर्षा

यहाँ की जलवायु दो अरबी भागो की जलवायु से मिलती है। मार्च के महीने से, वर्षा के आरम्भ होने तक गर्म तथा तेज हवा से चलती है। जिनमे मई, जून के महीने मे कठोर गर्मी पडती है। इस अवधि मे लू के थपेडे जनसाधारण के लिए दुखदायी हो जाते है। वर्षा के आरम्भ मे पुरवा हवाए चलती है। इसके पश्चात् अक्टूबर माह से तापक्रम कम होने लगता है और जनवारी माह मे तापक्रम सबसे कम रहता है। जुलाई मे वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो जाती है। भीषण गर्मी से व्याकुल सभी प्राणी पेड-पौधो मे नया जीवन आ जाता है। फसल बो दी जाती है। इस ऋतु मे पूर्व से आने वाली पुरवैया (मानसूनी) हवा के द्वारा पानी बरसता है। हमारे जिल मे प्रतिवर्ष 900 मिली मीटर पानी बरसता है।

यातायात

ये जनपद देश के अन्य मार्गों से सडक, रेल तथा वायुमार्ग द्वारा जुडा हुआ है। राष्ट्रीय मार्ग सख्या 25 जनपद को झासी तथा लखनऊ से मिलाती है। राष्ट्रीय मार्ग सख्या-2 (जी०टी० रोड) जो पेशावर से कलकत्ता तक जाती है, पर कानपुर नगर के बसे होने के कारण यह प्रदेश मे स्थित नगर वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, एटा, अलीगढ, बुलन्दशहर तथा मेरठ से जुडा है। प्रदेशीय मार्ग सख्या 16 कानपुर से हमीरपुर होते हुए सागर से जोडता है। रेलमार्ग मे जनपद को उत्तरी, उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी रेलवे की सुविधाए उपलब्ध है। उत्तरी रेलवे की दिल्ली से कलकत्ता तक जाने वाली प्रमुख लाइन कानपुर नगर से होकर गुजरती है तथा इसी रेलवे की ब्रान्च लाइन कानपुर को मुगलसराय लाइन पर स्थित प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोडती है। दक्षिणी रेलवे द्वारा जनपद बोंदा तथा बम्बई से व उत्तरी पूर्वी रेल जनपद को एक और कासगज होते हुए आगरा से तथा दूसरी ओर लखनऊ तथा गोरखपुर होते हुए

सिलीगडी से सीधे जोड़ती है। वायुमार्ग सेवा कानपुर को 01/02/1963 से उपलब्ध हो गयी है। कुल पक्की सड़कें 3068 किमी० हैं।

मुहल्ला का विवरण

1875 में जब लाला दरगाही लाल ने अपनी तारीख-ए-कानपुर का प्रकाशन किया तो नगर के मुहल्लों की संख्या 71 थी। अब यह संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। नई आबादियों के क्षेत्र में यहाँ के निवासियों ने अपनी इच्छा से छोटे-छोटे टुकड़ों के नाम रख लिये थे। जिसमें कुछ तो प्रसिद्धि पा चुके हैं और कुछ चल न पाये। किसी-किसी बास्ती के दो अथवा अधिक प्रतिद्वन्दी नाम भी हैं ऐसी गड़बड़ी में अनाधिकृत नामों की काफी भरमार है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कानपुर और वृहत्तर कानपुर के अन्तर्गत यहाँ अनेक और बड़े मुहल्ले हैं। कानपुर महानगर को 4 जानों में बाँटा गया है और इनके अन्तर्गत विभिन्न मुहल्ले हैं।

भाषा

कानपुर महानगर की भाषा मुख्यतया हिन्दी, पंजाबी, बंगाली, सिन्धी, उर्दू आदि भाषाएँ हैं। लोक भाषा के अन्तर्गत प्रायः दो बोलियाँ प्रचलित हैं—शिक्षित लोगों में खड़ी बोली, अशिक्षित लोगों में कन्नड़जी, अवधी, भोजपुरी बोली जाती है।

1991 के जनसंख्या के अनुसार—

भाषाएँ	कुल	प्रतिशत
हिन्दी	33,45,071	89.8
उर्दू	3,25,820	8.7
पंजाबी	29,434	0.8
बंगाली	10,792	0.3
अन्य	15,308	0.4
योग	37,26,425	100.0

धर्म

कानपुर महानगर में सभी धर्मों के लोग समान रूप से निवास करते हैं। सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। कानपुर महानगर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर है। नगर में सभी धर्मों के व्यक्ति हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, पारसी आदि समान रूप से निवास करते हैं और उनमें परस्पर प्रेम, सहयोग व सहिष्णुता की भावना है।

जनपद कानपुर महानगर में प्रमुख धर्मानुसार संख्या १९८१

मुख्य धार्मिक समुदाय	जनसंख्या	
	कुल	नगरीय
हिन्दू	15,51,295	12,57,392
मुसलमान	3,47,094	3,34,842
सिक्ख	31,348	31,337
ईसाई	12,721	12,519
अन्य	8,125	8,125
धर्म नहीं बताया	167	167
योग	19,50,750	16,44,382

शिक्षा

कानपुर महानगर में शिक्षा की भी समस्त सुविधाएँ प्राप्त हैं। भारत में 5 प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक कानपुर महानगर में आई०आई०टी० स्थित है। इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, एच०बी०टी०एल०, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल कालेज, पॉलिटेक्निक, स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र, सामान्य व उच्च शिक्षा सम्बन्धी अनेक संस्थाएँ हैं। इन क्षेत्रों में स्त्रियाँ भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। यहाँ (2001 साक्षरता जनगणना के अनुसार) 77.63 प्रतिशत है। 2455 प्राथमिक विद्यालय, 651 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 220 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 22 महाविद्यालय, 2 विश्व विद्यालय हैं।

नगरपालिका परिषदो की सख्या 2 है। 3 तहसील एव 10 विकास खण्ड है। 10005 ग्रामो की सख्या है। गंगा एव जमुना यहाँ की प्रमुख नदियों है। जनपद मे लोक सभा सदस्यो की सख्या 3 एव विधान सभा सदस्यो की सख्या 10 है। जिला सहकारी बैंक शाखाए 22 है। विद्युतीकृत ग्रामो की सख्या 671 है एव 125 चिकित्सालय एव औषधालय है।

प्रमुख उद्योग

चमड़ा, कालीन, सूती, रक्षा सामग्री, मशीनरी, होजरी वस्त्र, आभूषण आदि।

निदर्शन

प्रस्तुत अध्ययन मे शोध हेतु का तीन वर्गों से निदर्शन का निश्चयन किया गया है। वह वर्ग है महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी एव सामान्य जन के लोग जो कि विभिन्न क्षेत्रो से सम्बन्धित है, जिनका सम्पर्क महिला पुलिस एव पुरुष पुलिस दोनो ही रहता है।

पुलिसकर्मी सूचनादाताओ का चुनाव (महिला एव पुरुष दोनो के लिए) इलाहाबाद और कानपुर दोनो ही जनपद से है। लेकिन सामान्य सूचनादाताओ के लिए केवल इलाहाबाद क्षेत्र ही चुना है। शोधार्थी के लिए यहाँ निवास के आधार पर सुविधाजनक भी था।

निदर्शन प्रविधि का तात्पर्य उस विधि से है जिसकी सहायता से प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अध्ययन निष्कर्षों की यथकिता के लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। निदर्शन के चुनाव की ये प्रमुख प्रविधियाँ है।

- (1) दैव निदर्शन
- (2) उद्देश्य पूर्ण अथवा सविचार निदर्शन (Purposive sampling)
- (3) सस्तरित अथवा वर्गीकृत निदर्शन (Stratified Sampling)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निदर्शन के चयन का आधार उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन है। जिसमें शोधार्थी किसी विशेष उद्देश्य को समाने रखकर जान-बूझकर समग्र में कुछ इकाईयों का चुनाव करता है। इसमें समग्र की इकाईयों के लक्षणों से पूर्व परिचित होकर सविस्तार पूर्वक निदर्शनों का चुनाव किया जाता है। चुनाव का आधार अध्ययन का उद्देश्य होता है और उद्देश्यों को सामने रखते हुए उसी के अनुरूप सम्पूर्ण क्षेत्र से सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाईयों का चुनाव किया जाता है।

विभिन्न पदों को महिला एवं पुरुष पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उनके नियुक्ति स्थल यथा पुलिस थाना, पुलिस चौकी, पुलिस अधिकारी निवास, पुलिस कार्यालय अथवा मुख्यालय पर जा कर सूचना एकत्रित की है। ये कार्य इलाहाबाद के साथ-साथ कानपुर में भी किया गया है। अतः शोधकार्य के विस्तृत एवं व्यापक सर्वेक्षण के लिए पुलिस जन (महिला एवं पुरुष) के कार्य स्थलों पर जाकर सम्पर्क करना दुष्कर सा लगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग (विभिन्न स्तर पर हर तरह का) साथ ही वो लोग जिन्होंने अनुसूची भरने एवं भरवाने में सहयोग दिया, (जो सामान्यजन एवं पुलिस विभाग के लोग थे) उनके योगदान से ही शोधकार्य पूरा हो सका।

सर्वप्रथम इलाहाबाद में माघमेला क्षेत्र में तैनात महिला पुलिस एवं पुरुष पुलिस कर्मियों से सूचनाएं एकत्रित किया गया। उसके पश्चात् महिला थाना सिविल लाइन्स, पुरुष थाना सिविल लाइन्स, दारागज, थाना कोतवाली, चौकी बादशाही मण्डी, थाना मुट्ठीगज, चौकी मालवीय नगर, थाना खुल्दाबाद, पुलिस मुख्यालय, थाना कर्नलगज, पी०ए०सी० आदि जगहों पर जाकर सूचनाएं एकत्रित किया गया। इसके अलावा महिला पुलिस के निवास स्थान अधिकतर पुलिस लाइन जाकर सूचनाएं ली गयीं।

फरवरी 1999 में जब माघ मेला या कुम्भ मेला क्षेत्र में पहली बार कार्य के लिए गयी तो वहाँ का माहौल हमें जाना पहचाना सा लगा, शायद इसलिए की पारिवारिक पृष्ठभूमि पुलिस विभाग से जुड़ी हुई है। दूसरा, यदि वहाँ के अधिकारियों का सहयोग

न मिला होता तो कार्य आगे बढ़ा पाने की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होती। वहाँ के महिला पुलिस एव पुरुष पुलिस दोनों ने ही काफी, सहयोग प्रदान किया और कार्य की शुरुवात सही ढंग से हो पायी। कुछ एक अनुभवों को छोड़कर इलाहाबाद की महिला एव पुरुष दोनों ही पुलिस कर्मियों ने हमें सहयोग प्रदान किया।

कानपुर क्षेत्र में सूचना एकत्रित करने का कार्य एस०एस०पी० ऑफिस से शुरू हुई जहाँ जनवरी 2000 से कार्य शुरू हुआ और तत्कालीन एस०एस०पी० महोदय के सहयोग से कार्य ज्यादा ढंग से सम्पादित हो पाया। इसके बाद महिला थाना, पुलिस लाइन, थाना सीसामऊ, थाना बजरिया, थाना बादशाही नाका, थाना कल्याणपुर, थाना पनकी, थाना छावनी, थाना चकरी, थाना कोतवाली, पुलिस लाइन आदि स्थानों के साथ-साथ इन महिला पुलिस के निवास स्थान पर भी घर ढूँढ़ते हुए पहुँच गये। यहाँ पर भी महिला पुलिस ने सहयोग प्रदान किया। व्यस्त होने के बावजूद भी अनुसूची लिखाया और साक्षात्कार दिया है।

सामान्यजन के लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों से सूचनादाता को चुना है जो डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षक विभिन्न स्तरों के, व्यापारी, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, ज्योतिषी, वैज्ञानिक, छात्र-छात्राओं साधारण गृहणी आदि हैं।

तथ्य संकलन विधि

निर्दर्शन निश्चयन के उपरान्त शोधकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यशोध उपकरणों का निर्धारण होता है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने शोध उपकरणों के रूप में औपचारिक एव अनौपचारिक साक्षात्कार, अनुसूची तथा अवलोकन का प्रयोग किया है।

संक्षेप में, प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता के समक्ष तीन प्रकार के सूचनादाता थे—पहला सामान्यजन सूचनादाता, दूसरा महिला पुलिसकर्मी एव तीसरा पुरुष पुलिसकर्मी। शोध की व्यापकता एव महत्ता को देखते हुए तीन अलग-अलग अनुसूचीयों का निर्माण किया गया। कई प्रश्नों के समक्ष अनुमानित वैकल्पिक उत्तर अंकित किये गये जिससे वे सरलता से उत्तर दे सकें।

पूर्वगामी सर्वेक्षण

तथ्य सकलन हेतु वाछित अनुसूची के निर्माण को अन्तिम रूप प्रदान करने से पूर्व शोधार्थी द्वारा पूर्वगामी अध्ययन (Pilot Study) भी किया गया। जिससे अनुसूची की वस्तुनिष्ठता का ज्ञान हो सके तथा अनावश्यक प्रश्नों को निकाला जा सके। कभी-कभी कोई प्रश्न अस्पष्ट एवं जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूछा जा रहा है। उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी भी जाँच हो जाती है। अतः तीनों अनुसूचियों की बीस-बीस प्रतियाँ तैयार कर सामान्यजन एवं पुलिसजन (महिला एवं पुरुष) सूचनादाताओं पर परिक्षित की गयी। उनसे प्राप्त सूचनाओं एवं उत्तरों के सन्दर्भ में अनुसूचियों की सशोधित एवं परिमार्जित कर उन्हें अन्तिम रूप प्रदान किया गया।

अनुसूची को अन्तिम रूप देने के उपरान्त उन्हें मुद्रित कराकर सामान्य सूचनादाता एवं महिला पुलिस कर्मियों व पुरुष पुलिस कर्मियों से उनके कार्यस्थल एवं निवास स्थान पर सुविधानुसार सूचनाएँ एकत्र की गयीं।

महिला पुलिस एवं पुरुष पुलिस से सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए इसका पूर्वगामी सर्वेक्षण फरवरी 1999 में कुम्भ मेला क्षेत्र में किया गया और साथ ही साक्षात्कार में आने वाली समस्याओं और कमियों का भी पता चला जिसे बाद में कार्य के समय सुधार लिया गया।

महिला पुलिस एवं पुरुष पुलिस से सूचनाएँ इलाहाबाद एवं कानपुर से और सामान्य सूचनादाताओं से इलाहाबाद से एकत्रित की गयी हैं।

स्वतंत्र चर

प्रस्तुत अध्ययन में सामान्यजन एवं पुलिसजन सूचनादाताओं (महिला एवं पुरुष) की सामाजिक स्थिति एवं कार्यालय पदस्थिति, आयु, शिक्षा, जाति, धर्म आदि व्यापक स्वतंत्र चरों को नियत किया गया है। शिक्षा के वर्गीकरण में शोधार्थी द्वारा हाईस्कूल, इन्टर, बी०ए० (स्नातक), परास्नातक एवं अन्य उच्च शिक्षा के आधार पर महिला पुलिस एवं सामान्य सूचनादाताओं का अध्ययन किया गया। महिला पुलिसकर्मी एवं सामान्य सूचनादाताओं का धर्म के आधार पर वर्गीकरण हिन्दू, मुस्लिम एवं आदि के आधार पर किया गया है। महिला पुलिसकर्मी, पुरुष

पुलिसकर्मी एव सामान्यजन का जाति के आधार पर वर्गीकरण जैसे—उच्च जाति, पिछड़ी जाति एव अनुसूचित जाति के आधार पर किया गया है। महिला पुलिस का वैवाहिक आधार पर वर्गीकरण अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा एव विधवा में किया गया है। सभी प्रकार के सूचनादाताओं का वर्गीकरण लिंग के आधार पर किया गया है। महिला पुलिस एव पुरुष पुलिस का सेवाकाल के आधार पर 6 वर्गों (1) 0—5 वर्ष, (2) 6—10 वर्ष, (3) 11—15 वर्ष, (4) 16—20 वर्ष, (5) 21—25 वर्ष, (6) 26 वर्ष तथा इससे ऊपर में बाँटा है।

महिला पुलिस और सामान्य सूचनादाताओं का आयु के आधार पर वर्गीकरण 5 प्रकार से है जैसे— (1) 18—30 वर्ष (2) 31—40 वर्ष (3) 41—50 वर्ष (4) 51—60 वर्ष (5) 60 वर्ष से ऊपर।

आश्रित चर

इसमें अन्तर्गत महिला पुलिस का स्वयं के बारे में एव अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित विचार। पुरुष पुलिस का महिला पुलिस के सम्बन्ध के बारे में विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विचार। आम जनता जो विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित है, का महिला पुलिस के बारे में विभिन्न विचार। ये विचार महिला पुलिस में विभिन्न पदों के अनुसार भूमिकाओं, कार्यदशाओं, सफलताओं और बाधाओं के सम्बन्ध में हैं।

सारणीयन एवं विश्लेषण

प्राप्त दस्तों (तथ्यों) को सामान्य विशेषताओं के आधार पर क्रमों/समूहों में विन्यासित कर, विभिन्न परन्तु सम्बद्ध भागों में अलग—अलग करके वर्गीकृत किया, तदुपरान्त वर्गीकृत तथ्यों से सतत श्रेणियों में शृंखलावद्ध किया। तदुपरान्त शोधार्थी द्वारा उपलब्ध तथ्यों का विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत सारणीकरण किया गया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्यों के विश्लेषण को प्रक्रिया एकत्रित तथ्यों की सूक्ष्म परीक्षा, तथ्य विश्लेषण का योजना, सांख्यिकीय वर्णन तथा कारण कार्य सम्बन्धों का विश्लेषण चार सोपानों में सम्पन्न की गयी है।

कठिनाईयाँ

किसी भी कार्य को करते समय अनेक समस्याएँ, बाधाएँ एवं कठिनाईयाँ उत्पन्न होती हैं। प्रस्तुत शोध में भी शोधकर्ता के समक्ष अनेकानेक समस्याएँ एवं कठिनाईयाँ सामने आयी जिनमें कुछ निम्न प्रकार हैं—

- (1) प्रथम अध्ययन क्षेत्र (दो जनपदों इलाहाबाद और कानपुर) विस्तृत और व्यापक तो था ही जबकि सूचनाएँ अनुसूची, साक्षात्कार एवं आवलोकन के आधार पर एकत्रित की गयीं।
- (2) पुलिस जन (महिला एवं पुरुष दोनों) जिनके स्वभाव में शासकीय अह उत्पन्न हो जाता है, उनसे अनुसूची या साक्षात्कार के द्वारा सूचना एकत्रित करना अत्यन्त टेढ़ी खीर प्रतीत हुआ।
- (3) यद्यपि आरक्षी से लेकर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों तक सूचनाएँ एकत्रित की, लेकिन कुछ सूचनाओं के लिए कई-कई महिनो तक इन्तजार करना पड़ा कई बार वास्तविक रूप से महिला पुलिस की व्यस्तता रही और कई बार बिना कारण के। ये दिक्कत ऐसी नहीं थी, कि उच्च अधिकारियों की तरफ से ही हो, इलाहाबाद में थाना खुल्दाबाद में एक उपनिरीक्षक से अनुसूची लिखाने के लिए लगभग 8-9 महीने जाना पड़ा, लेकिन अन्ततः अनुसूची की पूर्ति नहीं की जा सकी।
- (4) कानपुर क्षेत्र में कार्यकर्ता समय सबसे ज्यादा दिक्कत तब महसूस हुई जब महिला थाने पर महिला उपाधीक्षक ने अनुसूची भरवाने से साफ इन्कार कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है और जबकि अच्छा खासा समय उनके पास था, तो ये केवल उनका अह था जो वहाँ पर प्रदर्शित हुआ।
- (5) सामान्यजन इतने प्रकार एवं विखरे हुए होते हैं कि उनका साक्षात्कार हेतु चयन करना, उनसे साक्षात्कार करना अत्यन्त कठिन हुआ।
- (6) वर्तमान युग अर्थ प्रधान है। इस विस्तृत क्षेत्र एवं व्यापार शोध हेतु अत्यधिक ससाधनों की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति करवाने के लिए पिता के ऊपर निर्भर है, जो पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर है। शोध कार्य के दौरान ही उनकी दोनों किडनी खराब हो गयी। उनका आपरेशन हुआ

जिससे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना परिवार को करना पड़ा जिसका प्रभाव शोधार्थी पर भी शोध प्रबन्ध तैयार करने में पड़ा। अतः उसे अत्यन्त सकट एवं विषम परिस्थितियों में अपना सर्वेक्षण पूरा करना पड़ा।

- (7) पूरा शोधकार्य अत्यन्त खर्चीला रहा क्योंकि विभिन्न सूचनादाताओं के पास सूचना एकत्रित करने के लिए जाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है। और यदि एक बार में काम हो गया तो ठीक अन्यथा एक ही जगह बार-बार जाने में काफी पैसे बर्बाद हुआ। पूरे इलाहाबाद जनपद में तो स्वयं अकेले ही विभिन्न थानों आदि में जा-जाकर कार्य किया है कई इलाके तो ऐसे थे जिसके बारे में ढग से जानकारी नहीं थी और वहाँ पर जाकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे—मालवीय नगर चौकी ढूढ़ने में (जो कि थाना मुट्ठीगज के ही बोर्ड लगाकर बनी है)। कानपुर क्षेत्र में कार्य करते समय तो कोई न कोई रिश्तेदार साथ ही रहा क्योंकि यहाँ के मुहल्लों की स्थिति के बारे में और आने-जाने में कौन-कौन से साधन कहाँ से कहाँ तक के लिए मिलेंगे मालूम नहीं था। शोधार्थी का ननिहाल कानपुर देहात होने के वजह से शुरू में तो रोज देहात से शहर में आते थे और उस पर महिला थाने की मिली महिला उपाधीक्षक का अनुसूची न भरना (अत्यन्त सदी के समय में जबकि लखनऊ जनपद में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान मापा गया) मनोबल को तोड़ने जैसा ही था। मोपेड की सवारी में एकाध बार दुर्घटना घटित हुई जिसके कारण शोध कार्य में विघ्न आया।

कुल मिलाकर हमारा अनुभव अनोखा रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि यह कार्य सम्पन्न हो पाया।

- 1 पी० वी० यग, साइन्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड सोशल रिसर्च ।
- 2 एफ० एन० कर्लीजर, फाउन्डेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च ।
- 3 उत्तर प्रदेश, 2002, सूचना एव जन सम्पर्क विभाग, उ० प्र० ।
- 4 उत्तर प्रदेश, 2002, सूचना एव जन सम्पर्क विभाग, उ० प्र० ।

अध्याय—३

उत्तरदाताओं का परिचय

(Introducing Respondents)

कोई भी सामाजिक शोध 'उत्तरदाता' जिन्हें सूचनादाता भी कहा जाता है, के बिना सम्पन्न करना असम्भव है। प्रत्येक उत्तरदाता की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और स्थिति अलग-अलग होती है, इस पृष्ठभूमि और स्थिति को ज्ञात करना शोध में इसीलिए आवश्यक माना जाता है। इससे सूचनादाताओं की विविधता का परिचय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सूचनादाताओं की पृष्ठभूमि का परिचय, उनकी समस्या के प्रति समझ तथा सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तरों के स्तर को जहाँ प्रकट करता है, वही वह उनसे सम्बन्ध स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होता है। अतः सूचनादाताओं का परिचय जो प्राप्त किया गया है, उनका विवरण प्रस्तुत किया है।

(1) आयु

आयु का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे-जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, उसके आचार-विचार, रहन-सहन एवं जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति उसकी मानसिकता परिपक्व होती जाती है।

मनुष्य होने के नाते पुलिस पर भी आयु का गहन प्रभाव पड़ता है। जहाँ पुलिसजन के युवा वर्ग में साहस, उत्साह, शारीरिक बल, कर्तव्यपरायणता एवं ईमानदारी पायी जाती है, वही आयु बढ़ने के साथ-साथ उसमें अनुभव, कौशल एवं कूटनीतिज्ञता की वृद्धि भी होती है। दूसरी ओर आयु वृद्धि का प्रभाव उनके शारीरिक बल, स्फूर्ति एवं चेतनता पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है, कि पुलिसजन की विभिन्न मानसिक प्रवृत्तियों एवं शारीरिक क्षमता पर आयु का प्रभाव परिलक्षित होता है।

जिस प्रकार पुलिसजन पर आयु का प्रभाव परिलक्षित होता है, उसी प्रकार सामान्यजन के दृष्टिकोण, अभिवृत्ति एवं समस्याओं के प्रति उनके चिन्तन आदि पर भी आयु के प्रभाव से अछूती नहीं रहता है। अतः महिला पुलिसकर्मी एवं सामान्यजन दोनों वर्गों के सूचनादाताओं की आयु सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जिनको निम्न सारणियों में दर्शाया गया है।

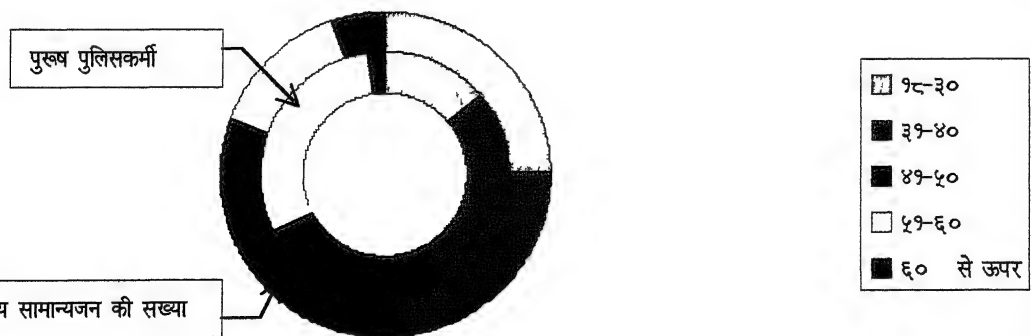
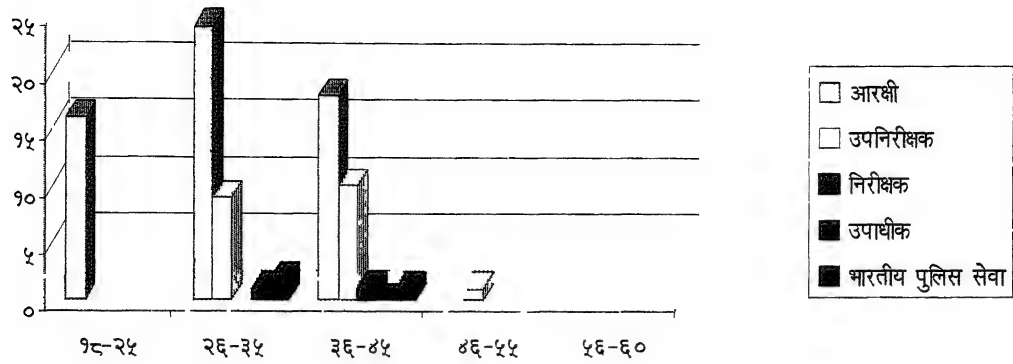
सारिणी संख्या-3.1

महिला पुलिस का वर्गीकरण (आयु के आधार पर)

क्रम	आयु	आरक्षी	उपनिरीक्षक	निरीक्षक	उपाधीक्षक	भारतीय पुलिस सेवा	योग	प्रतिशत
1	18-25	16	—	—	—	—	16	19.2
2	26-35	24	9	—	1	2	36	43.3
3	36-45	18	10	1	—	1	30	36.14
4	46-55	—	1	—	—	—	1	1.2
5	56-60	—	—	—	—	—	—	—
योग		58	20	1	1	3	83	100

पुलिस विभाग में भर्ती होने की आयु 18 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी गयी है, राजपत्रित पद के लिए विभाग में भर्ती की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सारिणी (संख्या 3.1) से स्पष्ट होता है कि 18-25 आयु वर्ग की 19.2 प्रतिशत, 26-35 आयु वर्ग की 43.3 प्रतिशत, 36-45 आयु वर्ग की 36.14 प्रतिशत तथा 46-55 आयु वर्ग की 1.2 प्रतिशत सूचनादाता प्रस्तुत शोध के आधार थे, तथा 56-60 आयु वर्ग में कोई भी सूचनादाता नहीं दी।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आरक्षी एवं भारतीय पुलिस सेवा में 26-35 वर्ष, आयु वर्ग में सर्वोच्च स्थान है। उपनिरीक्षक, निरीक्षक और उपाधीक्षक का सर्वाधिक प्रतिशत 36-45 वर्ष आयु वर्ग में सर्वोच्च स्थान रहा। 56-60 आयु वर्ग में



कोई भी सूचनादाता न होने का कारण है, कि महिलाओ की पुलिस मे भर्ती काफी देर से प्रारम्भ हुई।

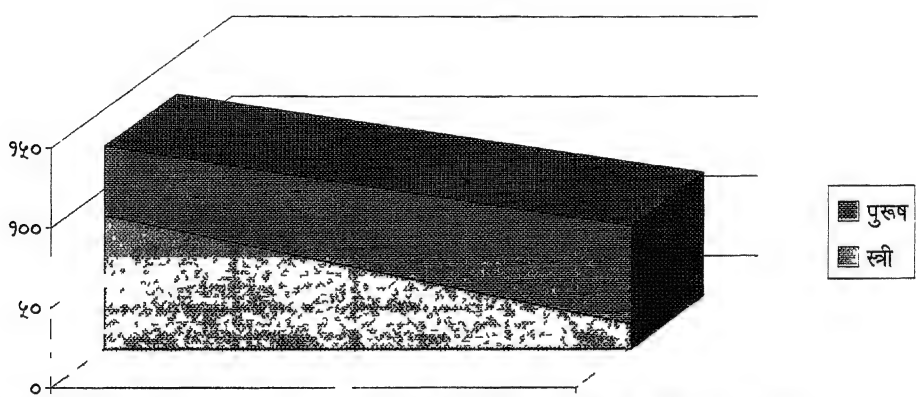
सारिणी संख्या-3.2

सामान्य सूचनादाताओं का आयु वर्गीकरण

क्रम	आयु वर्ग	सूचनादाताओं की संख्या		कुल सूचनादाताओ की	
		पुरुष पुलिसकर्मी	अन्य सामान्यजन की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	18-30	6	19	25	20 8
2	31-40	12	18	30	25 0
3	41-50	11	25	36	30 0
4	51-60	13	11	24	20 0
5	60 से ऊपर	1	4	5	4 1
योग		43	77	120	100

सामान्य जनसूचनादाताओ की आयु सारिणी से ज्ञात होता है कि सामान्य सूचनादाताओ मे 18-30 वर्ष आयु वर्ग के सूचनादाता 20 8 प्रतिशत, 31-40 वर्ष आयु वर्ग मे 25 प्रतिशत, 41-50 वर्ष आयु वर्ग मे 30 प्रतिशत, 51-60 वर्ष आयु वर्ग मे 20 प्रतिशत तथा 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के 4 1 प्रतिशत लोग थे। सामान्य जनसूचनादाताओ मे 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के उक्त सूचनादाताओ के चयन का कारण अधिक आयु वर्ग का प्रस्तुत शोध विषय के प्रति उनकी धारणा की जानकारी एव अनुभव का लाभ उठाना था

(2) लिंग



पुलिसकर्मियों का लिंग के आधार पर वर्गीकरण

सामान्य के सूचनादाताओं का लिंग के आधार पर वर्गीकरण

प्रस्तुत शोध महिला पुलिस कर्मियों पर होने के कारण शतप्रतिशत महिलाएं ही उत्तरदाता हैं, परन्तु इनका व्यक्तिगत अध्ययन हाने के कारण इनके सहकर्मी पुरुष पुलिसकर्मी भी उत्तरदाता हैं, साथ ही साथ समाज में विभिन्न कार्यक्षेत्रों से सम्बन्धित महिला को एव पुरुषों से भी जानकारी महिला पुलिस के सन्दर्भ में ली गयी है। अतः उत्तरदाताओं में महिला एव पुरुष दोनों ही शामिल हैं।

सारिणी संख्या-3.3

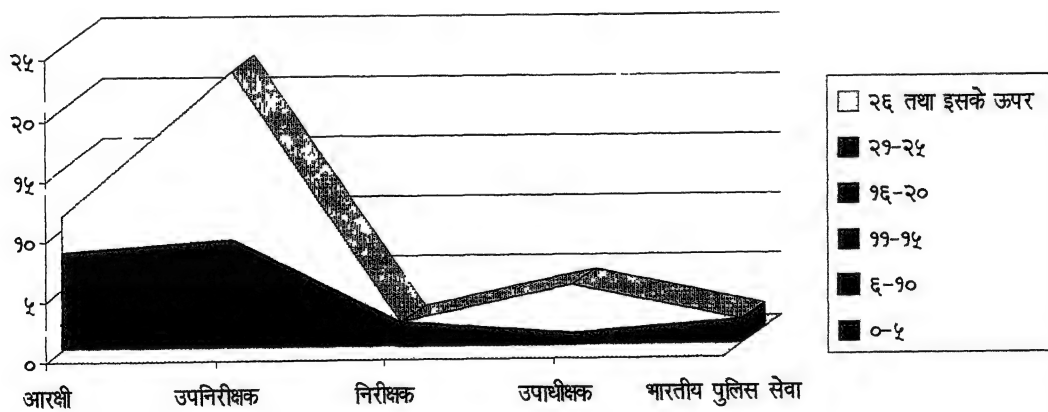
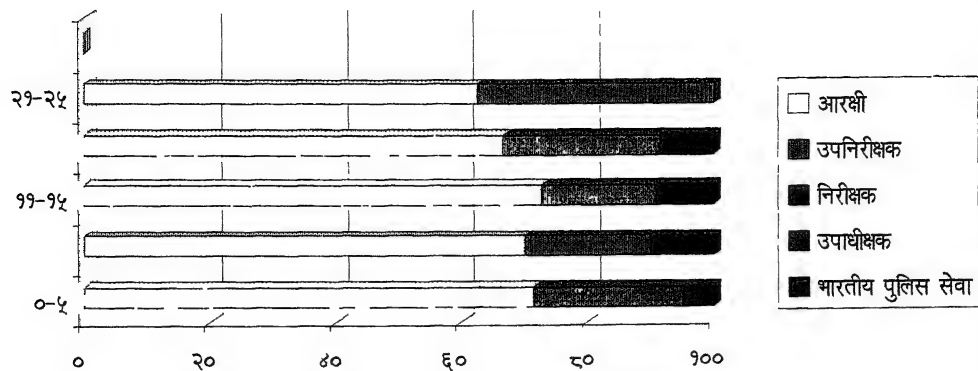
(1) सूचनादाताओं का लिंग के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	लिंग	पुलिसकर्मियों का लिंग के आधार पर वर्गीकरण		सामान्य के सूचनादाताओं का लिंग के आधार पर वर्गीकरण		कुल सूचनादाताओं का लिंग के आधार पर वर्गीकरण	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	कुल संख्या	कुल प्रतिशत
1	स्त्री	83	66	16	20.77	99	46
2	पुरुष	43	34	61	79.22	104	54
योग		126	100	77	100	203	100

पुलिस कर्मियों का लिंग के आधार पर वर्गीकरण में सारिणी (संख्या 3.3) से ज्ञात होता है कि 66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी सूचनादाता हैं, एव 34 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी सूचनादाता हैं।

सामान्यजन के सूचनादाताओं में 21 प्रतिशत महिला सूचनादाता हैं, और 79 प्रतिशत पुरुष सूचनादाता हैं।

कुल सूचनादाताओं में 46 प्रतिशत महिलाएं एव 54 प्रतिशत पुरुष सूचनादाता हैं।



(3) सेवाकाल

सारिणी संख्या-3.4

महिला पुलिस कर्मियों का सेवा अवधि के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	सेवाकाल (वर्ष)	पद						
		आरक्षी	उपनिरीक्षक	निरीक्षक	उपाधीक्षक	भारतीय पुलिस सेवा	कुल	प्रतिशत
1	0-5	30	10	—	1	1	42	50.6
2	6-10	7	2	—	—	1	10	12.0
3	11-15	8	2	—	—	1	11	13.25
4	16-20	8	3	1	—	—	12	14.45
5	21-25	5	3	—	—	—	8	9.6
6	26 तथा इसके ऊपर	—	—	—	—	—	—	—
योग		58	20	1	1	3	83	100

सारिणी (संख्या 34) से ज्ञात होता है कि 0-5 वर्ष की सेवा अवधि वाली 51 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हैं, 6-10 वर्ष की सेवा अवधि वाली 12 प्रतिशत महिलाएं हैं तथा 11-15 वर्ष की सेवा अवधि वाली 13 प्रतिशत महिलाएं हैं। 16-20 वर्ष की सेवा अवधि 14 प्रतिशत महिलाएं तथा 21-25 वर्ष की सेवा अवधि वाली 10 प्रतिशत महिलाएं हैं।

सर्वाधिक 51 प्रतिशत, 0-5 वर्ष की सेवा अवधि वाली महिलाओं की है तथा सबसे कम 10 प्रतिशत एव 21-25 वर्ष सेवा अवधि वाली महिलाएं हैं।

सारिणी संख्या-3.5

पुरुष पुलिसकर्मी का सेवा अवधि के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	सेवाकाल (वर्ष)	पद						
		आरक्षी	उपनिरीक्षक	निरीक्षक	उपाधीक्षक	भारतीय पुलिस सेवा	कुल	प्रतिशत
1	0-5	2	3	—	—	1	6	13.95
2	6-10	—	—	—	—	—	—	—
3	11-15	2	1	1	1	—	5	11.62
4	16-20	2	5	1	—	1	9	20.93
5	21-25	2	—	—	—	—	2	4.6
6	26 तथा इसके ऊपर	3	14	—	4	—	21	48.83
योग		11	23	2	5	2	43	100

सारिणी (सख्या 35) से ज्ञात होता है कि 0-5 वर्ष की सेवा अवधि वाले 14 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी हैं तथा 6-10 वर्ष की सेवा अवधि से कोई भी सूचनादाता नहीं है। 11-15 वर्ष की सेवा अवधि वाले 12 प्रतिशत लोग हैं। 16-20 वर्ष की सेवा अवधि वाले 21 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी हैं। 21-25 वर्ष की सेवा अवधि वाले 5 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी हैं। 26 वर्ष तथा उसके ऊपर की सेवा अवधि वाले 49 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी हैं।

सर्वाधिक 49 प्रतिशत 26 वर्ष या इससे ऊपर वाली सेवा अवधि के पुरुष पुलिसकर्मी हैं, जबकि सबसे कम 5 प्रतिशत, 21-25 वर्ष की सेवा अवधि वाले पुरुष पुलिसकर्मी हैं। 6-10 वर्ष सेवा अवधि वाले कोई भी सूचनादाता नहीं है।

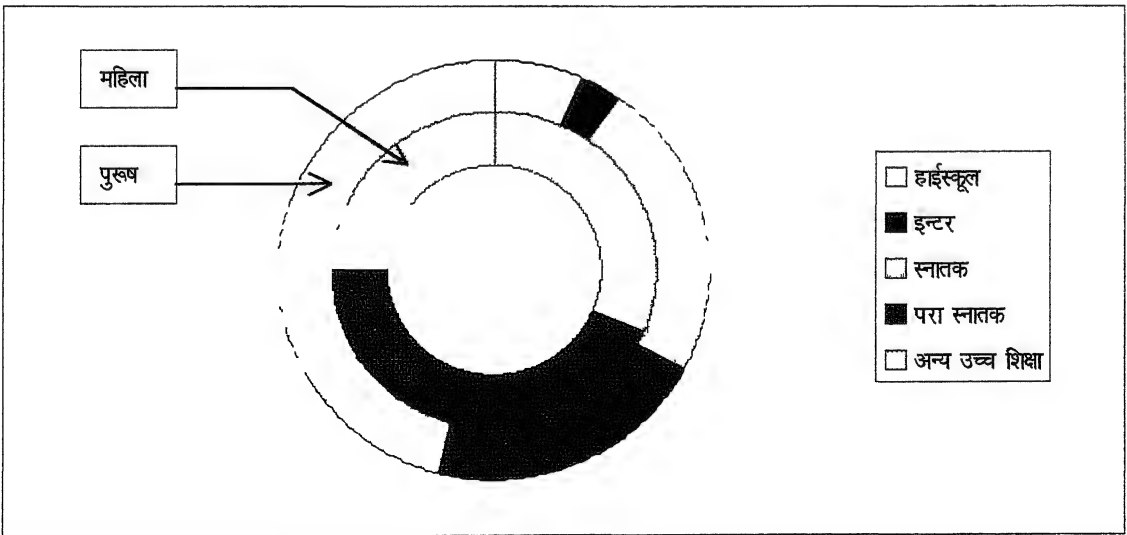
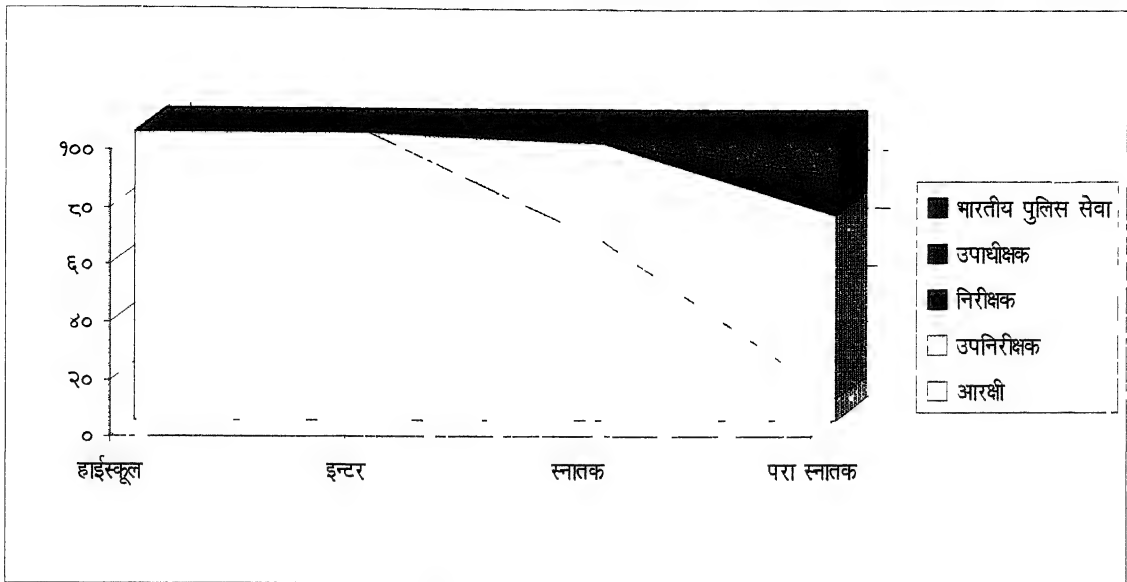
(4) शिक्षा

शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य का जीवन नियंत्रित, नियमित एवं अत्यधिक प्रभावित होता है। वह शिक्षा ही है जो मनुष्य को पशु वर्ग से अलग कर मानव बनाने में सहायक है। शिक्षा का स्तर उसके आचार-विचार, समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण, सूक्ष्मता और गहनता को तीव्र करता है। साथ ही मानसिकता का निर्माण करता है, महिला पुलिस कर्मियों एवं सामान्यजन दोनों वर्गों के लोगों से उनकी शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी जो इस प्रकार है—

सारिणी संख्या-3.6

महिला पुलिसकर्मियों का शैक्षणिक विवरण

क्रम	शिक्षा	आरक्षी		उपनिरीक्षक		निरीक्षक		उपाधीक्षक		भारतीय पुलिस सेवा		कुल	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हाईस्कूल	4	6.89	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.8
2	इन्टर	27	46.55	—	—	—	—	—	—	—	—	27	32.53
3	स्नातक	20	34.48	11	55	—	—	—	—	1	33	32	38.55
4	परा स्नातक	1	12.06	9	45	1	100	1	100	2	67	20	24.00
योग		58	100	20	100	1	100	1	100	3	100	83	100



सारिणी (संख्या 36) से ज्ञात होता है कि 7 प्रतिशत महिला आरक्षी हाईस्कूल पास है। 47 प्रतिशत इन्टर तथा 34 प्रतिशत स्नातक है। 12 प्रतिशत परास्नातक है, अर्थात् सर्वाधिक 47 प्रतिशत महिला आरक्षी इन्टर पास है तथा सबसे कम 7 प्रतिशत हाईस्कूल।

55 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक स्नातक है, तथा 45 प्रतिशत स्नातक है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक परास्नातक है। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक भी परास्नातक है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी स्नातक तथा 67 प्रतिशत परास्नातक है।

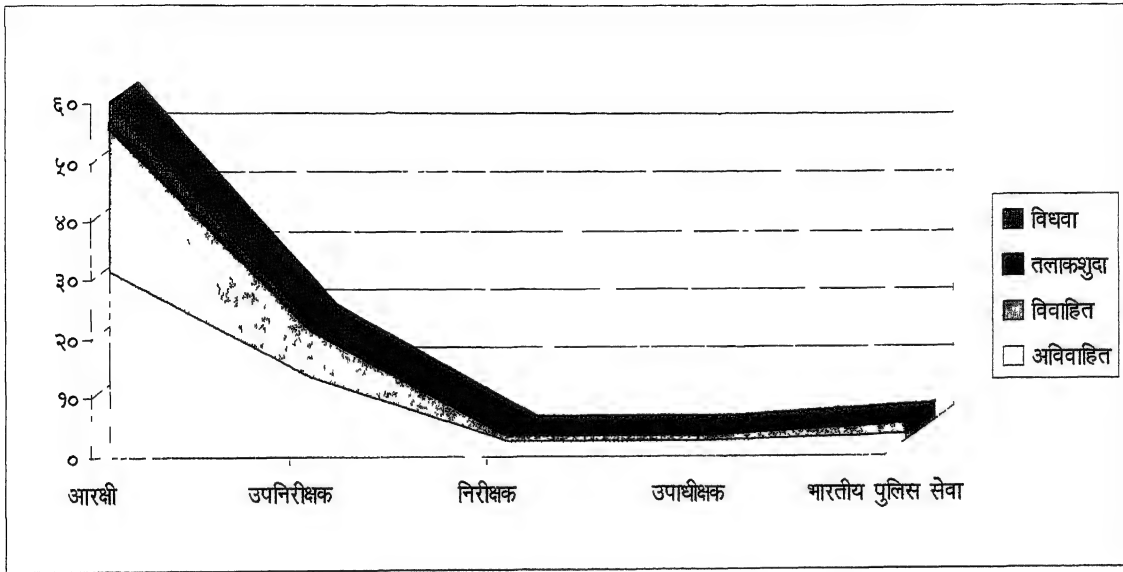
कुल प्रतिशत देखे तो 5 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हाईस्कूल, 33 प्रतिशत इन्टर एवं 39 प्रतिशत स्नातक तथा 24 प्रतिशत परास्नातक है।

सारिणी संख्या-3.7

सामान्य सूचनादाता का शैक्षणिक विवरण

क्रम	कक्षा	सामान्य सूचनादाताओं की संख्या				कुल योग	
		महिला		पुरुष			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हाईस्कूल	—	—	4	6.5	4	5.19
2	इन्टर	—	—	2	3.2	2	2.59
3	स्नातक	5	31.25	14	22.9	19	24.67
4	परा स्नातक	7	43.75	13	21.3	20	25.97
5	अन्य उच्च शिक्षा	4	25	28	45.9	32	41.55
योग		16	100	61	100	77	100

सारिणी (संख्या 37) से ज्ञात होता है कि सामान्य सूचनादाताओं के महिलाओं का शैक्षणिक विवरण में हाईस्कूल और इन्टर का प्रतिशत शून्य है, तथा 31 प्रतिशत स्नातक, 44 प्रतिशत परास्नातक तथा 25 प्रतिशत उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएँ हैं।



महिला पुलिस की वैवाहिक स्थिति

क्रम	पद	अविवाहित		विवाहित		तलाकशुदा		विधवा		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	29	50	24	41.37	1	1.72	4	6.89	58	69.87
2	उपनिरीक्षक	11	55	8	40	—	—	1	5	20	24.09
3	निरीक्षक	—	—	1	100	—	—	—	—	1	1.20
4	उपाधीक्षक	—	—	1	100	—	—	—	—	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33	2	67	—	—	—	—	3	3.61
योग		41	49.39	36	43.37	1	1.20	5	6.02	83	100

सारिणी (संख्या 3.8) से ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत महिला आरक्षी अविवाहित हैं, 41 प्रतिशत विवाहित, 2 प्रतिशत तलाकशुदा और 7 प्रतिशत विधवा हैं।

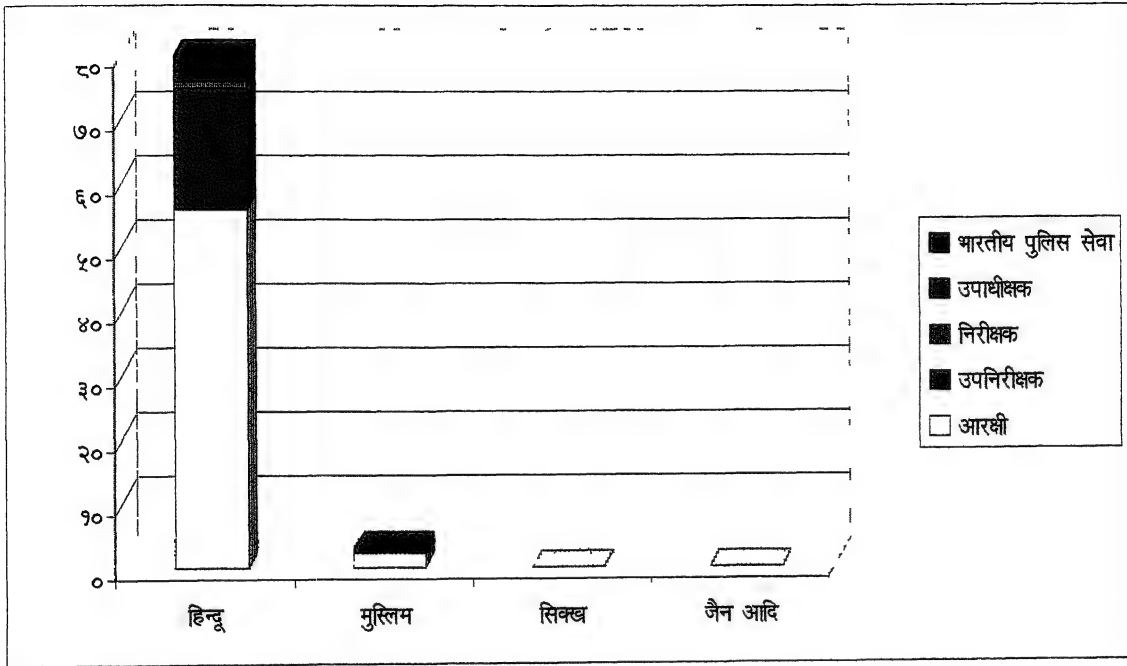
55 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक अविवाहित, 40 प्रतिशत विवाहित तथा 5 प्रतिशत विधवा हैं।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक तथा 100 प्रतिशत उपाधीक्षक विवाहित हैं।

33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अविवाहित तथा 67 महिलाएं विवाहित हैं।

कुल महिला पुलिस कर्मियों की वैवाहिक स्थिति देखे तो 49 प्रतिशत अविवाहित 43 प्रतिशत विवाहित तथा 1 प्रतिशत तलाकशुदा और 6 प्रतिशत विधवा हैं।

महिला आरक्षी और उपनिरीक्षक में अविवाहित का प्रतिशत सर्वाधिक क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 55 प्रतिशत है जो आधा और आधे से अधिक है।



(6) धर्म

धर्म एक तरफ मनुष्य के बाहरी आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करता है तो दूसरी ओर उसके आन्तरिक विचारों को उद्बलित कर उसमें दृढता एवं कट्टरता आदि भावों का समावेश करता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि प्रायः सभी धर्मावलम्बी निवास कर रहे हैं। यद्यपि भारत में संविधान में धर्मनिरपेक्षता की भावना को स्वीकारा गया है, परन्तु प्रदेश में समय-समय पर होने वाले साम्प्रदायिक दंगों ने संविधान की धर्मनिरपेक्षता को भावना को चोट पहुँचाई है। पुलिसजन का धर्म विशेष इस अवसर पर सदेह की परिधि में आ जाता है। अतः महिला पुलिस कर्मियों के साथ-साथ सामान्यजन जो विभिन्न व्यवसायिक वर्गों से जुड़े हैं, उनके धर्म के सम्बन्ध में प्रश्न किया है।

सारिणी संख्या-3.9

महिला पुलिस कर्मियों का धार्मिक आधार पर वर्गीकरण

क्रम	पद का नाम	हिन्दू		मुस्लिम		सिक्ख		जैन आदि		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	56	96.5	2	3.4	—	—	—	—	58	99.9
2	उपनिरीक्षक	19	95	1	5	—	—	—	—	20	99.5
3	निरीक्षक	1	100	—	—	—	—	—	—	1	100
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	—	—	—	—	1	100
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	—	—	—	—	—	—	3	100
योग		80	96.38	3	3.6	—	—	—	—	83	100

सारिणी (संख्या 3.9) से पता चलता है कि 97 प्रतिशत महिला आरक्षी हिन्दू एवं 3 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं।

95 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक हिन्दू एव 5 प्रतिशत मुस्लिम हैं। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक हिन्दू एव 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक हिन्दू हैं। 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिलाएं हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं।

सारिणी संख्या-3.10

पुरुष पुलिसकर्मी एवं सामान्यजन का धार्मिक आधार पर वर्गीकरण

क्रम	धर्म	पुरुष पुलिसकर्मी		सामान्य उत्तरदाताओं की संख्या		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	41	95.3	73	94.80	114	95
2	मुस्लिम	2	4.6	4	5.10	6	5
3	अन्य	—	—	—	—	—	—
योग		43	35.8	77	64.16	120	100

पुरुष पुलिसकर्मी और सामान्य सूचनादाता का धार्मिक आधार पर वर्गीकरण सारिणी (संख्या 3.10) से ज्ञात होता है, कि 95 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं एव 5 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं।

सामान्यजन जो विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, उसमें भी 95 प्रतिशत हिन्दू धर्म एव 5 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं।

कुल प्रतिशत देखे तो 95 प्रतिशत हिन्दू धर्म एव 5 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं।

(7) जाति

धर्म की भाँति समाज एव उसके सदस्यों के जीवन पर जाति का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय समाज अतीत में वर्गों में विभक्त किया गया था, जो कालान्तर में अनेक जातियों एव उपजातियों में विभाजित होता चला गया। इसमें अछूत एव पिछड़ी जाति को जन्म दिया जिसका प्रभुता सम्पन्न एव तथाकथित उच्च

जाति ने शोषण किया। स्वतन्त्र भारत में इन्हीं अछूत एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण हेतु भारतीय संविधान में व्यवस्था की गयी तथा वर्तमान समय में अनेक कारकों के परिणामस्वरूप जातीयता की वृद्धि हुई जिससे रूढ़िग्रस्तता, जाति, वैमनस्यता एवं जातीय संघर्षों में वृद्धि हुई।

जातीय सुधारों एवं विशेष व्यवस्थाओं से पुलिस विभाग भी अछूता नहीं है। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नीतियों के अनुसार पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजातियों के व्यक्तियों को आरक्षण सुविधा एवं अन्य प्रकार का लाभ पुलिस विभाग में भर्ती एवं प्रोन्नति आदि प्रदान कर दिया जाता रहा है।

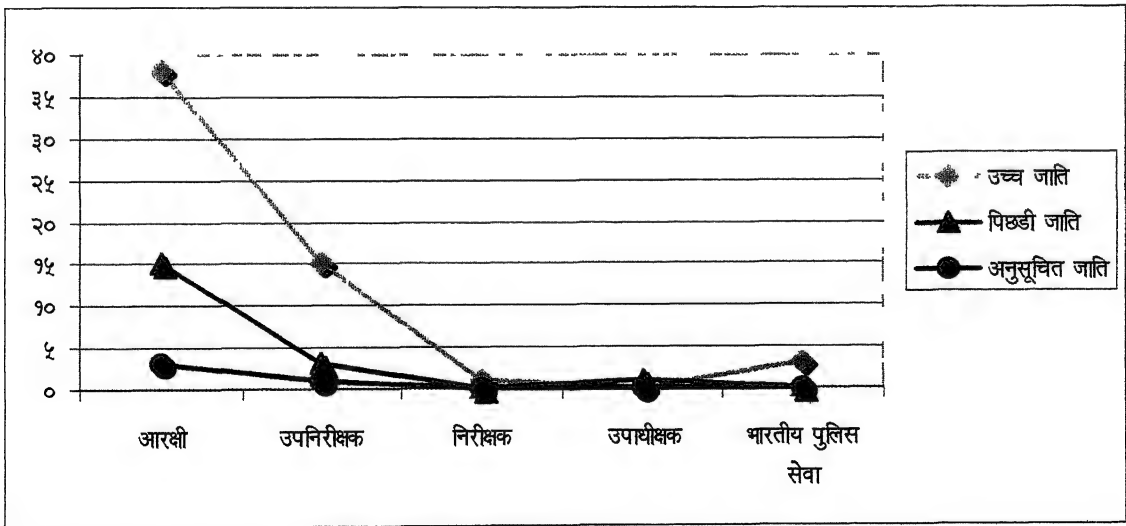
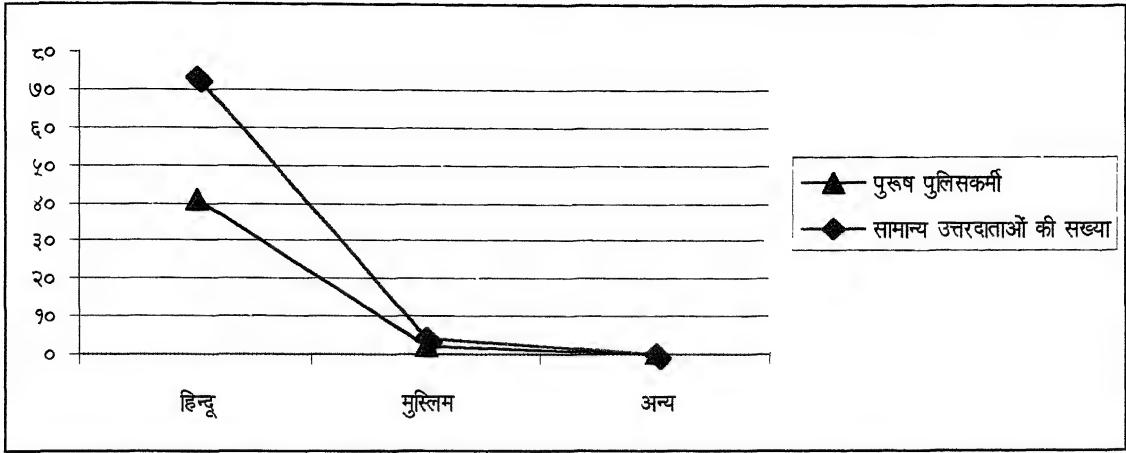
सारिणी संख्या-3.11

महिला पुलिस की सामाजिक कोटियाँ

क्रम	पदनाम	उच्च जाति		पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	39	67.24	15	25.86	4	6.89	58	69.87
2	उपनिरीक्षक	15	75	4	20	1	5	20	24.09
3	निरीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	1.20
4	उपाधीक्षक	—	—	1	100	—	—	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	—	—	—	—	3	3.61
योग		58	69.87	20	24.09	5	6.02	83	100

महिला पुलिस कर्मियों में जातिगत विवरण या सामाजिक कोटि के आधार पर सारिणी (संख्या 3.11) देखें तो पता चलता है कि 67 प्रतिशत महिला आरक्षी उच्च जाति एवं 26 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 7 प्रतिशत अनुसूचित जाति की हैं।

75 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक उच्च जाति, 20 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति की हैं। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक उच्च जाति की हैं। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक पिछड़ी जाति की तथा 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी उच्च जाति से सम्बन्धित हैं।



कुल प्रतिशत देखे तो 70 प्रतिशत मलिला पुलिसकर्मी उच्च जाति, 24 प्रतिशत पिछड़ी जाति एव 6 प्रतिशत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है। यानि सर्वाधिक प्रतिशत उच्च जाति का है।

सारिणी संख्या-3.12

पुरुष पुलिसकर्मी एवं सामान्यजन का जातिगत विवरण

क्रम	सामाजिक कोटि	पुरुष पुलिसकर्मी		सामान्य उत्तरदाताओं की संख्या		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	उच्च जाति	30	69.76	65	84.41	95	79.16
2	पिछड़ी जाति	12	27.60	9	11.68	21	17.5
3	अनुसूचित जाति	1	2.32	3	3.69	4	3.33
योग		43	100	77	100	120	100

पुरुष पुलिसकर्मी एवं सामान्यजन का जातिगत विवरण या सामाजिक कोटि के आधार पर विवरण सारिणी (संख्या 3.12) में निम्न प्रकार से है कि 70 प्रतिशत पुलिसकर्मी उच्च जाति, 28 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 2 प्रतिशत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है।

सामान्यजन जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, का सामाजिक कोटि के आधार पर विवरण इस प्रकार से है कि उच्च जाति के सामान्य सूचनादाता 84 प्रतिशत हैं, 12 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं।

कुल प्रतिशत देखे तो पुरुष पुलिस कर्मियों और सामान्य सूचनादाता के 79 प्रतिशत उच्च जाति, 18 प्रतिशत जाति एवं 3 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं।

पुरुष पुलिसकर्मी, सामान्य सूचनादाता एवं महिला पुलिसकर्मी तीनों ही वर्गों में उच्च जाति के लोग सर्वाधिक प्रतिशत क्रमशः 70, 84, 71 हैं।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली, कार्य पद्धति एवं मानसिकता में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है, अतः महिला पुलिस उत्तरदाताओं को उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने की दृष्टि से विभाजित करने का प्रयास किया गया है। जो इस प्रकार से है।

सारिणी संख्या-3.13

महिला पुलिस कर्मियों का मूल निवास स्थान

क्रम	पद नाम	जिलों का नाम
1	आरक्षी	वाराणसी (2), हरदोई (1), इटावा (2), मऊ (1), पिथौरागढ़ (1) कानपुर (5), झाँसी (2), सुल्तानपुर (1), फैजाबाद (9), बौदा (1) लखनऊ (1), गोरखपुर (2), देहरादून (1), रायबरेली (3), हमीरपुर (2), मैनपुरी (2), उन्नाव (5), प्रतापगढ़ (2), जालौन (1), अल्मोड़ा (3), इलाहाबाद (3), फतेहपुर (1), कन्नौज (2), जौनपुर (2), बस्ती (1)।
2	उपनिरीक्षक	आगरा (2), देवरिया (1), कलकत्ता (1), पिथौरागढ़ (1), कानपुर (3), सुल्तानपुर (1), फैजाबाद (1), बौदा (1), लखनऊ (1), मथुरा (1), गोरखपुर (1), अलीगढ़ (1), हमीरपुर (1), सीतापुर (1), मैनपुरी (1), उन्नाव (1), अल्मोड़ा (1)।
3	निरीक्षक	कानपुर (1)।
4	उपाधीक्षक	जौनपुर (1)।
5	भारतीय पुलिस सेवा	मुम्बई (1), हैदराबाद (1), शिमला (1)।

(कोष्ठक में संख्या दर्शायी गयी है।)

अध्याय—४

महिला पुलिस की भूमिका और प्रास्थिति

(Role and Status of Female Police)

प्रस्थिति के साथ ही भूमिका की अवधारणा जुड़ी हुई है। प्रस्थिति को भूमिका से अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी प्रस्थिति स्वतंत्र रूप से नहीं होती बल्कि भूमिका के ताने-बाने से गुँथी हुई रहती है। हम बिना भूमिका के किसी प्रस्थिति की कल्पना नहीं कर सकते तथा बिना प्रस्थिति के किसी भूमिका का विचार भी नहीं कर सकते। व्यक्ति अपनी प्रस्थिति के अनुरूप कार्य करता है, तब ही समाज व्यवस्थित रह पाता है। समाज में सगठन एक प्रमुख कारण भूमिका है।

लिटन¹ के अनुसार कोई भी भूमिका प्रस्थिति की गत्यात्मक पक्ष है तथा डेविस के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। हम प्रत्येक व्यक्ति से एक विशिष्ट प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करते हैं तथा उसके अनुसार व्यक्ति भूमिका ग्रहण करता है। भूमिका ग्रहण के बीच सन्तुलन ही समाज के सगठन का आधार है, इन दोनों के बीच खाई होने का अर्थ है समाज में अव्यवस्था। भूमिका का सम्बोध अन्ततः सामाजिक विभेदीकरण एवं सामाजिक मानदण्डन के प्रत्युत्तर एवं प्रभाव से उत्पन्न हुआ है।

भूमिका के सन्दर्भ में पाँच निम्न सम्प्रत्यय हैं—

- (1) **भूमिका पालन (Role Playing):** जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका समाज द्वारा अपेक्षित प्रतिमानों के आधार पर निभाता है, तो उसे भूमिका पालन कहा जाता है।
- (2) **भूमिका वरण (Role Taking):** इसमें हम विशिष्ट भूमिकाओं को सीखते हैं।
- (3) **अभिनय की भूमिका (Playing at Role):** इसके अन्तर्गत व्यक्ति अभिनय के माध्यम से किसी अन्य पात्र की भूमिका निभाता है।

(4) **भूमिका बाधा (Role Handicap):** इसमें उन तत्वों का उल्लेख करते हैं, जो कि किसी भूमिका को सम्पन्न करने में व्यवधान डालते हैं। हर भूमिका के साथ भौतिक एवं सस्थागत सुविधाओं का होना आवश्यक है। जैसे—एक प्रशासन को अपनी भूमिका निभाने में कई प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं, अगर वे आवश्यकताएँ जो कि उसके कार्य निर्वह में उपयुक्त व प्रकार्यात्मक हैं तब तो वह अपनी भूमिका सुचारू रूप से कर पाएगा और अगर उसे अपनी भूमिका से सम्बन्धित सुविधाएँ ठीक से उपलब्ध न हों तो वह अपने कार्य को भलि-भाँति नहीं कर सकेगा।

(5) **भूमिका वचन (Role Dispossession):** व्यक्ति की प्रस्थिति समयानुसार परिवर्तित होती रहती है इसके लिए उसे अपनी पोशाक, व्यवहार, रीति इत्यादि इस तरह से परिवर्तित करना पड़ता है, कि वह अपनी भूमिका निर्वह में उस भूमिका के अनुरूप व्यवहार कर सके।

व्यक्ति जब एक भूमिका को पूर्णरूप से विसर्जित करके दूसरी भूमिका ग्रहण करता है उस बीच की स्थिति को भूमिका सक्रमण (Role Transition) की स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में भूमिका तनाव (Role Strain) की सम्भावनाएँ रहती हैं, क्योंकि यह भूमिका सीखने की स्थिति है। कभी-कभी ऐसी अवसर भी आ जाते हैं जबकि दो भिन्न-भिन्न परिस्थितियों की भूमिका निभानी हो और उसे मानसिक अन्तर्द्वन्द्व का अनुभव होने लगे तो उसे भूमिका संघर्ष (Role Conflict) कहेंगे। ऐसी स्थिति में तनाव उत्पन्न होता है, तब हम एक या दो भूमिकाओं को छोड़ देते हैं।

मर्टन ने प्रस्थिति एवं भूमिका की श्रृंखला को निम्नलिखित तीन सम्बोधों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है²—

- (1) **भूमिका प्रतिमान (Role Set)**
- (2) **प्रस्थिति प्रतिमान (Status Set)**
- (3) **प्रस्थिति श्रृंखला (Status Sequence)**

(1) भूमिका प्रतिमान (Role Set)

भूमिका प्रतिमान तब कहते हैं, जब किसी व्यक्ति की एक ही प्रस्थिति द्वारा वह भिन्न-भिन्न लोगों के सदस्य में अलग-अलग भूमिकाएँ निभाता है अर्थात् एक प्रस्थिति से सम्बद्ध कार्यों के प्रतिमान को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं।

(2) प्रस्थिति प्रतिमान (Status Set)

व्यक्ति के जीवन में एक ही प्रस्थिति नहीं होती, बल्कि अनेक प्रस्थितियाँ होती हैं तथा उन प्रस्थितियों के अनुसार भूमिकाएँ भी होती हैं तब एक व्यक्ति की विभिन्न सस्थाओं में अलग-अलग प्रस्थिति हो तो उसे प्रस्थिति प्रतिमान कहते हैं। ये एक व्यक्ति के विभिन्न सस्थाओं (परिवार, विवाह, दफ्तर, मित्र मण्डली आदि) में विभिन्न प्रस्थितियों का सकलन है।

(3) प्रस्थिति श्रृंखला (Status Sequence)

प्रस्थिति श्रृंखला एक व्यक्ति की अलग-अलग समय में अलग-अलग प्रस्थितियों का प्रतीक है। जब एक ही व्यक्ति की प्रस्थितियाँ बदलती हैं तो इसे प्रस्थिति श्रृंखला कहते हैं।

यदि ऐसा अवसर आ जाए जबकि दो भिन्न प्रस्थितियों की भूमिका निभानी हो और उससे मानसिक अन्तर्द्वन्द्व का अनुभव होने लगे तो उसे भूमिका संघर्ष (Role Conflict) कहेंगे। कभी-कभी भूमिका संकट (Role Crisis) उत्पन्न हो जाता है जिसका कारण है, हमारी दूसरे व्यक्ति से तथा दूसरे व्यक्ति की हमसे अपेक्षाएँ हैं।

सर्वप्रथम हाइमैन³ ने 1942 में संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किया था। शेरिफ और शेरिफ⁴ के अनुसार संदर्भ समूह वह है जिसके साथ व्यक्ति अपने को एक अंग के रूप में सम्बन्धित करता है अथवा जिसके साथ वह मनोवैज्ञानिक रूप से सम्बन्धित होने की आकांक्षा करता है। न्यूकॉम के अनुसार सन्दर्भ समूह सामान्यतः एक समूह के लिए प्रयोग होता है, किन्तु ये व्यक्ति भी हो सकते हैं। इनके अनुसार सन्दर्भ

समूह वह है जिसे व्यक्ति तुलना के लिए प्रयोग करता है अर्थात् जिससे व्यक्ति अपने मूल्यों को प्राप्त करता है।

हेरी एम० जानसन की सन्दर्भ समूह⁵ की अवधारणा इस तथ्य से उत्पन्न होती है, कि किसी समूह का सदस्य सिर्फ अपने समूह (जिसका वह सदस्य है) के आदर्शों और मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनके आदर्शों और मूल्यों से भी प्रभावित होता है, जिनके वे सदस्य नहीं है किन्तु वह उसकी आकाक्षा करता है।

- 1 प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है, कि वह अपने को ऐसे समूह का सदस्य बनाये जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो। जिसके द्वारा उसकी महत्वाकाक्षाओं, एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हो। सन्दर्भ समूह की उत्पत्ति व्यक्ति की इन्हीं महत्वाकाक्षाओं का परिणाम है, अर्थात् सन्दर्भ समूह का सम्बन्ध अपेक्ष वचन (महत्वाकाक्षा) से है।
- 2 अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग सदर्थ समूह हो सकते हैं, और अनेक व्यक्तियों के लिए केवल एक सदर्थ समूह भी हो सकता है।
- 3 सदर्थ समूह की आवश्यकता व्यक्तियों के अपनी महत्वाकाक्षाओं के कारण होती है।
- 4 व्यक्ति स्थिति, समय, स्थान आदि से सम्बन्धित एक सापेक्ष समूह है। इस प्रकार के समूहों के आधार पर हम कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं।
- 5 व्यक्ति का सदस्यता समूह ही कभी-कभी सदर्थ समूह बन जाता है। जब समूह और उसके सदस्यों के बीच अन्त सम्बन्ध बहुत गहरा होता है, तब व्यक्ति का सदस्य समूह ही उसके लिए आदर्श बन जाता है।
- 6 व्यक्ति के लिए सदर्थ समूह आदर्श होता है, और उसे आदर्श, आचरण के प्रभाव के रूप में स्वीकार करता है, किन्तु ये जरूरी नहीं है कि वह समूह, समाज की दृष्टि से भी आदर्श समूह ही हो।

न्यूकॉम ने दो प्रकार के सदर्थ समूह की चर्चा की है —

(1) सकारात्मक संदर्भ समूह

यह वह समूह है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे समूह के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाना चाहता है, तथा जिसके साथ वह मनोवैज्ञानिक रूप से सम्बन्धित होने की आकाक्षा करता है।

(2) नकारात्मक संदर्भ समूह

यह वह समूह है जिसका व्यक्ति विरोध करता है और उससे सम्बन्ध नहीं रखना चाहता है।

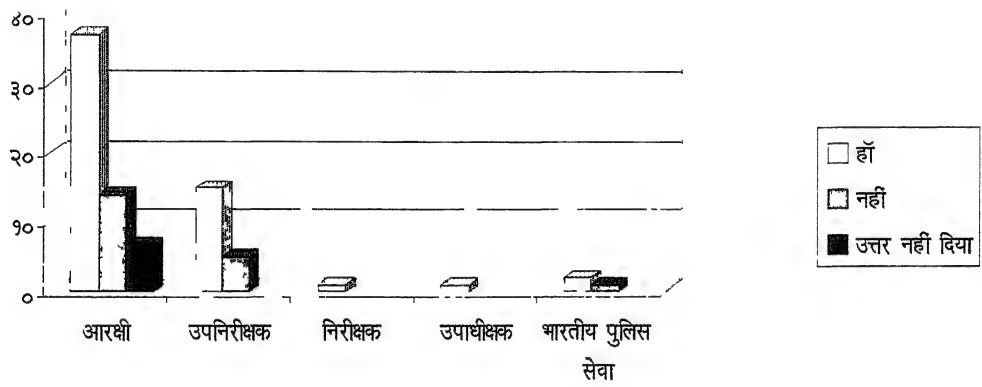
न्यूकॉम के अनुसार एक व्यक्ति का सदर्थ समूह उसका सदस्यता समूह भी हो सकता है।

जब किसी समूह का सदस्य दूसरे समूह के किसी एक व्यक्ति से प्रभावित होकर उस समूह के नियमों, आदर्शों, मूल्यों आदि का अनुसरण करना आरम्भ कर देता है, तो दूसरे समूह का व्यक्ति उसके लिए सदर्थ व्यक्ति कहलायेगा।

आर० के० मर्टन के अनुसार ये जानना भी आवश्यक है, कि किस प्रकार सदर्थ समूह समाज के लिए प्रकार्यात्मक और अप्रकार्यात्मक कार्य करता है। इनके अनुसार व्यक्ति की दूसरे समूह की सदस्यता की आकाक्षा के दो परिणाम हो सकते हैं।

पहला या तो वह व्यक्ति अपने इच्छित समूह में सम्मिलित कर लिया जायेगा अथवा दूसरा उसे इच्छित समूह की सदस्यता न मिले।

जब व्यक्ति दूसरे समूह में सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता है जिसका कि वह सदस्य बनना चाहता है, तब उसका प्रकार्यात्मक परिणाम होता है किन्तु इसके विपरीत वह दूसरे समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता या उसे उस समूह की सदस्यता नहीं मिलती जिसका कि वह सदस्य बनना चाहता है तब उसका अप्रकार्यात्मक परिणाम होता है, जिसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है।



मर्टन के अनुसार व्यक्ति का सदर्थ समूह या उसका अन्त समूह या सदस्यता समूह भी हो सकता है, और उसका वाह्य समूह या असदस्यता समूह भी हो सकता है।

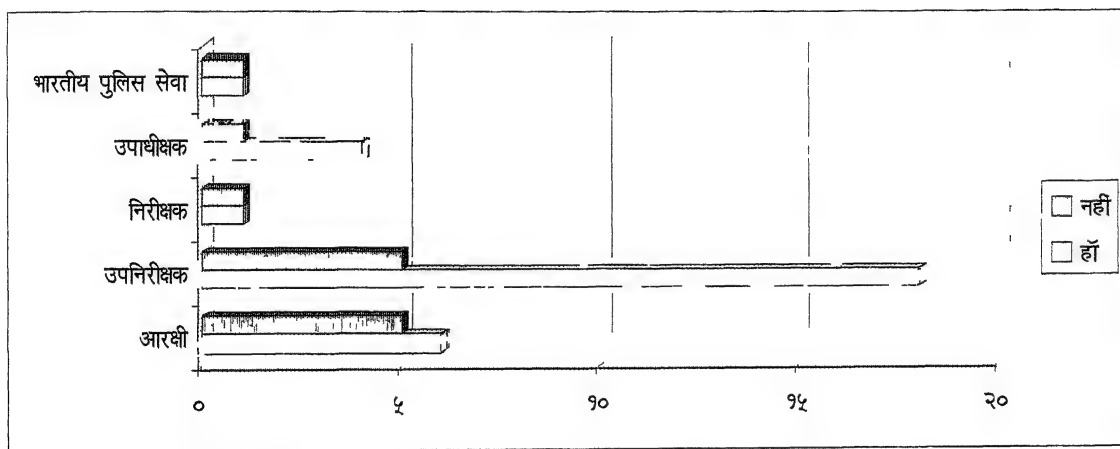
महिला पुलिस कर्मियों में भूमिका पालन (Role Playing) की अवधारणा को उनके स्वयं के अनुसार और साथ के कार्य करने वाले पुरुष पुलिस कर्मियों और समाज के अन्य व्यक्तियों के अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं।

सारिणी संख्या-4.1

महिला पुलिस कर्मियों की स्वयं की “भूमिका पालन” के बारे में मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	37	63.79	14	24.13	7	12.06	58	69.87
2	उपनिरीक्षक	15	75	5	25	—	—	20	24.09
3	निरीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	1.20
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	2	67	1	33	—	—	3	3.61
योग		56	67.46	21	25.30	7	8.49	83	100

सारिणी (संख्या 4.1) से स्पष्ट है कि 64 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने कहा है कि उनके कार्य को सराहा गया जबकि 24 प्रतिशत ने नकारात्मक उत्तर दिया एवं 12 प्रतिशत ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। 75 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने कहा उनके समूह में उनके कार्य को सराहा गया है। 25 प्रतिशत ने नहीं उत्तर दिया। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक का उत्तर सकारात्मक एवं 100 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक का उत्तर भी सकारात्मक है। 67 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों ने हाँ तथा 33 प्रतिशत ने नहीं उत्तर दिया है।



महिला पुलिस कर्मियों का मत है कि उनके कार्यों को सराहा गया है। इस सारिणी से ज्ञात होती है कि सकारात्मक यदि (उनके कार्यों को सराहा गया है) का प्रतिशत, नकारात्मक की अपेक्षा सभी पदों में अधिक है।

सारिणी संख्या-4.2

पुरुष पुलिस कर्मियों का महिला पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के बारे में विचार

क्रम	पद	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	6	54.54	5	45.45	11	25.58
2	उपनिरीक्षक	18	78.26	5	21.73	23	53.48
3	निरीक्षक	1	50.00	1	50.00	2	4.65
4	उपाधीक्षक	4	80.00	1	20.00	5	11.62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50.00	1	50.00	2	4.65
योग		30	70.00	13	30.00	43	100

पुरुष पुलिस कर्मियों से महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के बारे में विचार जानने के लिए उनसे प्रश्न किया तो निम्न मत सामने आये हैं, जो सारिणी (संख्या 4.2) से स्पष्ट है।

70 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों का मानना है कि महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ढग से निभाती है। 30 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों का मानना है, कि वे अपनी ड्यूटी ढग से नहीं निभाती हैं।

पुरुष निरीक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा के आधे लोगों का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी ठीक से करती हैं, आधे लोग कहते हैं कि ड्यूटी ठीक से नहीं करती। सभी पदों के (निरीक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर) लोगों ने महिलाओं की ड्यूटी के सम्बन्ध में सकारात्मक उत्तर का प्रतिशत, नकारात्मक की अपेक्षा अधिक है।

54 54 पुरुष आरक्षियों का महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के बारे में सकारात्मक एवं 45 45 प्रतिशत नकारात्मक मत है। 78 26 प्रतिशत उपनिरीक्षकों का उत्तर सकारात्मक एवं 21 73 का नकारात्मक मत है। 80 प्रतिशत उपाधीक्षकों का उत्तर सकारात्मक एवं 20 प्रतिशत नकारात्मक मत है। निरीक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा का उत्तर 50 प्रतिशत सकारात्मक तथा 50 प्रतिशत नकारात्मक मत है।

किसी मामले को निपटाने में पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा महिला पुलिस कर्मियों का रवैया कैसा रहता है, जब सामान्य सूचनादाताओं से पूछा गया तो निम्न तथ्य सामने आये हैं जो सारिणी से स्पष्ट हैं—

सारिणी संख्या-4.3

किसी मामले को निपटाने में महिला पुलिस कर्मियों के प्रति सामान्य सूचनादाताओं (विभिन्न क्षेत्र से सम्बन्धित स्त्री/पुरुष) का दृष्टिकोण

क्रम	दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
1	पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहता है।	46	60
2	पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा खराब रहता है।	6	8
3	दोनों का रवैया एक जैसा रहता है।	8	10
4	व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर है।	3	4
5	उत्तरदाताओं को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।	14	18
	योग	77	100

सारिणी (संख्या 4.3) से स्पष्ट है कि सामान्यजन का यह मत है कि 60 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों का रवैया किसी मामले को निपटाने में पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे-वे ज्यादा सक्रिय, सहयोगात्मक, बेहतर, तत्परता, विनम्रता, अधिक अनुशासित, सजग या जागरूक, सहानुभूतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, कर्तव्यनिष्ठ, गम्भीरता पूर्वक बातों को सुनती और महत्व देती हैं, साथ ही नारी मनोविज्ञान और मानसिकता को समझने के कारण महिला अपराधी से सहानुभूतिपूर्ण और सामाजिक परक सम्बन्ध स्थापित करने में कुशल

होती है। 8 प्रतिशत लोगो ने कहा है कि महिलाओ का रवैया पुरुषो की अपेक्षा खराब होता है, जैसे—दुलमुल या ढीला—ढाला होता है।

10 प्रतिशत लोगो का कहना है कि पुरुष पुलिसकर्मी एव महिला पुलिसकर्मी दोनो का व्यवहार एक जैसा ही रहता है और 4 प्रतिशत लोगो का कहना है कि ये हर व्यक्ति स्वभाव पर निर्भर करता है कि वह किसी समस्या का कैसे निपटाता है। 18 प्रतिशत लोग यह मानते हैं कि उन्हे इस बारे मे कोई जानकारी नही है, कि पुलिस की महिलाएं और पुरुष किसी मामले को निपटाने मे कैसा रवैया अपनाते है क्योंकि उन्हे इसका कोई अनुभव नही है।

67 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो का विचार है कि उनके कार्य को सराहा गया है। 70 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियो का मानना है कि महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ढग से करती है। 60 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता जो विभिन्न क्षेत्रो से सम्बन्धित है, मानते है कि महिला पुलिसकर्मी का रवैया किसी मामले को निपटाने मे पुरुष पुलिसकर्मी से ज्यादा अच्छा होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते है कि महिला पुलिसकर्मी अपनी भूमिका का पालन सही तरह से अपने सहकर्मी और सामान्यजन की प्रत्याशा के अनुसार ही निभा रही है।

महिला पुलिस कर्मियो मे कार्यों के दौरान कभी—कभी “भूमिका सघर्ष” की भी अवस्था कभी न कभी आ ही जाती है, क्योंकि इनका उत्तरदायित्व न केवल विभाग बल्कि पारिवारिक गतिविधियो मे भी महत्वपूर्ण होता है। महिला पुलिस कर्मियो से जब ये प्रश्न किया गया कि त्योहार, उत्सव, व्रत इत्यादि अवसरो पर क्या आप अपने आप को किसी तनाव की स्थिति मे पाती है तो इसका उत्तर निम्न प्रकार से दिया।

सारिणी संख्या-4.4

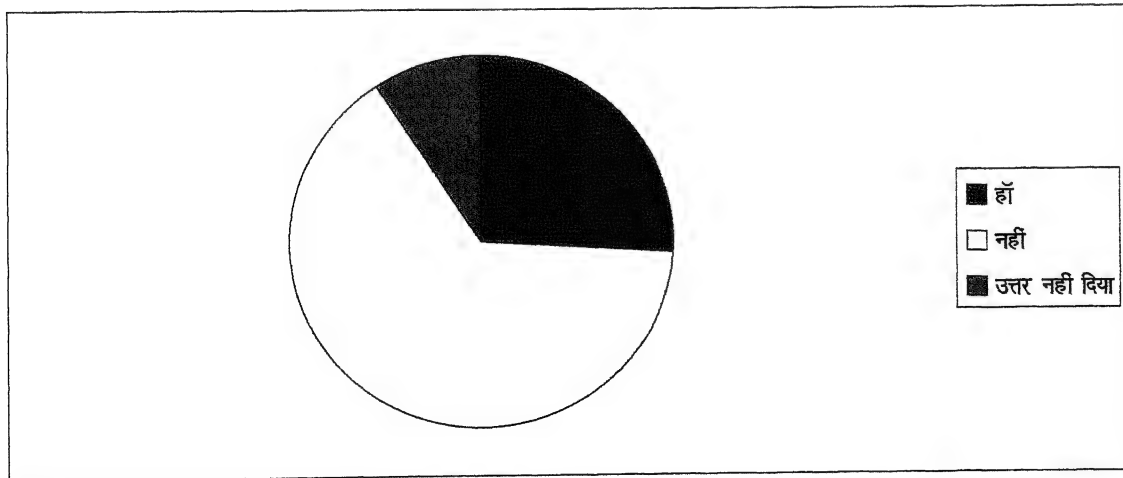
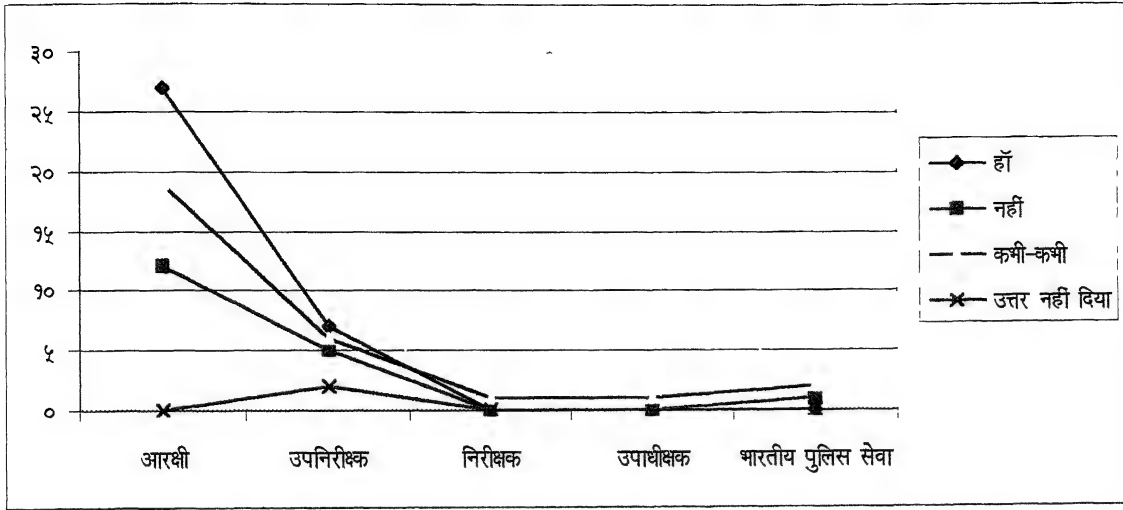
त्यौहार, उत्सव, व्रत इत्यादि अवसरो पर तनाव की स्थिति : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कभी-कभी		उत्तर नहीं दिया		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	27	46.55	12	20.68	19	32.75	—	—	58	69.87
2	उपनिरीक्षक	7	35	5	25	6	30	2	10	20	24.09
3	निरीक्षक	—	—	—	—	1	100	—	—	1	1.20
4	उपाधीक्षक	—	—	—	—	1	100	—	—	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	—	—	1	33	2	67	—	—	3	3.61
योग		35	42.16	18	21.68	33	39.75	2	2.40	83	100

सारिणी (संख्या 4.4) से मालूम होता है कि 46.5 प्रतिशत महिला आरक्षी हाँ में एवं 32.75 प्रतिशत कभी-कभी में और केवल 20.68 प्रतिशत नहीं में उत्तर देती हैं। 35 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने हाँ एवं 30 प्रतिशत ने कभी-कभी और 25 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने कभी-कभी में उत्तर दिया और 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक ने भी कभी-कभी तनाव की स्थिति को स्वीकार किया। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारियों ने नहीं में उत्तर दिया एवं 67 प्रतिशत ने कभी-कभी तनाव की स्थिति को स्वीकार किया।

सारिणी से ज्ञात होता है कि जैसे-जैसे पद में बढोत्तरी होती है, उसी के साथ-साथ तनाव की स्थितियाँ पाने के उत्तर में नहीं में बढोत्तरी हैं, यानि ऊँचे पदों पर आसीन पदाधिकारी अपने आप को कम तनाव की स्थिति में पाती हैं।

सामान्य जन सूचनादाता से प्रश्न किया गया कि पुलिस विभाग की महिला से यदि किसी भी तरह वैवाहिक सम्बन्ध (यानि पुत्र बधु, स्वयं या अन्य किसी पारिवारिक व्यक्ति से विवाह करवाने में) बनाने या विवाह करने या करवाने में क्या आप को कोई दिक्कत महसूस होगी तो इसके उत्तर में निम्न तथ्य सामने आये हैं।



सारिणी संख्या-4.5

पुलिस विभाग की महिला से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने में क्या कोई दिक्कत महसूस करेंगे ? : सामान्य सूचनादाताओं का मत

मत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	20	26
नहीं	50	65
उत्तर नहीं दिया	7	9
योग	77	100

सारिणी (संख्या 45) से पता चलता है कि 26 प्रतिशत लोगो ने महिला पुलिसकर्मी से विवाह करने में दिक्कत महसूस की है, जबकि 65 प्रतिशत ने दिक्कत महसूस नहीं की है। साथ ही 9 प्रतिशत लोगो ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया है।

सामान्य सूचनादाता के 26 प्रतिशत लोग, जिन्होंने वैवाहिक सम्बन्ध बनाने में दिक्कत महसूस की है, उसका कारण है कि समयाभाव के कारण सामाजिक एवं भावनात्मक दायित्वों को निभाने में महिला पुलिस कर्मियों का कठिनाई आयेगी तथा नारी स्वभाव में कमी आ जाती है, और उनका जीवन स्थानान्तरित एवं गतिशील रहता है। इसके साथ ही साथ अराजपत्रित पद पर आसीन महिला पुलिस कर्मियों से विवाह नहीं लेकिन राजपत्रित महिला पुलिस कर्मियों से विवाह स्वीकार है, क्योंकि राजपत्रित अधिकारी के पास पावर होती है कि काम के दबाव को भी झेल सकती है लेकिन अराजपत्रित में मानसिक कार्य के साथ-साथ शारीरिक रूप से भी काफी कार्य होते हैं जिसके कारण घर से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने में परेशानी होती है। सरकारी साधन राजपत्रित अधिकारियों को होती है, जिससे समय की बचत एवं सुविधा अधिक होती है।

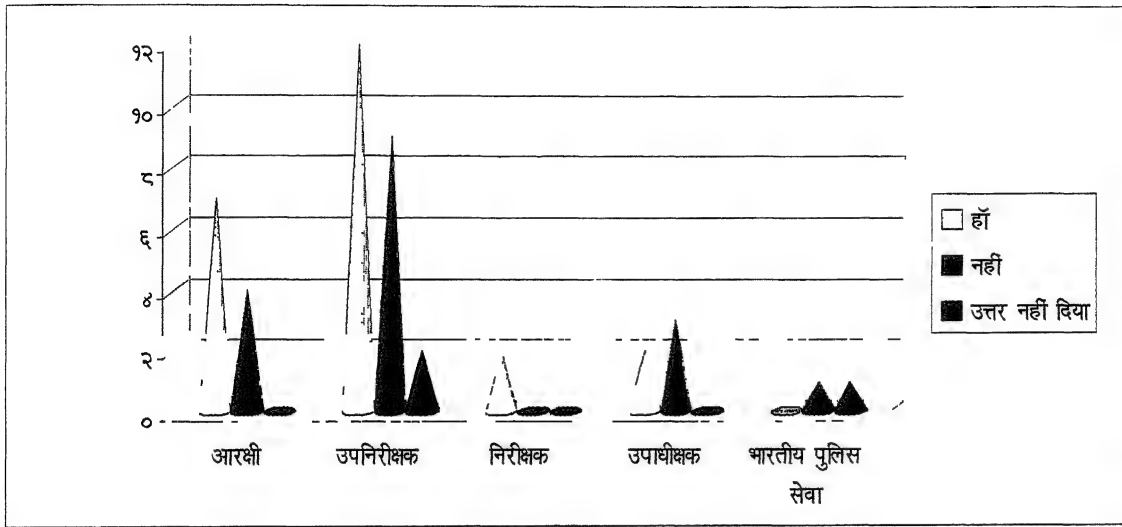
सामान्यजन सूचनादाताओं ने महिला पुलिस कर्मियों से विवाह न करने के कारण भी प्रस्तुत किये हैं जो सारिणी (संख्या 4.6) से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या-4.6

महिला पुलिस कर्मियों से विवाह न करने के कारण : सामान्य सूचनादाताओं का मत

क्रम	विभिन्न प्रकार के मत	संख्या	प्रतिशत
1	समयाभाव के कारण सामाजिक एवं भावनात्मक दायित्व निभाने में दिक्कत	6	30
2	कुशल गृहणी नहीं हो सकती	4	20
3	नारी स्वभाव कम हो जाता है	5	25
4	राजपत्रित अधिकारी है तो कोई दिक्कत नहीं परन्तु अराजपत्रित नहीं	5	25
	योग	20	100

यदि हम उपरोक्त सारिणी के पहले और दूसरे कारण को लगभग एक जैसा होने के कारण एक ही मान ले तो ये 50 प्रतिशत कारण हो जाता है कि समयाभाव के कारण महिला पुलिसकर्मी अपने सामाजिक एवं भावनात्मक दायित्व निभाने में दिक्कत महसूस करती हैं इसीलिए वह कुशल गृहणी का दर्जा पा सकने में दिक्कत महसूस करती हैं। तीसरा कारण उनके स्वभाव में कार्यक्षेत्र की दशाओं का वातावरण की कुछ मांग या असर के कारण नारी स्वभाव में अन्तर आ जाता है, जो विवाह न करने में 25 प्रतिशत कारण बनता है। चौथा कारण जो दिया गया है, वह राजपत्रित में दिक्कत नहीं परन्तु अराजपत्रित में है, वह भी 25 प्रतिशत है। क्योंकि इनके कार्यक्षेत्र में सत्ता की अधिकता और अधिकारों के कारण वह विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक थकान या परेशानियों से बच जाती है, और परिवार को कुछ ज्यादा ध्यान अराजपत्रित की अपेक्षा दे पाती है। एक अन्य कारण यह भी है कि राजपत्रित अधिकारी को समाज में अधिक सम्मान भी प्राप्त है अतः वैवाहिक सम्बन्ध में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है।



दूसरी तरफ इनके साथ काम करने वाली इन्ही के विभाग के लोगो का जो मत है, उसमे 53 48 प्रतिशत ने इनसे वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे दिक्कत महसूस की है। 39 53 प्रतिशत ने कोई दिक्कत महसूस नहीं की है। 6 9 प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया है। सामान्यत यह कह सकते हैं कि 53 48 प्रतिशत ने दिक्कत महसूस की है जिसका प्रतिशत अधिक है, यानि आधे से अधिक लोगो ने परेशानी महसूस की है जो पदानुसार सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या-4.7

महिला पुलिस कर्मियों से वैवाहिक सम्बन्ध में बनाने पर : पुरुष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	7	63 63	4	36 36	—	—	11	25 58
2	उपनिरीक्षक	12	52 17	9	39 13	2	8 6	23	53 48
3	निरीक्षक	2	100	—	—	—	—	2	4 65
4	उपाधीक्षक	2	40	3	60	—	—	5	11 62
5	भारतीय पुलिस सेवा	—	—	1	50	1	50	2	4 65
योग		23	53.48	17	39 53	3	6 9	43	100

सारिणी (संख्या 4 7) में पदानुसार देखे तो 64 प्रतिशत पुरुष आरक्षियों ने महिला पुलिस कर्मियों से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे दिक्कत महसूस की है जबकि 36 प्रतिशत ने नहीं की है। 52 प्रतिशत उपनिरीक्षको ने भी दिक्कत महसूस की है जबकि 39 प्रतिशत ने कोई दिक्कत महसूस नहीं की एव 9 प्रतिशत ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। 100 प्रतिशत निरीक्षको ने भी दिक्कत महसूस की है। 40 प्रतिशत उपाधीक्षको ने भी विवाह मे दिक्कत महसूस की एव 60 प्रतिशत ने महिला पुलिस कर्मियों से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने मे कोई दिक्कत महसूस नहीं की। 50 प्रतिशत

भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारियों ने महिला पुलिस कर्मियों से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं की है। 50 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

46.51 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने अपनी बहन या बेटी को पुलिस विभाग में आने से मना किया है उनमें मना करने का निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किये हैं।

सारिणी संख्या-4.8

अपने बहन या बेटी को पुलिस विभाग में आने से मना करने के बारे में : पुरुष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	मत	संख्या	प्रतिशत
1	उचित सम्मान नहीं मिलता है	4	20
2	असमय ड्यूटी और अत्यधिक कार्य के कारण परिवार में विघटन या तनाव उत्पन्न होता है।	6	30
3	विभाग की कार्यप्रणाली महिलाओं के अनुकूल नहीं है	5	25
4	अन्य	5	25
	योग	20	100

सारिणी (संख्या 4.8) से स्पष्ट है कि 20 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने माना है कि इस विभाग की महिला को उचित सम्मान नहीं मिलता है। 30 प्रतिशत ने माना कि असमय ड्यूटी और अत्यधिक कार्य के कारण परिवार में विघटन या तनाव होता है। 25 प्रतिशत का मानना है कि इस विभाग की कार्य प्रणाली महिलाओं के अनुकूल नहीं है तथा 25 प्रतिशत ने अन्य कई प्रकार के कारण बताये।

सर्वाधिक 30 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मी असमय ड्यूटी और कार्य के कारण परिवार में विघटन या तनाव उत्पन्न होने को मानते हैं जिसके कारण वे नहीं चाहते कि उनकी बहन या बेटी इस विभाग में आये।

भूमिका संघर्ष के रूप में महिला पुलिस कर्मियों से जब ये पूछा गया कि क्या वो किसी त्यौहार, उत्सव, व्रत इत्यादि अवसरों पर अपने आपको तनाव की स्थिति में पाती हैं, तो 'नहीं' का प्रतिशत सभी पदों पर सबसे कम है। 'हाँ' और कभी-कभी दोनों के प्रतिशत को मिला दे, तो हम देखेंगे कि कभी न कभी ये तनाव को महसूस करती हैं। इस बात की पुष्टि सामान्यजन के इस उत्तर ने भी किया है कि वे पुलिस विभाग की महिला से किसी भी तरह का वैवाहिक सम्बन्ध बनाने में दिक्कत महसूस करेंगे, जो कि 26 प्रतिशत है उसके कारण मुख्य तौर से ये ही है कि समय के अभाव के कारण वो पारिवारिक, सामाजिक एवं भावनात्मक उत्तरदायित्वों को ढंग से निभा नहीं पाती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उनमें नारी के सहज स्वभाव में अन्तर भी हो जाता है। कार्याधिक के कारण सभी कार्य को ढंग से नहीं कर पाती हैं और परिवार या या नौकरी दोनों में से किसी एक में ही अपने को उत्तम सिद्ध कर पाती हैं। दोनों क्षेत्रों अनुकूल स्थापित करने की कोशिश भी करती हैं। राजपत्रित अधिकारियों की सुविधाएँ एवं अधिकारों में अधिकता के साथ ही समाज में अच्छा स्थान भी है। अतः अराजपत्रित के अपेक्षा राजपत्रित अधिकारी को विवाह के लिए स्वीकार करते हैं।

महिला पुलिस कर्मियों के साथ काम करने वाले 5348 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी भी इनसे किसी भी तरह का वैवाहिक सम्बन्ध बनाने में एतराज करते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा करीब से जानने का मौका मिलता है। जिससे वो इनको समयाभाव के कारण दिक्कतों को ज्यादा बेहतर ढंग से जान पाते हैं। 46.51 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने अपनी बहन या बेटी को इस विभाग में आने से मना किया उनमें भी ये कारण प्रमुख है। 30 प्रतिशत असमय ड्यूटी और अत्यधिक कार्य के कारण परिवार में विघटन या तनाव उत्पन्न होता है। साथ ही 25 प्रतिशत विभाग की कार्यप्रणाली महिलाओं के अनुकूल नहीं है माना है। 20 प्रतिशत माना कि उन्हें समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता है, 25 प्रतिशत अन्य कारणों को बताया है।

इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महिला पुलिस में समयाभाव के कारण अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में अपने को भूमिका संघर्ष की स्थिति में पाती है और कार्यक्षेत्र तथा परिवार में जो ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है उसे चुन लेती है, जिससे कोई एक पक्ष कहीं न कहीं उपेक्षित रह जाता है, जबकि वह दोनों में ज्यादा से ज्यादा सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है।

26 प्रतिशत साधारणजन के सूचनादाताओं ने महिला पुलिस से विवाह में दिक्कत महसूस की है उसके कारणों में भी 25 प्रतिशत कारण उन्होंने माना कि नारी स्वभाव में कमी आ जाती है। इसी तरह से 46.51 पुरुष पुलिस कर्मियों ने जो कारण बताया है कि वो अपनी बहन, बेटी को इस विभाग में नहीं आने देंगे उसमें 25 प्रतिशत अन्य कारणों में एक कारण ये भी है कि नारी मानवीय दृष्टिकोण का लोप हो जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नारी में जो उसका स्वभाव जिसकी आशा अन्य व्यक्ति करते हैं, वो शुद्ध रूप में महिला पुलिस में अन्य व्यक्ति नहीं पा सकते हैं, या कम पाते हैं। उनका कारण भी ये है कि जिस कार्यक्षेत्र को उन्होंने चुना है, उसमें प्राचीन समय से (अंग्रेजों के समय से) जब केवल पुरुष ही इस विभाग में थे तब वो कठोर अनुशासन और सौबदार व्यक्तित्व के थे। जिसमें पहले हिसात्मक कार्यवाही कार्य के दौरान करते थे तब वह डराने-धमकाने में भी उपयुक्त था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यद्यपि की इसमें बदलाव आया है लेकिन पुलिस विभाग के लोग कठिन परिस्थितियों में लगातार ड्यूटी के कारण कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि बहुत ही रूखे स्वभाव से किसी व्यक्ति से उस दौरान मिले जबकि वो अत्यन्त थके हो तो वही छवि दिमाग में साधारण जन रखते हैं, साथ ही कुछ कार्यक्षेत्र की आवश्यकता भी है कि भाषा में अपशब्द का प्रयोग होता है। यही काम जब एक महिला करती है तो वह अजीब लगता है, क्योंकि अभी तक हम इसको देखने के आदी नहीं हैं। महिला पुलिसकर्मी के लिए भी यह दिक्कत की चीज है कि वह अपने नारी स्वभाव सम्बन्धित चीजों को यदि नहीं छोड़ेगी तो कुछ हद तक तो वह साधारण रूप से अपराधियों से पूँछ-ताँछ भी नहीं कर पायेगी। उसे अपने को केवल नारी के अलावा पद के अनुरूप भी कार्यक्षेत्र में सिद्ध करना होता है। अतः वह अपने में कुछ बदलाव तो लाती है जिससे उस विभाग के कार्य के

अनुरूप अपने को रख पाये इसे भूमिका वचन की स्थिति कहेंगे। अधिकतर ये रूप उसके कार्यक्षेत्र तक ही सीमित होता है, परन्तु लगातार आदत के पश्चात् कुछ हद तक निजी जीवन में भी कहीं न कहीं प्रभाव होता है।

जब महिला पुलिस अपनी ट्रेनिंग समाप्त करके पोस्टिंग वाले स्थान पर जाती है तो वह भूमिका सक्रमण की स्थिति में होती है। इस स्थिति में भूमिका तनाव की संभावनाएं रहती हैं क्योंकि यह भूमिका सीखने की स्थिति में होती है। ये तनाव और भी बढ़ जाता है यदि वह अपने पोस्टिंग वाले स्थान पर लोगों का सहयोग उसे प्राप्त न हो। पोस्टिंग वाले स्थान पर उपस्थित लोग सहयोग न भी करें तो कम से कम वातावरण को दूषित करके मानसिक तनाव इन महिला पुलिस कर्मियों का न बढ़ाये। ऐसा ही अनुभव एक महिला सबइन्स्पेक्टर ने अपने पहले ही दिन थाना—सोराव में अपने पुरुष एस० ओ० का व्यवहार को अनुभव किया कि शिष्टाचार का अभाव एवं महिला एस० आई० को देखकर और भी अभद्रता करना, अश्लील बातों का उच्चारण जिससे शर्म से सर भी न उठाया जा सके। दीवान या पुरुष सिपाही भी जानना चाहते हैं कि किस मजबूरी से महिला पुलिसकर्मी हैं, इस विभाग में आयीं। इस महिला उपनिरीक्षक के अनुसार यदि शुरुवाती समय में ऐसे लोग मिल जाते हैं तो कार्यकाल मुश्किल हो जाता है परन्तु ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे ही हों, धूरपुर—एस० ओ० के साथ काम करने में कोई परेशानी अनुभव नहीं की और उचित सम्मान व स्नेह भी मिला।

सदर्भ समूह के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही पहलू महिला पुलिस कर्मियों में किस सीमा तक हैं इसको जानने के लिए हमने जब इनसे प्रश्न किया कि यदि आपके सामने विकल्प के सारे द्वार खुले हों तो आप किस नौकरी को चुनेंगी तो उनके उत्तर निम्न प्रकार से थे।

सारिणी संख्या-4.9

स्वयं के संदर्भ समूह के बारे में महिला पुलिस कर्मियों के मत

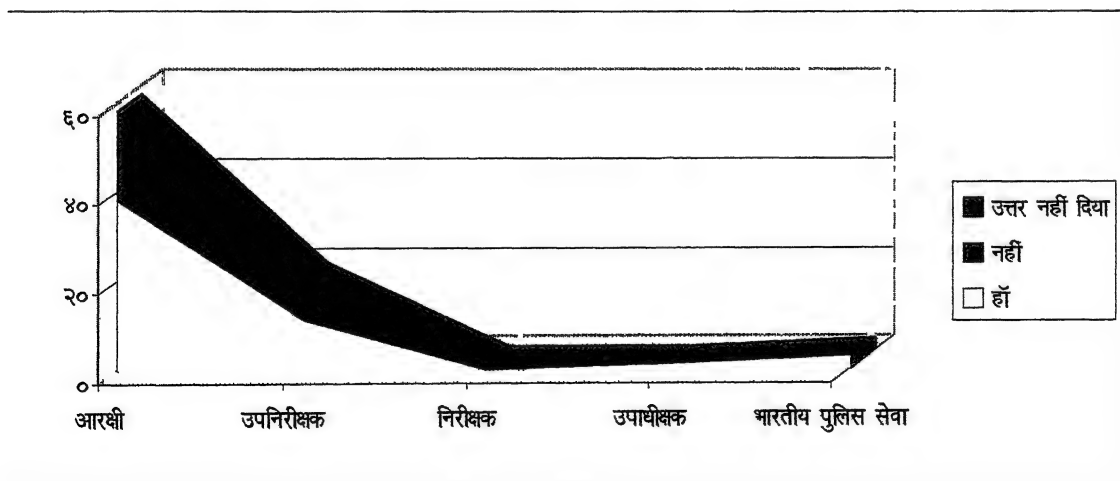
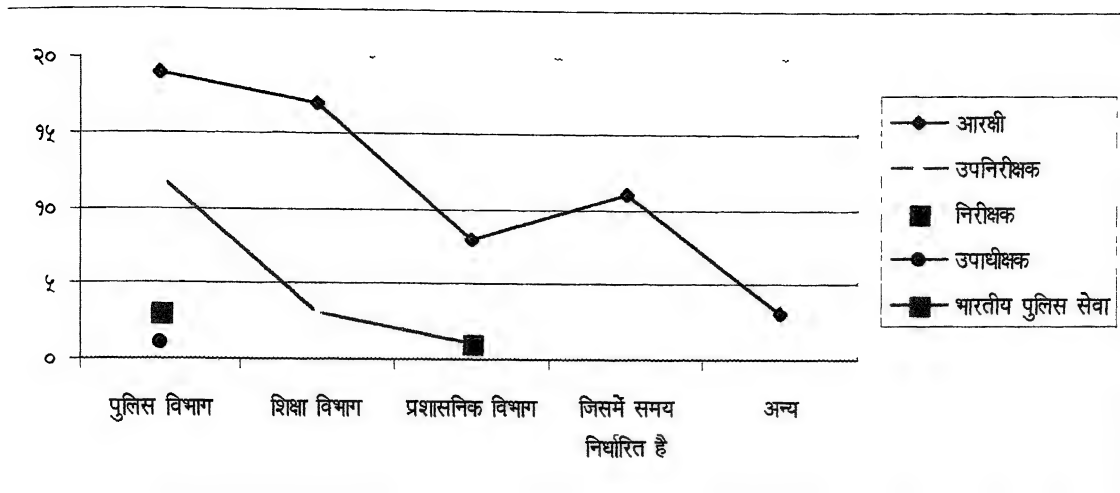
क्रम	पद	पुलिस विभाग		शिक्षा विभाग		प्रशासनिक विभाग		जिसमे समय निर्धारित है		अन्य	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	19	32.75	17	29.31	8	13.79	11	18.96	3	5.17
2	उपनिरीक्षक	12	60	3	15	1	5	—	—	4	20
3	निरीक्षक	—	—	—	—	1	100	—	—	—	—
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	—	—	—	—	—	—
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	—	—	—	—	—	—	—	—
योग		35	42.16	20	24	10	12.04	11	13.25	7	8.43

सारिणी (संख्या 4.9) से पता चलता है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षी अपने पुलिस विभाग को ही पसंद करती हैं। 67 प्रतिशत अन्य विभागों को जैसे 29 प्रतिशत शिक्षा विभाग को, 14 प्रतिशत प्रशासनिक विभाग, 19 प्रतिशत कोई भी ऐसी नौकरी जिसमें समय निर्धारित है ड्यूटी को और 3 प्रतिशत अन्य विभिन्न प्रकार की नौकरियों को पसंद करती हैं।

60 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक पुलिस विभाग को ही पसंद करती हैं 15 प्रतिशत शिक्षा विभाग को, 5 प्रतिशत प्रशासनिक सेवा एवं 20 अन्य विभिन्न प्रकार की नौकरियों को पसंद करती हैं।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक प्रशासनिक विभाग को पसंद करती हैं एवं 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक पुलिस विभाग को पसंद करती हैं। 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी अपने ही विभाग को पसंद करती हैं।

अपने ही विभाग को पसंद करने का मतलब है कि सदस्यता समूह ही उनका संदर्भ समूह भी है। कुल 42 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी के लिए ये सदस्यता समूह ही



सदर्भ समूह है। 24 प्रतिशत के लिए शिक्षा विभाग, 12 प्रतिशत के लिए प्रशासनिक सेवा, 13 प्रतिशत के लिए ऐसी नौकरी जिसमें ड्यूटी का समय निर्धारित हो एव 8 प्रतिशत अन्य विभिन्न प्रकार के विभाग है जो इनके लिए सदर्भ समूह है।

महिला पुलिस कर्मियों से एक अन्य प्रश्न पूछा गया कि यदि आपके बच्चे इस विभाग में आना चाहे तो आप उसे आने देंगी या नहीं तो निम्न उत्तर प्राप्त होते हैं।

सारिणी संख्या-4.10

अपने बच्चों को पुलिस विभाग में आने देंगी या नहीं :
महिला पुलिस कर्मियों के मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	38	65.5	19	32.7	1	1.7	58	69.87
2	उपनिरीक्षक	11	55	8	40	1	5	20	24.09
3	निरीक्षक	—	—	1	100	—	—	1	1.20
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	—	—	—	—	3	3.61
योग		53	63.85	28	33.73	2	2.4	83	100

सारिणी (संख्या 4.10) से पता चलता है कि 65 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने कहा कि वो अपने बच्चों को इस विभाग में आने देंगी। 33 प्रतिशत ने कहा नहीं आने देंगी तथा 2 प्रतिशत ने जबाब नहीं दिया।

55 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने कहा कि वो अपने बच्चों को इस विभाग में आने देंगी। 40 प्रतिशत ने मना किया है एव 5 प्रतिशत ने जबाब नहीं दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने अपने बच्चों को इस विभाग में आने देने से मना

किया है। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक एवं 100 प्रतिशत भारत पुलिस रूप की अधिकारियों ने आने देने के लिए हॉ कहा है।

जिन्होंने भी अपने बच्चों को इस विभाग में आने के लिए हॉ कहा है इसका मतलब है कि उतने प्रतिशत लोगों के बच्चों के लिए पुलिस विभाग सकारात्मक सदर्भ समूह हो सकता है जिसमें उनको कोई एतराज नहीं होगा।

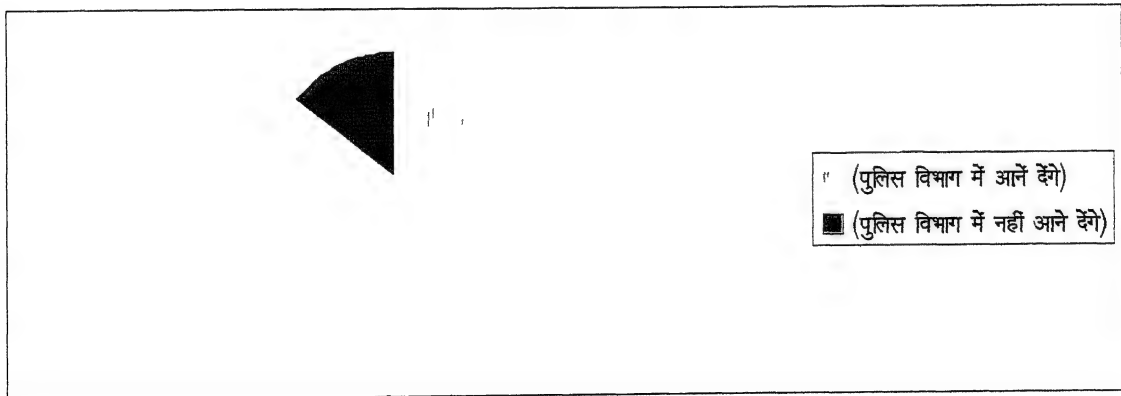
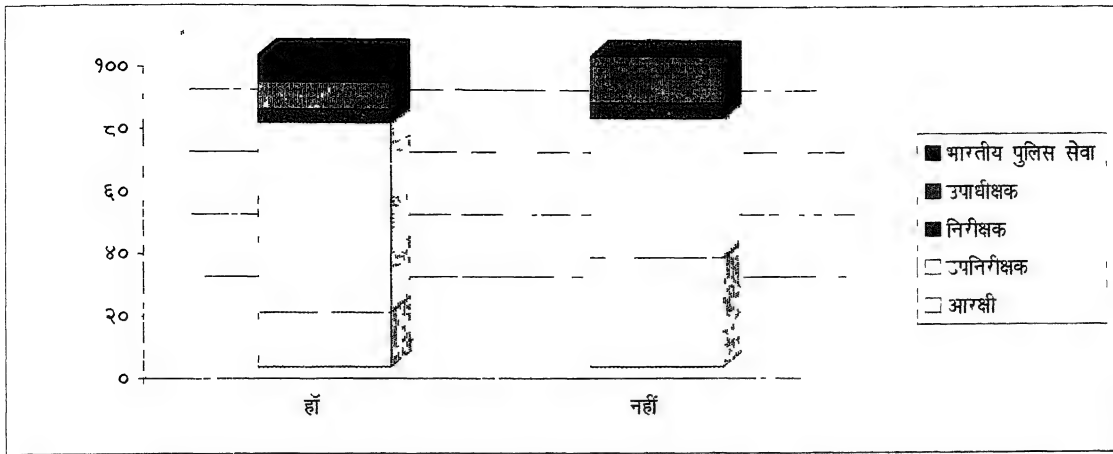
पुरुष पुलिस कर्मियों से जब ये प्रश्न किया, कि वे अपनी बेटी या बहन को जो इस विभाग में आना चाहे तो क्या आप उसे आने देंगे ? तो निम्न तथ्य सामने आये।

सारिणी संख्या-4.11

आपकी बेटी या बहन को इस विभाग में आना चाहें तो क्या आप उसे आने देंगे : पुरुष पुलिस कर्मियों के मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	4	36.36	7	63.63	11	25.58
2.	उपनिरीक्षक	14	60.86	9	39.13	23	53.48
3	निरीक्षक	1	50	1	50	2	4.65
4	उपाधीक्षक	2	40	3	60	5	11.62
5	भारतीय पुलिस सेवा	2	100	—	—	2	4.65
योग		23	53.48	20	46.51	43	100

सारिणी (संख्या 4.11) से स्पष्ट है कि 53.48 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने अपनी बहन या बेटी के लिए अपने सकारात्मक सदर्भ समूह के रूप में चुना है। 46.51 प्रतिशत ने नकारात्मक सदर्भ समूह के रूप में चुना है।



पदानुसार देखे तो 36 प्रतिशत पुलिस आरक्षियो ने अपनी बेटी या बहन को इस विभाग में आने की अनुमति प्रदान की है। 64 प्रतिशत ने मना किया है। इसी तरह 61 प्रतिशत उपनिरीक्षको ने हाँ, एव 39 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 50 प्रतिशत निरीक्षक ने हाँ, एव 50 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 40 प्रतिशत उपाधीक्षक ने हाँ, एव 60 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियो ने हाँ में उत्तर दिया है। जिन पुरुष पुलिस कर्मियो ने हाँ में उत्तर दिया है उनके लिए पुलिस विभाग सकारात्मक सदर्थ समूह है एव जिन्होंने नहीं में उत्तर दिया है उनके लिए पुलिस विभाग नकारात्मक सदर्थ समूह है।

सामान्य सूचनादाता से भी ये प्रश्न किया गया कि यदि अपकी बेटी या बहन जो, इस विभाग में आना चाहे तो क्या आप उसे आने देंगे तो निम्न उत्तर प्राप्त हुए।

सारिणी संख्या-4.12

अपनी बेटी या बहन जो इस विभाग में आना चाहें तो क्या उसे आने देंगे : सामान्य सूचनादाताओं का मत

क्रम	हाँ (पुलिस विभाग में आने देंगे)		नहीं (पुलिस विभाग में नहीं आने देंगे)		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	66	85.71	11	14.28	77	100

सारिणी (संख्या 4.12) से स्पष्ट है कि 14.28 प्रतिशत लोगो ने अपने लोगो के लिए पुलिस विभाग को सदर्थ समूह हाने का समर्थन नहीं किया है, यानि नकारात्मक सदर्थ समूह है। 85.71 प्रतिशत लोगो ने अपने लोगो के लिए पुलिस विभाग को सदर्थ समूह होने का समर्थन किया है, जबकि पद के सम्बन्ध में उनकी निम्न व्याख्या है।

सारिणी संख्या-4.13

वो सामान्य सूचनादाता जो अपनी बहन या बेटी को इस विभाग में आने देंगे : उनके पद के सम्बन्ध में मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	केवल राजपत्रित (उपाधीक्षक या भारतीय पुलिस सेवा)	42	63.63
2	योग्यतानुसार किसी भी पद पर	15	22.72
3	आरक्षी से ऊपर कम से कम सब-इन्स्पेक्टर पद पर	7	10.6
4	उत्तर नहीं दिया है	2	3
	योग	66	100

सारिणी (संख्या 4.13) से स्पष्ट है कि इसमें भी 63.63 प्रतिशत केवल राजपत्रित पदों को ही पसन्द करते हैं। 22.72 प्रतिशत योग्यतानुसार किसी भी पद पर एवं 10.6 प्रतिशत ने आरक्षी से ऊपर कम से कम सब-इन्स्पेक्टर पद पर अपनी बेटी या बहन के लिए पसन्द करते हैं। 3 प्रतिशत लोगो ने इसका उत्तर नहीं दिया है कि वह कौन सा पद चाहते हैं।

महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी तथा सामान्य सूचनादाता (जो कि विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं) इनसे जब यह पूछा गया कि क्या वे अपने बच्चों या बहन या बेटी को इस विभाग में आने की अनुमति देंगे तो हमें जो विचार मिले हैं वह इस तरह से हैं, कि 64 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों ने हाँ में उत्तर दिया है, 53 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने भी हाँ में उत्तर दिया तथा 86 प्रतिशत सामान्य सूचनादाताओं ने भी हाँ में उत्तर दिया है। यानि जिन्होंने भी 'हाँ' में उत्तर दिया है उतने लोगो के लिए इनके बच्चों, बहन आदि के लिए पुलिस विभाग सकारात्मक संदर्भ समूह होने की सम्भावना है। साथ ही 42 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों के लिए उनका स्वयं का पुलिस समूह यानि सदस्यता समूह ही संदर्भ समूह है।

34 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों ने अपने बच्चों को इस विभाग में आने देने से मना किया है, 47 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने भी मना किया है। 14 प्रतिशत सामान्य सूचनादाताओं ने भी मना किया है। इसका मतलब है कि इनके बच्चों को पुलिस विभाग संदर्भ समूह होने की सम्भावना से मना करता है यानि नकारात्मक संदर्भ समूह होने की सम्भावना है।

- 1 लिटन रॉल्फ, द स्टडी ऑफ़ जैन , पृ० 113-119
- 2 मर्टन, आर० के० सोशल स्ट्रक्चर एण्ड सोशल थ्योरी फ्री प्रेस 1963, पृ० 668-71
- 3 हाईमेन, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेट्स (1942), लेख ।
- 4 शेरिफ एण्ड शेरिया, ऐन आउट लाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, पृ० 175
- 5 जानसन, हैरी एम०, सोशियोलॉजी, ए सिस्टमेटिक इन्ट्रोडक्शन, लन्दन 1963

अध्याय—५

महिला पुलिस की कार्यदशा और सफलता

(Working condition and Achievements of Female Police)

महिला पुलिसकर्मी की सफलताओं एवं असफलताओं को हम तभी ढग से समझ सकते हैं जब यह पता हो कि वास्तव में महिला पुलिसकर्मी किस प्रकार उपयोगी हैं। यह प्रश्न स्वयं महिला पुलिस कर्मियों एवं उनके साथ कार्य करने वाले पुरुष पुलिस कर्मियों की राय जानने के बाद ही कह सकते हैं, साथ ही आम जनता की राय भी महत्व रखती है।

प्रस्तुत अध्याय में महिला पुलिस कर्मियों की कार्यदशा तथा सफलताएँ सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी दी जा रही है।

महिला पुलिस से उनकी उपयोगिता के बारे में प्रश्न करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं।

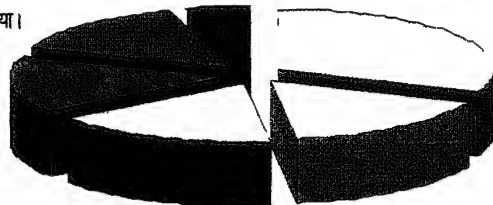
सारिणी संख्या—5.1

महिला पुलिस कर्मियों का मत: महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ-तॉछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी हैं।	26	31.32
2	महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने एवं न्याय दिलाने में सहायक हैं।	14	16.86
3.	सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी हैं।	14	16.86
4	सवेदनशील होने के कारण महिलाओं के समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने में ये सहायक हैं।	13	15.66
5	उत्तर नहीं दिया।	12	14.45
6	अन्य	4	4.8
योग		83	100

☐ a ☐ b ☐ c ☒ d ☒ e ☒ f

- a** महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ-ताछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी हैं।
b महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने एवं न्याय दिलाने में सहायक है।
c सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी हैं।
d स्वेदनशील होने के कारण महिलाओं के समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने में ये सहायक हैं।
e उत्तर नहीं दिया।
f अन्य

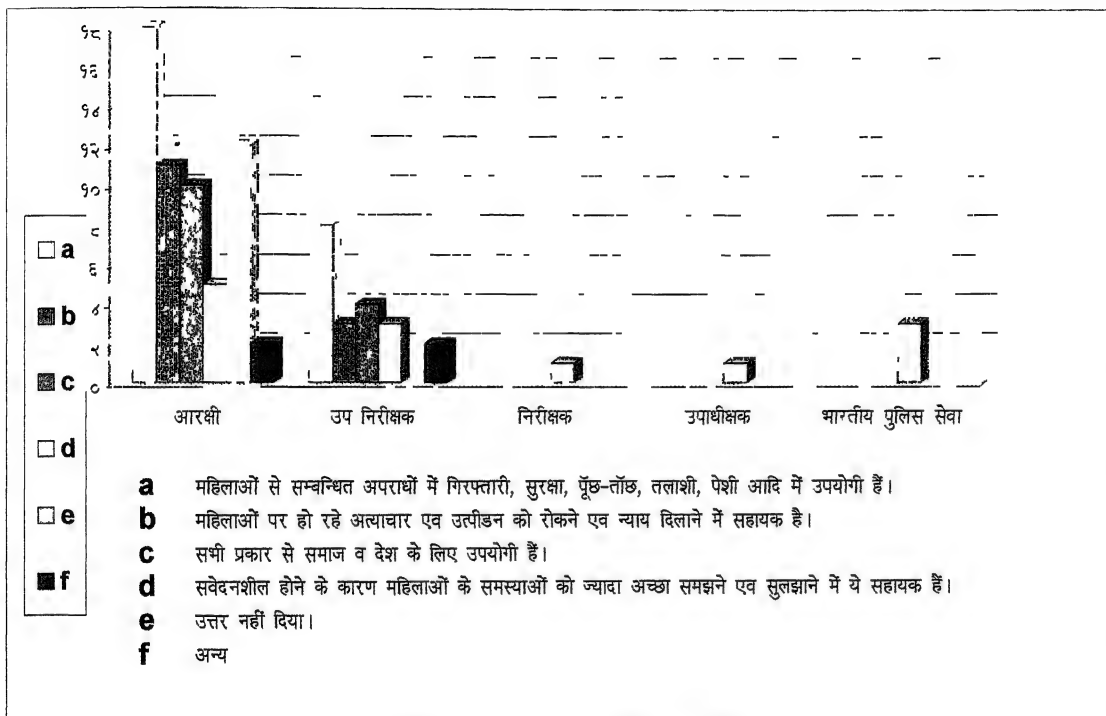


सारिणी (सख्या 51) से स्पष्ट होता है कि 31 32 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ये मानती है कि उनकी उपयोगिता महिलाओ से सम्बन्धि अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ-तौँछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगी है। 16 86 प्रतिशत का मानना है, कि वे महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने तथा न्याय दिलाने मे सहायक है। 16 86 प्रतिशत मानती है, कि महिला पुलिसकर्मी सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है। 15 66 प्रतिशत मानती है, कि महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता इस कारण है कि वे सवेदनशील होने के कारण महिलाओ की समस्याओ को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने मे सहायक है। जबकि 14 45 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियो ने उत्तर नही दिया है।

इस सारिणी मे अन्य कारण जो 4 8 प्रतिशत है, उसमे यह कहा गया है कि वर्तमान मे महिलाओ मे भी अपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ रही है जिन्हे रोकने के लिए महिला पुलिस कर्मियो की आवश्यकता है, साथ ही महिलाए अपनी समस्याओ को नि सकोच होकर महिला पुलिस कर्मियो से कहती है।

क्रम 1, 2, 4, 6 का कुल योग 69 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है, कि 69 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस कर्मियो की उपयोगिता महिलाओ से सम्बन्धित क्षेत्र मे ही अनुभव करती है। 16 86 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी सभी प्रकार से देश व समाज के लिए महिला पुलिस कर्मियो को उपयोगी मानती है।

विभिन्न मतों मे पद के अनुसार प्रतिशत भी भिन्न-भिन्न है जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है।



आटिणी संख्या-5.2

महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता : महिला पुलिस कर्मियों का पदानुसार मत

क्रम	विभिन्न मत	आरक्षी		उप निरीक्षक		निरीक्षक		उपाधीक्षक		भारतीय पुलिस सेवा		योग	
		स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र
1	महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ-ताँछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगी है।	18	31 03	8	40	—	—	—	—	—	—	26	31 32
2	महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने मे सहायक है।	11	18 96	3	15	—	—	—	—	—	—	14	16 86
3	सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है।	10	17 24	4	20	—	—	—	—	—	—	14	16 86
4	सवेदनशील होने के कारण महिलाओ के समस्याओ को ज्यादा अच्छा समझने एव सुलझाने मे ये सहायक है।	5	8 6	3	15	1	100	1	100	3	100	13	15 66
5	उत्तर नहीं दिया।	12	20 68	—	—	—	—	—	—	—	—	12	14 45
6	अन्य	2	3 44	2	10	—	—	—	—	—	—	4	4 8
योग		58	100	20	100	1	100	1	100	3	100	33	100

31 03 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो मे गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ-ताँछ, तलाशी, पेशी आदि मे उपयोगिता स्वीकार की है। 18 96 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने महिलाओ पर हो रहे अत्याचार एव उत्पीडन को रोकने एव न्याय दिलाने मे सहायक है, स्वीकार किया है। 17 24 प्रतिशत महिला आरक्षियो ने माना कि महिला पुलिसकर्मी सभी प्रकार से देश व समाज के लिए

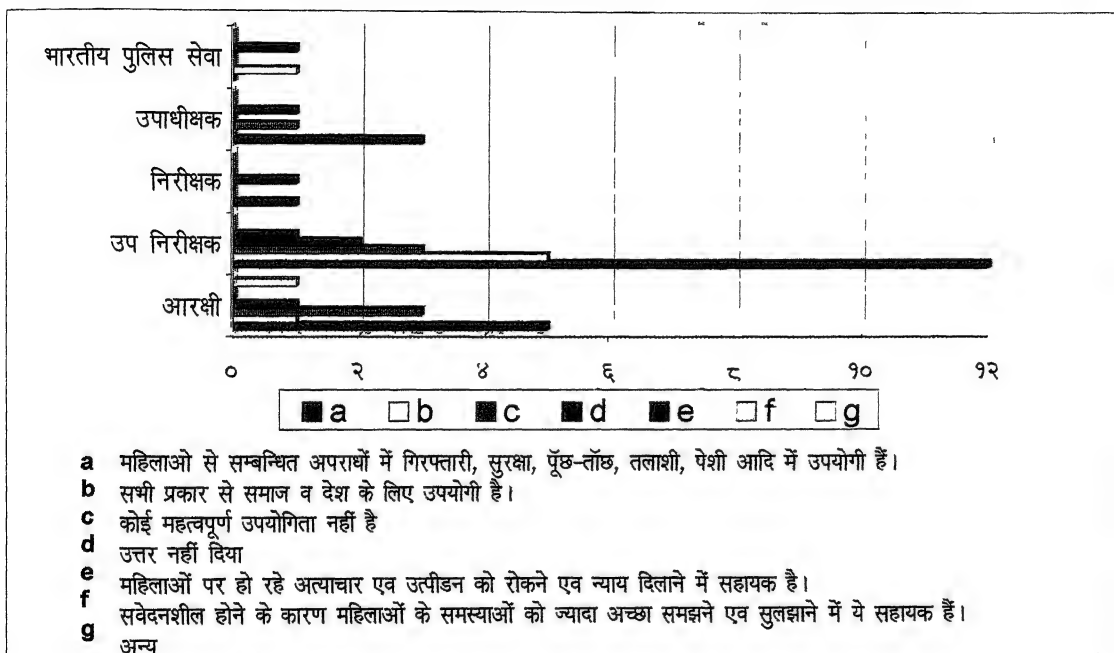
उपयोगी है। 86 प्रतिशत ने माना कि महिला पुलिसकर्मी सवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह से समझने एवं सुलझाने में सहायक है। 2068 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने कोई उत्तर नहीं दिया एवं 344 प्रतिशत ने महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता के अन्य कारण बताये हैं।

महिला आरक्षियों के मतों में यदि हम कुल महिलाओं से सम्बन्धित उपयोगिता को देखें तो क्रम 1, 2, 4, 6 क्रमशः 3103, 1896, 86, 344 यानि कुल 62 प्रतिशत लोगो ने माना है। जबकि 2068 प्रतिशत लोगो ने उत्तर नहीं दिया है। 17 प्रतिशत लोगो ने महिलाओं की इस विभाग में उपयोगिता सभी प्रकार से स्वीकार की है।

40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने महिला पुलिस की उपयोगिता, महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ-तॉछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी माना है। 15 प्रतिशत महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने एवं न्याय दिलाने में सहायक है, स्वीकार किया है। 20 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने सभी प्रकार से समाज व देश के लिए महिला पुलिस कर्मियों को उपयोगी माना है। 15 प्रतिशत ने सवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्या को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने में सहायक है, स्वीकार किया है। 10 प्रतिशत ने अन्य कई कारण माने हैं, जहाँ पर महिला पुलिस की उपयोगिता है। इस प्रकार से महिलाओं से सम्बन्धित होने के कारण को कुल [(क्रम 1, 2, 4, 6) का क्रमशः प्रतिशत 40, 15, 15, 10] 80 प्रतिशत माना है तथा सभी क्षेत्रों में उपयोगी होने को 20 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं।

खास बात यह है कि महिला निरीक्षक, उपाधीक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारियों ने अपने 100 प्रतिशत मत सवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्या को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने में महिला पुलिसकर्मी उपयोगी है, को प्रदान किया है।

महिला आरक्षी एवं उपनिरीक्षकों ने अपने दिये गये मतों में सर्वाधिक मत महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता को महिलाओं गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ-तॉछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी स्वीकार किया है। जबकि निरीक्षक, उपाधीक्षक एवं भारतीय पुलिस



सेवा की अधिकारियों ने सवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने में सहायक है, को प्रदान किया है।

पुरुष पुलिस कर्मियों ने अपने साथ काम करने वाली महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित मत पदानुसार व्यक्त किये हैं।

सारिणी संख्या-5.3

महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता : पुरुष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	विभिन्न मत	आस्था		उप निरीक्षक		निरीक्षक		उपाधीक्षक		भारतीय पुलिस सेवा		योग	
		स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र	स	प्र
1	महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ-ताँछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी है।	5	45 45	12	52 17	1	50	3	60	—	—	21	48 83
2	सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है।	1	9 09	5	21 73	—	—	—	—	1	50	7	16 27
3	कोई महत्वपूर्ण उपयोगिता नहीं है	3	27 27	3	13 04	—	—	1	20	—	—	7	16 27
4	उत्तर नहीं दिया	1	9 09	2	8 69	1	50	—	—	—	—	4	9 30
5	महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने एवं न्याय दिलाने में सहायक है	—	—	1	4 34	—	—	1	20	—	—	2	4 65
6	सवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने में ये सहायक है।	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	1	2 32
7	अन्य	1	9 09	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2 32
योग		11	25 58	23	53 48	2	4 65	5	11 62	2	4 65	43	100

सारिणी (संख्या 53) से पता चलता है कि पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता के बारे में जो विभिन्न मत प्रस्तुत किये हैं, उसमें

सर्वाधिक 48 83 प्रतिशत मत महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूँछ-तौँछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगिता को दिया है। 16 27 प्रतिशत मत सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है, को प्रदान किये है। 16 27 प्रतिशत लोगो ने कहा है, कि महिला पुलिस का कोई महत्वपूर्ण उपयोगिता नहीं है। 9 30 प्रतिशत लोगो ने इसका उत्तर नहीं दिया है। 4 65 प्रतिशत ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने एवं न्याय दिलाने में सहायक माना है। 2 32 प्रतिशत ने कहा है कि संवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने में सहायक है। 2 32 प्रतिशत ने अन्य विचार प्रस्तुत किये हैं।

16 27 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों का मानना है, कि महिला पुलिसकर्मी का इस विभाग में कोई उपयोगिता नहीं है, जो कि नकारात्मक रूख है।

यदि हम पद के अनुसार इन मतों को देखें तो पुरुष आरक्षियों ने क्रम (1) को सर्वाधिक 45 45 प्रतिशत मत दिये उसके बाद क्रम (2) को 9 09 प्रतिशत, क्रम (3) को 27 27 प्रतिशत, क्रम (4) को 9 09 प्रतिशत, क्रम (5) व (6) के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया एवं क्रम (7) को 9 09 प्रतिशत मत दिये हैं।

पुरुष उपनिरीक्षकों ने भी क्रम (1) को सर्वाधिक 52 17 प्रतिशत मत प्रदान किये हैं। क्रम (2) 21 73 प्रतिशत, क्रम (3) को 13 04 प्रतिशत, क्रम (4) को 8 69 प्रतिशत, क्रम (5) 4.34 प्रतिशत मत प्रदान किये हैं एवं क्रम (6) व (7) के बारे में कुछ नहीं कहा है।

पुरुष निरीक्षकों ने क्रम (1) को 50 प्रतिशत एवं क्रम (4) को भी 50 प्रतिशत मत प्रदान किये हैं। पुरुष उपाधीक्षकों ने क्रम (1) को 60 प्रतिशत, क्रम (3) को 20 प्रतिशत एवं क्रम (5) को भी 20 प्रतिशत मत दिये हैं। भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारियों ने क्रम (2) को 50 प्रतिशत एवं क्रम (6) को भी 50 प्रतिशत मत प्रदान किये हैं।

पुरुष आरक्षी, उपनिरीक्षक, निरीक्षक एवं उपाधीक्षक पद के लोगो ने अपने सर्वाधिक मत क्रम (1) को दिये है। यदि हम कुल पुरुष पुलिस कर्मियों के मत महिला पुलिस कर्मियों के बारे में देखे तो इनकी उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित उपयोगिता वाले क्रम को (1, 5 और 6) क्रमश 48 83+4 65+2 32=55 8 प्रतिशत यानि 56 प्रतिशत मत दिये है।

इस आधार पर हम कह सकते है कि महिलाओं से सम्बन्धित में मामलों में तो महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता तो है, ही इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि आधे से अधिक मत इनको प्राप्त होते है।

सामान्य सूचनादाता ने भी महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया है जो कि सारिणी (संख्या 54) से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या-5.4

महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता : सामान्य सूचनादाताओं का मत

क्रम	विभिन्न प्रकार के मत	संख्या	प्रतिशत
1	महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने एवं न्याय दिलाने में सहायक है।	28	36 36
2.	महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ-तॉछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी है।	16	20 77
3.	संवदेनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने के कारण पारिवारिक विवादों में उपयोगी है।	12	15 58
4.	सभी प्रकार से देश के लिए उपयोगी है।	7	9 09
5.	अधिक नम्र एवं जनता की समस्या को ढंग से सुनती है	5	6 49
6.	उत्तर नहीं दिया	9	11 68
योग		77	100

सामान्य सूचनादाता ने अपने विभिन्न मत जो महिला पुलिस की उपयोगिता के बारे में प्रस्तुत किये है, उसमें सर्वाधिक 36 36 प्रतिशत मत महिलाओं पर हो रहे

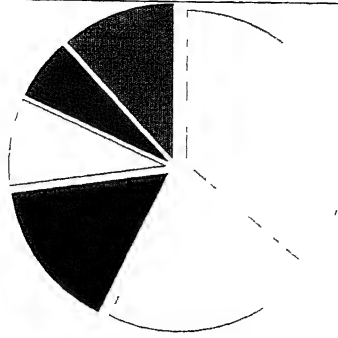
अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने एवं न्याय दिलाने में सहायक है, को दिये हैं। 20 77 प्रतिशत लोग मानते हैं कि महिला पुलिस कर्मी महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ-तॉछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी हैं। 15 58 प्रतिशत लोग मानते हैं, कि महिला पुलिसकर्मी संवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने के कारण पारिवारिक विवादों में उपयोगी हैं। 9 09 प्रतिशत लोग इन्हें सभी प्रकार से देश के लिए उपयोगी मानते हैं। 6 49 प्रतिशत लोग मानते हैं कि महिला पुलिसकर्मी का स्वभाव पुरुष पुलिसकर्मी के अपेक्षा ज्यादा नम्र होता है और जनता की समस्या को ढग से सुनती है। 11 68 प्रतिशत लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। सामान्य जन के मत में यदि क्रम 1, 2, 3 का (36 36, 20 77, 15 58) कुल 73 प्रतिशत है जो ये मानता है कि इनकी उपयोगिता उन सभी घटनाओं में है जिसमें कोई भी महिला प्रत्यक्षत किसी घटना में जुड़ी होती है। इनकी उपयोगिता को यदि हम ध्यान से देखें तो स्वयं महिला होने एवं महिलाओं से सम्बन्धित होने के कारण इनकी उपयोगिता 73+6 49 (अधिक नम्र एवं जनता की समस्याओं को ढग से सुनती हैं) = 79 प्रतिशत है। अतः इनकी उपयोगिता समाज में है।

यदि हम महिला पुलिस की उपयोगिता के बारे में विप्लेषण करें तो पायेंगे कि 69 प्रतिशत स्वयं महिला पुलिसकर्मी अपनी उपयोगिता उन सभी मामलों में जिसमें कोई महिला प्रत्यक्षत शामिल हैं उनमें सर्वाधिक मानती हैं।

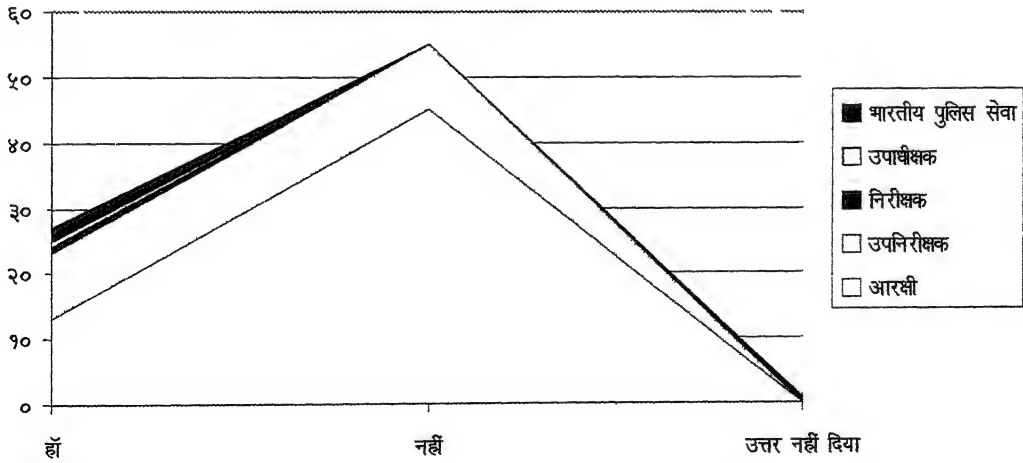
पुरुष पुलिस कर्मियों ने भी इस मत में अपने 56 प्रतिशत मत प्रदान किये हैं, साथ ही साथ सामान्य जनता भी महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता 73 प्रतिशत मानती है जो कि महत्व रखती है।

जनसंख्या की आधी आबादी यदि हम महिलाओं को मानते हैं, तो भी महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता है। समाज में अपराधिक प्रवृत्ति की महिलाएं भी हैं, तो महिला पुलिस की जरूरत जरूर महसूस होगी।

- ☐ a
- ☐ b
- ☒ c
- ☐ d
- ☒ e
- ☒ f



- a** महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने एवं न्याय दिलाने में सहायक है।
- b** महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ-ताछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी हैं।
- c** सवदेनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने के कारण पारिवारिक विवादों में उपयोगी हैं।
- d** सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी है।
- e** अधिक नम्र एवं जनता की समस्या को ढग से सुनती हैं
- f** उत्तर नहीं दिया



17 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपनी उपयोगिता सभी क्षेत्रों में स्वीकार करती हैं। 16.27 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी भी यह मानते हैं, एव 9.09 प्रतिशत सामान्य जनता भी यही मानती है।

महिला पुलिस कर्मियों से जब यह प्रश्न किया गया कि पिछले कुछ महीनों या वर्षों में आपको किसी विशेष समस्या सम्बन्धी कार्य सौंपा गया, तो उन्होंने पदानुसार निम्न प्रकार से उत्तर प्रदान किये।

सारिणी संख्या-5.5

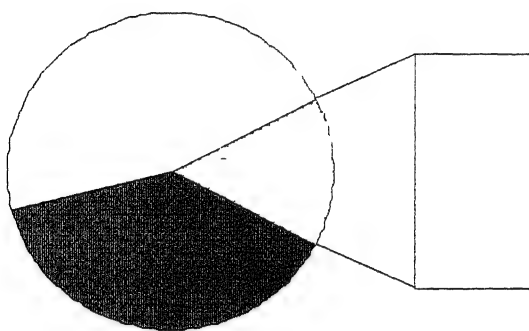
महिला पुलिस कर्मियों को कोई विशेष कार्य सौंपने के सम्बन्ध में : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	13	22.41	45	77.58	—	—	58	
2	उपनिरीक्षक	10	50.00	10	50.00	—	—	20	
3	निरीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	
5	भारतीय पुलिस सेवा	2	67	—	—	1	33	3	
योग		27	32.53	55	66.26	1	1.2	83	

सारिणी (संख्या 5.5) से पता चलता है कि 22.41 प्रतिशत महिला आरक्षी ने किसी विशेष समस्या सम्बन्धी कार्य सौंपे जाने के लिए हाँ कहा है, तथा 77.58 प्रतिशत ने मना किया है। इसी प्रकार महिला उपनिरीक्षकों में 50 प्रतिशत ने हाँ तथा 50 प्रतिशत ने नहीं कहा है।

महिला निरीक्षक एवं उपाधीक्षक ने 100 प्रतिशत हाँ कहा है, जबकि भारतीय पुलिस सेवा की महिलाओं ने 67 प्रतिशत हाँ एवं 33 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया,

आरक्षी



■ क्रिस्ती विवादास्पद धार्मिक स्थानों पर इयूटियों

□ महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की इयूटियों

□ क्रिस्ती खास सांस्कृतिक कार्य अथवा खेलकूद में भाग लिया

२२ प्रतिशत जिन्होंने हों के जबाब दिया है।

क्योंकि वह अभी नयी-नयी विभाग में आयी थी और अभी तक उन्हें कोई खास काम सौंपा नहीं गया था, यानि अभी अन्दर ट्रेनिंग में थी।

कुल महिला पुलिस कर्मियों को देखेंगे तो 32.53 प्रतिशत ने ही हाँ में उत्तर दिया है, काफी मात्रा में यानि 66.26 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया एवं 1.2 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया।

सारिणी संख्या-5.6

विगत महीनों या वर्षों में सौंपे गये कार्यों में महिला आरक्षियों का मत

क्रम	पद	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी 22 प्रतिशत जिन्होने हॉ के जबाब दिया है।	किसी विवादास्पद धार्मिक स्थानो पर ड्यूटियाँ	6	46 15
2		महिलाओ से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ	5	38 46
3		किसी खास सांस्कृतिक कार्य अथवा खेलकूद मे भाग लिया	2	15 38
योग			13	100

यदि हम हाँ में उत्तर देने वाले लोगों के बारे में विचार करें कि उन्हें किस तरह की जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी हैं, तो पदानुसार यह निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि सभी को अपने पद के अधिकार के अनुसार ही कार्य प्राप्त हुए हैं। सारिणी (संख्या 5.6) से स्पष्ट है कि जैसे कुल 22 प्रतिशत आरक्षियों ने जो हाँ में उत्तर दिये हैं, उनमें से 46.15 प्रतिशत ने किसी विवादस्पद धार्मिक या अन्य स्थानों पर ड्यूटियाँ कहा है। 38.46 प्रतिशत ने महिलाओं से सम्बन्धित किसी खास केस में विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ कहा है। 15.38 प्रतिशत ने किसी खास सांस्कृतिक कार्य अथवा खेलकूद में भाग लिया है।

विगत महीनों या वर्षों में सौंपे गये कार्य : महिला उपनिरीक्षकों का मत

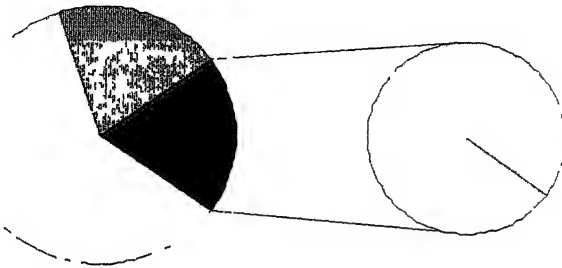
क्रम	पद	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	महिला उपनिरीक्षक 50 प्रतिशत जिन्होंने हों के जबाब दिया है।	महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करवाया।	6	60
2		थानाध्यक्ष या चौकी इंचार्ज के पद पर रहते हुए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य।	2	20
3		किसी खास समस्या का समाधान किया	2	20
योग			10	100

सारिणी (57) से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने किसी विशेष कार्य को सौंपी जाने के सम्बन्ध में हॉ कहा है उन्हें निम्न प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। 60 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि उन्हें महिलाओं से सम्बन्धित कुछ खास केस या समस्याओं का समाधान करवाया है। 20 प्रतिशत ने कहा कि थानाध्यक्ष या चौकी इंचार्ज के पद पर रहते हुए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य तथा 20 प्रतिशत ने किसी खास समस्या का समाधान किया जो कि केवल महिलाओं से ही सम्बन्धित नहीं था।

100 निरीक्षक को जो काम सौंपे गये हैं, उनमें वी० आई० पी० सुरक्षा एव दस्यु उन्मूलन (एन्टी डकैती) के कार्य हैं। 100 प्रतिशत उपाधीक्षक ने कुम्भ व माघमेला व चुनाव ड्यूटी से सम्बन्धित कार्य के लिए कहा है। 67 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिलाओं ने मानवाधिकारों से सम्बन्धित जितने मामले सी० आई० ओ० में थे, उनका पर्यवेक्षण तथा उत्तराखण्ड के विवाद के समय वहाँ चुनाव करना था।

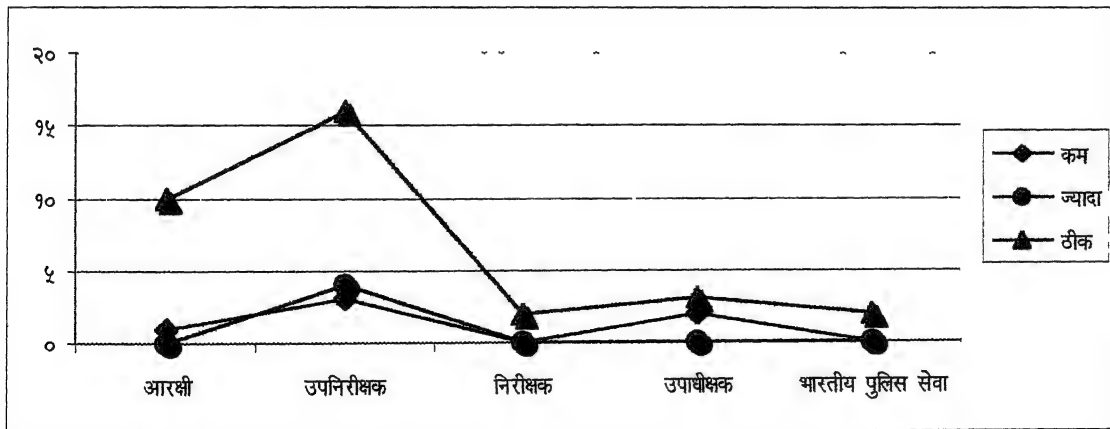
काम सौंपे जाने का मतलब है कि वह कार्य को ढग से कर पा रही है, या समाज में उसकी जरूरत है, और उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएँ उसके पद के अनुसार कार्य लिये जाते हैं। लेकिन क्या ये जो काम उनको सौंपे जाते हैं

महिला उपनिरीक्षक



- ☐ महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करवाया।
- ☒ थानाध्यक्ष या चौकी इंचार्ज के पद पर रहते हुए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य।
- ☐ किसी खास समस्या का समाधान किया।

५० प्रतिशत जिन्होंने हाँ के जवाब दिया है।



वह इनकी सामर्थ्य एव क्षमता के अनुसार होते हैं, जब ये प्रश्न उनके साथ कम करने वाले पुरुष पुलिस कर्मियों से पूछा गया तो निम्न बातें सामने आयी हैं।

सारिणी संख्या-5.8

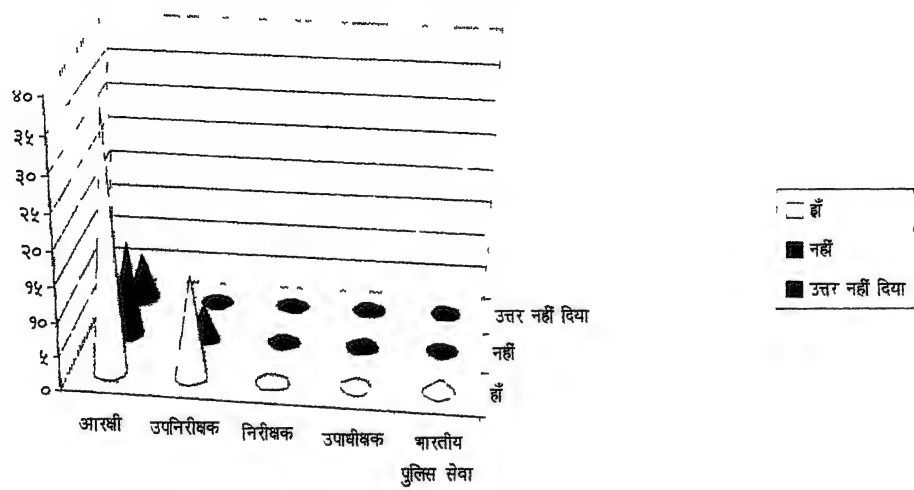
महिला पुलिस को दी गयी ड्यूटी उनकी क्षमता या सामर्थ्य के अनुरूप पुरुष पुलिस कर्मियों के विचार

क्रम	पद	कम		ज्यादा		ठीक		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	1	9	—	—	10	90.9	11	100
2	उपनिरीक्षक	3	13.04	4	17.39	16	69.5	23	100
3	निरीक्षक	—	—	—	—	2	100	2	100
4	उपाधीक्षक	2	40	—	—	3	60	5	100
5	भारतीय पुलिस सेवा	—	—	—	—	2	100	2	100
योग		6	14	4	9.30	33	77	43	100

सारिणी (संख्या 5.8) से स्पष्ट है कि 9 प्रतिशत पुरुष आरक्षी ये मानते हैं कि महिला पुलिस को दी जाने वाली ड्यूटी उनकी सामर्थ्य या क्षमता से कम होती है। 91 प्रतिशत मानते हैं कि ठीक होती है।

13 प्रतिशत पुलिस उपनिरीक्षकों का मानना है कि क्षमता से कम कर दी जाती है। 17 प्रतिशत मानते हैं क्षमता से ज्यादा दी जाती है। 70 प्रतिशत मानते हैं कि उनकी क्षमता के अनुसार ठीक ही दी जाती है। 100 प्रतिशत निरीक्षक मानते हैं कि उनकी क्षमता के अनुसार ही दी जाती है। 40 प्रतिशत उपाधीक्षक मानते हैं कि क्षमता से कम कर दी जाती है एव 60 प्रतिशत मानते हैं, ठीक दी जाती है। 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के लोग मानते हैं, कि ठीक दी जाती है।

अगर हम कुल योग देखें तो 14 प्रतिशत लोग क्षमता से कम, 9 प्रतिशत ज्यादा एव 77 प्रतिशत ठीक मानते हैं। ठीक मानने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक फिर दूसरे नम्बर पर कम और तीसरे स्थान पर ज्यादा है। इससे ये भी पता चलता है 14 प्रतिशत लोग मानते हैं कि जो ड्यूटी दी गयी है वो उससे भी अधिक कने की क्षमता रखती है। 77 प्रतिशत मानते हैं कि वो उस ड्यूटी के लिए एकदम ठीक है। 9 प्रतिशत मानते हैं, कि उनकी क्षमता उतनी नहीं है, जितनी कि ड्यूटी दी जाती है।



कुल $77 + 14 = 91$ प्रतिशत मत ये हुआ कि महिला पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में सामर्थ्य है यानि सफल है।

महिला पुलिस से ये प्रश्न किया गया कि आपके काम को कभी सराहा गया है तो इसका उत्तर विभिन्न पदों के अनुसार निम्न प्रकार से दिया।

सारिणी संख्या-5.9

महिला पुलिस कर्मियों के कार्य को कभी सराहा गया : महिला पुलिस कर्मियों का मत

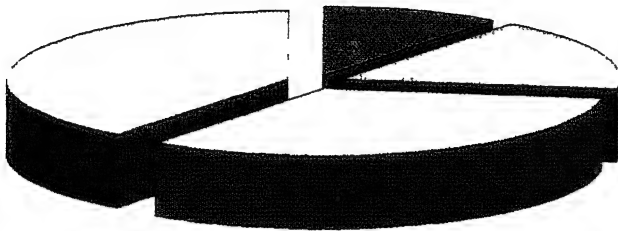
क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	37	64	14	24	7	12	58	
2	उपनिरीक्षक	15	75	5	25	—	—	20	
3	निरीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	
5	भारतीय पुलिस सेवा	2	67	1	33	—	—	3	
योग		56	67.46	20	24	7	8.43	83	

सारिणी (संख्या 5.9) से स्पष्ट है कि 67.46 महिला पुलिसकर्मी कहती हैं कि उनके कार्य को सराहा गया है जो सर्वाधिक है। 24 प्रतिशत ने माना कि उनके काम को कभी विभाग में सराहा नहीं गया है। 8.43 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

पदानुसार हाँ या नहीं को देखें तो पायेगे कि 64 प्रतिशत आरक्षियों ने हाँ, 24 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया। 12 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। हाँ का प्रतिशत इनमें भी सर्वाधिक है।

75 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने हाँ एवं 25 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। निरीक्षक और उपाधीक्षक ने 100 प्रतिशत हाँ में उत्तर दिया है। भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों में 67 प्रतिशत ने हाँ एवं 33 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है।

विभिन्न मत



- ☒ महिलाओं से सम्बन्धित दायित्व
- ☐ विभिन्न प्रकार की इयूटियों
- ☐ पद के अनुरूप सभी प्रकार के कार्य
- ☐ उत्तर नहीं दिया

सभी पदों के अनुसार उनका प्रतिशत हॉ में ही सर्वाधिक है और कुल में भी हॉ में ही अधिक उत्तर दिया है। अब जानना यह है कि पद के अनुसार इन्हें किस तरीके के कार्य करने को ज्यादा मिले हैं। यह प्रश्न महिला पुलिस से किया गया है कि विभाग से सम्बन्धित कौन-कौन से दायित्व आपको प्राप्त हुए हैं, तो पद के अनुसार विभिन्न मत प्रस्तुत किया गया है।

सबसे पहले हम महिला आरक्षियों के मतों को सारिणी के अनुसार देखेंगे।

सारिणी संख्या-5.10

विभाग से प्राप्त दायित्व : महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1.	पद के अनुरूप सभी प्रकार के कार्य	19	32.75
2	विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ	10	17.24
3	महिलाओं से सम्बन्धित दायित्व	6	10.34
4.	उत्तर नहीं दिया	23	39.65
योग		58	100

सारिणी (संख्या 5.10) के अनुसार 40 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने इस प्रश्न के उत्तर नहीं दिया है, जो कि सर्वाधिक मत है। 33 प्रतिशत ने पद के अनुरूप उन सभी प्रकार के कार्यों को किया है। 17.24 प्रतिशत ने विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों की है जैसे—मेले, रैली, वी०आइ०पी०, कुम्भ, कचेहरी, स्कूल, नाइट सेंटर, आफिस, वोट, विवादास्पद स्थानों की ड्यूटी इत्यादि। 10.34 प्रतिशत ने महिलाओं से सम्बन्धित दायित्वों को निभाया है जैसे—सुरक्षा, पेशी, डाक्टरी, गिरफ्तारी, अपराध एवं उत्पीड़न को रोकने आदि में।

अब हम महिला उपनिरीक्षकों के मत हम सारिणी से जान सकते हैं।

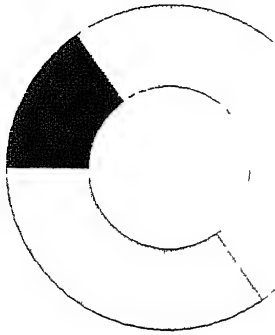
विभाग से प्राप्त दायित्व : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	पद के अनुरूप सभी प्रकार के कार्य।	8	40
2	चौकी प्रभारी एव थाना प्रभारी से सम्बन्धित सभी कार्य।	7	35
3	कुछ खास नही केवल औपचारिकता निभाई जाती है।	3	15
4	उत्तर नही दिया	2	10
योग		20	100

सारिणी (संख्या 511) से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने कहा है कि उन्होंने पद के अनुरूप सभी प्रकार के कार्य किये हैं। 35 प्रतिशत ने कहा है कि उन्होंने चौकी प्रभारी एव थाना प्रभारी के सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य किये हैं। दूसरा मत भी पहले मत में शामिल किया जा सकता है कि जो भी उन्हें पद दिया गया है उसके अनुरूप सभी विभिन्न प्रकार के कार्य किया है, इसका कुल मत (1+2 क्रम यानि 40+35=75 प्रतिशत) 75 प्रतिशत पद के अनुरूप विभिन्न दायित्व निभाये हैं। 15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने कहा है, कि कुछ खास नही केवल औपचारिकता निभाई जाती है और उन्हें अभी तक कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नही मिला है। 10 प्रतिशत महिला पुलिस ने इसका उत्तर नही दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने कहा कि उसे अपने पद के अनुरूप दायित्व प्राप्त हुए हैं सिविल पुलिस में चौकी इंचार्ज पदोन्नति से पहले फिर पी०ए०सी० में दलनायक तथा कुम्भ मेला में आर०आई० जल पुलिस आदि। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक के अनुसार अपने क्षेत्र में पद के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करने को मिले हैं।

विभिन्न मत



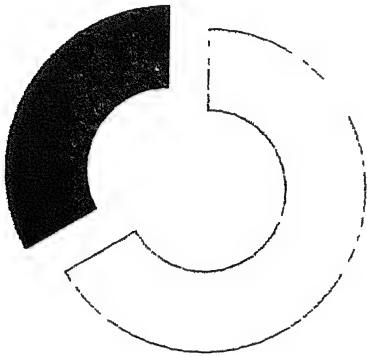
☐ पद के अनुरूप सभी प्रकार के कार्य।

☐ चौकी प्रभारी एवं थाना प्रभारी से सम्बन्धित सभी कार्य।

☒ कुछ खास नहीं केवल औपचारिकता निभाई जाती है।

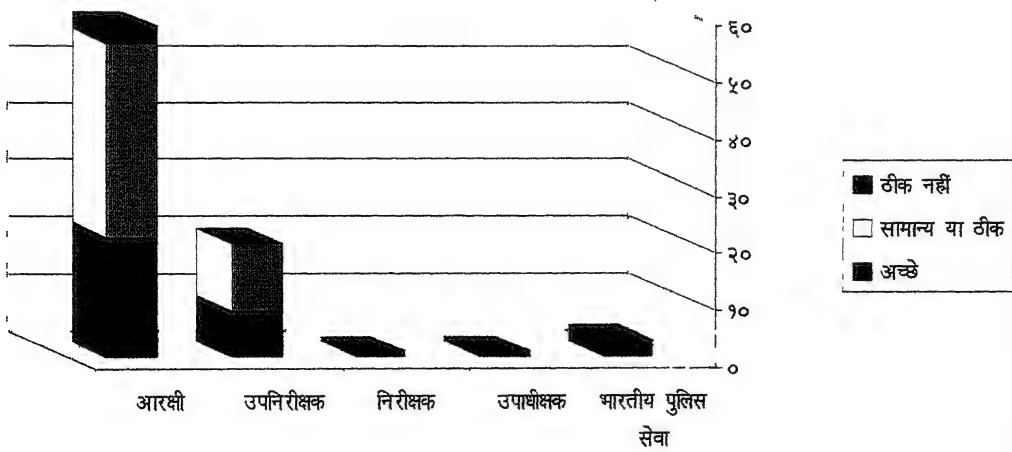
☐ उत्तर नहीं दिया

विभिन्न मत



☐ पदानुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करने को मिला है।

☒ उत्तर नहीं दिया



सारिणी संख्या-5.12

विभाग से प्राप्त दायित्व : भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों के विचार

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	पदानुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करने को मिला है।	2	67
2	उत्तर नहीं दिया	1	33
योग		3	100

सारिणी (संख्या 5 12) से स्पष्ट है कि भारतीय पुलिस सेवा की 67 प्रतिशत महिला अधिकारियों का कहना है कि उन्हें पद के अनुरूप सभी कार्य करने को मिले हैं। 33 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है।

सभी पदों के अनुसार (जिन्होंने उत्तर दिया है) इस मत का सर्वाधिक प्रतिशत है, कि पदानुसार विभिन्न कार्य करने को मिले हैं।

महिला पुलिस कर्मियों के अपने पुरुष वरिष्ठ अधिकारियों से सम्बन्ध में उनके स्वयं के विचार निम्न प्रकार से हैं।

सारिणी संख्या-5.13

अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सम्बन्ध : महिला पुलिस कर्मियों के विचार

क्रम	पद	अच्छे		सामान्य या ठीक		ठीक नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	21	36.20	34	58.62	3	5.17	58	69.87
2	उपनिरीक्षक	8	40	12	60	—	—	20	24.09
3	निरीक्षक	1	100					1	1.20
4	उपाधीक्षक	1	100					1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100					3	3.61
योग		34	40.96	46	55.42	3	3.6	83	100

सारिणी (संख्या 5 13) से स्पष्ट है कि 41 प्रतिशत महिला पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उनके सम्बन्ध अच्छे हैं, 55 प्रतिशत के सामान्य हैं एवं 36 प्रतिशत के सम्बन्ध ठीक नहीं हैं। यदि हम पदानुसार देखे तो 36 प्रतिशत आरक्षियों के अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सम्बन्ध अच्छे, 58.62 प्रतिशत के सामान्य, एवं 5 प्रतिशत के सम्बन्ध ठीक नहीं हैं। 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों के सम्बन्ध अच्छे, 60 प्रतिशत सामान्य हैं। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक, उपाधीक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे हैं। यानि कार्यक्षेत्र में सामान्यतः महिला पुलिस का अच्छा रहता है।

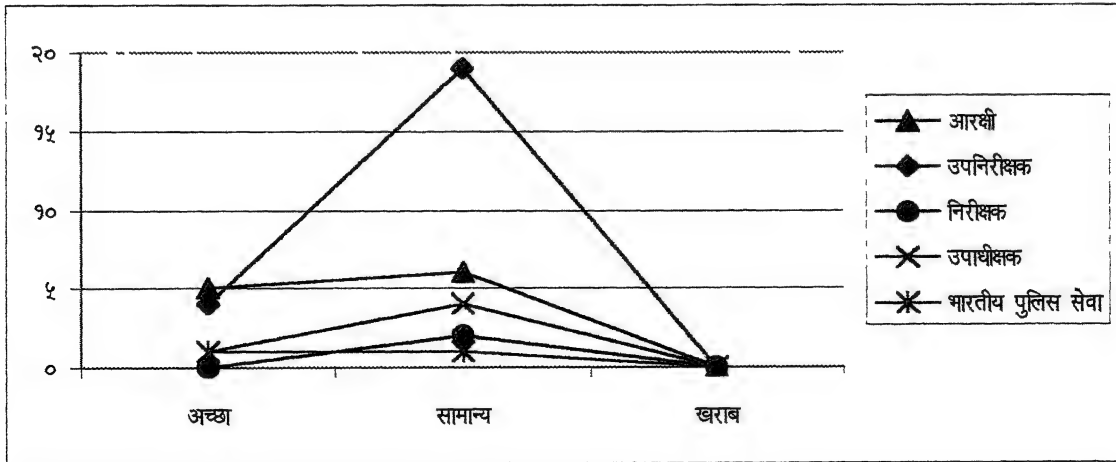
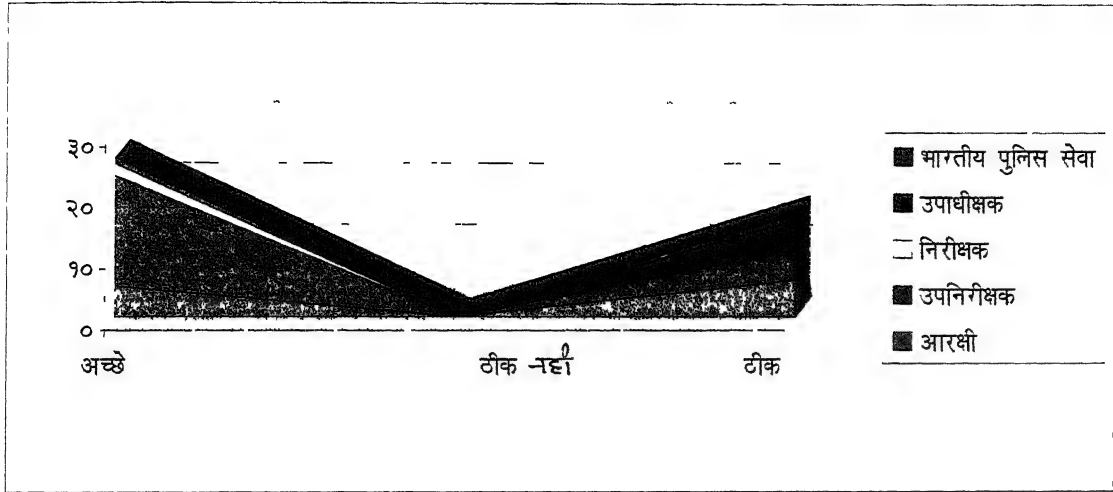
पुरुष पुलिस कर्मियों से प्रश्न किया कि सामान्यतः आपकी उच्च महिला अधिकारी का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है तो उसका उत्तर पदानुसार निम्नवत् था।

सारिणी संख्या-5.14

सामान्यतः उनकी उच्च महिला अधिकारी का व्यवहार उनके प्रति कैसा रहता है : पुरुष पुलिस कर्मियों के विचार

क्रम	पद	अच्छे		ठीक नहीं		सामान्य		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	5	45.45	—	—	6	54.54	11	25.58
2	उपनिरीक्षक	18	78.26	—	—	5	21.73	23	53.48
3	निरीक्षक	2	100	—	—	—	—	2	4.65
4	उपाधीक्षक	—	—	—	—	5	100	5	11.62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	—	—	1	50	2	4.65
योग		26	60.46	—	—	17	39.53	43	100

उपरोक्त सारिणी (संख्या 5 14) से ज्ञात होता है कि 60.46 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने अपनी उच्च महिला अधिकारी का व्यवहार अच्छा स्वीकार किया है। 40 प्रतिशत ने कहा है कि व्यवहार सामान्य रहता है न अच्छा न बुरा। हम



पदानुसार सारिणी में देखेंगे तो आरक्षियों ने 45 प्रतिशत अच्छा एवं 55 प्रतिशत ने सामान्य कहा है। पुलिस उपनिरीक्षकों ने 78 प्रतिशत अच्छा एवं 21.73 प्रतिशत यानी 22 प्रतिशत सामान्य कहा है। 100 प्रतिशत निरीक्षकों ने अच्छा एवं 100 प्रतिशत उपाधीक्षकों ने सामान्य कहा। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने अच्छा एवं 50 प्रतिशत सामान्य कहा है।

इस सारिणी से समझ सकते हैं कि महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार अपने अधीनस्थ पुरुष पुलिस कर्मियों से 60 प्रतिशत अच्छा रहता है एवं 40 प्रतिशत सामान्य यानी कार्यक्षेत्र में अपने अधीनस्थों के प्रति व्यवहार कुशल रहती हैं।

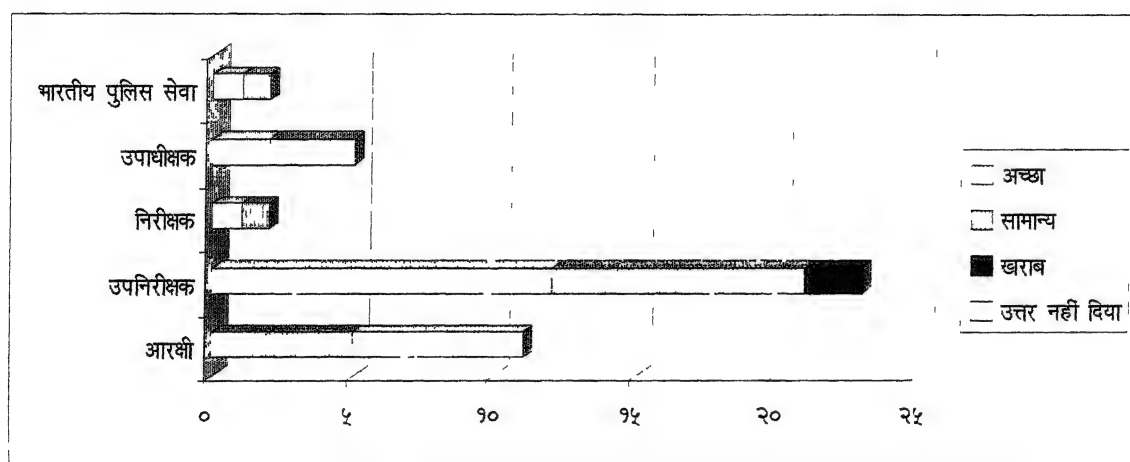
अब हम बराबर के पद पर आसीन महिला पुलिस कर्मियों के व्यवहार के बारे में जानना चाहेंगे कि अपने साथ के पुरुष पुलिस कर्मियों के प्रति कैसा रहता है।

झारिणी संख्या-5.15

अपने साथ कार्य करने वाली समान पदों की महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार: पुरुष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	अच्छा		सामान्य		खराब		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	5	45.45	6	54.54	—	—	11	25.58
2	उपनिरीक्षक	4	17.39	19	82.60	—	—	23	53.48
3	निरीक्षक	—	—	2	100	—	—	2	4.65
4	उपाधीक्षक	1	20	4	80	—	—	5	11.62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	1	50	—	—	2	4.65
योग		11	25.58	32	74.41	—	—	43	100

सारिणी (संख्या 5.15) से स्पष्ट है कि कुल 26 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों का मानना है कि साथ की समान पद पर आसीन महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार अच्छा रहता है। 74 प्रतिशत के अनुसार व्यवहार सामान्य रहता है।



पदानुसार देखे, तो 45 प्रतिशत आरक्षी अच्छा एव 55 प्रतिशत आरक्षी सामान्य व्यवहार स्वीकार करते हैं। 17 प्रतिशत उपनिरीक्षक अच्छा एव 83 प्रतिशत सामान्य कहते हैं। 100 प्रतिशत निरीक्षक सामान्य कहते हैं। 20 प्रतिशत उपाधीक्षक अच्छा एव 80 प्रतिशत सामान्य कहते हैं। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अच्छा एव 50 प्रतिशत सामान्य व्यवहार स्वीकार करते हैं।

यदि हम भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के मत 50 प्रतिशत अच्छा एव 50 प्रतिशत सामान्य को छोड़कर देखे, तो सभी पदों में 50 प्रतिशत ज्यादा मत सामान्य व्यवहार को मिला है, यानि सभी पदों में सर्वाधिक मत सामान्य को आधे से ज्यादा मिले हैं।

पुरुष पुलिस कर्मियों से जब ये प्रश्न किया कि उनके नीचे पदों पर नियुक्त महिला पुलिस का व्यवहार कैसा रहता है तो निम्न प्रकार से उत्तर प्राप्त हुए जो कि सारिणी (संख्या 5.16) से ज्ञात होता है। 37.20 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने अच्छे व्यवहार के प्रति हामी भरी है 44 प्रतिशत ने सामान्य एव 4.65 प्रतिशत यानि 5 प्रतिशत ने खराब व्यवहार एवं 13.95 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया।

सारिणी संख्या-5.16

पुरुष पुलिस कर्मियों का अपने पद से नीचे की महिला पुलिस के अपने प्रति व्यवहार पर विचार

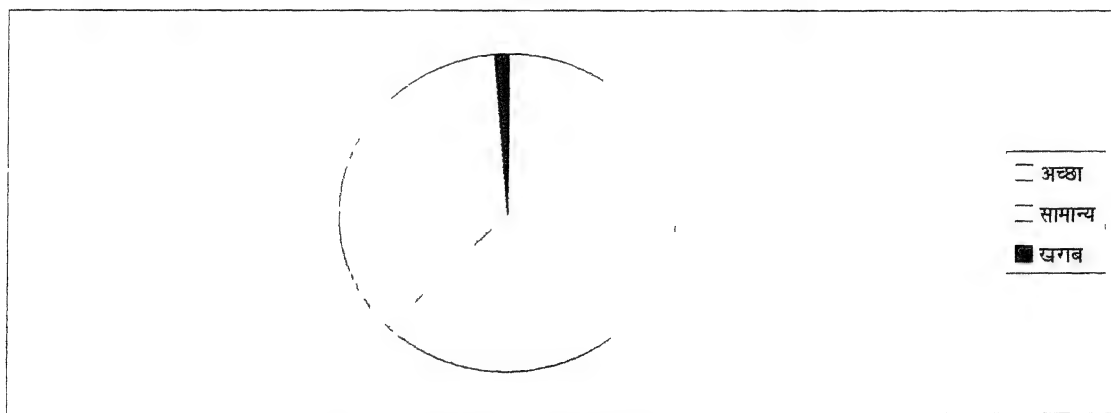
क्रम	पद	अच्छा		सामान्य		खराब		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	—	—	5	45.45	—	—	6	54.54	11	25.58
2	उपनिरीक्षक	12	52.17	9	39.13	2	8.6	—	—	23	53.48
3	निरीक्षक	1	50	1	50	—	—	—	—	2	4.65
4	उपाधीक्षक	2	40	3	60	—	—	—	—	5	11.62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	1	50			—	—	2	4.65
योग		16	37.20	19	44.18	2	4.65	6	13.95	43	100

पदानुसार हम देखेंगे तो सर्वप्रथम पुरुष आरक्षियों से जब ये प्रश्न किया गया कि आपसे नीचे के पदों पर तैनात महिला पुलिस का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है, तो 55 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है, कारण उनसे नीचे पदों की महिला पुलिसकर्मी हैं ही नहीं। 45 प्रतिशत लोगों ने सामान्य उत्तर दिया है, उसमें वो लोग हैं जो हेड कास्टेबिल या दीवान हैं। 52.17 प्रतिशत उपनिरीक्षक अच्छा व्यवहार कहते हैं, 39 प्रतिशत सामान्य एवं 9 प्रतिशत पुरुष उपनिरीक्षकों का मानना है कि उनसे नीचे पदों की महिला पुलिस का व्यवहार खराब है।

50 प्रतिशत पुरुष निरीक्षकों ने अच्छा तथा 50 प्रतिशत ने सामान्य कहा है। 40 प्रतिशत उपाधीक्षकों ने अच्छा एवं 60 प्रतिशत ने सामान्य कहा है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिसकर्मी अच्छा एवं 50 प्रतिशत सामान्य कहते हैं।

41 महिला पुलिस कर्मियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सम्बन्ध में ये कहा है, कि उनके सम्बन्ध उनसे अच्छे हैं एवं 55 प्रतिशत ने सामान्य एवं 36 प्रतिशत यानि 4 प्रतिशत ने कहा ठीक नहीं है। यह तो उनके अपने विचार हैं, दूसरी तरफ उनके उच्च पुरुष अधिकारियों का कहना है उनके नीचे पदों पर आसीन महिला पुलिस का व्यवहार अच्छा है। 37 प्रतिशत ने कहा साथ 44 प्रतिशत ने सामान्य एवं 5 प्रतिशत ने कहा ठीक नहीं है। 13.95 ने उत्तर नहीं दिया है। फिर यदि अधिकारी महिला हैं तो उसमें अधीनस्थ पुरुषों का भी मत मायने रखता है।

60 प्रतिशत पुरुष पुलिस कहते हैं कि महिला पुलिस का व्यवहार अच्छा रहता है, एवं 40 प्रतिशत कहते हैं कि सामान्य रहता है। खराब की बात नहीं की गयी है। साथ-साथ काम करने वाले एक से पदों की महिलाओं एवं पुरुषों के अपने समान स्तर के बारे में 26 प्रतिशत का कहना है कि अच्छा रहता है। 74 प्रतिशत का कहना है, कि सामान्य रहता है। खराब की बात स्वीकार नहीं की गयी है।



इन आकड़ों से पता चलता है, कि महिला पुलिस का अपने उच्च पुरुष अधिकारियों एवं उच्च पुरुष अधिकारियों का अपने अधीनस्थ महिला पुलिस कर्मियों से व्यवहार में कुछ यानि जैसा कि महिलाओं ने 4 प्रतिशत एवं पुरुषों ने 5 प्रतिशत ठीक नहीं है स्वीकार किया है। ये सम्बन्ध आरक्षी एवं उपनिरीक्षक स्तर पर ही है, लेकिन है। परन्तु महिला पुलिस यदि उच्च पद पर है तो उसके अधीनस्थों से उसका सम्बन्ध खराब नहीं है। एक समान पद पर पुरुष एवं महिला पुलिस कर्मियों का आपस में भी व्यवहार काफी हद तक अच्छा है।

इसके अलावा अब हम सामान्य जनता से जब पूछते हैं कि महिला पुलिसकर्मी का व्यवहार पुरुष पुलिसकर्मी की अपेक्षा कैसा रहता है, तो निम्न तथ्य सामने आते हैं।

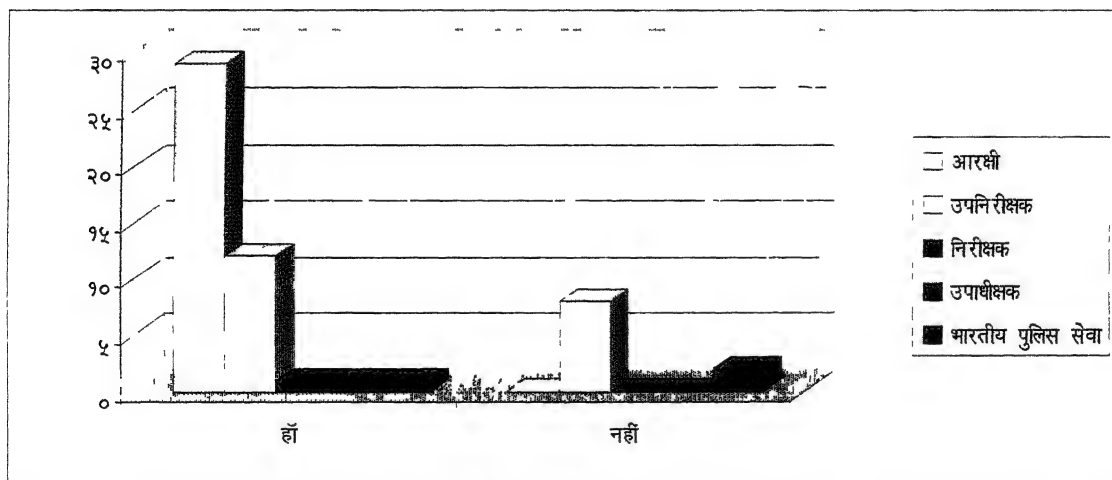
सारणी संख्या-5.17

महिला पुलिस का व्यवहार पुरुष पुलिस की अपेक्षा कैसा रहता है : सामान्य सूचनादाताओं का मत

क्रम	अच्छा		समान		खराब		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	48	62 33	28	36 36	1	1 2	77	100

सारणी (संख्या 5.17) से स्पष्ट है कि सामान्य जनता जिसमें विभिन्न नौकरियों एवं व्यवसायों से जुड़े महिला एवं पुरुष हैं। उनका मानना है कि महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा अच्छा है। इसे 62 प्रतिशत मानते हैं। पुरुषों के समान ही व्यवहार को 36 प्रतिशत लोग मानते हैं। 1 प्रतिशत लोग इनका व्यवहार पुरुषों की अपेक्षा भी खराब मानते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत अच्छे का है जो आधे से भी ज्यादा है। यानि काफी हद तक इनका व्यवहार ठीक रहता है। इस सारिणी से भी ज्ञात होता है

एक प्रश्न महिला पुलिस से पूछा गया है कि पुरुषों के व्यवहार में आपके प्रति कोई परिवर्तन आया है तो इसका उत्तर पदानुसार इस प्रकार है।

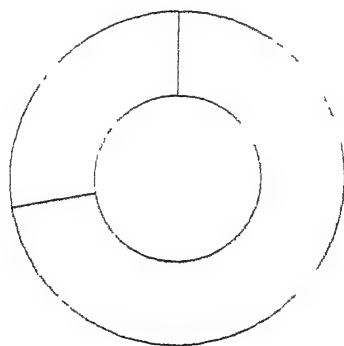


पुरुषों के व्यवहार में उनके प्रति कोई परिवर्तन आया है : महिला पुलिस कर्मियों के विचार

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	29	50	29	50	58	69.87
2	उपनिरीक्षक	12	60	8	40	20	24.09
3	निरीक्षक	1	100	—	—	1	1.20
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33	2	67	3	3.61
योग		44	53	39	46.98	83	100

सारिणी (संख्या 5.18) से ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि पुरुषों के व्यवहार में उनके प्रति बदलाव आया है। 50 प्रतिशत मानती है कि कोई बदलाव नहीं आया है। 60 प्रतिशत उपनिरीक्षक हाँ में एव 40 प्रतिशत नहीं में उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक एव महिला उपाधीक्षक हाँ में उत्तर देती है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी हाँ में एव 67 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है।

कुल प्रतिशत देखे तो 53 प्रतिशत महिला पुलिस ने हाँ में एव 47 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। इन आकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि काफी हद तक बदलाव आया है पर पूरी तरह से नहीं, फिर भी महिला पुलिस कर्मियों के प्रति पुरुषों के व्यवहार में जो भी बदलाव आया है, उसमें कुछ प्रभाव शायद पुलिस विभाग की होने की वजह से भी आया है, क्योंकि जब साधारण जन से ये पूछा गया कि अन्य विभाग की महिलाओं की अपेक्षा पुलिस विभाग की महिला में क्या कोई खास अन्तर पाते हैं तो साधारण जन के पुरुषों का निम्न उत्तर था।



<input type="checkbox"/>	हाँ
<input type="checkbox"/>	नहीं

सारिणी संख्या-5.19

**पुलिस विभाग की महिला में अन्य विभाग की महिला की
अपेक्षा अन्तर होता है ? : सामान्य जन सूचनादाताओं
(केवल पुरुषों का) मत**

क्रम	हाँ		नहीं		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	44	72.13	17	27.86	61	100

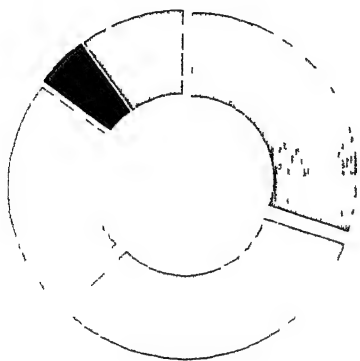
सारिणी (संख्या 5.19) से स्पष्ट होता है कि 72.13 प्रतिशत सामान्य जन के पुरुषों का मानना है कि पुलिस विभाग की महिलाओं और अन्य विभाग की महिलाओं में अन्तर पाया जाता है। 28 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि कोई अन्तर नहीं है। 72.13 लोगों में अधिकतर लोगों ने इसका कारण भी बताया है, जो इस प्रकार से है।

सारिणी संख्या-5.20

**सामान्य जन सूचनादाताओं के पुरुषों का मत : पुलिस
विभाग की महिला एवं अन्य विभाग की महिला में
अन्तर का कारण**

क्रम	विभिन्न विचार	संख्या	प्रतिशत
1.	व्यवहार में अन्तर रहता है।	12	30
2.	कठिन परिश्रमी होती हैं।	13	32.5
3.	अधिक निडर एवं साहसी हैं।	9	22.5
4.	हीनता बोध की ग्रंथि पुरुष प्रधानता के कारण	2	5
5.	इस विभाग की महिला को उचित सम्मान नहीं मिलता	4	10
योग		40	100

विभिन्न विचार



☐ व्यवहार में अन्तर रहता है।

☐ कठिन परिश्रमी होती हैं।

☐ अधिक निडर एवं साहसी हैं।

☒ हीनता बोध की ग्रंथि पुरुष प्रधानता के कारण

☐ इस विभाग की महिला को उचित सम्मान नहीं मिलता

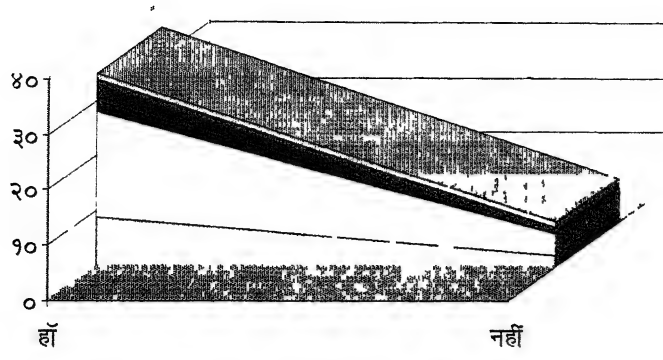
सारिणी (संख्या 520) से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 325 या 33 प्रतिशत लोगो ने कहा कि महिला पुलिस कठिन परिश्रमी होती है। 30 प्रतिशत लोगो ने कहा कि उनके व्यवहार मे अन्तर होता है यानि उनके अन्दर औरतो से अलग व्यवहार होता हे जैसे उठना, चलना, बातचीत का अन्दाज जिससे कभी-कभी लगता है, कि रूखा व्यवहार या शिष्टाचार का अभाव है। 225 लोगो ने कहा कि ये अधिक निडर एव साहसी है। 10 प्रतिशत लोगो ने कहा कि इस विभाग की महिला को उचित सम्मान नही मिलता है एव 5 प्रतिशत ने कहा कि इस विभाग की महिलाओ मे हीनता बोध की ग्रथि पायी जाती है, क्योकि पुरुष प्रधान विभाग है।

पुरुष पुलिस कर्मियो से पूछा गया कि साधारण महिला मे और महिला पुलिस मे आपको कोई अन्तर मिलता है (स्वभाव मे) तो निम्न उत्तर प्राप्त हुए।

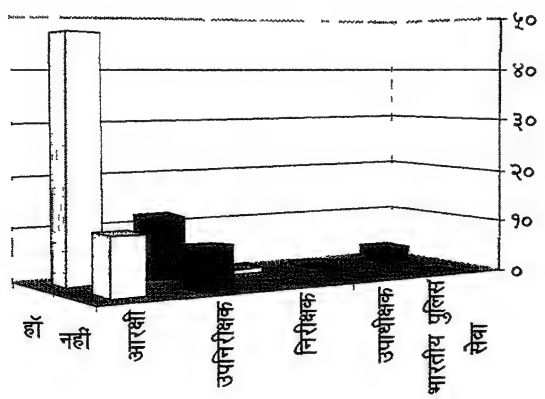
सारिणी संख्या-5.21

पुरुष पुलिस कर्मियों का मत : साधारण महिला एवं महिला पुलिस में स्वभाव सम्बन्धी क्या कोई अन्तर पाते हैं ?

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	9	81.81	2	18.18	11	25.58
2	उपनिरीक्षक	19	82.60	4	17.39	23	53.48
3	निरीक्षक	2	100	—	—	2	4.65
4	उपाधीक्षक	4	80	1	20	5	11.62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	1	50	2	4.65
योग		35	81.39	8	18.60	43	100



- भारतीय पुलिस सेवा
- उपाधीक्षक
- निरीक्षक
- उपनिरीक्षक
- आरक्षी



- आरक्षी
- उपनिरीक्षक
- निरीक्षक
- उपाधीक्षक
- भारतीय पुलिस सेवा

सारिणी (संख्या 521) से ज्ञात होता है कि 81.39 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी मानते हैं कि साधारण महिला एवं महिला पुलिस में अन्तर है। 19 प्रतिशत मानते हैं कि कोई मिलता नहीं है।

पदानुसार देखें तो 82 प्रतिशत आरक्षियों ने हाँ एवं 18 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 83 प्रतिशत उपनिरीक्षकों ने हाँ एवं 17 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत निरीक्षक 'हाँ' में उत्तर देते हैं। 80 प्रतिशत उपाधीक्षक हाँ एवं 20 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने हाँ में एवं 50 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है।

50 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है कि पुरुषों के व्यवहार में उनके प्रतिशत बदलाव आया है तो बदलाव के कारण के रूप में हमने ये देखा कि साधारण जन के 72 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि पुलिस विभाग की महिलाओं एवं अन्य विभाग की महिलाओं में अन्तर होता है, जब अन्तर मान रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यवहार भी परिवर्तित होगा (पुरुषों का इस विभाग की महिलाओं के प्रति) दूसरी तरफ 81 प्रतिशत पुरुष पुलिस का भी मानना है कि महिला पुलिस एवं साधारण महिलाओं के स्वभाव में अन्तर पाया जाता है।

इन आकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 50 प्रतिशत महिला पुलिस का मानना लगभग सही ही है।

महिला पुलिस कर्मियों से प्रश्न किया कि क्या आप वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट हैं तो इसका उत्तर निम्न प्रकार से पदानुसार दिया है जैसा कि सारिणी (संख्या 522) से ज्ञात होता है।

आदिणी संख्या-5.22

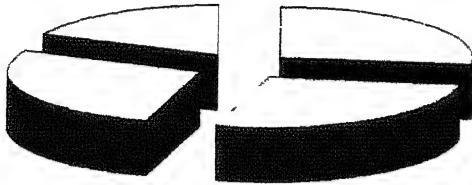
क्या सूचनादाता स्वयं अपनी वर्तमान सेवा से संतुष्ट हैं ? : महिला पुलिस कर्मियों के विचार

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	47	81	11	18.96	58	69.87
2	उपनिरीक्षक	12	60	8	40	20	24.09
3	निरीक्षक	1	100	—	—	1	1.20
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	—	—	3	3.61
योग		64	77.10	19	22.89	83	100

81 प्रतिशत महिला आरक्षियों का मानना है कि वे अपनी वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट हैं एवं 19 प्रतिशत ने कहा कि वे सन्तुष्ट नहीं हैं। 60 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती हैं कि वे वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट हैं एवं 40 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक, उपाधीक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारियों ने कहा कि वे वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट हैं। इन्होंने नहीं में उत्तर नहीं दिया है। सर्वाधिक 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने नहीं में उत्तर दिया है।

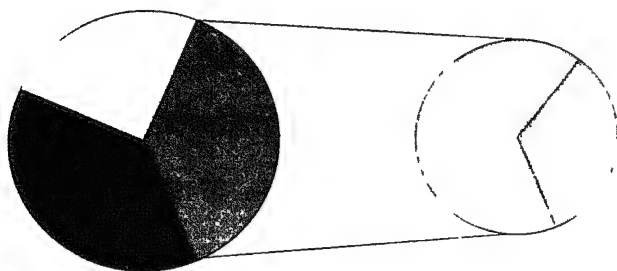
19 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने वर्तमान सेवा से असन्तुष्टि दर्शायी है उसके निम्न कारण बताये हैं।

विभिन्न विचार



- ☐ अधिकारियों का सहयोग न मिलना
- ☐ छोटे कर्मचारियों का शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता है
- ☐ समयअभाव के कारण परिवार पर ध्यान न दे पाना
- ☐ पदोन्नति के उचित अवसर न प्राप्त होना

विभिन्न विचार



☒ महिला पुलिस के प्रति विभाग का रवैया सही नहीं है

☐ पदोन्नति समय से नहीं मिलती है

☐ जो कार्य करना चाहती हूँ नहीं कर पाती हूँ

☐ अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है

सारिणी संख्या-5.23

वर्तमान सेवा से असन्तुष्टि के कारण : महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार	संख्या	प्रतिशत
1	अधिकारियों का सहयोग न मिलना	3	27 27
2	छोटे कर्मचारियों का शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता है	3	27 27
3	समयाभाव के कारण परिवार पर ध्यान न दे पाना	3	27 27
4	पदोन्नति के उचित अवसर न प्राप्त होना	2	18 18
योग		11	100

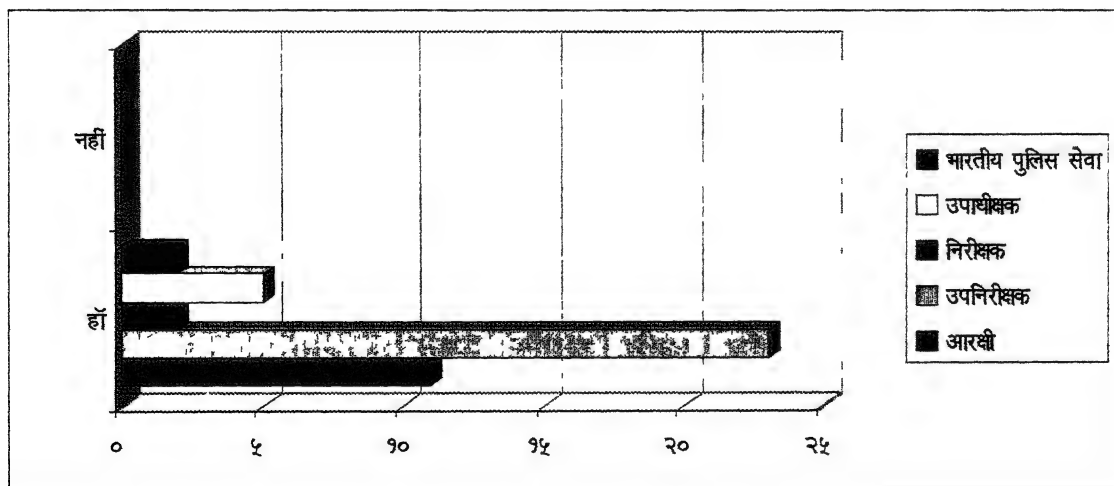
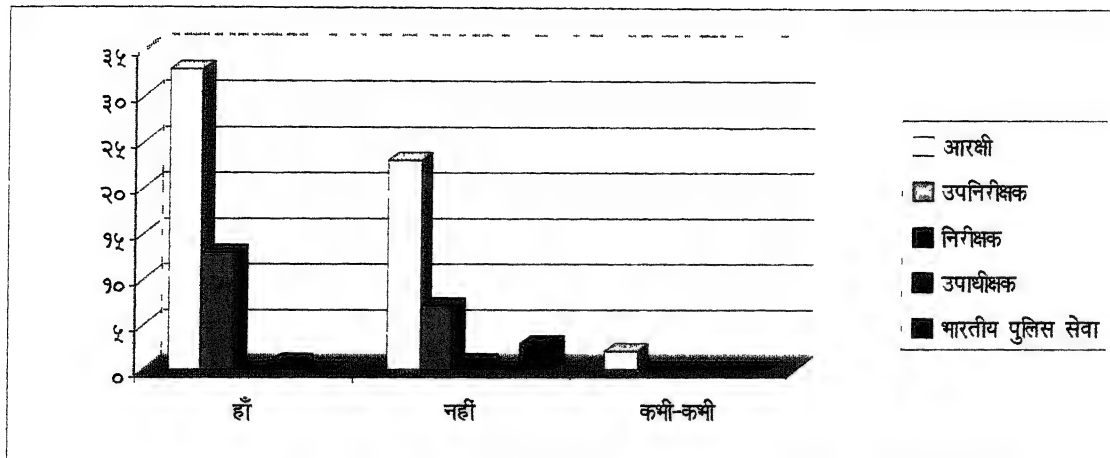
सारिणी (संख्या 523) से स्पष्ट है कि 27 प्रतिशत महिला आरक्षियों का मानना है कि अधिकारियों से सहयोग नहीं मिलता है। 27 प्रतिशत का मानना है कि छोटे कर्मचारियों का शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता है। 27 प्रतिशत का कहना है कि समय के अभाव के कारण परिवार पर उचित ढंग से ध्यान नहीं दे पाती है। 18 प्रतिशत का कहना है कि पदोन्नति के उचित अवसर नहीं प्राप्त होते हैं।

40 प्रतिशत उपनिरीक्षकों ने वर्तमान सेवा के असंतोष व्यक्त किया है उसके निम्न कारण भी बताये हैं।

सारिणी संख्या-5.24

वर्तमान सेवा से असंतुष्टि के कारण : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न विचार	संख्या	प्रतिशत
1	महिला पुलिस कर्मियों के प्रति विभाग का रवैया सही नहीं है	3	37 5
2	पदोन्नति समय से नहीं मिलती है	2	25
3	जो कार्य करना चाहती हूँ नहीं कर पाती हूँ	2	25
4	अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है	1	12.5
योग		8	100



सारिणी (संख्या 524) से स्पष्ट है कि 37.5 प्रतिशत महिला पुलिस का कहना है कि महिला पुलिस के प्रति विभाग का रवैया सही नहीं है यानि उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, और कार्यक्षमता का आकलन महिला होने के कारण कम हो जाता है। पुलिस में आना पुलिस के ही अधिकारी मजबूरी में आना समझते हैं। इस विभाग में महिला की योग्यता का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो रहा है। 25 प्रतिशत महिला पुलिस का कहना है कि पदोन्नति समय से नहीं मिलती (21 साल या इससे भी अधिक समय में) है। 25 प्रतिशत महिला पुलिस का मानना है कि वे जो करना चाहती हैं वह नहीं कर पाती हैं क्योंकि राजनैतिक हस्तक्षेप और कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारीगणों (पुरुष) का हाथ न्यायपूर्ण कार्यवाही करने में दबाव और हस्तक्षेप के कारण। 12.5 प्रतिशत महिला का मानना है कि अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है।

महिला पुलिस से पूछा गया कि ड्यूटी के दौरान क्या कभी किसी तरह का अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो निम्न प्रकार से उत्तर प्राप्त हुए हैं।

सारिणी संख्या-5.25

ड्यूटी के दौरान किसी तरह का अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है ? : महिला पुलिस का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कभी-कभी		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	आरक्षी	33	56.89	23	39.65	2	3.44	58	69.87
2.	उपनिरीक्षक	13	65	7	35	—	—	20	24.09
3.	निरीक्षक	—	—	1	100	—	—	1	1.20
4.	उपाधीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	1.20
5.	भारतीय पुलिस सेवा	—	—	3	100	—	—	3	3.61
योग		47	56.62	34	40.96	2	2.40	83	100

सारिणी (संख्या 5.25) से पता चलता है कि 57 प्रतिशत महिला आरक्षियों का मानना है कि ड्यूटी के दौरान कभी किसी भी तरह का अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। 3.44 प्रतिशत ने कहा कभी-कभी ऐसा होता है, 40 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 65 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने हाँ में एव 35 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने नहीं में एव 100 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक ने हाँ में उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी ने नहीं में उत्तर दिया है।

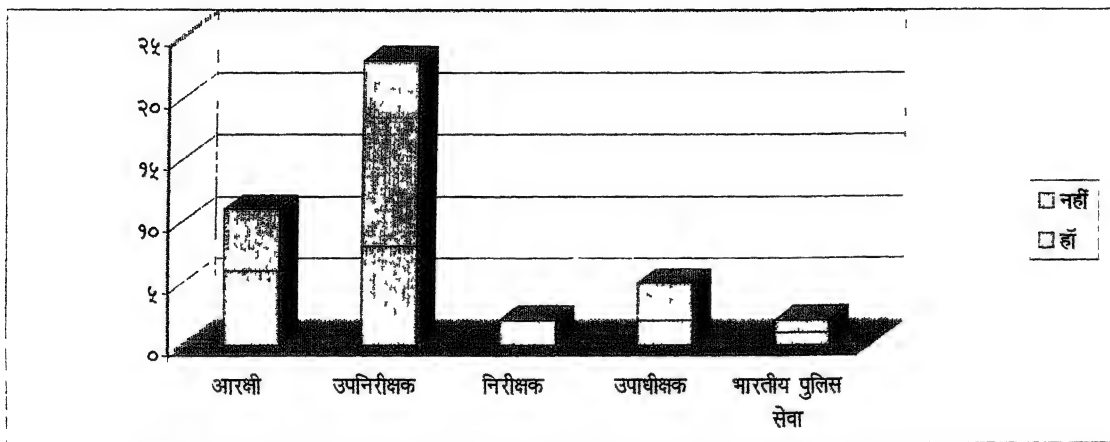
यदि हम कुल प्रतिशत देखें तो 57 प्रतिशत महिला पुलिस ने हाँ में उत्तर दिया है, 41 प्रतिशत ने नहीं में एव 2 प्रतिशत कभी-कभी माना है। आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि ड्यूटी के दौरान अपमान जनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

अब हम पुरुष पुलिस कर्मियों से जानना चाहते हैं कि क्या वे अगर उनकी उच्च अधिकारी कोई महिला है तो उसको पुरुष अधिकारी की भाँति ही सम्मान दे पाते हैं या नहीं, इसमें कार्यक्षेत्र पर महिला पुलिस की स्थिति का पता चलेगा। इस प्रश्न का उत्तर पुरुष पुलिस कर्मियों ने इस प्रकार से दिया है जो सारिणी (संख्या 5.26) से पता चलता है।

सारिणी संख्या-5.26

अपनी उच्च महिला अधिकारियों को वैसा ही सम्मान दे पाते हैं जैसा कि पुरुषों को : पुरुष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	11	100	—	—	11	25.58
2	उपनिरीक्षक	23	100	—	—	23	53.48
3.	निरीक्षक	2	100	—	—	2	4.65
4	उपाधीक्षक	5	100	—	—	5	11.62
5	भारतीय पुलिस सेवा	2	100	—	—	2	4.65
योग		43	100	—	—	43	100



जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है कि सभी पदों के पुरुष पुलिसकर्मी अपनी महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के समान ही सम्मान देते हैं। कुछ पुरुष उपनिरीक्षकों का कहना है कि अपेक्षाकृत ज्यादा सम्मान देते हैं। साथ ही कुछ पुलिस आरक्षियों का भी कहना है कि पुलिस अधिकारियों से अधिक सम्मान देना पड़ता है क्योंकि किसी भी मामले में काफी भावुक हो जाती है।

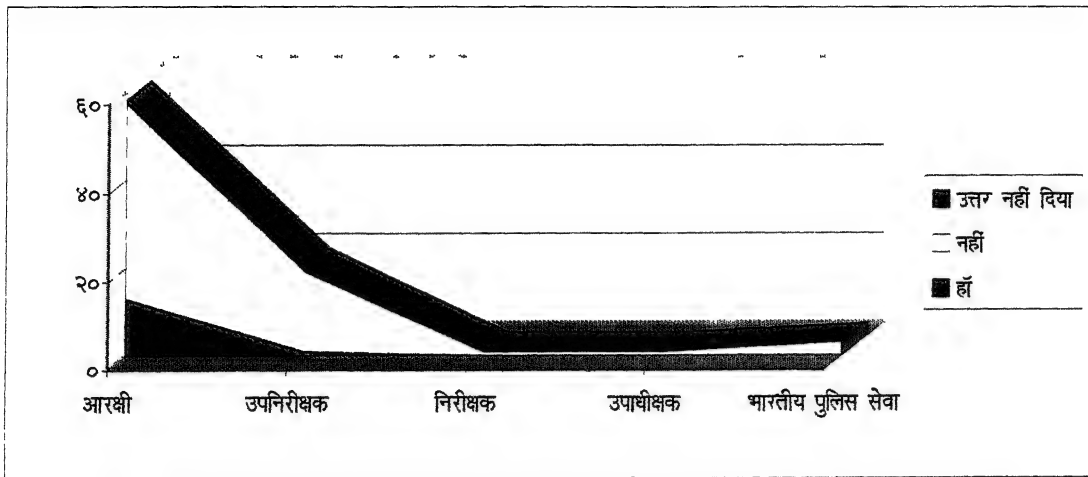
महिला पुरुष पुलिस कर्मियों के आपस के तालमेल में एक प्रश्न ये भी पुरुष पुलिस कर्मियों से पूछा गया कि क्या पुरुष पुलिस कर्मियों के व्यवहार में कोई नियंत्रण लगता है महिला पुलिस की उपस्थिति में तो इस प्रश्न के उत्तर पदानुसार इस प्रकार से हैं।

सारिणी संख्या-5.27

महिला पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में पुरुष पुलिस कर्मियों के व्यवहार में नियंत्रण लगता है ? : पुरुष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	6	54.54	5	45.45	11	25.58
2	उपनिरीक्षक	8	34.78	15	65.21	23	53.48
3	निरीक्षक	2	100	—	—	2	4.65
4	उपाधीक्षक	2	40	3	60	5	11.62
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	1	50	2	4.65
योग		19	44.18	24	55.81	43	100

सारिणी (संख्या 5.27) से पता चलता है कि 55 प्रतिशत पुरुष आरक्षी मानते हैं महिला पुलिस की उपस्थिति से उनके व्यवहार में नियंत्रण लगता है। 45 प्रतिशत ने कहा कि उनके व्यवहार में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। 35 प्रतिशत महिला



उपनिरीक्षको का मानना है कि उनके व्यवहार में नियंत्रण लगता है। 65 प्रतिशत का मानना है कि उनके व्यवहार में नियंत्रण नहीं लगता है। 100 प्रतिशत पुरुष निरीक्षको का मानना है कि उनके व्यवहार में नियंत्रण लगता है। 40 प्रतिशत उपधीक्षको का मानना है कि उनके व्यवहार में नियंत्रण लगता है। 60 प्रतिशत का मानना है कि नियंत्रण नहीं लगता है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हों में एव 50 प्रतिशत नहीं में उत्तर देते हैं।

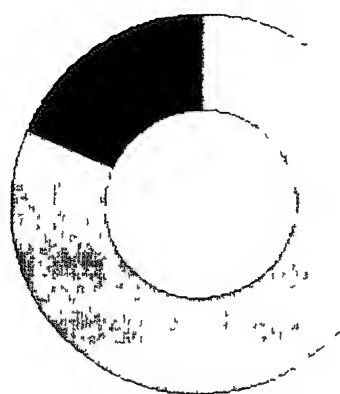
कुल 44 प्रतिशत का मानना है कि महिला पुलिस के उपस्थिति में उनके व्यवहार में नियंत्रण लगता है, एव 56 प्रतिशत का कहना है कि नियंत्रण नहीं लगता है, पहले की भाँति ही रहता है।

महिला पुलिस से पूछा गया कि क्या आपकी भाषा में परिवर्तन या अपशब्द का प्रयोग करना बढ़ जाता है तो इस पद पदानुसार इस प्रकार से जबाब मिले हैं।

साटिणी संख्या-5.28

उनकी स्वयं की भाषा में परिवर्तन या अपशब्द का प्रयोग करना बढ़ जाता है : महिला पुलिस के विचार

क्रम	पद	हों		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	13	22.41	44	75.86	1	1.72	58	69.87
2.	उपनिरीक्षक	1	5	18	90	1	5	20	24.09
3	निरीक्षक	—	—	1	100	—	—	1	1.20
4.	उपाधीक्षक	—	—	1	100	—	—	1	1.20
5.	भारतीय पुलिस सेवा	—	—	3	100	—	—	3	3.61
योग		14	16.86	67	80.72	2	2.40	83	100



□ हाँ
■ नहीं

सारिणी (संख्या 528) से स्पष्ट है कि 22 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने हाँ में उत्तर दिया है एवं 76 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 2 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। 5 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने हाँ में एवं 90 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 5 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक, 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक एवं 100 प्रतिशत उपाधीक्षक एवं 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों ने नहीं में उत्तर दिया है।

कुल 17 प्रतिशत महिला पुलिस ने अपनी भाषा में परिवर्तन या अपशब्दों का प्रयोग करना बढ़ जाता है स्वीकार किया है। 81 प्रतिशत महिला पुलिस ने नहीं में उत्तर दिया है एवं 2 प्रतिशत ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

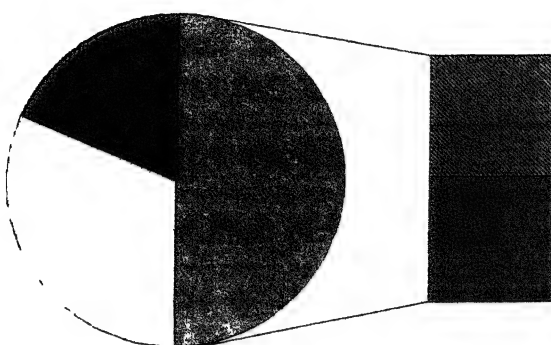
पुरुष पुलिस कर्मियों से पूँछा गया कि साधारण महिला के एवं महिला पुलिस में क्या कोई अन्तर दिखाई देता है स्वभाव, में 81 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया था। इसी तरह साधारण जन के पुरुषों से पूँछा गया तो 72 प्रतिशत हाँ एवं 28 प्रतिशत ने नहीं कहा। 72 प्रतिशत ने हाँ कहा है उसमें 30 प्रतिशत ने कहा कि उनके व्यवहार में अन्तर आ जाता है जैसे—उठना, बैठना, बातचीत का अन्दाज सब कुछ न कुछ प्रभावित हो जाता है। साधारण जन की महिलाओं से पूँछा गया कि अन्य विभाग की महिलाओं की अपेक्षा पुलिस विभाग की महिला में क्या कोई खास अन्तर पाते हैं तो निम्न उत्तर मिला।

सारिणी संख्या-5.29

**अन्य विभाग की महिला एवं पुलिस विभाग की महिला
में क्या कोई खास अन्तर पाती हैं ? : सामान्य
सूचनादाताओं की महिलाओं का मत**

क्रम	हाँ		नहीं		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	13	81 25	3	18 75	16	100

विभिन्न विचार



- महिलाओं के उत्पीड़न एवं शोषण को गंभीरता से ज़्यादा मददगार सिद्ध होती है
- वे कठिन परिश्रमी होती हैं
- अधिक निडर एवं साहसी होती हैं
- बातचीत का ढंग बदल जाता है अधिकांशतः अपशब्दों का प्रयोग भी करती हैं।

सारिणी (सख्या 5 29) से स्पष्ट है कि 81 25 प्रतिशत ने हाँ एवं 19 प्रतिशत ने नहीं मे उत्तर दिया है। जिन्होने हाँ कहा है उन्होंने अन्तर भी बताया है जो निम्न प्रकार से है।

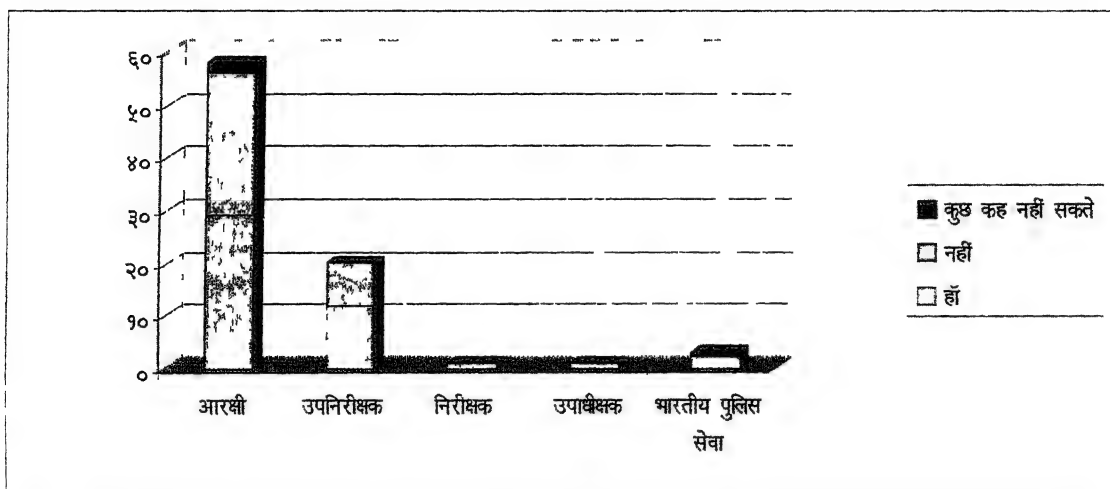
सारिणी संख्या-5.30

महिला पुलिस की अन्य विभाग की महिलाओं से अन्तर होने के विभिन्न कारण : सामान्य सूचनादाताओं (केवल महिलाओं) का मत

क्रम	विभिन्न विचार	कुल	
		सख्या	प्रतिशत
1	महिलाओ के उत्पीडन एव शोषण को राकेने मे ज्यदा मददगार सिद्ध होती है	5	31 25
2	वे कठिन परिश्रमी होती हैं	3	18 75
3	अधिक निडर एव साहसी होती है	4	25
4	बातचीत का ढग बदल जाता है अधिकाशत अपशब्दो का प्रयोग भी करती हैं।	4	25
योग		16	100

सारिणी (सख्या 5 30) से स्पष्ट है कि 25 प्रतिशत सामान्य सूचनादाताओ की महिलाए मानती है कि उनकी भाषा मे परिवर्तन आ जाता है।

महिला पुलिस स्वय 17 प्रतिशत मानती हैं, कि उनकी भाषा के परिवर्तन या अपशब्दों का प्रयोग बढ जाता है। साधारण जन के पुरुषों मे 30 प्रतिशत पुरुष मानते है कि उनके व्यवहार एव भाषा में अन्तर आ जाता है। सामान्यजन की महिला मे 25 प्रतिशत महिला मानती है, कि उनकी भाषा मे परिवर्तन आ जाता है। साथ काम करने वाली पुरुष सहकर्मी भी 81 प्रतिशत मानते है कि साधारण महिला एव महिला पुलिस के स्वभाव मे अन्तर होता है यानि पुलिस विभाग की नौकरी की वजह से उनके स्वभाव व भाषा में परिवर्तन आ जाता है।



महिला पुलिस से पूछा कि क्या अपराधों के प्रति आपका व्यवहार पुरुष पुलिसकर्मी के अपेक्षा अलग रहता है ? तो पदानुसार निम्न उत्तर प्राप्त हुए हैं।

सारिणी संख्या-5.31

महिला पुलिस का व्यवहार अपराधी के प्रति पुरुष पुलिस की अपेक्षा क्या अलग रहता है : महिला पुलिस का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुछ कह नहीं सकते		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	आरक्षी	29	50	27	46.55	2	3.44	58	69.87
2	उपनिरीक्षक	12	60	8	40	—	—	20	24.09
3.	निरीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	1.20
4.	उपाधीक्षक	—	—	1	100	—	—	1	1.20
5.	भारतीय पुलिस सेवा	2	66.66	—	—	1	33.33	3	3.61
योग		44	53	36	43.37	3	3.6	83	100

सारिणी (संख्या 53) से पता चलता है कि 50 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती हैं कि उनका व्यवहार पुरुषों से अलग रहता है एवं 47 प्रतिशत कहती हैं कि पुरुषों के समान रहता है। 3 प्रतिशत कहती हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं, कि उनके समान रहता है या अलग।

60 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों का मानना है कि उनका व्यवहार अपराधी के प्रति पुरुष पुलिस की अपेक्षा अलग रहता है। 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक कहती हैं कि उनसे अलग नहीं होता है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक का कहना है, कि 'हाँ' उनका व्यवहार अपराधी के प्रति अलग रहता है पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक का मानना है कि उनका व्यवहार पुरुष पुलिस से अलग नहीं रहता है।

67 भारतीय सवेा की महिला अधिकारियों का मानना है कि उनका व्यवहार पुरुषों की अपेक्षा अलग रहता है एवं 33 प्रतिशत ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते कि पुरुषों के समान ही रहता है या अलग।

कुल 53 प्रतिशत महिला पुलिस का मानना है कि अपराधी के प्रति उनका व्यवहार पुरुष पुलिस की अपेक्षा अलग रहता है एवं 43 प्रतिशत का मानना है कि अलग नहीं रहता है एवं 4 प्रतिशत कहती है कि वो बता नहीं सकती कि उनकी समान रहता है या अलग।

जिन 53 प्रतिशत महिलाओं ने माना है कि अपराधी के प्रति उनका व्यवहार पुरुष पुलिस की अपेक्षा अलग रहता है तो वा अलग केवल इस आधार पर मानती है कि पूँछ-तौँछ करने के तरीके में अन्तर होता है और बिना ज्यादा हिंसा का सहारा लिए कार्य करती है, और जहाँ तक सजा दिलाने की कोशिश में वह पुरुष की तरह कार्य करती है केवल डील करने के तरीके में अन्तर है।

अध्याय—६

महिला पुलिस की समस्याएँ

(Problems of Female Police)

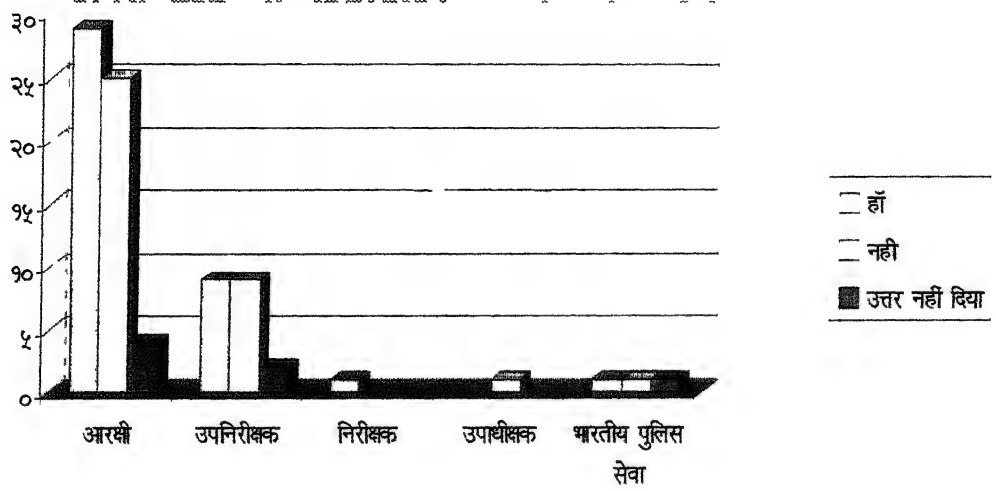
प्रस्तुत अध्याय मे 'साक्षात्कार अनुसूची' मे समावेशित चयनित प्रश्नों से प्राप्त तथ्यों का वर्णन तथा विश्लेषण किया गया है।

महिला पुलिस से एक प्रश्न किया कि कर्तव्य पालन मे आप क्या कोई तनाव व दबाव, भ्रष्टाचार जैसे कारणों से महसूस करती है तो उनका पदानुसार उत्तर निम्नवत् है—

सारणी संख्या—6.1

कर्तव्य पालन में तनाव या दबाव भ्रष्टाचार जैसे कारणों से महसूस करती है: महिला पुलिस का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल
		सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	
1	आरक्षी	29	50	25	43	4	6.8	58
2	उपनिरीक्षक	9	45	9	45	2	10	20
3	निरीक्षक	1	100	—	—	—	—	1
4	उपाधीक्षक	—	—	1	100	—	—	1
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33.3	1	33.3	1	33.3	5
	कुल	40	48	36	43	7	8.43	83



जो सारिणी (संख्या 61) से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत महिला आरक्षीयो ने कर्तव्य पालन में दबाव व तनाव महसूस किया है। 43 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 7 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। 45 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षको ने हाँ में, 45 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है एवं 10 प्रतिशत उत्तर नहीं दिया है। 100 प्रतिशत निरीक्षक ने हाँ एवं 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक ने नहीं में उत्तर दिया है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी ने हाँ, 33 प्रतिशत ने नहीं में एवं 33 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है।

कुल 48 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों ने हाँ में उत्तर दिया है, 43 प्रतिशत नहीं में एवं 8 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है।

महिला पुलिस से ये जानकारी ली गयी कि क्या इस विभाग की महिला के विवाह में क्यो कोई खास दिक्कत होती है। तो पदानुसार अपने विचार व्यक्त किये है।

सारिणी संख्या-6.2

इस विभाग की महिला में विवाह में क्या कोई खास दिक्कत होती है ? : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	आरक्षी	28	48.27	21	36.20	9	15.54	58
2	उपनिरीक्षक	13	65	3	15	4	20	20
3	निरीक्षक	1	100	—	—	—	—	1
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	—	—	1
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33	2	67	—	—	5
	कुल	44	53	26	31.32	13	15.66	83

सारिणी (सख्या 62) से स्पष्ट है कि 48 प्रतिशत आरक्षियों ने हाँ में उत्तर दिया है जिसका कि मतलब है कि इस विभाग की लडकी को विवाह में दिक्कत महसूस की जाती है। 36 प्रतिशत ने कहा कि नहीं दिक्कत नहीं होती है। 16 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

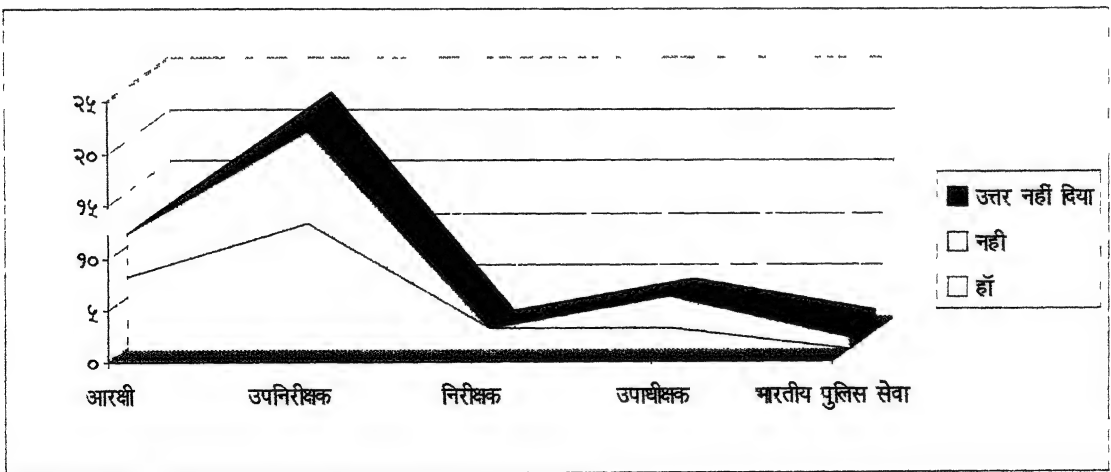
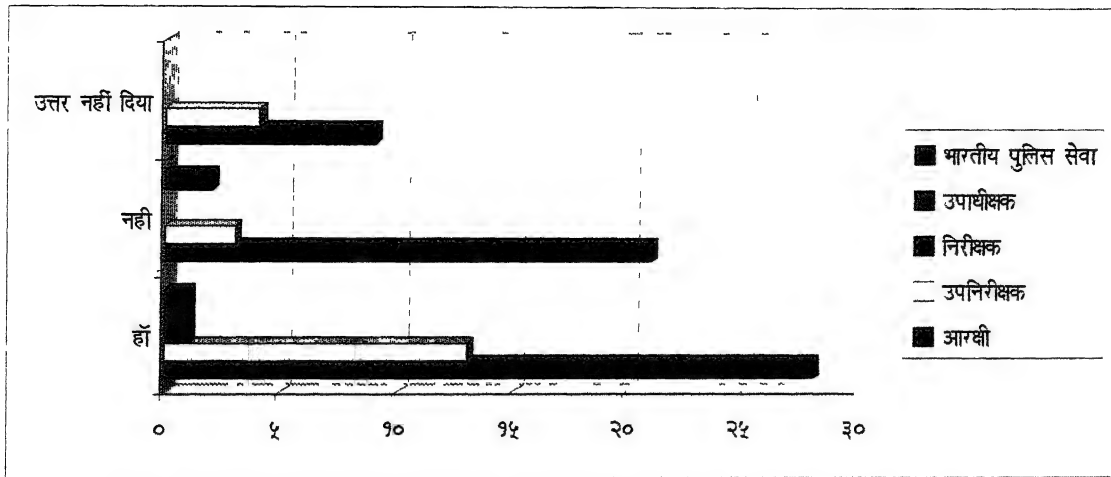
65 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने स्वीकार किया है कि विवाह में दिक्कत होती है। 15 प्रतिशत ने कहा कि विवाह के दिक्कत नहीं होती है। 20 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक एवं उपाधीक्षक ने स्वीकार किया कि इस विभाग की महिला को विवाह में दिक्कत होती है।

33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी का मानना है कि विवाह में दिक्कत होती है। 67 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि विवाह में दिक्कत नहीं होती है।

कुल 53 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों का मानना है कि इस विभाग की महिला के विवाह में दिक्कत आती है एवं 31 प्रतिशत ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। 16 प्रतिशत ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, इस प्रश्न की वास्तविकता के लिए हम पहले साधारण जन से जो प्रश्न किया था, कि इस विभाग की महिला से किसी भी तरह का वैवाहिक सम्बन्ध बनाने में क्यों कोई दिक्कत महसूस करेंगे, तो उसमें 26 प्रतिशत लोगों ने कहा था कि उन्हें इस विभाग की महिला से विवाह में दिक्कत होगी, 65 प्रतिशत ने कहा नहीं एवं 9 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया था।

26 प्रतिशत साधारण जन सूचनादाताओं के जिन लोगों ने विवाह से इन्कार किया था। उसमें 30 प्रतिशत ने समयाभाव के कारण मना किया, कि उनके सामाजिक एवं भावनात्मक दायित्व निभाने में दिक्कत होगी। 20 प्रतिशत ने कहा कि महिला पुलिस कुशल गृहणी नहीं हो सकती। 25 प्रतिशत ने कहा नारी स्वभाव कम



हो जाता है। 25 प्रतिशत लोगो ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी है, तो कोई दिक्कत नहीं परन्तु अराजपत्रित ने विवाह नहीं कर सकते।

इसके अलावा महिला पुलिस कर्मियों के पुरुष पुलिस सहकर्मियों से पूछा गया कि क्या आप इनसे वैवाहिक सम्बन्ध बनाने में क्या दिक्कत महसूस करेंगे तो विभिन्न उत्तर पदों के अनुसार दिये हैं।

सारिणी संख्या-6.3

महिला पुलिस कर्मियों से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने पर क्या पुरुष पुलिसकर्मी दिक्कत महसूस करेंगे, के बारे में पुरुष पुलिस कर्मियों के मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	आरक्षी	7	63.63	4	36.36	—	—	11
2	उपनिरीक्षक	12	52.17	9	39.23	2	8.6	23
3	निरीक्षक	2	100	—	—	—	—	2
4	उपाधीक्षक	2	40	3	60	—	—	5
5	भारतीय पुलिस सेवा	—	—	1	50	1	50	2
	कुल	23	53.48	17	39.53	3	6.9	43

सारिणी (संख्या 63) से स्पष्ट है कि 63 प्रतिशत पुरुष आरक्षियों ने, 52 प्रतिशत उपनिरीक्षकों ने 100 प्रतिशत निरीक्षकों ने 40 प्रतिशत उपाधीक्षकों ने विवाह में दिक्कत महसूस की है। कुल 53 प्रतिशत पुरुष पुलिस ने महिला पुलिस से विवाह के दिक्कत महसूस की है।

जब साधारण जन एवं पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिला पुलिस से विवाह में दिक्कत महसूस की है, तो निश्चित रूप से 53 प्रतिशत महिला पुलिस ने जब ये कहा कि महिला पुलिस के विवाह में दिक्कत होती है, तो ये मत सही ही प्रतीत होता है। 53 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने दिक्कत महसूस की है एवं 26 प्रतिशत साधारण जन के लोगो ने भी दिक्कत महसूस की है।

महिला पुलिसकर्मी सूचनादाता से पूछा गया, कि क्या महिला पुलिस कर्मी किसी प्रकाश के शोषण का शिकार है। तो इस प्रश्न के जबाब में पदानुसार निम्न तथ्य सामने आये हैं।

सांख्यिकी संख्या-6.4

क्या महिला पुलिसकर्मी किसी प्रकार के शोषण के शिकार है : महिला पुलिस का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल संख्या
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	आरक्षी	22	37.93	36	62.06	58
2	उपनिरीक्षक	13	65	7	35	20
3	निरीक्षक	1	100	—	—	1
4	उपाधीक्षक	—	—	1	100	1
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33	2	67	3
	कुल	37	44.57	46	55.42	83

सारणी (संख्या 6.4) से पता चलता है कि 38 प्रतिशत महिला आरक्षी हाँ में उत्तर देती हैं एवं 62 प्रतिशत नहीं में तथा 65 प्रतिशत महिला पुलिस उपनिरीक्षकों ने हाँ में एवं 35 प्रतिशत नहीं में उत्तर दिया है। एवं 100 ने हाँ एवं 100 प्रतिशत

उपाधीक्षक ने नही मे उत्तर दिया है 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिलाओ ने हॉ मे एव 67 प्रतिशत ने नही मे उत्तर दिया है।

कुल 45 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियो ने ये स्वीकार किया है कि महिला पुलिस शोषण का शिकार है, 55 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है कि महिला पुलिस शोषण का शिकार नही है।

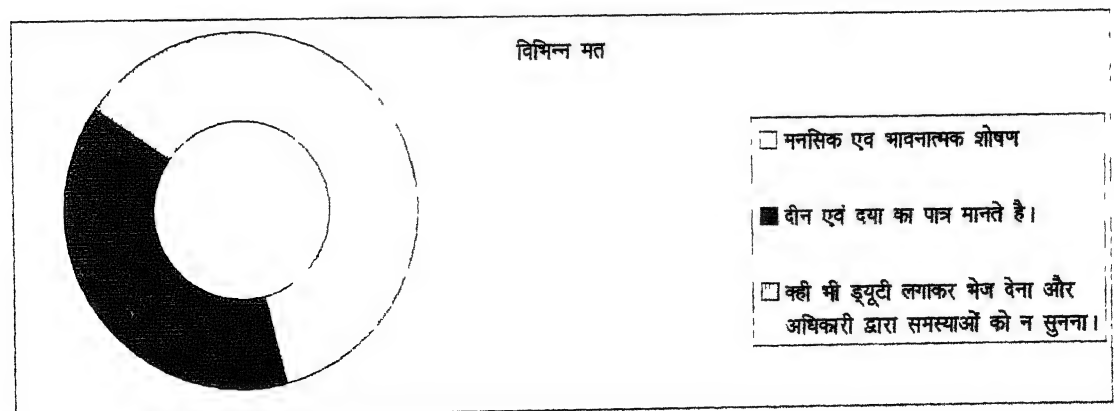
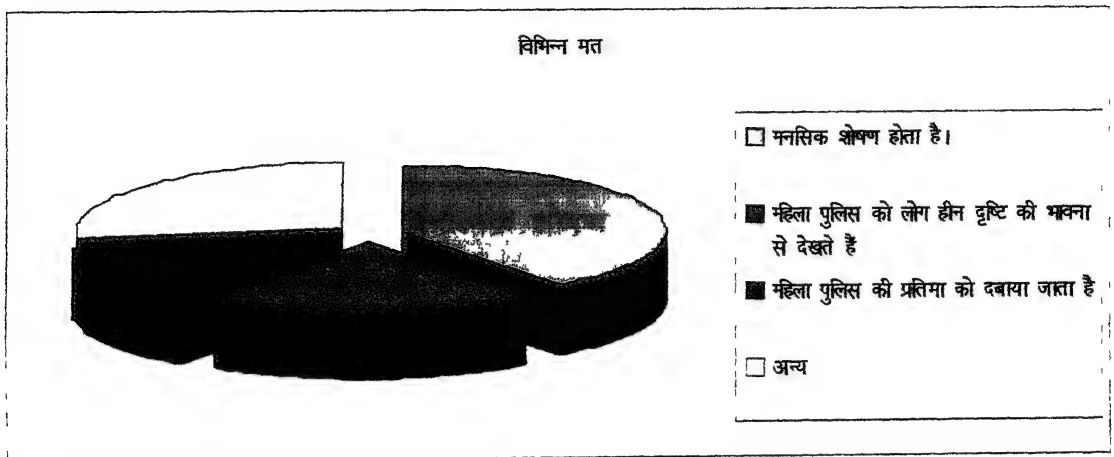
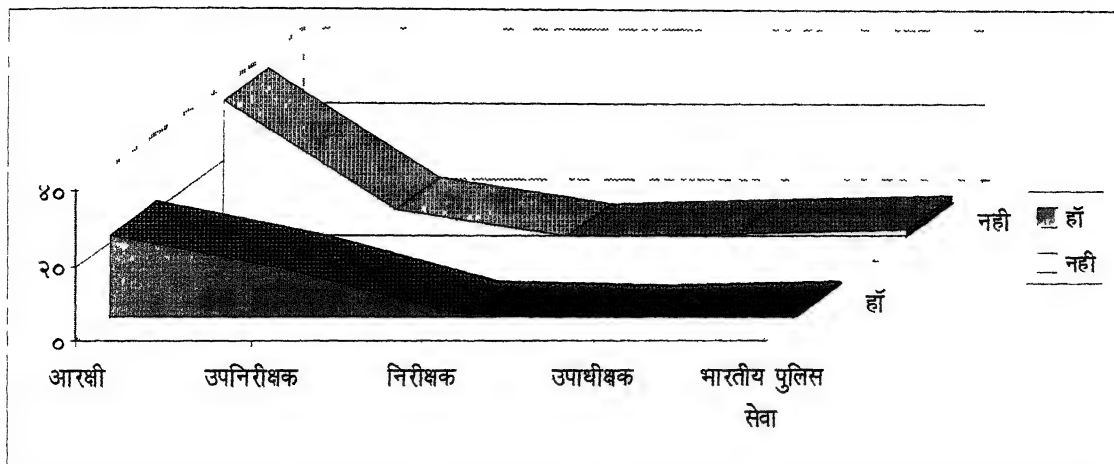
जिन महिला पुलिस कर्मियो ने हॉ मे उत्तर दिया है उनमे कुछ सूचनादाताओ ने कारण भी पदानुसार अलग-2 प्रकार से दिया।

सारिणी संख्या-6.5

शोषण के प्रकार या शोषण के विभिन्न रूपों पर महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	मानसिक शोषण होता है।	6	40
2	महिला पुलिस को लोग हीन दृष्टि की भावना से देखते है	3	20
3	महिला पुलिस की प्रतिभा को दबाया जाता है	2	13 33
4	अन्य	4	26 66
	कुल	15	100

जिन 38 प्रतिशत महिला आरक्षियो का मानना है कि उनका शोषण होता है तो उसके निम्न प्रकार बताये हैं, जो सारिणी (सख्या 65) से ज्ञात होता है कि 40 प्रतिशत महिला आरक्षियो का मानना है कि उनका मानसिक शोषण होता है। 20 प्रतिशत मानती है कि महिला पुलिस कर्मियो को लोग हीन दृष्टि की भावना से देखते है। 13 प्रतिशत का कहना है कि महिला पुलिस की प्रतिभा को दबाया जाता है एवं 27 प्रतिशत अन्य विभिन्न कारणो मे बताया है कि असमय ड्यूटी के



साथ-साथ अधिकारियों का शोषण है। ये भी माना है कि महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी रात्रि में लगाने से पुरुष पुलिसकर्मी, महिला पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार एवं अश्लील बातों का प्रयोग करते हैं। साथ ही कहा कि उनका कोई सहायता नहीं मिलती है और जातिवाद का भी महिला पुलिसकर्मी शिकार है।

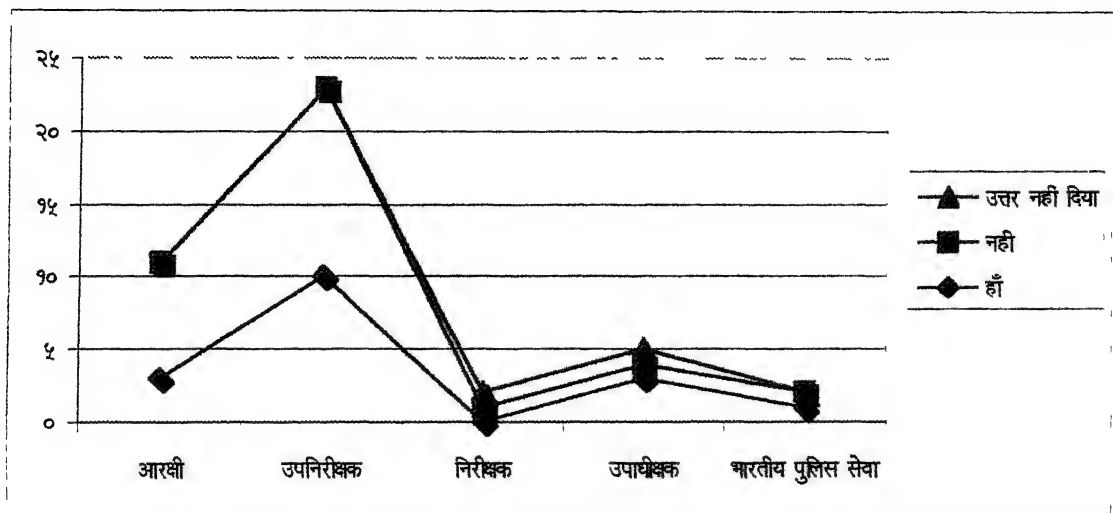
65 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने माना है कि उनका शोषण होता है और इसके प्रकार भी बताए हैं जो निम्नवत हैं।

सारिणी संख्या-6.6

शोषण के प्रकार के बारे में महिला उपनिरीक्षकों के विभिन्न मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	मानसिक एवं भावनात्मक शोषण	6	46 15
2	हीन एवं दया का पात्र मानते हैं।	5	38 46
3	कही भी ड्यूटी लगाकर भेज देना और अधिकारी द्वारा समस्याओं को न सुनना।	2	15 38
	कुल	13	100

सारिणी (संख्या 66) से पता चलता है कि 46 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती हैं कि उनका मानसिक एवं भावनात्मक शोषण किया जाता है। 38 प्रतिशत का मानना है कि उन्हें पुरुषों की अपेक्षा हीन एवं दया की पात्र मानते हैं। 15 प्रतिशत का मानना है कि उनकी कही भी ड्यूटी लगाकर भेज देना और अधिकारी द्वारा समस्याओं को न सुनना।



100 प्रतिशत महिला निरीक्षक का मानना है कि उनका शोषण होता है। प्रकार के स्वरूप पर उनका कहना है, कि बराबर काम करने पर भी पुरुषों के बराबर महत्व नहीं दिया जाता है।

33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी का कहना है, कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता है, उन्हें कम महत्वपूर्ण कार्य दिये जाते हैं। ज्यादातर महिला प्रकोष्ठ से जोड़ दिया जाता है।

यही प्रश्न जब पुरुष पुलिस कर्मियों से पूछा गया कि क्या महिला पुलिस कर्मियों का शोषण होता है। तो इस प्रश्न के जबाब में निम्न मत पदानुसार दिये हैं।

सारिणी संख्या-6.7

महिला पुलिस कर्मियों का शोषण होता है या नहीं : पुरुष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		कुल
		सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	
1	आरक्षी	3	27.27	8	72.72	—	—	11
2	उपनिरीक्षक	10	43.47	13	56.52	—	—	23
3	निरीक्षक	—	—	1	50	1	50	2
4	उपाधीक्षक	3	60	1	20	1	20	5
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	50	1	50	—	—	2
	कुल	17	39.53	24	55.81	2	4.65	43

सारिणी (संख्या 6.7) से ज्ञात होता है 27 आरक्षियों ने हाँ में उत्तर दिया है एवं 72 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 43 प्रतिशत पुलिस उपनिरीक्षकों ने माना है कि महिला पुलिस कर्मियों का शोषण होता है एवं 57 प्रतिशत ने इन्कार दिया है। 50 प्रतिशत निरीक्षकों ने माना है कि इनका कोई शोषण नहीं होता है एवं 50

प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। 60 प्रतिशत उपाधीक्षकों ने माना है कि महिला पुलिस कर्मियों का शोषण होता है 20 प्रतिशत ने इन्कार किया है। 20 प्रतिशत ने जबाब नहीं दिया है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारियों ने माना है कि उनका शोषण होता है 50 प्रतिशत ने कहा ऐसा नहीं है।

कुल प्रतिशत देखे तो पता चलता है कि 40 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मियों की मानना है कि महिला पुलिस कर्मियों का शोषण होता है। 56 प्रतिशत का मानना है, कि उनका किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होता है। 4 प्रतिशत ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

वास्तविकता को जानने के लिए पुरुषों और महिला दोनों पुलिसकर्मियों के उत्तर की तुलना करेंगे तो पायेंगे कि 45 प्रतिशत पुलिसकर्मी मानती हैं, कि उनका शोषण होता है एवं 40 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मी भी मानते हैं, कि उनका शोषण होता है। इससे पता चलता है कि लगभग एक जैसा ही प्राप्त होता है कि कुछ हद तक शोषण है, और इन्कार करने वाली महिला पुलिस कर्मियों की प्रतिशत 55 प्रतिशत एवं पुरुष पुलिस कर्मियों का प्रतिशत 56 प्रतिशत है। ये भी लगभग बराबर ही है। यानि महिला और पुरुषों दोनों ने ही काफी हद तक वास्तविक उत्तर प्रदान किये हैं।

महिला पुलिस कर्मियों से पदोन्नति के बारे में उनकी राय क्या है, प्रश्न किया तो विभिन्न पदों के लोगो ने अलग-अलग तरह से विचार प्रस्तुत किये हैं। सर्वप्रथम महिला आरक्षियों के विचार जानेंगे।

सारिणी संख्या-6.8

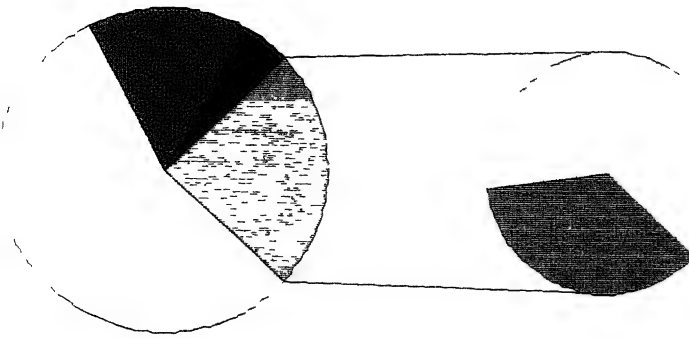
पदोन्नति के बारे में महिला आरक्षियों के विभिन्न मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए।	32	55.17
2	कार्य या योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए	9	15.51
3	पुरुषों और महिलाओं को बराबर पदोन्नति मिलनी चाहिए।	3	5.17
4	अन्य	5	8.6
5	उत्तर नहीं दिया	9	15.51
	कुल	58	100

सारिणी (संख्या 6.8) से ज्ञात होता है कि 55 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती हैं कि समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए। 16 प्रतिशत का मानना है अच्छे कार्य या योग्यता के अनुसार अपने आप मिलनी चाहिए। 5 प्रतिशत का मानना है कि पुरुषों और महिलाओं को बराबर पदोन्नति मिलनी चाहिए, यानि महिलाओं को भी पुरुषों के समान हो पदोन्नति मिलनी चाहिए। 7 प्रतिशत अन्य में विभिन्न मत हैं कि परीक्षा देकर पदोन्नति की जाय या 50 प्रतिशत डायरेक्ट एव 50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति होनी चाहिए या 50 प्रतिशत कोटा महिलाओं के लिए निर्धारित होना चाहिए। एक अन्य मत के अनुसार रैंकर पदोन्नति हेतु या विभागीय परीक्षा हेतु सेवा पूरी करने, (कितने वर्ष) इस प्रकार का बन्धन नहीं होना चाहिए। पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा या अन्य मौके जल्दी-2 प्रदान करने चाहिए। 16 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

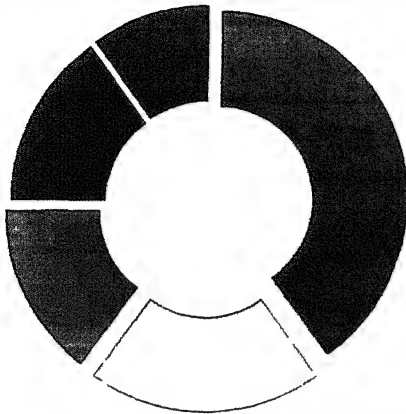
महिला उपनिरीक्षकों ने भी अपने विभिन्न प्रकार के मत पदोन्नति पर दिये हैं।

विभिन्न मत



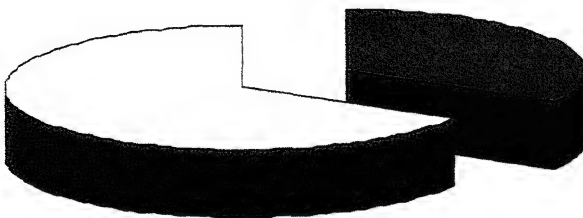
- ☐ समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए।
- ☒ कार्य या योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए
- ☒ पुरुषों और महिलाओं को बराबर पदोन्नति मिलनी चाहिए।
- ☒ अन्य
- ☐ उत्तर नहीं दिया

विभिन्न मत



- ☒ समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए।
- ☐ पदोन्नति सही मूल्यांकन के आधार पर न कि अनुचित या फर्जी कर््यों के आधार पर।
- ☒ पदोन्नति बहुत कम होती है
- ☒ अन्य
- ☒ उत्तर नहीं दिया

विभिन्न मत



- ☒ अधिकांश पदोन्नति साफ सुथरे तरीके से ही होते हैं।
- ☐ उत्तर नहीं दिया प्रश्न का

पदोन्नति पर महिला उपनिरीक्षकों के विभिन्न मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए।	8	40
2	पदोन्नति सही मूल्यांकन के आधार पर न कि अनुचित या फर्जी कार्यों के आधार पर।	4	20
3	पदोन्नति अहुत कम होती है	3	15
4	अन्य	3	15
5	उत्तर नहीं दिया	2	10
	कुल	20	100

सारिणी (संख्या 69) से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती हैं कि पदोन्नति समयानुसार वरिष्ठता के आधार पर दी जानी चाहिए। 20 प्रतिशत का मानना है कि पदोन्नति सही मूल्यांकन के आधार पर न कि अनुचित या फर्जी कार्यों के आधार पर। 15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों का मानना है कि पदोन्नति इस विभाग में बहुत कम होती है। 15 प्रतिशत अन्य में, महिला उपनिरीक्षक का कहना है महिला एवं पुरुष दोनों की समान रूप से पदोन्नति हो। कुछ ने कहा महिलाओं की पदोन्नति आरक्षण के आधार पर होनी चाहिए और ये भी कहा कि जैसे उपनिरीक्षक को निरीक्षक बनने के लिए किसी भी थाने का एस०ओ० होना जरूरी है, जो कि नहीं होना चाहिए। 10 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

महिला निरीक्षक पदोन्नति के बारे में कहती हैं कि योग्य कर्मचारियों की पदोन्नति तो होती ही है, लेकिन कभी-कभी अनियमितता हो जाती है।

महिला उपाधीक्षक का मनना है कि समय-समय पर पदोन्नति होती रहती है।

भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों के विभिन्न मत पदोन्नति के बारे में इस प्रकार से हैं।

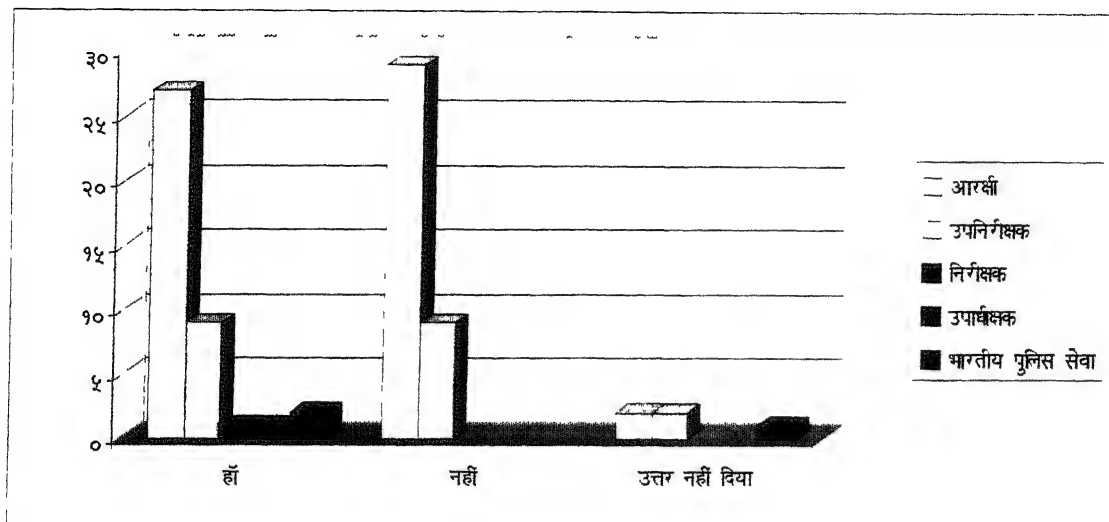
सारिणी संख्या-6.10
पदोन्नति पर भारतीय पुलिस सेवा की महिला
अधिकारियों का मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1	अधिकता पदोन्नति साफ सुथरे तरीको से ही होते हैं।	1	33
2	प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।	2	67

सारिणी (संख्या 610) से स्पष्ट है कि 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मानना है कि अधिकतर पदोन्नति साफ सुथरे तरीको से ही होती है, यानि कुछ तो अनियमित या साफ सुथरे तरीको से नहीं होते हैं। 67 प्रतिशत महिला अधिकारियों ने इसका जबाब नहीं दिया है।

सभी महिला पुलिस कर्मियों ने अधिकतर माना है कि समय से पदोन्नति यदि नहीं होती है, तो हीन भावना पनपती है और समयानुसार मिलने पर मनोबल बना रहता है।

महिला पुलिस से जब ये पूछा गया कि क्या विभाग द्वारा दी गई छुट्टियाँ पर्याप्त हैं, और समय से मिल जाती हैं। पदानुसार निम्न प्रकार से उत्तर प्राप्त हुए हैं।



सारिणी संख्या-6.11

विभाग द्वारा दी गयी छुट्टियाँ पर्याप्त हैं, और समय से मिल जाती हैं इस पर महिला पुलिस कर्मियों के विभिन्न विचार

क्रम	पद	हाँ		नहीं		उत्तर नहीं दिया		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	27	46.55	29	50	2	3.44	58	69.87
2.	उपनिरीक्षक	9	45	9	45	2	10	20	24.09
3	निरीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	1.20
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	—	—	1	1.20
5.	भारतीय पुलिस सेवा	2	67	—	—	1	33	3	3.6
योग		40	48.19	38	45.78	5	6.02	83	100

सारिणी (संख्या 6.11) से स्पष्ट है कि 48 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों का मानना है कि दी हुई छुट्टियाँ पर्याप्त हैं और समय से मिल जाती हैं। 46 प्रतिशत कहती हैं कि छुट्टियाँ न पर्याप्त हैं और न ही समय से मिलती हैं। 6 प्रतिशत महिला पुलिस ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

पदानुसार देखे तो 47 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती हैं कि छुट्टियाँ पर्याप्त हैं और समय से मिलती हैं। 50 प्रतिशत मानती हैं कि छुट्टियाँ न पर्याप्त हैं और न ही समय से मिलती हैं। 3 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

45 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती हैं कि छुट्टियाँ पर्याप्त हैं और समय से मिल जाती हैं। 45 प्रतिशत उपनिरीक्षकों का मानना है कि न छुट्टियाँ पर्याप्त हैं और न ही समय से मिलती हैं। 10 प्रतिशत ने इसका उत्तर नहीं दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक एवं 100 प्रतिशत महिला अधीक्षक का कहना है कि छुट्टियाँ पर्याप्त हैं और समय से मिल जाती है। 67 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी भी यही मानती है कि छुट्टियाँ पर्याप्त हैं और समय से मिल जाती है। लेकिन डी०एफ० में नहीं नान डी०एफ० में मिलती है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी ने इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया।

सारिणी से यह ज्ञात होता है कि महिला आरक्षी एवं उपनिरीक्षक स्तर पर छुट्टियों के अपर्याप्त और समय से न मिलने के प्रति असंतोष ज्यादा है।

महिला पुलिस कर्मियों से स्थानान्तरण के बारे में उनके विचार जानने की कोशिश की है। जो पदानुसार विभिन्न प्रकार से है।

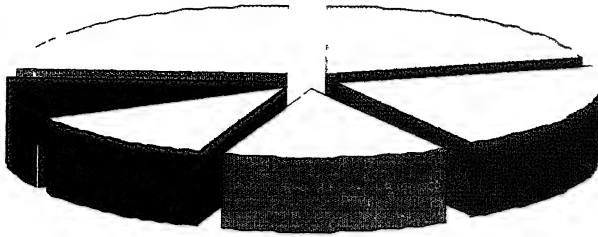
सारिणी संख्या-6.12

स्थानान्तरण के बारे में महिला आरक्षियों के विभिन्न मत

क्रम	आरक्षियों के विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1.	कही भी हो जाय	12	20.68
2	बहुत जल्दी-जल्दी न हो	12	20.68
3	आवेदन पत्र लेकर सुविधानुसार नियुक्ति की जाय	8	13.79
4	गृह जनपदों के निकट ही रखा जाय	7	12.06
5	स्थायी हो या एक ही जिले में कुछ वर्ष के लिए निश्चित हो	5	8.62
6.	उत्तर नहीं दिया	14	24.13
योग		58	100

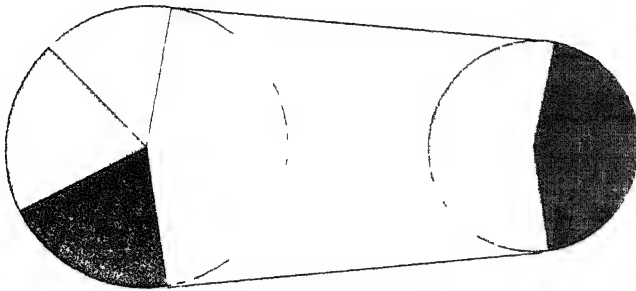
सारिणी (संख्या 6.12) से स्पष्ट है कि 20.68 प्रतिशत महिला आरक्षियों का मानना है, कि कही भी स्थानान्तरण हो जाय। 20.68 प्रतिशत का विचार है बहुत जल्दी-जल्दी स्थानान्तरण न हो। 13.79 प्रतिशत का मानना है, कि आवेदन पत्र लेकर सुविधानुसार नियुक्ति की जाय। 12 प्रतिशत कहती हैं, कि उन्हें गृह जनपदों के निकट ही रखा जाय। 9 प्रतिशत चाहती है कि स्थानान्तरण स्थायी हो, या कम

महिला आरक्षियों के स्थानान्तरण के बारे में विभिन्न मत



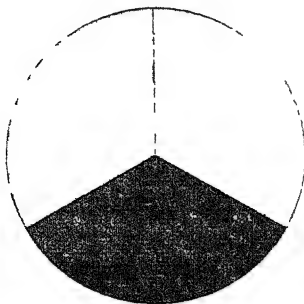
- ☐ कहीं भी हो जाय
- ☐ बहुत जल्दी-जल्दी न हो
- ☐ आवेदन पत्र लेकर सुविधानुसार नियुक्ति की जाय
- ☐ गृह जनपदों के निकट ही रखा जाय
- ☒ स्थाई हो या एक ही जिले में कुछ वर्ष के लिए निश्चित हो
- ☐ उत्तर नहीं दिया

महिला उपनिरीक्षकों का स्थानान्तरण के बारे में विभिन्न मत



- ☒ जल्दी-जल्दी नहीं होना चाहिए
- ☐ स्थानान्तरण आवश्यक है अतः होते रहने चाहिए
- ☐ कुछ निश्चित अवधि के बाद होना चाहिए
- ☐ उत्तर नहीं दिया
- ☒ अन्य

भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का स्थानान्तरण पर मत



- ☐ उत्तर प्रदेश में अनावश्यक अत्यधिक स्थानान्तरण होते हैं
- ☒ कुछ समय अवश्य निर्धारित होना चाहिए
- ☐ उत्तर नहीं दिया

से कम एक ही जिले में कुछ वर्ष के लिए निश्चित हो। 24 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

सारिणी संख्या-6.13

स्थानान्तरण के बारे में महिला उपनिरीक्षकों के विभिन्न मत

क्रम	महिला उपनिरीक्षकों का स्थानान्तरण के बारे में विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1.	जल्दी-जल्दी नहीं होना चाहिए	4	20
2	स्थानान्तरण आवश्यक है अतः होते रहने चाहिए	4	20
3	कुछ निश्चित अवधि के बाद होना चाहिए	3	15
4.	उत्तर नहीं दिया	5	25
5.	अन्य	4	20
योग		20	100

सारिणी (संख्या 6.13) से स्पष्ट है कि, 20 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों का कहना है कि स्थानान्तरण जल्दी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा असुविधा होती है। 20 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों का कहना है कि स्थानान्तरण स्वाभाविक है ये आवश्यक भी है अतः होते रहना चाहिए, ये मानती है कि स्थानान्तरण से शिक्षा भी मिलती है। 15 प्रतिशत का मानना है कि स्थानान्तरण कुछ निश्चित अवधि के बाद ही होना चाहिए। यानि इनका भी मानना है कि जल्दी-जल्दी स्थानान्तरण नहीं होने चाहिए। 20 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक ने अन्य विचार प्रस्तुत किये हैं, जिनमें है कि स्थानान्तरण घर के नजदीक होना चाहिए या पारिवारिक समस्या को देखते हुए स्थानान्तरण होना चाहिए। बिना शिकायत स्थानान्तरण भेदभाव युक्त होता है। 25 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक मानती है कि स्थानान्तरण में कई प्रकार की विसंगतियाँ हैं। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक भी ये मानती हैं कि ये एक निश्चित समय पर होते रहना चाहिए।

सारिणी संख्या-6.14

स्थानान्तरण पर भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1	उत्तर प्रदेश में अनावश्यक अत्यधिक स्थानान्तरण होते हैं	1	33
2	कुछ समय अवश्य निर्धारित होना चाहिए	1	33
3	उत्तर नहीं दिया	1	33
योग		3	100

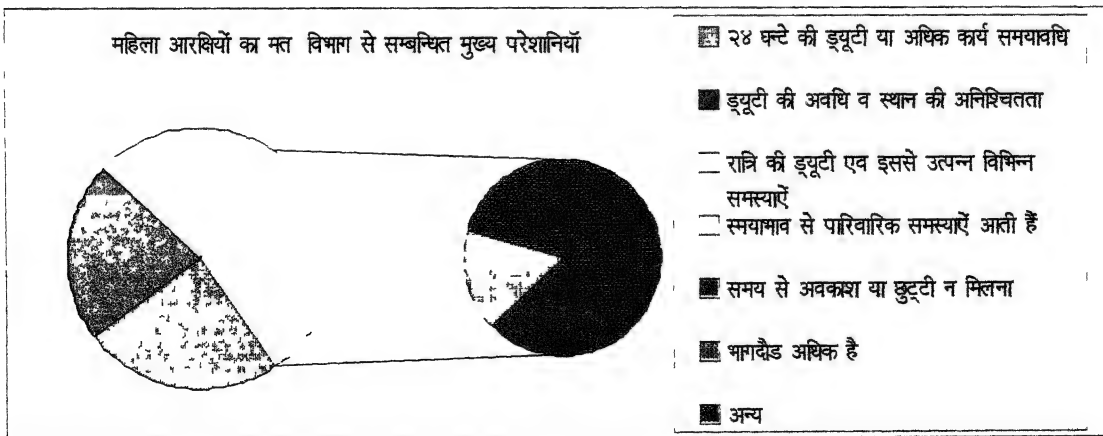
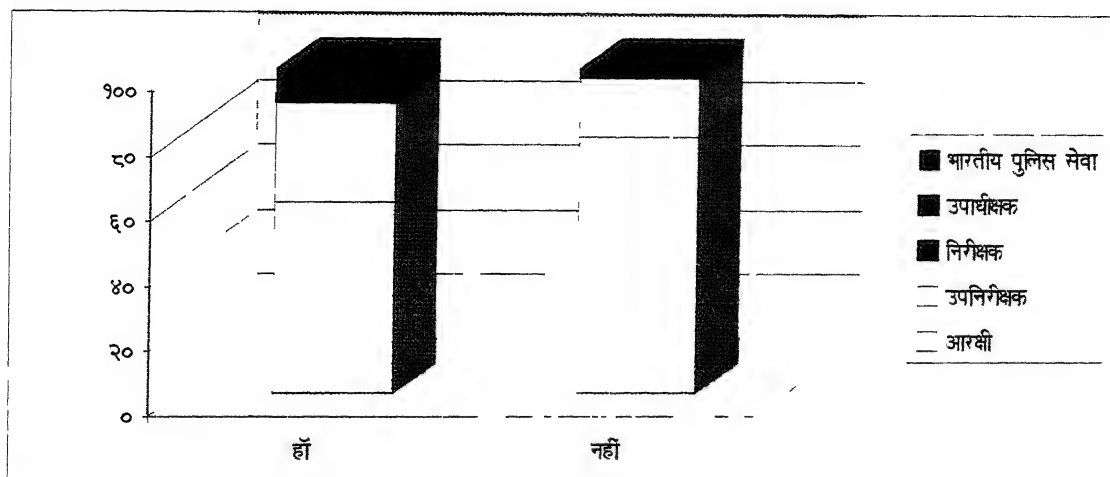
सारिणी (संख्या 614) से स्पष्ट है कि 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती हैं कि उत्तर प्रदेश में अनावश्यक अत्यधिक स्थानान्तरण होते हैं जिसकी वजह से जो कार्य वो कर रही होती हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है और जो वादा वह करती हैं उसे पूरा नहीं कर पाती। 33 प्रतिशत मतानी हैं कि स्थानान्तरण कुछ समय अवश्य निर्धारित होना चाहिए, 33 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है।

महिला पुलिस से उसकी आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में पूछा गया कि क्या आपका वेतन एवं भत्ते आपकी पारिवारिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त हैं। इस प्रश्न का उत्तर पदानुसार इस प्रकार से हैं जो सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या-6.15

वेतन एवं भत्ते पारिवारिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त हैं : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	आरक्षी	23	39.65	35	60.34	58	69.87
2	उपनिरीक्षक	12	60	8	40	20	24.09
3	निरीक्षक	—	—	1	100	1	1.20
4.	उपाधीक्षक	1	100	—	—	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	—	—	3	3.61
योग		39	46.98	44	53.01	83	100



सारिणी (संख्या 615) से स्पष्ट है कुल 47 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है, कि उनके वेतन एवं भत्ते पारिवारिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त है। 53 प्रतिशत मानती है कि पर्याप्त नहीं है। असतोष व्यक्त करने का प्रतिशत आधे से अधिक है।

40 प्रतिशत महिला आरक्षी कहती है कि उनका वेतन और भत्ते पारिवारिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त है। 60 प्रतिशत कहती है कि पर्याप्त नहीं है।

60 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक का मानना है, कि उनका वेतन और भत्ते पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 40 प्रतिशत मानती है कि वेतन और भत्ते पर्याप्त नहीं है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक भी मानती है कि वेतन और भत्ते अपर्याप्त है।

100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक एवं 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों ने कहा कि वेतन एवं भत्ते पारिवारिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त है।

सारिणी (संख्या 6.15) से स्पष्ट है कि अराजपत्रित महिला पुलिस अपने वेतन एवं भत्तों से असंतुष्ट है जबकि राजपत्रित अपने वेतन एवं भत्तों से सतुष्ट है।

महिला पुलिस से पूछा गया कि अन्य नौकरियों या विभाग की अपेक्षा इस विभाग की मुख्य परेशानियाँ क्या हैं। निम्न मत पदानुसार व्यक्त किये गये हैं। महिला आरक्षियों के अनुसार मुख्य परेशानियाँ निम्नलिखित हैं—

सारिणी संख्या-6.16

विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियाँ : महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न मत	संख्या	प्रतिशत
1.	24 घण्टे की ड्यूटी या अधिक कार्य समयावधि	14	24.13
2	ड्यूटी की अवधि व स्थान की अनिश्चितता	13	22.41
3.	रात्रि की ड्यूटी एवं इससे उत्पन्न विभिन्न समस्याएँ	8	13.79
4	समयाभाव से पारिवारिक समस्याएँ आती हैं	5	8.62
5	समय से अवकाश या छुट्टी न मिलना	4	6.89
6	भागदौड़ अधिक है	3	5.17
7	अन्य	11	18.96
योग		58	100

सारिणी (संख्या 616) से स्पष्ट है कि 24 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि मुख्य परेशानी 24 घंटे की ड्यूटी होना है या इस विभाग की अधिक कार्य समयावधि है, जो अन्य किसी भी विभाग की नहीं है। 22 प्रतिशत का मानना है कि ड्यूटी की अवधि और स्थान दोनों की अनिश्चितता रहती है। 14 प्रतिशत मानती है कि रात्रि की ड्यूटी एव इससे उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं, जिनसे महिला आरक्षी शारीरिक एव मानसिक दोनों प्रकार से कष्ट का अनुभव करती है। 9 प्रतिशत मानती है कि समयाभाव से उनके सामने पारिवारिक समस्याएँ आती हैं। 7 प्रतिशत मानती है कि जरूरत के समय अवकाश या छुट्टी नहीं मिलती है इसके लिए उन्हें काफी भटकना पड़ता है और मेडिकल रेस्ट लेने पर उपार्जित अवकाश अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। 5 प्रतिशत मानती है कि भागदौड़ अधिक है। 19 प्रतिशत आरक्षियों ने इस विभाग के सम्बन्ध में अन्य परेशानियों को बताया है जैसे—दूर दराज पोस्टिंग से समस्याएँ, महिलाओं का शोषण, अपराधियों से सामना करना पड़ता है, ईमानदारी से कार्य न कर पाना, महिलाओं की उपेक्षा, आवास की व्यवस्था न होना है, कार्यक्षेत्र का बहुत विस्तृत होना, फील्ड ड्यूटी के दौरान आने वाली परेशानियाँ, ड्यूटी के अनुसार वेतनमान का कम होना, आराम का समय न मिल पाना आदि हैं।

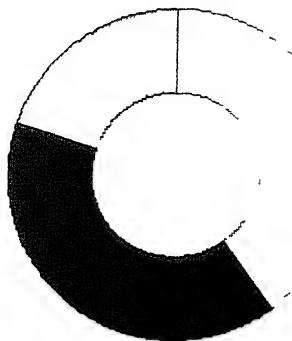
अन्य विभाग की अपेक्षा इस विभाग की मुख्य परेशानियों में महिला उपनिरीक्षकों के निम्नलिखित मत हैं—

सारिणी संख्या-6.17

विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियाँ : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1	अहर्निश ड्यूटी के कारण कार्य की अधिकता	8	40
2	समयाभाव के कारण पारिवारिक दायित्व ढग से न निभा पाना	3	15
3.	महिला पुलिस को पुलिस विभाग के पुरुष एव कार्यक्षेत्र के पुरुष दोनों ही पुरुष पुलिस की अपेक्षा कम अकन, उपेक्षा एव उचित सम्मान व सहयोग न प्रदान करना	5	25
4	अन्य	4	20
योग		20	100

महिला उपनिरीक्षकों का मत विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियों



☐ अहर्निश ड्यूटी के कारण कार्य की अधिकता

☒ समयाभाव के कारण पारिवारिक दायित्व ढग से न निभा पाना

☒ महिला पुलिस को पुलिस विभाग के पुरुष एवं कार्यक्षेत्र के पुरुष दोनों ही पुरुष पुलिस की अपेक्षा कम अकल, उपेक्षा एवं उचित सम्मान व सहयोग न प्रदान करना

☐ अन्य

भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत मुख्य परेशानियों अन्य विभाग की अपेक्षा



☒ लम्बी कार्य अवधि के कारण, पूर्व नियोजित कोई भी कार्यक्रम अपनी इच्छा से बनाना मुश्किल होता है।

☒ कार्य का अनियमित समय

☐ कार्य के कठिन घटे, स्थायित्व का अभाव, कार्य स्थल पर आधारभूत आवश्यकताओं (टॉयलेट इत्यादि) की

सारिणी (संख्या 617) से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि अहर्निश ड्यूटी के कारण कार्य की अधिकता रहती है। 25 प्रतिशत मानती है कि, महिला पुलिस कर्मियों को पुलिस विभाग के पुरुष एवं कार्यक्षेत्र में सम्पर्क में आने वाले पुरुष, दानो ही पुरुष पुलिस की अपेक्षा कम आँकते हैं। उपेक्षा करते हैं, साथ ही उचित सम्मान व सहयोग भी नहीं मिलता है। 15 प्रतिशत मानती है कि समयाभाव के कारण पारिवारिक दायित्व ढग से न निभा पाना है। 20 प्रतिशत ने अन्य परेशानियाँ बतायी हैं जैसे—उनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने की सामाजिक भावना, आवास की समस्या एवं अन्य ड्यूटियों में रहने और खान की समस्या, महिला पुलिसकर्मियों के अधिकारियों से बात करने पर शक की दृष्टि से देखना, अनुशासन की कठोरता जबकि अन्य नौकरियों में इस पर इतना बल नहीं दिया जाता है।

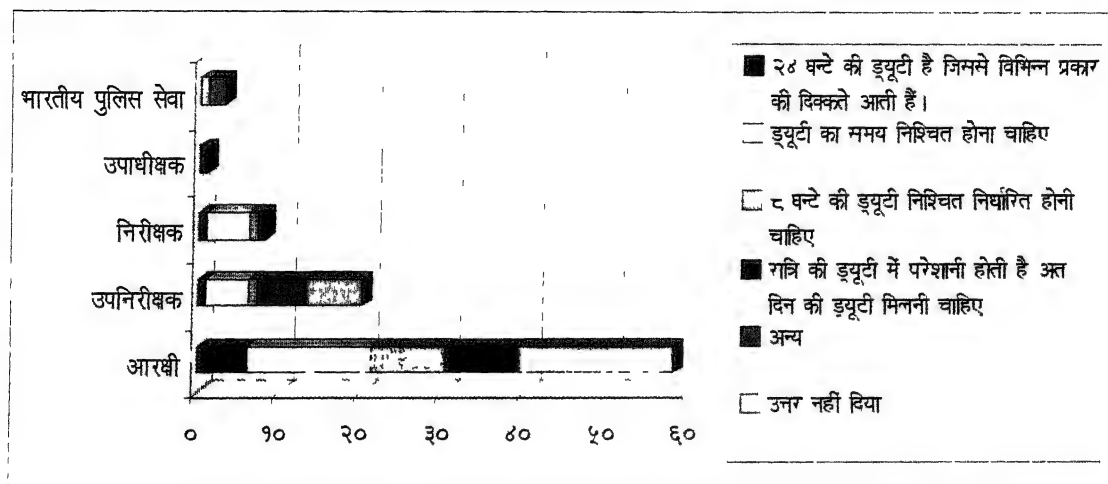
100 प्रतिशत महिला निरीक्षक का कहना है, कि पारिवारिक जीवन संभव नहीं हो पाता, बच्चों की देखभाल व शिक्षा ठीक से न हो पाने के कारण भविष्य की असुरक्षा व तनावपूर्ण जीवन रहता है।

100 प्रतिशत महिला अधीक्षक का कहना है कि समय का अभाव इस विभाग की नौकरी के कारण रहता है। भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों ने भी अपने विचार निम्नवत् स्पष्ट किये हैं—

सारिणी संख्या-6.18

विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियाँ : भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1.	लम्बी कार्य अवधि के कारण, पूर्व नियोजित कोई भी कार्यक्रम अपनी इच्छा से बनाना मुश्किल होता है।	1	33 33
2	कार्य का अनियमित समय	1	33 33
3.	कार्य के कठिन घटे, स्थायित्व का अभाव, कार्य स्थल पर आधारभूत आवश्यकताओं (टॉयलेट इत्यादि) की कमी।	1	33 33
योग		3	100



सारिणी (सख्या 618) से स्पष्ट है कि 33.33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती हैं, कि लम्बी कार्य अवधि के कारण पूर्व नियोजित कोई भी कार्यक्रम अपनी इच्छा से बनाना मुश्किल होता है। 33.33 प्रतिशत मानती हैं कि कार्य का अनियमित समय है। 33.33 प्रतिशत मानती हैं कि कार्य के कठिन घटे, स्थायित्व का अभाव, कार्यस्थल पर आधारभूत आवश्यकताओं (टॉयलेट आदि) की कमी रहती है।

महिला पुलिस से ड्यूटी के सम्बन्ध में उनकी राय पूँछा गया तो निम्नलिखित उत्तर पदानुसार प्राप्त हुए जो सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या-6.19

ड्यूटी के सम्बन्ध में : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	महिला पुलिस विभिन्न मत	पद										कुल	
		आरक्षी		उपनिरीक्षक		निरीक्षक		उपाधीक्षक		भारतीय पुलिस सेवा			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	24 घन्टे की ड्यूटी है जिससे विभिन्न प्रकार की दिक्कते आती हैं।	6	10.34	1	5	—	—	1	100	—	—	8	9.63
2	ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए	15	25.86	5	25	1	100	—	—	—	—	21	25.30
3	8 घन्टे की ड्यूटी निश्चित निर्धारित होनी चाहिए	9	15.51	1	5	—	—	—	—	1	33	11	13.25
4	रात्रि की ड्यूटी में परेशानी होती है अतः दिन की ड्यूटी मिलनी चाहिए	9	15.51	1	5	—	—	—	—	—	—	10	12.04
5	अन्य	—	—	5	25	—	—	—	—	2	67	7	8.43
6	उत्तर नहीं दिया	19	32.75	7	35	—	—	—	—	—	—	26	31.32
योग		58	69.87	20	24.09	1	1.20	1	1.20	3	3.61	83	100

सारिणी (सख्या 619) से स्पष्ट है कि कुल 25.30 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों का मानना है कि ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए, 13.25 प्रतिशत मानती हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए। 12.04 प्रतिशत का मानना है

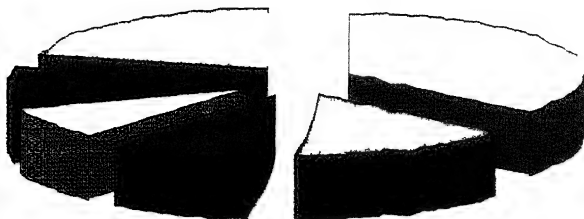
कि रात्रि की ड्यूटी में परेशानी होती है, अतः दिन की ही ड्यूटी मिलनी चाहिए। 9 63 प्रतिशत मानती है कि 24 घण्टे की ड्यूटी इस विभाग में है, जिससे विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं। 843 प्रतिशत ने ड्यूटी के सम्बन्ध में अन्य विभिन्न प्रकार के मत प्रस्तुत किये हैं। 31 32 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है।

पदानुसार देखें तो 25 86 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए। 15 51 प्रतिशत का मानना है कि 8 घण्टे की ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए। 15 51 प्रतिशत मानती है कि रात्रि ड्यूटी में परेशानी होती है अतः दिन की ड्यूटी मिलनी चाहिए। 10 प्रतिशत कहती है कि 24 घण्टे की वजह से विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं। 32.75 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

25 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए। 5 प्रतिशत मानती है 8 घण्टे की ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए। 5 प्रतिशत मानती हैं रात्रि की ड्यूटी मिलनी चाहिए। 5 प्रतिशत मानती है कि 24 घण्टे की ड्यूटी से विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं। 35 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया एवं 25 प्रतिशत ने अन्य विचार व्यक्त किये हैं जैसे—सप्ताह में एक अवकाश मिलना चाहिए, इमरजेन्सी के समय तत्काल अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए, विभाग में फोर्स की कमी नहीं अतः शिफ्टवाइज आरेन्जमेंट करके 8 घण्टे की ड्यूटी होनी चाहिए। महिलाओं को भी महत्वपूर्ण मौकों प्रदान करने चाहिए आदि। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक मानती है, कि ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए। 100 प्रतिशत उपाधीक्षक का कहना है कि 24 घण्टे की ड्यूटी है अतः विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी कहती है कि 8 घण्टे की ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए, अराजपत्रित महिला पुलिस की खासतौर पर महिला आरक्षियों की। 67 प्रतिशत ने अन्य ने विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं कि इस विभाग की ड्यूटी चुनौतीपूर्ण एवं रुचिकर है, लेकिन परिणाम हमेशा सुखदायक नहीं होता है। इस विभाग की ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी की है क्योंकि ये समाज की महत्वपूर्ण नौकरी है।

महिला पुलिस कर्मियों से ये पूछा कि किस तरह की ड्यूटी में आपको सुविधा या असुविधा होती है तो पदानुसार विभिन्न मत उन्होंने व्यक्त किये सबसे पहले महिला आरक्षियों के विचार सारिणी में देखें तो स्पष्ट होगा।

महिला आरक्षियों का मत किस् तरह की इयूटी में सुविधा या असुविधा



☐ रात्रि इयूटी में असुविधा

☐ शहर से बाहर की इयूटी में असुविधा

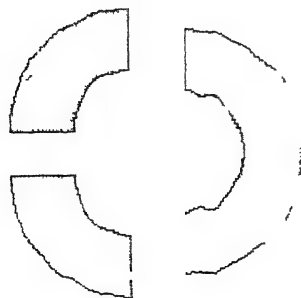
☒ किसी भी इयूटी में कोई दिक्कत नहीं है।

☐ कार्यालयल इयूटी में कोई दिक्कत नहीं है

☒ अन्य

☐ उत्तर नहीं दिया

महिला उपनिरीक्षकों का मत किस् तरह की इयूटी में सुविधा या असुविधा होती है



☐ जनपद से बाहर की इयूटी में असुविधा

☐ रात्रि इयूटी में असुविधा

☒ अन्य

सारिणी संख्या-6.20

किस तरह की ड्यूटी में सुविधा या असुविधा : महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1	रात्रि ड्यूटी में असुविधा	21	36 20
2	शहर से बाहर की ड्यूटी में असुविधा	9	15 51
3	किसी भी ड्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है।	6	10 34
4.	कार्यालयल ड्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है	5	8 6
5.	अन्य	5	8 62
6	उत्तर नहीं दिया	12	20 68
योग		58	100

सारिणी (संख्या 620) से स्पष्ट है कि 36 प्रतिशत महिला आरक्षी कहती हैं कि रात्रि ड्यूटी में असुविधा होती है। 16 प्रतिशत कहती हैं कि शहर से बाहर की ड्यूटी में परेशानी होती है। 10 प्रतिशत कहती हैं कि किसी भी प्रकार की ड्यूटी में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है। 9 प्रतिशत कहती हैं कि कार्यालय ड्यूटी में सुविधा होती है। 9 प्रतिशत ने अन्य विचार प्रस्तुत किये हैं जैसे-ऐसे समय में ड्यूटी करने में दिक्कत होती है जब अपना कोई जरूरी काम हो और छुट्टी या परमीशन न मिले। अधिक समय तक या असमय ड्यूटी में दिक्कत आती है। 21 प्रतिशत आरक्षियों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

इसी प्रश्न का उत्तर महिला उपनिरीक्षकों ने इस प्रकार से दिया है जो सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या-6.21

किस तरह की ड्यूटी में सुविधा या असुविधा होती है : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1	जनपद से बाहर की ड्यूटी में असुविधा	10	50
2.	रात्रि ड्यूटी में असुविधा	5	25
3.	अन्य	5	25
योग		20	100

50 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि जनपद से बाहर की ड्यूटी में असुविधा होती है, क्योंकि आवागमन का कोई साधन नहीं होता है इसके अलावा रहने, खाने इत्यादि की दिक्कत होती है। 25 प्रतिशत रात्रि ड्यूटी में असुविधा महसूस करती है। 25 प्रतिशत ने अन्य विचार व्यक्त किये हैं, जैसे—यूनीफार्म की ड्यूटी में सुविधा सादे कपड़ों में ड्यूटी में असुविधा होती है, आफिस या रूटीन वे की ड्यूटी में सुविधा रहती है, फील्ड ड्यूटी में रिवाल्वर न होने से असुविधा महसूस होती है या किसी नेता के घर में ड्यूटी देने पर बहुत खराब महसूस होता है, हीन भावना भी आती है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक भी मानती है, कि स्थानीय ड्यूटी में सुविधा होती है पर बाहर की ड्यूटियों में असुविधा होती है।

100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक की मानती है कि मेला, त्यौहार, रात्रि या वी०आई०पी० ड्यूटी में दिक्कत या असुविधा होती है। किन्तु 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती है, कि किसी भी ड्यूटी में कोई खास असुविधा नहीं होती है।

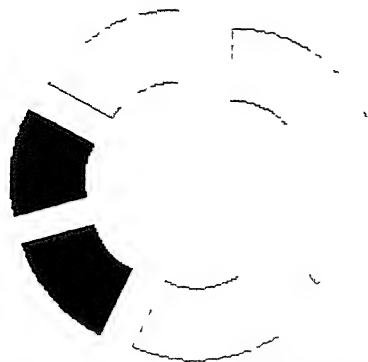
ड्यूटी के सम्बन्ध में एक और प्रश्न किया गया कि ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की शारीरिक या मानसिक परेशानियाँ आती हैं, तो विभिन्न मत पदानुसार मिले हैं।

साटिणी संख्या-6.22

ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानिया आती हैं ? : महिला आरक्षियों का मत

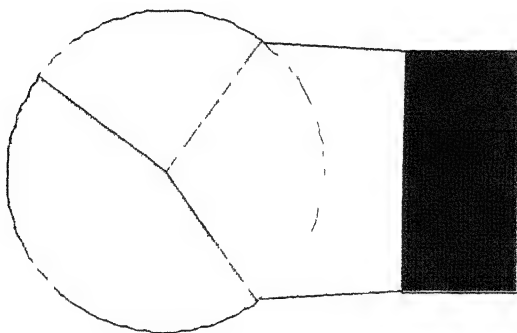
क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1.	लगातार अत्यधिक ड्यूटियों से ड्यूटी के दौरान शारीरिक थकान एवं मानसिक व पारिवारिक तनाव	23	39.65
2.	नारी सुलभ क्रियाओं या बीमारी के दौरान ड्यूटी में शारीरिक व मानसिक कष्ट	10	17.24
3.	रात्रि में या जिले से बाहर की ड्यूटियों में शारीरिक व मानसिक दोनों परेशानियाँ	8	13.79
4.	कोई परेशानी नहीं आती है	7	12.06
5.	उत्तर नहीं दिया	10	17.24
योग		58	100

महिला आरक्षियों का मत ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानिया आती हैं ?



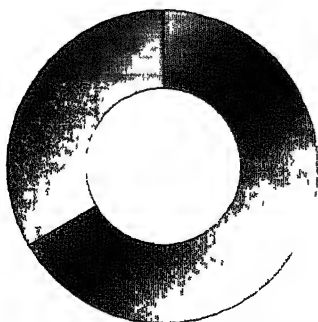
- ☐ लगातार अत्यधिक ड्यूटियों से ड्यूटी के दौरान शारीरिक थकान एवं मानसिक व पारिवारिक तनाव
- ☐ नारी सुलभ क्रियाओं या बीमारी के दौरान ड्यूटी में शारीरिक व मानसिक कष्ट
- ☒ रात्रि में या जिले से बाहर की ड्यूटियों में शारीरिक व मानसिक दोनों परेशानियों
- ☒ कोई परेशानी नहीं आती है
- ☐ उत्तर नहीं दिया

महिला उपनिरीक्षकों का मत ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की शारीरिक या मानसिक परेशानियाँ आती हैं।



- ☐ नारी सुलभ समस्याएँ मूलभूत सुविधाओं के न होने के कारण
- ☐ २४ घण्टे की ड्यूटी से परिवार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी मानसिक व शारीरिक परेशानियाँ आती हैं
- ☒ सही देखते हुए भी ऊपरी दबाव के कारण सही न्याय न दे पाने से मानसिक कष्ट
- ☒ अन्य

भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानियाँ आती हैं ?



- ☒ अत्यधिक या लगातार कार्य में जब आराम नहीं मिलता तो दोनों परेशानियाँ आती हैं।
- ☒ कोई दिक्कत नहीं आती

40 प्रतिशत महिला आरक्षी कहती है कि लगातार अत्यधिक ड्यूटियों से ड्यूटी के दौरान शारीरिक थकान एवं मानसिक व पारिवारिक तनाव आता है। 17 प्रतिशत ने कहा कि नारी सुलभ क्रियाओं या बीमारी के दौरान ड्यूटी से शारीरिक व मानसिक कष्ट होता है इनका ये भी कहना है कि बीमारी में तो आना ही पड़ता है तब बाद में छुट्टी मजूर होती है। 14 प्रतिशत कहती है रात्रि में या जिले से बाहर की ड्यूटियों के दौरान आने वाली रहने, खाने और आवागमन के साधनों की परेशानियों से शारीरिक, मानसिक परेशानी उत्पन्न होती है।

12 प्रतिशत मानती है, कोई दिक्कत नहीं आती है एवं 17 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

महिला उपनिरीक्षकों का इसी प्रश्न के उत्तर के फलस्वरूप निम्न तथ्य सामने आये हैं, जो कि सारिणी से स्पष्ट हैं।

सारिणी संख्या-6.23

ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की शारीरिक या मानसिक परेशानियाँ आती हैं : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1.	नारी सुलभ समस्याएँ मूलभूत सुविधाओं के न होने के कारण	9	45
2	24 घण्टे की ड्यूटी से परिवार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी मानसिक व शारीरिक परेशानियाँ आती हैं	5	25
3.	सही देखते हुए भी ऊपरी दबाव के कारण सही न्याय न दे पाने से मानसिक कष्ट	2	10
4.	अन्य	4	20
योग		20	100

सारिणी (संख्या 6.23) से स्पष्ट है कि 45 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि नारी सुलभ समस्याएँ, मूलभूत सुविधाओं के न होने के कारण ड्यूटी के

दौरान आती है जिससे शारीरिक व मानसिक परेशानियाँ होती है। 25 प्रतिशत मानती है कि 24 घन्टे की ड्यूटी से परिवार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी मानसिक व शारीरिक परेशानियाँ आती है। 10 प्रतिशत मानती है कि सही देखते हुए भी ऊपरी दबाव के कारण सही न्याय न दे पाने से मानसिक कष्ट होता है। 20 प्रतिशत ने अन्य विचार व्यक्त किया है जैसे—व्यक्ति विशेष की समस्या सुनने के बाद, निस्तारण पुलिस के हाथ न होने के बावजूद व्यक्तियों द्वारा उसकी आशा करना और मानसिक रूप से परेशान करते हैं। अधिक समय की ड्यूटी होने के कारण ड्यूटी बोज़िल व दुष्कर हो जाती है। बाहर या रात्रि की ड्यूटी में आवागमन की सुविधा न मिलने से भी तनाव होता है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक भी मानती है कि अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक परेशानियाँ ड्यूटी के दौरान आती है। 100 प्रतिशत उपाधीक्षक भी मानती है कि कभी—कभी मानसिक परेशानियाँ ड्यूटी के दौरान आती है।

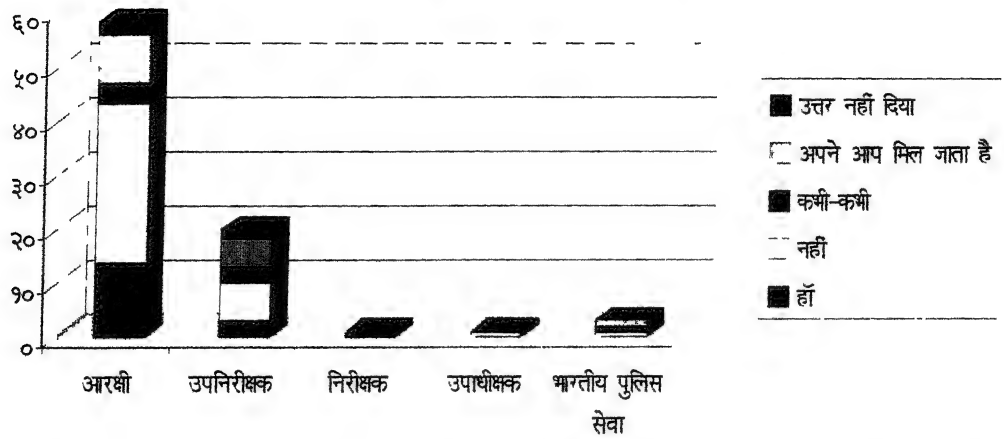
झाटिणी संख्या-6.24

ड्यूटी के दौरान क्या किसी तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानियाँ आती हैं ? : भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1.	अत्यधिक या लगातार कार्य में जब आराम नहीं मिलता तो दोनों परेशानियाँ आती हैं।	2	67
2.	कोई दिक्कत नहीं आती	1	33
योग		3	100

भारतीय पुलिस सेवा की 33 प्रतिशत महिला अधिकारियों का मानना है कि कोई दिक्कत नहीं आती है, जबकि 67 प्रतिशत मानती है कि लम्बे समय के कार्य में जब आराम नहीं मिलता है, तो शारीरिक, मानसिक परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं।

महिला पुलिस का मत क्या अपनी नौकरी का कभी लाभ उठाया है ?



महिला पुलिस से पूछा गया कि क्या आपने अपनी नौकरी का कभी लाभ उठाया है, तो पदानुसार निम्न मत व्यक्त किये हैं जो सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या-6.25

क्या अपनी नौकरी का कभी लाभ उठाया है ? :

महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	महिला पुलिस विभिन्न मत	पद										कुल	
		हाँ		नही		कभी-कभी		अपने आप मिल जाता है		उत्तर नहीं दिया			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	14	24.13	29	50	4	6.89	9	15.5	2	3.44	58	69.8
2	उपनिरीक्षक	3	15	7	35	3	15	5	25	2	10	20	24
3	निरीक्षक	—	—	—	—	1	100	—	—	—	—	1	120
4	उपाधीक्षक	—	—	1	100	—	—	—	—	—	—	1	120
5	भारतीय पुलिस सेवा	—	—	1	33.33	1	33.33	1	33.33	—	—	3	36
योग		17	20.48	38	45.78	9	10.84	15	18.07	4	4.81	83	100

सारिणी (संख्या 6.25) से स्पष्ट है कि 20 प्रतिशत महिला पुलिस स्वीकार करती हैं, कि उन्होंने अपनी नौकरी का लाभ उठाया गया है। 46 प्रतिशत स्वीकार करती हैं कभी भी लाभ नहीं उठाया है। 11 प्रतिशत मानती हैं कभी-कभी लाभ उठाया है एवं 18 प्रतिशत कहती हैं कि अपने आप लाभ मिल जाता है एवं 5 प्रतिशत महिला पुलिस ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

किसी भी तरह का लाभ जो कभी-कभी उठाया गया हो या अपने आप मिल जाता है या जिन्होंने हाँ में स्वीकार किया है कि लाभ उठाया है, तो कुल योग क्रमश 11 प्रतिशत + 18 प्रतिशत + 24 प्रतिशत = 53 प्रतिशत है तो हम कह सकते हैं कि 53 महिला पुलिस अपनी पूरी नौकरी में कभी-कभी कभी लाभान्वित अवश्य हुई हैं, चाहे उसके लिए उन्हें प्रयास करना पड़ हो या न करना पड़ा हो।

यदि पदानुसार देखे तो 24 प्रतिशत महिला आरक्षी स्वीकार करती है कि उन्होंने अपनी नौकरी का लाभ उठाया है। 50 प्रतिशत कहती है कोई लाभ नहीं उठाया है। 7 प्रतिशत कहती है कभी-कभी एव 16 प्रतिशत कहती है कि अपने आप मिल जाता है। 3 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि उन्होंने अपनी नौकरी का लाभ उठाया है 35 प्रतिशत ने कहा कि कोई लाभ नहीं उठाया है, 15 प्रतिशत ने कहा कभी-कभी लाभ उठाया है एव 25 प्रतिशत कहती है कि अपने आप लाभ मिल जाता है। 10 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने कहा कि उन्होंने लाभ कभी-कभी उठाया है।

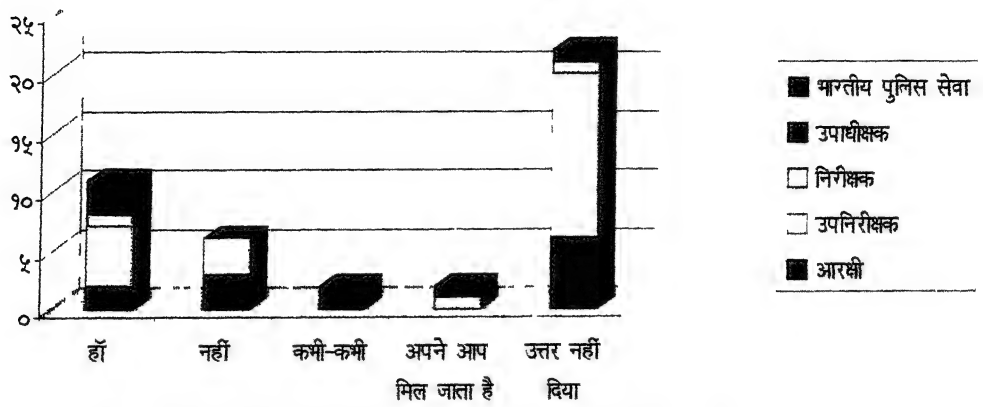
100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक कहती हैं कि उन्होंने लाभ नहीं उठाया है।

33 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी ने कहा कि लाभ नहीं उठाया है, 33 33 प्रतिशत ने कहा कि कभी-कभी लाभ उठाया है एवं 33 33 प्रतिशत का कहना है कि लाभ अपने आप मिल जाता है।

लाभ कभी-कभी सुविधाओं से भी सम्बन्धित है। उस तरह से जब हर पद पर कुछ लोगो को अपने आप लाभ मिल जाता है तो कम से कम उपाधीक्षक पद को भी कही न कही से कोई न कोई लाभ सुविधाओं का अवश्य मिलता होगा जिससे इकार नहीं किया जा सकता।

महिला पुलिस के साथ कार्य करने वाले पुरुष पुलिस से भी ये पूछा कि क्या महिला पुलिस अपनी नौकरी से कभी लाभ उठाती है, तो पदानुसार ये मत व्यक्त किया।

पुरुष पुलिस का मत क्या महिला पुलिस अपनी नौकरी का कभी लाभ उठाती हैं ?



सारिणी संख्या-6.26

क्या महिला पुलिस अपनी नौकरी का कभी लाभ
उठाती हैं ? : पुरुष पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	महिला पुलिस विभिन्न मत	पद										कुल	
		हाँ		नहीं		कभी-कभी		अपने आप मिल जाता है		उत्तर नहीं दिया			
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	2	18.18	3	27.27	—	—	—	—	6	54.54	11	25.58
2	उपनिरीक्षक	5	21.73	3	13.04	—	—	1	4.34	14	60.86	23	53.78
3	निरीक्षक	1	50	—	—	—	—	—	—	1	50	2	4.65
4	उपाधीक्षक	3	60	—	—	1	20	1	20	—	—	5	11.62
5	भारतीय पुलिस सेवा	—	—	—	—	1	50	—	—	1	50	2	4.65
योग		11	25.58	6	13.95	2	4.65	2	4.65	22	51.16	43	100

सारिणी (संख्या 6.26) से स्पष्ट है कि कुल 26 प्रतिशत मानते हैं कि महिला पुलिस अपनी नौकरी का लाभ उठाती हैं, 14 प्रतिशत मानते हैं कि महिला पुलिस लाभ नहीं उठाती है, 5 प्रतिशत मानते हैं कभी-कभी लाभ उठाती है, 5 प्रतिशत मानते हैं कि अपने आप लाभ मिल जाता है। सर्वाधिक 51 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

18 प्रतिशत आरक्षी मानते हैं कि महिला पुलिस अपनी नौकरी का लाभ उठाती है, 27 प्रतिशत मानते हैं कि लाभ नहीं उठाती हैं। 54 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

22 प्रतिशत पुरुष उपनिरीक्षक मानते हैं कि महिला पुलिस नौकरी का लाभ उठाती है। 13 प्रतिशत मना करते हैं। 14 प्रतिशत मानते हैं कि अपने आप लाभ मिल जाता है, एव 61 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

50 प्रतिशत पुलिस निरीक्षक मानते हैं कि महिला पुलिस अपनी नौकरी का लाभ उठाती है। 50 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है।

60 प्रतिशत पुरुष उपाधीक्षक मानते हैं कि महिला पुलिस अपनी नौकरी का फायदा उठाती है। 20 प्रतिशत कहते हैं, कि कभी-कभी लाभ उठाती है। 20 प्रतिशत मानते हैं कि अपने आप लाभ मिल जाता है।

50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारी मानते हैं कि कभी-कभी लाभ उठाती है। 50 प्रतिशत ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

यदि हम महिला पुलिस के उत्तर को देखे तो 20 प्रतिशत महिला पुलिस स्वीकार करती है, कि उन्होंने अपनी नौकरी का लाभ उठाया है। 26 प्रतिशत पुरुष पुलिस भी मानते हैं कि महिला पुलिस अपनी नौकरी का फायदा उठाती है। इन दोनों का प्रतिशत का लगभग आसपास ही है, बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है।

महिला पुलिस से उनकी यूनीफार्म या वर्दी के बारे में राय पूँछी गयी, तो पदानुसार विभिन्न प्रकार के मत सामने आये हैं।

महिला आरक्षियों ने अपने मत निम्न प्रकार से व्यक्त किये हैं—

साटिणी संख्या-6.27

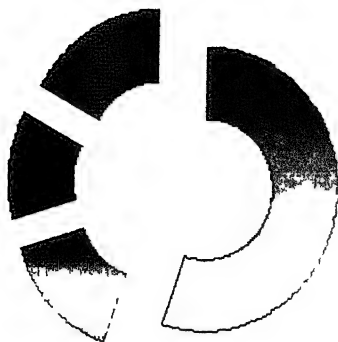
यूनीफार्म या वर्दी : महिला आरक्षियों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1.	ठीक है	32	55.17
2	परिस्थितियों के अनुसार परिधान धारण की सुविधा होनी चाहिए	9	15.51
3	अन्य	7	12.06
4.	उत्तर नहीं दिया	10	17.24
योग		58	100

55 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है, कि उनकी यूनीफार्म ठीक है। 16 प्रतिशत कहती हैं कि परिस्थितियों के अनुरूप परिधान धारण करने की सुविधा होनी चाहिए जैसे—महीने के कुछ दिनों में, गर्भावस्था में या उम्र के बढ़ने पर या मोटापा आदि बढ़ने पर सूट या साडी पहनने की छूट होनी चाहिए।

12 प्रतिशत अन्य विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं जैसे—शर्ट बाहर की ओर यानि एन०सी०सी० जैसी, पैट से बाहर होनी चाहिए। यूनीफार्म ही मेरी पहचान है, आम लडकियों से अलग महसूस करती हूँ, वर्दी निर्धारित समय पर मिल नहीं पाती और

महिला आरक्षियों का मत यूनिफ़ॉर्म या वर्दी के बारे में



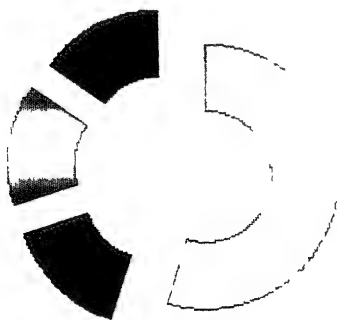
☐ उचित है

☐ परिस्थितियों के अनुसार परिधान धारण की सुविधा होनी चाहिए

☐ अन्य

☐ उत्तर नहीं दिया

महिला उपनिरिक्षकों का मत वर्दी या यूनीफ़ॉर्म के बारे में



☐ उचित है

☐ परिस्थितियों के अनुसार परिधान धारण की सुविधा होनी चाहिए

☐ अन्य

☐ उत्तर नहीं दिया

अपने वेतन आदि से बनवाना पड़ता है। जिससे काफी कष्ट होता है। अतः समय पर वर्दी मिलनी चाहिए। 17 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

महिला उपनिरीक्षकों की वर्दी के बारे में निम्नलिखित विभिन्न मत हैं जो सारिणी से स्पष्ट हैं।

सारिणी संख्या-6.28

वर्दी या यूनीफार्म : महिला उपनिरीक्षकों का मत

क्रम	विभिन्न विचार या मत	संख्या	प्रतिशत
1	उचित है	11	55
2	परिस्थितियों के अनुसार परिधान धारण की सुविधा होनी चाहिए	3	15
3.	अन्य	3	15
4.	उत्तर नहीं दिया	3	15
योग		20	100

सारिणी (संख्या 6.28) से स्पष्ट है कि 55 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती हैं कि वर्दी उचित है। 15 प्रतिशत मानती हैं कि परिस्थितियों के अनुसार धारण करने की सुविधा होनी चाहिए। जैसे—मोटापा या उम्र बढ़ने पर (40-45 की उम्र के बाद) शलवार कुर्ता या साड़ी पहनने की छूट होनी चाहिए। 15 प्रतिशत में अन्य विचार व्यक्त किये हैं। जैसे—वर्दी आकर्षण नौकरी की तरफ खींचता है या बैरट कैप ठीक नहीं लगती, सुविधा के लिए लगा ली जाती है। पी कैप अनिवार्य कर देनी चाहिए। 15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक मानती हैं कि यूनीफार्म ठीक है।

100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक मानती हैं कि परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदल लेने की छूट होनी चाहिए।

100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती हैं, कि वर्दी ठीक है।

महिला पुलिस से उनके प्रति परिवार के सदस्यों के व्यवहार के बारे में पूछा कि, उनके प्रति परिवार वालों का व्यवहार आम महिला की तरह ही होता है या खास। तो पदानुसार निम्न मत प्राप्त होते हैं।

सारिणी संख्या-6.29

उनके प्रति परिवार के सदस्यों का व्यवहार आम महिला की तरह या खास : महिला पुलिस कर्मियों का मत

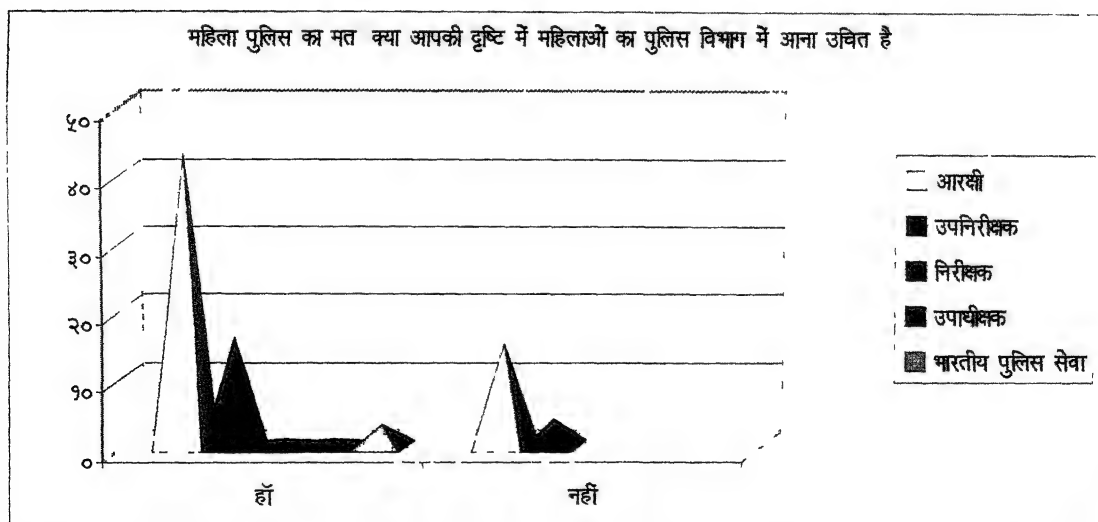
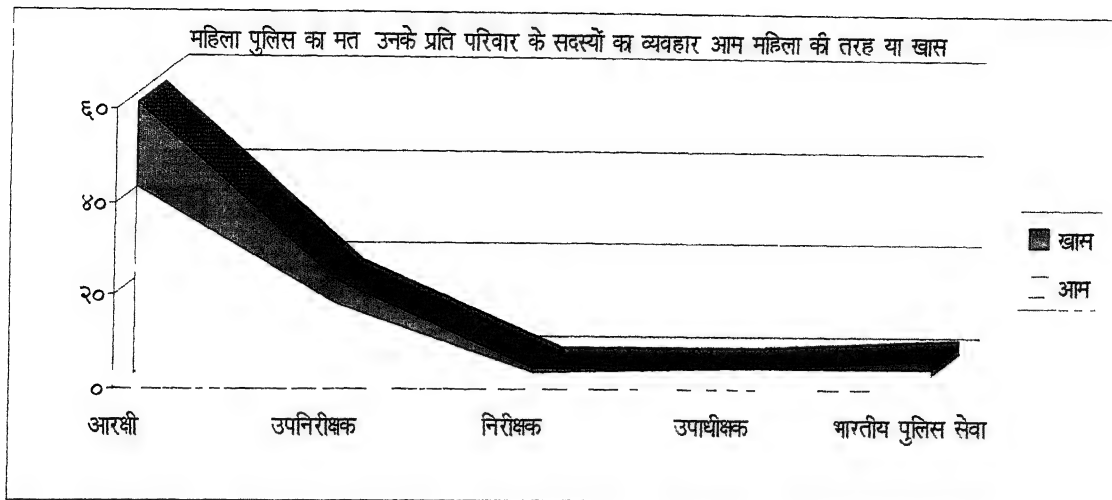
क्रम	पद	आम		खास		कुल योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	40	68.96	18	31	58	69.8
2	उपनिरीक्षक	15	75	5	25	20	24
3	निरीक्षक	—	—	1	100	1	1.20
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	1	33	2	67	3	3.6
योग		57	68.67	26	31.32	83	100

सारिणी (संख्या 6.29) से स्पष्ट है कि 69 प्रतिशत महिला पुलिस मानती हैं कि उनके प्रति परिवार का व्यवहार आम महिला की तरह ही होता है, 31 प्रतिशत मानती है खास व्यवहार उनके प्रति होता है या कुछ हटकर होता है।

पदानुसार देखे तो 69 प्रतिशत महिला आरक्षी आने प्रति आम महिला की तरह ही व्यवहार मानती हैं। 31 प्रतिशत खास मानती हैं।

75 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी आम व्यवहार मानती हैं। 25 प्रतिशत खास।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक खास व्यवहार मानती हैं। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक आम व्यवहार मानती हैं।



33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी आम व्यवहार स्वीकार करती है जबकि 67 प्रतिशत खास व्यवहार स्वीकार करती है।

महिला पुलिस से पूछा गया कि क्या आपकी दृष्टि में महिलाओं का पुलिस विभाग में आना उचित है तो पदानुसार निम्न मत प्राप्त हुए हैं—

सारिणी संख्या-6.30

क्या आपकी दृष्टि में महिलाओं का पुलिस विभाग में आना उचित है : महिला पुलिस कर्मियों का मत

क्रम	पद	हाँ		नहीं		कुल योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आरक्षी	43	74.13	15	25.8	58	69.8
2	उपनिरीक्षक	16	80	4	20	20	24
3	निरीक्षक	1	100	—	—	1	1.20
4	उपाधीक्षक	1	100	—	—	1	1.20
5	भारतीय पुलिस सेवा	3	100	—	—	3	3.6
योग		64	77.10	19	22.89	83	100

सारिणी (संख्या 6.30) से स्पष्ट है कि कुल 77 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है, कि महिलाओं का पुलिस विभाग में आना उचित है। 23 प्रतिशत मानती है कि पुलिस विभाग में महिलाओं का आना उचित नहीं है।

पदानुसार देखे तो 74 प्रतिशत आरक्षी मानते हैं, कि महिला को पुलिस विभाग में आना चाहिए। 26 प्रतिशत मानती है, कि पुलिस विभाग में आना उचित नहीं है।

80 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि महिलाओं का पुलिस विभाग में आना उचित है। जबकि 20 प्रतिशत मानती हैं, कि पुलिस विभाग में आना उचित नहीं है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक, 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक एव 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती है कि महिलाओं का इस विभाग में आना उचित है।

सारिणी से पता चलता है कि आरक्षी एव उपनिरीक्षक पद की कुछ महिलाओं को लगता है कि महिलाओं का पुलिस विभाग में आना उचित नहीं है जबकि निरीक्षक, उपाधीक्षक एव भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों को महिलाओं का इस विभाग में आना अनुचित नहीं लगता है।

अध्याय—७

निष्कर्ष एवं सुझाव

(Conclusion and Suggestions)

उ० प्र० महिला पुलिस के बारे में जानकारी से पहले भारत में पुलिस बल की स्थिति देखे तो, 1995 में देश में कुल स्वीकृत पुलिस बल 13.29 लाख थी, जबकि वास्तविक पुलिस बल 12.5 लाख व्यक्तियों का था, इसमें से 9.7 लाख सिविल पुलिस (73.34 प्रतिशत) एवं 2.81 लाख (26.6 प्रतिशत) सशस्त्र पुलिस है। सिविल पुलिस का सबसे बड़ा दस्ता 1.21 लाख (12.8 प्रतिशत) तथा सशस्त्र पुलिस बल (12.1 प्रतिशत) सबसे अधिक उ० प्र० में है।

स्वीकृत महिला सिविल पुलिस बल की कुल संख्या (1995 में) 18,373 थी जबकि वास्तविक संख्या 15,337 थी। यह अनुपात कुल वास्तविक सिविल पुलिस का 1:63 है।

महिला पुलिस बल महाराष्ट्र में सबसे अधिकतम (16.4 प्रतिशत) है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है।

1938 में कानपुर में श्रमिक अशान्ति के समय में एक दर्जन महिला आरक्षी भर्ती की गयी और हड़ताल की समाप्ति के बाद उक्त महिला कर्मचारियों के पद समाप्त कर दिये गये। इसके बाद 1952, 1964 एवं 1966 में आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं सब-इन्स्पेक्टर के पद समय-समय पर सृजित किये गये, लेकिन वर्ष 1974 में उ० प्र० शासन ने महिला पुलिस के नियमित गठन के आदेश दिये। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1979 ने महिला पुलिस की अनिवार्यता को अनुभव किया और पुलिस में महिलाओं की भर्ती किये जाने की सन्तुति की। पूरे प्रदेश में महिला थाना की संख्या 13 है, जो कि 13 जनपदों में स्थित है, उनके नाम क्रमशः (वर्ष 30.04.2000 की स्थिति के अनुसार) आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, अल्मोड़ा, मेरठ, पौड़ीगढ़वाल, गोरखपुर, वाराणसी, तथा कानपुर नगर। महिला थानों पर स्वीकृत महिला पुलिस के पद हैं इसके अलावा जनपदवार स्वीकृत पद भी हैं।

प्रदेशीय पुलिस का मुख्यालय प्रदेश की भूतपूर्व राजधानी इलाहाबाद में स्थित है, परन्तु पुलिस प्रमुख 'पुलिस महानिदेशक' का कार्यालय वर्तमान राजधानी लखनऊ में स्थित है। प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के मुख्यालय लखनऊ में स्थित हैं, मात्र पुलिस का प्रशासनिक विभाग ही इलाहाबाद में स्थित है। प्रदेश पुलिस के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पद ऊँचे से नीचे पदों की ओर क्रमशः (1) पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक (2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (3) पुलिस महानिरीक्षक (4) पुलिस उपमहानिरीक्षक (5) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक (6) सहायक पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (7) पुलिस उपाधीक्षक (8) निरीक्षक (9) उपनिरीक्षक (10) मुख्य आरक्षी (11) आरक्षी हैं।

1902 के पुलिस आयोग की सस्तुतियों के फलस्वरूप प्रदेश में सर्वप्रथम मुरादाबाद में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया। वर्तमान में तीन पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (मुरादाबाद में—2 तथा सीतापुर में—1) एक सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र सीतापुर, पाँच पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (एक मुरादाबाद में, एक उन्नाव में तथा तीन गोरखपुर में हैं।) एक रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र चुनार में स्थित है। शाहजहाँपुर पुलिस लाइन में महिला कान्सटेबुल प्रशिक्षणार्थियों हेतु एक आर०टी०सी० कार्यरत है।

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक प्रकार का है, शोध का विषय "उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों की कार्यदशाएँ, सफलताएँ और समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण" है, जिस पर प्रथम बार कार्य होने के कारण तथ्यों का संकलन या सूचनाओं के एकत्रीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक स्रोतों के द्वारा किया गया है। जिसमें औपचारिक व अनौपचारिक, साक्षात्कार, अनुसूची का प्रयोग मुख्य तौर पर तथा अवलोकन प्रयोग किया गया है। जिसका उद्देश्य महिला पुलिस की भूमिका सफलताएँ एवं कार्यदिशाएँ तथा कर्तव्य पालन में आने वाली बाधाएँ हैं।

प्रस्तुत शोध में तीन वर्गों से निदर्शन का निश्चयन किया है। वह वर्ग हैं, महिला पुलिस कर्मी, पुरुष पुलिस कर्मी एवं सामान्यजन के लोग जो कि विभिन्न

क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। निर्देशन के चयन का आधार उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निर्दर्शन है। पुलिस कर्मी सूचनादाताओं का चुनाव (महिला एवं पुरुष दोनों के लिए) इलाहाबाद और कानपुर दोनों ही जगह है, लेकिन सामान्य सूचनादाताओं के लिए केवल इलाहाबाद क्षेत्र ही चुना गया है। पुलिस कर्मियों में विभिन्न पदों, आयु वर्गों और सेवाकाल के लोगों का चुनाव किया है।

18-25 आयु वर्ग की 19 प्रतिशत महिला पुलिस है, 26-35 आयु वर्ग में 43 प्रतिशत महिला पुलिस हैं, 36-45 आयु वर्ग में 36 प्रतिशत, 46-55 आयु वर्ग की 12 प्रतिशत महिला पुलिस है। सामान्य सूचनादाता में 18-30 आयु वर्ग के 21 प्रतिशत लोग हैं, 31-40 आयु वर्ग में 25 प्रतिशत लोग, 41-50 आयु वर्ग में 30 प्रतिशत तथा 51-60 आयु वर्ग में 20 प्रतिशत लोग एवं 60 से ऊपर में 4 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता हैं।

कुल पुलिस कर्मियों का लिंग के आधार पर वर्गीकरण में 66 प्रतिशत स्त्री तथा 34 प्रतिशत पुरुष है। सामान्य सूचनादाताओं में 21 प्रतिशत स्त्रियाँ तथा 79 प्रतिशत पुरुष हैं।

5 वर्ष की सेवा अवधि की 51 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी 6-10 वर्ष के सेवा अवधि वाली 12 प्रतिशत महिला पुलिस हैं। 11-15 वर्ष की सेवा अवधि में 13 प्रतिशत, 16-20 वर्ष की सेवा अवधि वाली 14 प्रतिशत, 21-25 वर्ष की सेवा अवधि वाली 10 प्रतिशत महिला पुलिस हैं।

पुरुष पुलिस कर्मी में 5 वर्ष की सेवा अवधि के 14 प्रतिशत, 6-10 वर्ष के अवधि के एक भी सूचनादाता नहीं है। 11-15 वर्ष की सेवा अवधि में 12 प्रतिशत लोग हैं। 16-20 वर्ष की सेवा अवधि में 21 प्रतिशत तथा 21-25 वर्ष की सेवा अवधि में 5 प्रतिशत लोग हैं। सर्वाधिक 26 वर्ष एवं इसके ऊपर में 49 प्रतिशत लोग हैं।

5 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी हाई स्कूल, 33 प्रतिशत इन्टर, 39 प्रतिशत स्नातक, 24 प्रतिशत परास्नातक हैं। सामान्य सूचनादाताओं में 5 प्रतिशत हाई

स्कूल, 3 प्रतिशत इन्टर, 25 प्रतिशत स्नातक, 26 प्रतिशत परास्नातक 42 प्रतिशत अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं।

49 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अविवाहित, 43 प्रतिशत विवाहित, 1.20 प्रतिशत तलाकशुदा एवं 6 प्रतिशत विधावा हैं।

96 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हिन्दू तथा 4 प्रतिशत मुस्लिम हैं। पुरुष पुलिस कर्मियों में 95 प्रतिशत हिन्दू, 5 प्रतिशत मुस्लिम हैं। सामान्य सूचनादाताओं में 95 प्रतिशत हिन्दू तथा 5 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित है। महिला पुलिसकर्मी जाति के आधार पर सामाजिक कोटियाँ यदि देखें तो 71 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी उच्च जाति, 24 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं। 70 प्रतिशत पुरुष पुलिस उच्च जाति 28 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 2 प्रतिशत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं। 84 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता उच्च जाति 12 प्रतिशत पिछड़ी जाति 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं।

67 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों की स्वयं की भूमिका पालन के संदर्भ में विचार है कि उनके कार्य को सराहा गया है। 70 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मी भी यह मानते हैं कि वो अपनी ड्यूटी को ढंग से निभाती हैं। 60 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं मानते हैं कि महिला पुलिस का रवैया किसी मामले को निपटाने में पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा अच्छा रहता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दिये हुए कर्तव्यों को निभाने में महिला पुलिस सफल रही है।

महिला पुलिस कर्मियों को कार्यों के दौरान कभी-कभी 'भूमिका संघर्ष' की अवस्था भी आती हैं। 42 प्रतिशत ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, 40 प्रतिशत कभी-कभी के रूप में स्वीकार किया है।

26 प्रतिशत सामान्यजन सूचनादाताओं ने महिला पुलिस से वैवाहिक सम्बन्ध बनाने में दिक्कत महसूस की हैं। 53 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने भी दिक्कत महसूस की है साथ ही 53 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी भी मानती हैं कि महिला

पुलिस कर्मियों के विवाह में दिक्कत आती है। पुरुष पुलिस कर्मियों और महिला पुलिस कर्मियों में दिक्कत महसूस करने का प्रतिशत एक समान ही है। सामान्य सूचनादाताओं का इसका लगभग आधा प्रतिशत है। इतना अवश्य है, कि महिला पुरुष के विवाह में कुछ न कुछ दिक्कत जरूर होती है। राजपत्रित महिला पुलिस कर्मियों के विवाह में दिक्कत कम और अराजपत्रित महिला पुलिस कर्मियों के विवाह में दिक्कत राजपत्रित की अपेक्षा आती है।

पुलिस विभाग महिला पुलिस के सदस्य समूह के रूप में 42 प्रतिशत है, जबकि उनके बच्चों की सम्भावना के रूप में 64 प्रतिशत है। 53 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी अपनी बहन या बेटी को इस विभाग में आने देंगे। 86 प्रतिशत सामान्य सूचनादाताओं की बहन या बेटी के लिए सदस्य समूह हो सकता है। इस 85 प्रतिशत में 64 प्रतिशत मत केवल राजपत्रित होने पर ही पुलिस विभाग में आने देने के लिए है।

69 प्रतिशत महिला पुलिस, महिला पुलिस की उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित क्षेत्र में ही अनुभव करती है। 17 प्रतिशत सभी प्रकार से देश व समाज के लिए महिला पुलिस कर्मियों को उपयोगी मानती है।

56 प्रतिशत पुरुष पुलिस ने महिला पुलिस की उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में स्वीकार की है। 16 प्रतिशत सभी प्रकार से देश व समाज के लिए उपयोगी मानती हैं।

79 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता के अनुसार भी महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित मामलों के स्वीकार करते हैं। 9 प्रतिशत सभी प्रकार से उपयोगी मानते हैं।

स्वयं महिला पुलिसकर्मी पुरुष पुलिसकर्मी एवं सामान्य सूचनादाता महिला पुलिस की उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में स्वीकार करते हैं साथ ही समाज में सभी प्रकार से उपयोगी भी मानते हैं।

महिला पुलिस कर्मियों ने किसी खास काम को सौंपने के सम्बन्ध में 33 प्रतिशत ने हाँ, 66 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है इसमें भी महिला आरक्षियों का हाँ में उत्तर सबसे कम है, फिर उपनिरीक्षक, भारतीय पुलिस सेवा, निरीक्षक और उपाधीक्षक का है यानि अराजपत्रित महिला पुलिस को विशेष कार्य कम मात्रा में सौंपे जाते हैं।

महिला आरक्षियों जिन्होंने हाँ में उत्तर दिया है, उसमें उनके पदानुसार कार्य सौंपे गये हैं लेकिन अधिकतर धार्मिक स्थानों और महिलाओं से सम्बन्धित ड्यूटी दी है।

महिला उपनिरीक्षक के भी 60 प्रतिशत महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों या समस्याओं का समाधान ही करवाया है।

महिला निरीक्षक ने भी वी०आई०पी० सुरक्षा एवं दस्यु उन्मूलन के कार्य बताये, महिला उपाधीक्षक ने कुम्भ मेला, चुनाव ड्यूटी से सम्बन्धित कार्य रहा है। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारियों ने मानवाधिकार से सम्बन्धित मामले और चुनाव की ड्यूटी कहा है।

काम सौंपे जाने का मतलब है कि वह कार्य को ढग से कर रही हैं और समाज में उसकी उपयोगिता भी है। 77 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी मानते हैं कि महिला पुलिस कर्मियों को उनकी क्षमता के अनुसार ही ड्यूटी दी जाती है। 67 प्रतिशत महिला पुलिस मानती भी है कि उनके कार्यों की प्रशंसा भी कभी न कभी की गयी है। जबकि 24 प्रतिशत इनकार करती हैं।

33 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती हैं कि उन्हें पद के अनुभव सभी प्रकार के कार्य मिले हैं, 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी यही मानती हैं। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने भी स्वीकार किया कि पदानुसार सभी प्रकार के कार्य किये हैं। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक ने भी यही कहा है कि सभी प्रकार के कार्य मिले हैं। 67 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी भी यही मानती हैं। 15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती हैं कि कुछ खास नहीं केवल औपचारिकता निभाई जाती है।

41 प्रतिशत महिला पुलिस ने अपने पुरुष वरिष्ठ अधिकारियों के सम्बन्ध में कहा है कि उनके सम्बन्ध उनसे अच्छे हैं। 55 प्रतिशत ने कहा है कि सामान्य या ठीक है। 4 प्रतिशत ने कहा ठीक नहीं है।

60 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने कहा है कि उनके उच्च महिला अधिकारियों से सम्बन्ध अच्छे हैं, 40 प्रतिशत ने कहा सामान्य है।

26 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मी मानते हैं कि उनके साथ काम करने वाली समान स्तर की महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार अच्छा है, 74 प्रतिशत ने कहा सामान्य है।

37 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी मानते हैं, कि अपने से नीचे पदों पर तैनात महिला पुलिस का व्यवहार उनके प्रति अच्छा रहा है। 44 प्रतिशत मानते हैं सामान्य एवं 5 प्रतिशत ने कहा है कि खराब रहा है।

महिला पुलिस कर्मियों का अपने से उच्च पुरुष पुलिस कर्मियों से एवं उच्च पुरुष पुलिस कर्मियों का अपने अधीनस्थ महिला पुलिस कर्मियों से व्यवहार में कुछ यानि जैसा कि महिलाओं ने 4 प्रतिशत एवं पुरुषों ने 5 प्रतिशत ठीक नहीं है, स्वीकार किया है। पुरुष पुलिस कर्मियों एवं महिला पुलिस कर्मियों का एक समान पद पर रहने पर आपस में सम्बन्ध अच्छे हैं। इसके अलावा यदि उच्च अधिकारी महिला है तो उसके अधीनस्थों से उसमें सम्बन्ध अच्छे हैं।

62 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता मानते हैं कि महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा अच्छा रहता है। 36 प्रतिशत मानते हैं पुरुष पुलिस कर्मियों की तरह ही रहता है। 1.2 प्रतिशत मानते हैं खराब रहता है।

53 महिला पुलिसकर्मी मानती है, कि उनके प्रति पुरुषों के व्यवहार में परिवर्तन आया है। 47 प्रतिशत मानती है कोई परिवर्तन नहीं आया है।

72 प्रतिशत साधारण जन के पुरुष उत्तरदाता ये मानते हैं कि पुलिस विभाग की महिला में एव अन्य विभाग की महिला की अपेक्षा अन्तर होता है। 28 प्रतिशत मानते हैं कोई अन्तर नहीं होता है।

81 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी भी मानते हैं कि इस विभाग की महिला एव साधारण महिला में अन्तर होता है, जबकि 19 प्रतिशत मानते हैं कि कोई अन्तर नहीं होता है।

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकतर लोग ये मानते हैं, कि इस विभाग की महिला अन्य विभाग की महिलाओं से अलग होती है या अन्तर होता है।

77 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपनी वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट हैं, 23 प्रतिशत असन्तुष्ट हैं। असन्तुष्ट के लिए पदानुसार अलग-अलग कारण दिये हैं। 18 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती हैं कि पदोन्नति न मिलने के कारण, 27 प्रतिशत मानती हैं कि अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है। 27 प्रतिशत मानती हैं छोटे कर्मचारियों का शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता है। 27 प्रतिशत मानती हैं, समयाभाव के कारण परिवार को समय दे पाना।

25 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी मानती हैं, कि पदोन्नति समय से नहीं मिलती है। 13 प्रतिशत कहती हैं कि अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है। 37 प्रतिशत कहती हैं महिला पुलिस के प्रति विभाग का रवैया सही नहीं है। 25 प्रतिशत कहती हैं जो कार्य करना चाहती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। जबकि निरीक्षक, उपाधीक्षक और भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी अपनी सेवा से संतुष्ट हैं।

57 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती हैं कि ड्यूटी के दौरान उन्हें अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। 2 प्रतिशत ने कहा है कि कभी-कभी ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ता है, 41 प्रतिशत मानती हैं कि कोई अपमान जनक व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ता है।

100 प्रतिशत पुरुष पुलिस मानते हैं कि यदि उनकी उच्च अधिकारी महिला हो तो वे उनको वैसा ही सम्मान देते हैं, जैसे कि एक पुरुष अधिकारी को लेकिन

44 प्रतिशत पुरुष पुलिस मानते हैं कि महिला पुलिस की उपस्थिति से उनके व्यवहार में नियंत्रण लगता है।

17 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती हैं कि उनकी भाषा में परिवर्तन या अपशब्द का प्रयोग करना बढ़ जाता है। 81 प्रतिशत ने मना किया है। 2 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। 81 प्रतिशत सामान्यजन महिला सूचनादाताओं ने भी माना है, कि अन्य विभाग की महिलाओं की अपेक्षा, महिला पुलिस में अन्तर पाती है। अन्तर के कारणों में 25 प्रतिशत मत बातचीत का ढग बदल जाता है या अपशब्दों का प्रयोग करती हैं, को स्वीकार किया है।

53 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती हैं कि उनका व्यवहार अपराधों के प्रति पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा अलग रहता है, लेकिन केवल इस आधार पर कि पूँछ-ताँछ करने के तरीके में अन्तर होता है। हिंसा का सहारा ज्यादा नहीं लेती हैं और सजा दिलाने की कोशिश में वह पुरुष पुलिस की तरह ही कार्य करती हैं।

48 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी कर्तव्यपालन में भ्रष्टाचार के कारण दबाव या तनाव महसूस करती हैं। 43 प्रतिशत ऐसा महसूस नहीं करती हैं और 8 प्रतिशत ने जबाब नहीं दिया।

53 प्रतिशत महिला पुलिस मानती हैं कि इस विभाग की महिला के विवाह में दिक्कत होती है, 16 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है, 31 प्रतिशत ने माना कोई खास दिक्कत नहीं होती है।

53 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों ने, महिला पुलिस से किसी प्रकार का वैवाहिक सम्बन्ध बनाने के दिक्कत महसूस करती हैं। 40 प्रतिशत ने कोई दिक्कत महसूस नहीं की है यानि वे स्वयं या उनके परिवार में बहू के रूप में महिला पुलिस कर्मियों से विवाह में दिक्कत नहीं महसूस करते हैं। 7 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। 45 प्रतिशत महिलाकर्मी पुलिस मानती हैं कि महिला पुलिस शोषण का शिकार है, जबकि 55 प्रतिशत ऐसा नहीं मानती हैं।

40 प्रतिशत महिला आरक्षी मानते हैं कि मानसिक शोषण होता है। 20 प्रतिशत मानती हैं कि महिला पुलिस को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। 3 प्रतिशत मानती हैं कि महिला पुलिस की प्रतिभा को दबाया जाता है।

46 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती हैं कि मानसिक व भावनात्मक शोषण होता है। 38 प्रतिशत मानती हैं कि उन्हें हीन एव दया का पात्र मानते हैं। 15 प्रतिशत मानती हैं कि उन्हें कहीं भी ड्यूटी में भेज दिया जाता है और अधिकारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक मानती हैं कि बराबर काम करने पर भी पुरुष के बराबर महत्व नहीं दिया जाता है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी का कहना है, कि उन्हें गम्भीरता से नहीं लिया जाता है, उन्हें कम महत्वपूर्ण कार्य दिये जाते हैं।

40 प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी का शोषण होता है, 55 प्रतिशत का कहना है कि शोषण नहीं होता है एव 5 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। 55 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती हैं कि समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल जानी चाहिए। 16 प्रतिशत मानती हैं कार्य या योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, 5 प्रतिशत मानती हैं कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर पदोन्नति मिलनी चाहिए।

40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक कहती हैं कि समयानुसार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जानी चाहिए। 20 प्रतिशत कहती हैं कि ये सही मूल्यांकन के आधार पर होनी चाहिए फर्जी नहीं। 15 प्रतिशत मानती हैं कि पदोन्नति बहुत कम होती है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक कहती हैं कभी-कभी अनियमितता हो जाती है, 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक मानती हैं कि समय-समय पर पदोन्नति होती रहती है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों ने माना कि अधिकतर साफ सुथरे तरीकों से ही होती है।

सामान्यत महिला पुलिसकर्मी के अनुसार समय पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जानी चाहिए।

48 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है कि विभाग द्वारा दी हुई छुट्टी पर्याप्त है और समय से मिल जाती है जबकि 46 प्रतिशत मानती है कि न तो छुट्टी पर्याप्त है और न ही समय से मिलती है, 6 प्रतिशत महिला पुलिस ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

स्थानान्तरण पर भी पदानुसार विभिन्न मत व्यक्त किये हैं पर 21 प्रतिशत महिला आरक्षी ने कहा है कि कहीं भी हो जाय, 21 प्रतिशत ने कहा जल्दी-जल्दी न हो। 14 प्रतिशत ने कहा कि आवेदन पत्र लेकर सुविधानुसार किया जाय। 12 प्रतिशत कहती है गृह जनपदों के निकट रखा जाय, 7 प्रतिशत कहती है कि स्थायी हो या एक ही जिले में कुछ वर्ष के लिए निश्चित हो।

20 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी ये मानती हैं कि जल्दी-जल्दी नहीं होना चाहिए, 20 प्रतिशत कहती है कि आवश्यक है अतः होते रहने चाहिए, 15 प्रतिशत ने कहा कुछ निश्चित अवधि के पश्चात् होना चाहिए यानि कुल 35 प्रतिशत मानती है कि स्थानान्तरण कुछ निश्चित अवधि के बाद होना चाहिए, जल्दी-जल्दी नहीं। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक कहती हैं कि स्थानान्तरण के विभिन्न विसंगतियाँ हैं। 100 प्रतिशत महिला अधीक्षक मानती है कि एक निश्चित समय बाद ही हो। जबकि 66 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी मानती हैं कि उ०प्र० में अनावश्यक अत्यधिक स्थानान्तरण होते हैं, स्थानान्तरण एक निश्चित समय बाद होना चाहिए।

कुल निष्कर्ष ये है कि जल्दी-जल्दी स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए बल्कि एक निश्चित अवधि के पश्चात् ही होना चाहिए।

47 प्रतिशत महिला पुलिस अपने वेतन और भत्तों से संतुष्ट हैं जबकि 53 प्रतिशत असंतुष्ट है। संतुष्ट होने का सर्वाधिक प्रतिशत उपाधीक्षक और भारतीय पुलिस सेवा के पदों में ही है।

विभाग से सम्बन्धित मुख्य परेशानियों में सभी पदों के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं लेकिन उनका निष्कर्ष यह है कि भागदौड़ की 24 घण्टे की ड्यूटी के कारण पारिवारिक समस्याएँ आती हैं। ड्यूटी स्थान व समय की अनिश्चितता व रात्रि ड्यूटी से दिक्कत होती है।

महिला पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी के सम्बन्ध के सर्वाधिक 25 प्रतिशत मत इसको दिये हैं कि ड्यूटी का समय निश्चित होना चाहिए। 13 प्रतिशत ने कहा कि 8 घण्टे ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए, यानि कुल 38 प्रतिशत मानते हैं कि कुछ निश्चित समय की ही ड्यूटी होनी चाहिए।

10 प्रतिशत मानती है कि 24 घण्टे की ड्यूटी से विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं। 12 प्रतिशत ने कहा कि रात्रि की ड्यूटी में परेशानी होती है अतः दिन की ड्यूटी मिलनी चाहिए।

36 प्रतिशत महिला आरक्षियों की रात्रि ड्यूटी में असुविधा होती है। 16 प्रतिशत शहर से बाहर की ड्यूटी में असुविधा महसूस करती हैं, 9 प्रतिशत ने कार्यालय ड्यूटी में सुविधा महसूस करती हैं।

50 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने कहा, कि जनपद से बाहर की ड्यूटी में असुविधा महसूस होती है। 25 प्रतिशत ने रात्रि ड्यूटी में असुविधा महसूस की है।

100 प्रतिशत महिला निरीक्षक भी मानती हैं कि शहर से बाहर की ड्यूटियों में असुविधा होती है। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक ने भी मेला, त्यौहार, रात्रि व वी०आई०पी० ड्यूटी में असुविधा महसूस की है।

इन असुविधाओं में अगर हम देखें तो लगभग सभी पदों की महिलाओं ने रात्रि एवं शहर से बाहर की ड्यूटी में असुविधा महसूस की है। क्योंकि शहर से बाहर जाने पर रहने, खाने एवं आवागमन की असुविधाएँ होती हैं।

ड्यूटी के दौरान तरह-तरह की दिक्कतें आती हैं। तो पदानुसार विभिन्न मत प्रस्तुत किये हैं उन सबका निष्कर्ष यदि हम देखें तो लगातार ड्यूटी से शारीरिक थकान, मानसिक व पारिवारिक तनाव मिलता है या रात्रि एवं शहर की ड्यूटीयों में

शारीरिक कष्ट है, या नारी सुलभ क्रियाओं या बीमारी के दौरान ड्यूटी में शारीरिक व मानसिक कष्ट होता है। सभी पदों में ये दिक्कत दिखाई देती है वो है कि लगातार काम के कारण समयभाव से उत्पन्न दिक्कतें और आराम न मिलने के कारण दिक्कतें आती हैं।

20 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी का फायदा उठाया है। 46 प्रतिशत एकदम मना किया है, 11 प्रतिशत ने कभी-कभी स्वीकार किया है एवं 18 प्रतिशत मानती हैं कि अपने आप पदों के अनुसार मिल जाता है, बिना प्रयास के और 5 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। 26 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी भी मानती हैं कि महिला पुलिस ने अपनी नौकरी का फायदा उठाया है, 14 प्रतिशत मना करते हैं, 5 प्रतिशत कभी-कभी कहते हैं, 5 प्रतिशत उन्हें अपने आप मिल जाता है, 51 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। स्पष्ट रूप से हों में 20 प्रतिशत मत महिला पुलिस ने एवं 26 प्रतिशत पुरुष पुलिस के बारे में कहते हैं। इसका मतलब है कि ये सही है कि कम से कम 20 प्रतिशत तो लाभ उठाती ही हैं।

55 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती हैं कि उनकी यूनीफॉर्म ठीक है। 16 प्रतिशत मानती हैं कि परिस्थितियों के अनुसार परिधान धारण की सुविधा होनी चाहिए। 55 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी मानती हैं कि वर्दी उचित है, जबकि 15 प्रतिशत मानती हैं कि परिस्थितियों के अनुसार धारण करने की सुविधा होनी चाहिए। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक भी मानती हैं कि वर्दी ठीक है। 100 प्रतिशत महिला अधीक्षक भी मानती हैं कि परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदल लेने की छूट होनी चाहिए। 100 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी भी मानती हैं कि वर्दी ठीक है।

इन मतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अधिकांशतः महिला पुलिस मानती हैं कि उनकी वर्दी अच्छी है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में जैसे-उम्र के साथ मोटापे के बढ़ने के बाद या गर्भावस्था या महीने के कुछ दिनों में वर्दी में साड़ी या शलवार कुर्ता धारण करने की छूट होनी चाहिए, क्योंकि कार्य स्थल पर मूलभूत सुविधाएँ (शौचालय इत्यादि) सभी जगह उपलब्ध नहीं हैं, और 24 घंटे की लगातार ड्यूटी से मानसिक तनाव व शारीरिक परेशानियाँ आती हैं।

69 प्रतिशत महिला पुलिस मानती है कि उनके प्रति परिवार के सदस्यों का व्यवहार आम महिला की ही तरह होता है। लेकिन 31 प्रतिशत मानती है कि उनके प्रति व्यवहार खास महिला की तरह होता है, उन्हें कुछ अलग समझा जाता है।

77 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती है कि महिलाओं का इस विभाग में आना उचित है। 23 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती है कि महिलाओं का इस विभाग में आना उचित नहीं है।

उचित नहीं है, इसको मानने में आरक्षियों और उपनिरीक्षकों के पदों पर तैनात महिला पुलिसकर्मी हैं। सामान्य सूचनादाता एवं पुरुष पुलिस भी तो यही मानते हैं, कि यदि उनकी बहन, बेटी इस विभाग में आये भी तो केवल राजपत्रित पदों पर, अराजपत्रित पद पर नहीं क्योंकि इन पदों में दिक्कतें ज्यादा हैं।

महिला पुलिस कर्मियों के विभाग में संशोधन पर सुझाव

महिला पुलिस ने विभाग में निम्नलिखित संशोधन करने का सुझाव दिया है जो कि पदानुसार विभिन्न प्रकार के हैं।

महिला आरक्षियों के सुझाव निम्नलिखित हैं।

- (1) कार्य के घटे निश्चित हो।
- (2) आवास की सुविधा होनी चाहिए।
- (3) स्थानान्तरण निश्चित समय बाद हो।
- (4) पदोन्नति समय से वरिष्ठता के आधार पर दी जाय।
- (5) महिला पुलिस की संख्या पुरुष पुलिस के बराबर कर दी जाय यानि 50 प्रतिशत महिला पुलिस का होना चाहिए।
- (6) अन्य विभिन्न सुझाव निम्नलिखित हैं—
 - (i) बच्चों के लिए स्कूल का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए।
 - (ii) महिला पुलिस को सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए।
 - (iii) दूसरे जिलों में मेले वगैरह में ड्यूटी नहीं मिलना चाहिए।

- (iv) रात्रि ड्यूटी में छोटा हथियार देना चाहिए।
- (v) वेतन में बढोत्तरी हो।
- (vi) अधिकारीगण उनकी बातों को भी सुने।
- (vii) इस विभाग में दण्डात्मक कार्यवाही तुरन्त होती है, लेकिन यह अच्छी प्रकार से जाँच करने के बाद ही होनी चाहिए।
- (viii) महिला उत्पीडन के मामलों में महिला अधिकारी व कर्मचारी को शक्ति (अधिकारियों का सहयोग) प्रदाना करना, ताकि महिला उत्पीडन के मामलों में रोकथाम हो सके, अपराधों की संख्या में कमी आए क्योंकि महिला पुलिस कर्मी भी उस स्तर से कहीं न कहीं गुजर चुकी हैं।

पहले सुझावों को देने वाली महिला आरक्षियों का प्रतिशत 21 (12) है, दूसरे का प्रतिशत 16 (9), तीसरे का प्रतिशत 12, संख्या (7), चौथे का प्रतिशत 10 (6), पाँचवें का प्रतिशत 12 (7), है। छठे का प्रतिशत 14, (8) 16 प्रतिशत (9) महिला पुलिस ने अपने सुझाव व्यक्त नहीं किये हैं।

महिला उपनिरीक्षकों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:-

- (1) कार्य के घटे निश्चित हो।
- (2) आवास की सुविधा होनी चाहिए।
- (3) महिला पुलिस को पुरुष पुलिस के बराबर महत्व दिया जाय।
- (4) अन्य विभिन्न सुझाव निम्नलिखित हैं—
 - (i) समय से आवश्यकता पर छुट्टी मिलनी चाहिए।
 - (ii) सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए।
 - (iii) महिला पुलिस के प्रति अच्छा दृष्टिकोण एवं अधिकारियों का सहयोग मिलना चाहिए।

पहले सुझाव को 25 प्रतिशत (5), दूसरे को 20 प्रतिशत (4), तीसरे को 35 प्रतिशत (7) चौथे सुझाव जिसमें विभिन्न मत हैं को 15 प्रतिशत (3) मत दिये एवं 5 प्रतिशत (1) ने कोई सुझाव नहीं दिये।

महिला निरीक्षक सुझाव देती हैं कि काम के घंटे निश्चित हों। महिला उपाधीक्षक सुझाव देती हैं कि महिला सम्बन्धी कार्यगत परेशानियों से सम्बन्धित उपाय होने चाहिए। भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी कहती हैं कि उनकी अधीनस्थ महिला पुलिस को बड़ी जिम्मेदारी के कार्य सौंपने चाहिए ये मत 33 प्रतिशत (1) का है एवं 67 प्रतिशत (2) ने कोई सुझाव नहीं दिया है।

शोधार्थी के सुझाव

महिला पुलिस के साथ-साथ शोधार्थी के भी अपने सुझाव हैं जो कार्य करने के दौरान उसने महसूस किया। जो निम्नलिखित हैं।

- (1) पुलिस कर्मियों को 24 घंटे का नौकर नहीं माना जाना चाहिए, भूतकाल में इसका कोई औचित्य रहा होगा लेकिन आज यह निरर्थक है। काम के घंटे के विषय में एक व्यवहारिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

महिला पुलिस कर्मियों पर कार्यक्षेत्र और परिवार का उत्तरदायित्व होने के कारण निश्चित समयावधि की ड्यूटी उन्हें दोनों ही क्षेत्रों में अधिक सक्षम सिद्ध करेगी। अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त भत्ता दिया जाना चाहिए।

- (2) जल्दी-जल्दी और दुर्भावनावश किये गये स्थानान्तरण भी महिला पुलिस कर्मियों के मनोबल को प्रभावित करते हैं। अतः स्थानान्तरण कुछ निश्चित समयावधि के पश्चात् ही अन्य जनपदों में हो।

- (3) प्रस्तुत शोध में 53 प्रतिशत महिला पुलिस मानती हैं कि उनके वेतन और भत्ते पारिवारिक गतिविधियों हेतु अपर्याप्त हैं और 53 प्रतिशत

महिला पुलिस स्वीकार करती है कि उन्होंने अपनी नौकरी का फायदा भी उठाया है चाहे वो अपने आप मिल गया हो या कभी-कभी उठाया हो या स्पष्ट रूप से उठाया हो।

अतः यदि हम ये अपेक्षा रखते हैं कि पुलिस कर्मी हमें बिना किसी तरह से भ्रष्ट हुए हमें अपनी सेवाएँ प्रदान करें तो जरूरी है कि उनका वेतन उनकी कार्यगुणता के आधार पर हो। अतः वेतन में संशोधन होना आवश्यक है।

- (4) पदोन्नति समय से वरिष्ठता के आधार पर दी जानी चाहिए, जिससे कार्य में उत्साह बना रहे और समाज को उनका सकारात्मक योगदान प्राप्त हो।
- (5) महिला पुलिस की संख्या में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए, जिससे कार्यक्षेत्र में महिला पुलिस की कुछ परेशानियाँ दूर होंगी।
- (6) कार्यक्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ (शौचालय इत्यादि) उपलब्ध करानी चाहिए।
- (7) नारी सुलभ समस्याओं के कारण वर्दी में परिवर्तन तो नहीं लेकिन परिस्थितियों के अनुसार साड़ी या शलवार-कुर्ता पहनने की छूट होनी चाहिए।
- (8) महिला पुलिस के प्रति भारतीय समाज के स्त्री और पुरुष दोनों को अपनी बँधी मानसिकता के संकीर्ण दायरे से बाहर आकर इनके प्रति दृष्टिकोण को स्वस्थ और व्यापक बनाना आवश्यक है। उनके कार्य और उपस्थिति को पुरुष पुलिस कर्मी के समकक्ष महत्व देना चाहिए। समानता की स्थिति उनके आत्म विश्वास का आधार बनेगी, जो उनके कार्य की इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करेगी।

- (9) महिला पुलिस की रात के समय थाने या चौकी पर ड्यूटी तभी हो जबकि इनके साथ कम से कम तीन या चार अन्य महिला पुलिस कर्मी भी ड्यूटी पर हो, अकेले ड्यूटी में वे असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहती हैं।

रात के समय किसी दबिश पर या घटना स्थल पर केवल तभी इन्हें साथ ले जाया जाए, जबकि घटना किसी महिला से सम्बन्धित हो। जैसे—दहेज, बलात्कार या रेड लाइट एरिया आदि।

- (10) रात के समय ड्यूटी के लिए इन्हें घर से ले आने और जाने के लिए जरूरी साधन उपलब्ध कराये जाए जिससे रास्ते की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। जिनका घर दूर है उन्हें ये सहायता अवश्य दी जानी चाहिए।

- (11) महिला पुलिस को बाहर के व्यक्तियों से सहयोग की अपेक्षा घर के सदस्यों का सहयोग ज्यादा मजबूत बनाता है। पति और बच्चों के अलावा अन्य सबन्धियों का उनके कार्य के प्रति सकारात्मक रुख इन्हें भावात्मक सहयोग देकर कार्य के उत्तम परिणामों को सामने लाने में आवश्यक सहायक होगा। इनके कार्य के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि से इन्हें बचाना होगा जो इन्हें हतोत्साहित करती हैं।

- (12) कार्य क्षेत्र के पुरुष सहयोगियों और अधिकारियों को भी इनके कार्यों और उपस्थिति को सामाजिक आवश्यकता को स्वीकार करके उपहास पूर्ण दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। मात्र हँसी मजाक और समय व्यतीत करने के साधन के रूप में उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने की सोच को नई दिशा देने की आवश्यकता है। यद्यपि सभी पुरुष पुलिस कर्मी ऐसा नहीं सोचते हैं। बदले सकारात्मक वातावरण में ही इनके कार्यों के नये क्षितिज इनकी महत्ता व उपस्थिति के नये आयाम उद्घाटित करेंगे और सही मायनों में भारतीय समाज और सोच को आधुनिक बनाने की असली पहल होगी।

संदर्भ-सूची

- 1 उत्तर प्रदेश, 2002, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ० प्र०।
- 2 एफ० एन० कर्लीजर, फाउन्डेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च।
- 3 क्राइम इन इंडिया (1995), पृ० 329
- 4 क्राइम इन उत्तर प्रदेश-1 990, स्टेट क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो, लखनऊ, पृ० 111-113
- 5 जानसन, हैरी एम०, सोशियोलॉजी, ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन, लन्दन 1963
- 6 नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट, प्रथम, पृ० 15
- 7 नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट।
- 8 पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद।
- 9 पी० वी० यग, साइन्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड सोशल रिसर्च।
- 10 मर्टन, आर० के० सोशल स्ट्रक्चर एण्ड सोशल थ्यरी - फ्री प्रेस 1963, पृ० 668-71
- 11 लखनऊ सिटी मैगजीन, दिसम्बर 1988, प्रिन्टडएट प्रकाश पैकजर्स, 257, गोलगज, लखनऊ, लेख-एन्स इन साइड व्यू, पृ० 12
- 12 लिटन रॉल्फ, द स्टडी ऑफ चैन, पृ० 113-119
13. संविधान के प्रथम एवं चतुर्थ संशोधन आदेश 1960 (G O 3 Dec 25 01 1950)
- 14 हाईमेन, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेट्स (1942), लेख।